भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित)

61वीं वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

कुलाधिपति

श्री राजेश अग्रवाल
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य भवन
नई दिल्ली–110001

आईआईएफटी प्रबंधन बोर्ड

अध्यक्ष

प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी
कुलपति
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
बी–21, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली–110016.

सदस्य

श्री अजय भादू
अतिरिक्त सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य भवन
नई दिल्ली–110011
ईमेल: astpd-doc@nic.in

सुश्री पेटल ढिल्लन
संयुक्त सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य भवन
नई दिल्ली–110011
ईमेल: petal.dhillon@nic.in

श्री पी एस गंगाधर
संयुक्त सचिव (इ.डी.)
विदेश मंत्रालय, कमरा नम्बर –1067
ए विंग, पहली मंजिल
जवाहरलाल नेहरू भवन
नई दिल्ली.
ईमेल: jsed@mea.gov.in

आई आई एफ टी संकाय

डॉ. के. रंगाराजन
प्रमुख, कोलकाता परिसर
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
प्लॉट नंबर 1583, मदुरदाहा, वार्ड नंबर 108
ईएम बाईपास, रूबी अस्पताल के निकट
कोलकाता–700107
ईमेलः head_kol@iift.edu

डॉ. राम सिंह
प्रमुख (सीडीओई)
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
बी–21, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली–110016
ईमेलः headcdoe@iift.edu

डॉ. एम. वेंकटेसन
प्रोफेसर
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
बी–21, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली–110016.
ईमेलः venkatesan@iift.edu

डॉ. जैकलीन सिम्स
एसोसिएट प्रोफेसर
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
बी–21, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली–110016.
ईमेलः jsymss@iift.edu

सचिव

श्री गौरव गुलाटी
कुलसचिव
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
बी–21, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली–110016.
ईमेलः registrar@iift.ac.in

विषय

1 समीक्षागत वर्ष

2 2024-25 में आईआईएफटी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां : त्वरित चित्र

3 आईआईएफटी का संस्थागत ढांचा

4 शिक्षा और प्रशिक्षण

5 आईआईएफटी में शोध

6 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7 कार्यकारिणी प्रबंधन कार्यक्रम

8 आई आई एफ टी में उत्कृष्टता के केंद्र

9 कॉर्पोरेट संबंध और प्लैस्मेंट प्रभाग

10 छात्र गतिविधियाँ 2022-23

11 उद्योग, व्यापार और वाणिज्य जगत संबंधी संपर्क

12 विदेश व्यापार पुस्तकालय

13 कंप्यूटर केंद्र और आई टी सहायक सेवाएं

14 पत्रिका प्रभाग

15 राजभाषा हिन्दी की गतिविधियां

16 वार्षिक लेखा

17 आईआईएफटी संकाय

18 आईआईएफटी प्रशासन

19 आईआईएफटी सहायक सेवाएं

20 अतिथि संकाय

21 स्थायी सदस्य

वर्ष की समीक्षा

(भारत की वैश्विक विकास संबंधी चिंताएँ और चुनौतियाँ)

प्रस्तावना

आर्थिक विकास सामान्यतः विभिन्न देशों और क्षेत्रों में आर्थिक और वित्तीय कल्याण, उत्पादक क्षमता और जीवन स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया से संबंधित है। व्यापार, विकास, रोज़गार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और एकीकरण को बढ़ावा देकर वैश्विक आर्थिक विस्तार के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में कार्य करता है। प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति, जलवायु संबंधी पहलों और बदलते भू-राजनीतिक गठबंधनों ने आर्थिक विकास पर व्यापार के प्रभाव को बढ़ा दिया है। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी, ऋण संकट और भू-राजनीतिक तनावों से असमान रूप से उबर रही है, नियमों, प्रोत्साहनों और यहाँ तक कि प्रमुख हितधारकों की भी पुनर्परिभाषा हो रही है। परिणामस्वरूप, वैश्वीकरण के पारंपरिक मॉडल समीक्षा के दायरे में हैं क्योंकि राष्ट्र न केवल आर्थिक सुधार, बल्कि लचीलेपन, स्थिरता और रणनीतिक स्वतंत्रता की भी तलाश कर रहे हैं। (फोर्सगेट, 2025)

देश और क्षेत्र वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के संबंध में उत्तरोत्तर सक्रिय रुख अपना रहे हैं। वे अपनी व्यापार, औद्योगिक और पर्यावरण नीतियों की गहन समीक्षा कर रहे हैं ताकि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जा सके जो अधिक मज़बूत, टिकाऊ और लचीली हों। ऐतिहासिक रूप से, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मुख्यतः उनकी दक्षता के लिए सराहा जाता था; हालाँकि, अब उनकी कमज़ोरियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप आत्मनिर्भरता और रणनीतिक क्षेत्रों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। (राइजिंगर, 2025)। साथ ही, अग्रणी अर्थव्यवस्थाएँ महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय औद्योगिक रणनीतियों को क्रियान्वित कर रही हैं, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और भविष्योन्मुखी रोज़गार के अवसरों के लिए पर्याप्त निवेश आवंटित कर रही हैं। (आईईए, 2023) हालाँकि, जहाँ ये प्रयास जलवायु परिवर्तन से निपटने और उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए हैं, वहीं इन्होंने समानता, संरक्षणवाद और वैश्विक समावेशिता के बारे में महत्वपूर्ण बहसों को भी जन्म दिया है।

भारत के लिए, ये परिवर्तन अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करते हैं। सबसे तेज़ी से विस्तार करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते, भारत अपने घरेलू उद्योगों और विकास संबंधी प्राथमिकताओं की सुरक्षा करते हुए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपने एकीकरण को बढ़ाना चाहता है। फिर भी, भारत के सामने कई गंभीर चिंताएँ हैं: एक खंडित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का प्रबंधन, कार्बन सीमा समायोजन जैसे एकतरफा व्यापार और जलवायु उपायों का जवाब देना, और वैश्विक पर्यावरणीय अपेक्षाओं को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना। भारत की संरचनात्मक समस्याओं, जिनमें बुनियादी ढाँचे की कमियाँ, ऊर्जा पर निर्भरता, और अपनी विशाल जनसंख्या को लाभ पहुँचाने वाले समान विकास की खोज शामिल है, के कारण ये चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं।

इस पृष्ठभूमि में, यह रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक विकास के उभरते परिदृश्य की पड़ताल करती है, जिसमें भारत की चिंताओं और चुनौतियों पर विशेष जोर दिया गया है। यह वैश्विक व्यापार नीति के तीन आयामों का स्पष्ट विश्लेषण करती है: बहुपक्षीय मुद्दे, एकतरफा दबाव और पर्यावरणीय विचार। इन विषयों में, हमारा उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि भारत को एक बढ़ती हुई अनिश्चित और विवादास्पद वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ते हुए विभिन्न मुद्दों के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए।

1. बहुपक्षीय मुद्दे

समकालीन व्यापार ढाँचे के भीतर बहुपक्षवाद के सामने आने वाले दबावों को समझने के लिए, वैश्विक व्यापार प्रणाली के विकास का विश्लेषण करके उदारीकरण की ऐतिहासिक प्रगति की जाँच करना आवश्यक है। 1996 से 2023 तक, दुनिया भर में लागू औसत सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) टैरिफ दर 12.5% से घटकर 8.5% हो गई। फिर भी, इस कमी का केवल एक प्रतिशत अंक विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत आयोजित बहुपक्षीय वार्ताओं के कारण था। इसके विपरीत, शेष तीन प्रतिशत अंक अलग-अलग राष्ट्रों द्वारा लागू एकतरफा टैरिफ कटौती के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। (बैचेटा, 2025)

चित्र 1
वैश्विक औसत MFN टैरिफ दर में बहुपक्षीय और एकतरफा कटौतियों का योगदान

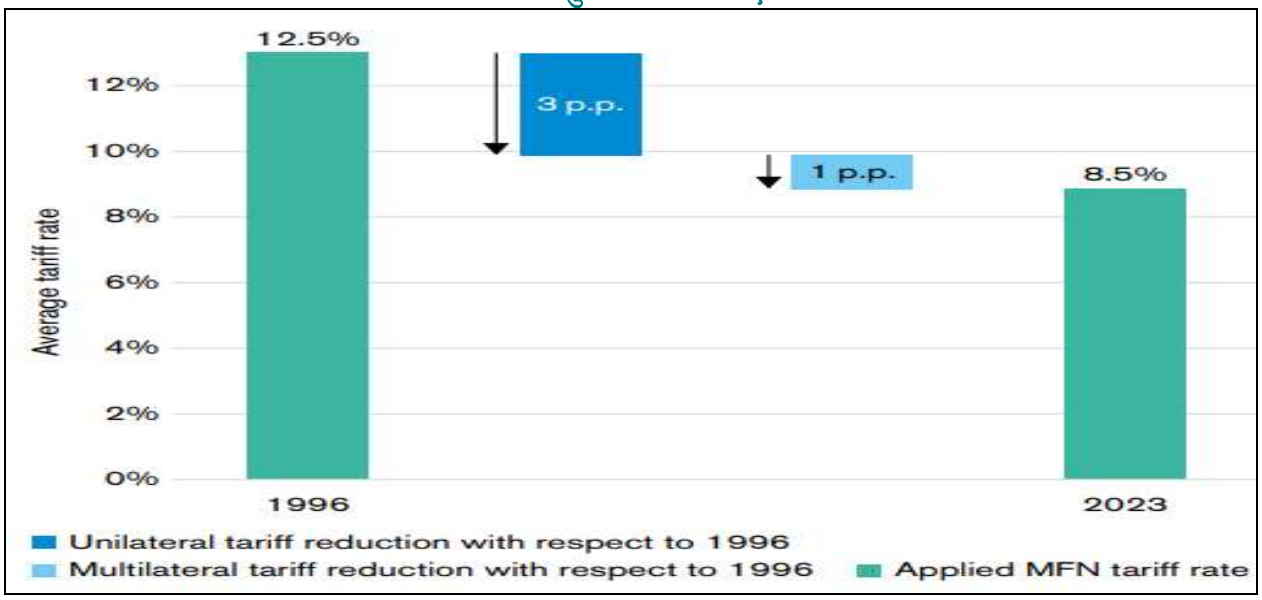

स्रोत: लागू MFN और बाध्य टैरिफ दरों पर WTO डेटा।

नोट: यह आंकड़ा औसत लागू MFN टैरिफ दर में बहुपक्षीय और एकतरफा कटौतियों के बीच प्रतिशत अंकों (प्रतिशत) में व्यक्त कमी को दर्शाता है।

यह पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन में एक व्यापक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जहाँ विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत पारंपरिक सहमति-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेजी से अधिक लचीली, मुद्दा-विशिष्ट व्यवस्थाओं जैसे कि बहुपक्षीय समझौतों और संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। हालाँकि ये पहल तकनीकी रूप से सभी WTO सदस्यों के लिए खुली हैं, ये कानूनी रूप से केवल हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी हैं और इनके लिए सार्वभौमिक सहमति की आवश्यकता नहीं है, जिससे पारदर्शिता, समावेशिता और वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोणों के बहिष्कार को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। भारत ने इस बदलाव के खिलाफ लगातार चेतावनी दी है, इसे निष्पक्ष नियम-निर्माण और कृषि, डिजिटल विनियमन और औद्योगिक समर्थन सहित अपनी घरेलू प्राथमिकताओं के लिए आवश्यक नीतिगत गुंजाइश के लिए खतरा माना है।

1.1 संयुक्त वक्तव्य पहल

हाल के वर्षों में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने बहुपक्षीय समझौतों की ओर एक बदलाव देखा है, जिन पर सदस्यों के एक उपसमूह द्वारा बातचीत की जाती है और ये केवल उन्हीं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं जो सदस्यता लेना चुनते हैं। ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा, सेवा विनियमन और MSME समर्थन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI) के माध्यम से ऐसे कई समझौते सामने आ रहे हैं। हालाँकि ये समझौते तकनीकी रूप से सभी WTO सदस्यों के लिए सुलभ हैं, लेकिन ये पारंपरिक आम सहमति-आधारित प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार नियमों के निर्माण में समावेशिता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। JSI अक्सर व्यापार नियमों के विखंडन में योगदान करते हैं, और संभवतः JSI में भाग नहीं लेने वाले सदस्यों को उभरते अंतर्राष्ट्रीय मानकों, विशेष रूप से डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में, के विकास से बाहर कर देते हैं।

दूसरा पहलू भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के समक्ष आने वाले नुकसान से संबंधित है, जिन्होंने संयुक्त व्यापार समझौतों (जेएसआई) की वैधता और निष्पक्षता को चुनौती दी है और दावा किया है कि ये बहुपक्षवाद को कमजोर करते हैं और परिणामस्वरूप कुछ विश्व व्यापार संगठन सदस्यों को नुकसान में डालते हैं। इसके अलावा, इन व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप कुछ सदस्यों के लिए नीतिगत गुंजाइश कम हो रही है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, जिसने घरेलू नियामक स्वायत्तता की रक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधानों (जैसे, डेटा प्रवाह, स्रोत कोड नियम) के लिए समर्थन वापस ले लिया है। भारत ऐसी व्यवस्थाओं को विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय भावना के लिए हानिकारक मानता है, जो समान भागीदारी और आम सहमति

के सिद्धांतों पर आधारित है। यह आशंका है कि इच्छुक सदस्यों के गठबंधन के बीच नियम-निर्माण की अनुमति देने से विकासशील देश हाशिए पर आ सकते हैं और मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के बिना गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं पर नियम थोपे जा सकते हैं। (मानक, 2025)

इसका एक विशिष्ट उदाहरण विकास के लिए निवेश सुविधा (आईएफडी) समझौते का भारत द्वारा विरोध है, जिस पर 130 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं—जिनमें 89 विकासशील देश और 27 अल्प-विकसित देश शामिल हैं—क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने पहले ही यह प्रतिबद्धता जताई थी कि वे बिना सर्वमान्य सहमति के व्यापार वार्ता में निवेश के मामलों को शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा, भारत ने डेटा गोपनीयता, डिजिटल कराधान और डिजिटल वस्तुओं पर सीमा शुल्क से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए ई-कॉमर्स पर संयुक्त वक्तव्य पहल (जेएसआई) में भाग लेने से परहेज किया है—ये मुद्दे इतने जटिल और संवेदनशील माने जाते हैं कि चुनिंदा बातचीत के ज़रिए इनका समाधान नहीं किया जा सकता। (दोशी, 2024)।

भारत इस बात पर ज़ोर देता है कि व्यापार नियमों का विकास एक पारदर्शी, समावेशी और आम सहमति से संचालित प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, ताकि विकासशील देशों के पास अपनी डिजिटल और व्यापार नीतियाँ तैयार करने के लिए पर्याप्त स्थान और समय हो। भारत आगाह करता है कि बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं में जल्दबाजी, विशेष रूप से डिजिटल व्यापार जैसे तेज़ी से बदलते क्षेत्रों में, नियामक संप्रभुता को कमज़ोर कर सकती है और आवश्यक नीतिगत लचीलेपन को कम कर सकती है।

1.2 कृषि सुधार

भारत की कृषि नीतियाँ, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इसकी स्थिति के संबंध में, केवल फसल प्रबंधन और सब्सिडी तक ही सीमित नहीं हैं; ये किसानों की आजीविका और वैश्विक कृषि की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। 26 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ, खाद्य सुरक्षा की रक्षा और ग्रामीण क्षेत्र को मज़बूत करना अनिवार्य है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सब्सिडी सीमा निर्धारित करने के आधार के रूप में 1986-1988 से बाह्य संदर्भ मूल्य ('ईआरपी') का उपयोग करना जारी रखता है, एक ऐसी प्रथा जिसे भारत पुराना मानता है। भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीतियां और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पहल वर्तमान में इन बेंचमार्क के कारण जांच के दायरे में हैं। आलोचकों का तर्क है कि 2022-2023 के दौरान चावल (87.85%) और गेहूं (67.54%) के लिए भारत का समर्थन स्तर डब्ल्यूटीओ द्वारा स्थापित सीमाओं से अधिक है; फिर भी, भारत इन आंकड़ों की सटीकता पर विवाद करता है। (शर्मा, 2024)। एओए विनियम 1980 के दशक के अंत में स्थापित ढांचे के अनुसार सब्सिडी को वर्गीकृत करते हैं भारत का कहना है कि उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यक्रम और सार्वजनिक भंडारण पहल, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 800 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करते हैं, को अनुचित रूप से इन स्थापित सीमाओं का उल्लंघन माना जाता है।

इसलिए, यह इन दावों से दृढ़ता से असहमत है, कह रहा है कि गणना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वे पुरानी कीमतों का उपयोग करते हैं, मुद्रा परिवर्तनों को अनदेखा करते हैं, और वास्तविक खरीद के बजाय कुल उत्पादन को गलत तरीके से गिनते हैं। भारत दोहरे मानदंडों को उजागर करता है: संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश कहीं अधिक सब्सिडी का आनंद लेते हैं। 2020 में, अमेरिका को चावल उत्पादन मूल्य के 576% के बराबर समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें किसानों को प्रति व्यक्ति 67 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई, जो उनके भारतीय समकक्षों की तुलना में लगभग 180 गुना अधिक है। इसी समय, यूक्रेन और अर्जेंटीना सहित भारत से पारदर्शिता की मांग करने वाले कई देश अधिसूचनाएं प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका नियमित रूप से समय सीमा चूक जाते हैं। भारत अकेला नहीं है। विकासशील देशों और समूहों का एक गठबंधन, जिसमें G33, अफ्रीकी समूह और ACP शामिल हैं, मांग करते हैं यहां तक कि ओईसीडी ने भी कहा है कि जब 2023 ईआरपी का उपयोग किया जाएगा, तो चावल के लिए 47.9 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 29.9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत की कृषि सब्सिडी नगण्य हो जाएगी। (शर्मा, 2024)।

1.3 विशेष एवं विभेदक व्यवहार

विश्व व्यापार संगठन के 166 सदस्यों में से 60% से अधिक विकासशील देश हैं; हालाँकि, इस बहुमत के पास शायद ही कभी महत्वपूर्ण बातचीत करने का प्रभाव होता है या विवाद समाधान में सफलता प्राप्त होती है। संरचनात्मक कमियाँ—जैसे सीमित सौदेबाजी क्षमता, संकीर्ण निर्यात आधार और कमज़ोर कानूनी ढाँचा—उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में हैं।

विशेष एवं विभेदक व्यवहार (S&DT) ने ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों को व्यापार दायित्वों को पूरा करने के लिए समय, लचीलापन और सहायता प्रदान करके समर्थन दिया है। फिर भी, अस्पष्ट प्रारूपण, सीमित प्रवर्तनीयता और चीन जैसी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के उदय ने सुधारों की माँग को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ से। 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आय स्तर, OECD या G20 सदस्यता, या वैश्विक व्यापार में 0.5% से अधिक योगदान जैसे मानदंडों के आधार पर देशों को S&DT से बाहर करने का प्रस्ताव रखा था। भारत और चीन सहित कई देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और तर्क दिया कि ऐसे मानदंड गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसे मौजूदा मुद्दों को ध्यान में नहीं रखते। भारत ने गरीबी, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास से जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए व्यापक और लचीले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&DT) की आवश्यकता पर लगातार ज़ोर दिया है।

कृषि वार्ताओं में, S&DT केंद्रीय बना हुआ है। कृषि समझौते का अनुच्छेद 6.2 ("विकास बॉक्स") कम आय वाले या संसाधन-विहीन किसानों को बिना किसी सीमा के सब्सिडी की अनुमति देता है। भारत के लिए, यह खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका का समर्थन करता है। तनाव इसलिए पैदा होता है क्योंकि विकसित देश बड़े पैमाने पर समग्र समर्थन मापन अधिकार रखते हैं, जो विशिष्ट वस्तुओं पर सब्सिडी केंद्रित करते हैं जबकि WTO के अनुरूप बने रहते हैं। अधिकांश विकासशील सदस्य न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग बनाए रखने के लिए न्यूनतम सीमा और S&DT लचीलेपन पर निर्भर करते हैं। भारत और G33, ACP, और अफ्रीकी समूह जैसे समूह अनुच्छेद 6.2 का बचाव करते हैं और TTDS फॉर्मूले के तहत सभी समर्थन को सीमित करने के केर्न्स समूह के प्रस्तावों का विरोध करते हैं। (शर्मा, 2024)।

भारत ने मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता में संक्रमण काल को बढ़ाने की भी वकालत की है, जिसे कई सदस्यों ने समझौते को कमज़ोर करने वाला माना। (कुमार, 2017)। भारत एक दोराहे पर खड़ा है: उसे विकास आवश्यकताओं की रक्षा और एक ज़िम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में अपनी छवि के बीच संतुलन बनाना होगा। आगे का रास्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (S&DT) में सुधार करके उसे और अधिक सटीक, आवश्यकता-आधारित और लागू करने योग्य बनाना है।

तालिका 1
एस एंड डी टी प्रावधानों वाले प्रमुख डब्ल्यूटीओ समझौते

सख्या क्रम .	डब्ल्यूटीओ समझौते	प्रमुख एस एंड डी टी विशेषताएं
1	जीऐटीटी 1947/1994	अनुच्छेद XVIII विकासशील देशों को नवजात उद्योगों की सुरक्षा करने की अनुमति देता है; भाग IV (1965 में जोड़ा गया) विकास की आवश्यकताओं पर जोर देता है।
2	कृषि पर समझौता (AOA)	विकासशील देशों के लिए अधिक विस्तारित अवधि के लिए कार्यान्वयन करना तथा प्रतिबद्धताओं को कम करना (अनुच्छेद 6.2)।
3	(SCM) सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों पर समझौता (SCM)	सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों पर समझौता (SCM)
4	बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स)	एलडीसी के लिए आईपी नियमों का अनुपालन करने हेतु विस्तारित संक्रमण अवधि।
5	व्यापार सुविधा समझौता (TFA)	अनुरूप कार्यान्वयन कार्यक्रम और संबद्ध तकनीकी सहायता।
6	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS)	उदारीकरण प्रतिबद्धताओं और समय-निर्धारण में लचीलापन।
7	सक्षम करने वाला खंड (1979)	गैर-पारस्परिक अधिमान्य उपचार के लिए कानूनी आधार (जैसे, जीएसपी योजनाएं)।

स्रोत: लेखक.

1.4 मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ताएँ

वैश्विक मत्स्य पालन सब्सिडी व्यापार और पर्यावरणीय शासन में विवाद का विषय हैं क्योंकि अत्यधिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, बाज़ारों को विकृत करने और समुद्री संसाधनों को कम करने में उनकी भूमिका है। (मानक, 2025)।

विकसित और विकासशील देशों के बीच सब्सिडी के आवंटन में काफ़ी भिन्नता है। जून 2022 में 12वें विश्व व्यापार संगठन (WTO) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अनुमोदित मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। यह पारिस्थितिक चिंता को दूर करने और सतत विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाला पहला बाध्यकारी WTO समझौता है, और 1995 के बाद से यह केवल दूसरा बहुपक्षीय समझौता है। यह संधि अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मत्स्य पालन के साथ-साथ अत्यधिक मत्स्य पालन में योगदान देने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना और स्थायी मत्स्य पालन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। इस समझौते को परिचालन का दर्जा प्राप्त करने के लिए, इसे WTO के दो-तिहाई सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अंततः, विश्व व्यापार संगठन के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृति दस्तावेज़ जमा करने के बाद, यह समझौता 15 सितंबर 2025 को प्रभावी हो गया। (विश्व व्यापार संगठन, 2025)

चित्र 2
विभिन्न देशों और सब्सिडी प्रकारों में मत्स्य पालन सब्सिडी का वैश्विक आवंटन

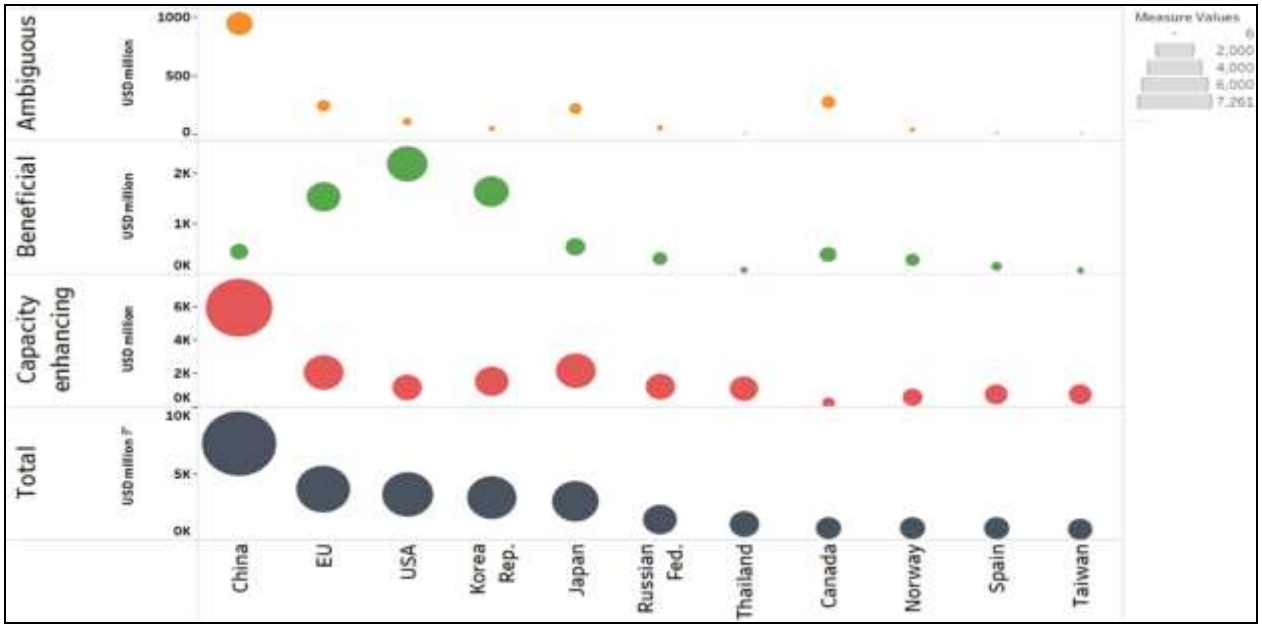

स्रोत: लेखकों द्वारा एफएओ, ओईसीडी, यूएनईपी, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, राष्ट्रीय बजट दस्तावेजों, आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों और पूरक समकक्ष-समीक्षित एवं ग्रे साहित्य पर आधारित संकलन।

चित्र 2 विभिन्न देशों और सब्सिडी प्रकारों में मत्स्य पालन सब्सिडी के वैश्विक आवंटन को दर्शाकर भारत की चिंताओं का अनुभवजन्य समर्थन करता है। भारत ने एक दृढ़ रुख अपनाया है और कहा है कि छोटे पैमाने के मछुआरे, विशेष रूप से 12 समुद्री मील से आगे के, अपनी आजीविका के लिए सब्सिडी पर निर्भर हैं। इसने आगाह किया कि इन सब्सिडी में व्यापक कटौती उन लाखों लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है जो अपनी आय और जीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने समानता संबंधी चिंताएँ व्यक्त कीं: वर्तमान मत्स्य पालन क्षमता को बनाए रखने से यूरोपीय संघ और जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है, जबकि यह विकासशील देशों की विकास संभावनाओं को बाधित करता है। (कुमार, 2017)। सबसे हानिकारक और क्षमता बढ़ाने वाली सब्सिडी मुख्य रूप से चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया जैसी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित हैं, जो विशेष रूप से ईंधन, पोत निर्माण और आधुनिकीकरण पहलों का समर्थन करती हैं। इसके विपरीत, स्टॉक प्रबंधन के लिए लाभकारी सब्सिडी तुलनात्मक रूप से कम हैं और उनमें अनियमितताएँ अधिक हैं। विस्तारित संक्रमण अवधि और व्यापक लचीलेपन की भारत की वकालत

का विरोध हुआ, आलोचकों का तर्क था कि इससे समझौते की अवहेलना हुई और तत्काल सुधारों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। (भटनागर, 2025)

1.5 विशिष्ट शुल्क चुनौतियाँ (AVEs)

भारत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ढाँचे और नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) दोनों के अंतर्गत काफी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं में विशिष्ट शुल्क शामिल हैं जो यथामूल्य (add valorem) के संदर्भ में सुसंगत नहीं हैं, और ऐसे शुल्क वर्तमान में मौजूदा रिपोर्टिंग प्रारूपों, पारदर्शिता तंत्रों और बहुपक्षीय व्यापार विनियमों द्वारा स्थापित पूर्वानुमान प्रणालियों के अंतर्गत पारदर्शी नहीं हैं। विशिष्ट शुल्कों का महत्व वस्तुओं की प्रति इकाई (उदाहरण के लिए, ₹50 प्रति किलोग्राम) पर स्थिर शुल्क के रूप में उनकी प्रकृति में निहित है, जबकि यथामूल्य शुल्कों की गणना वस्तुओं के मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है। ये स्थिर शुल्क वास्तविक टैरिफ भार को अस्पष्ट कर सकते हैं, खासकर जब वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। उदाहरण के लिए, ₹100 प्रति किलोग्राम की कीमत वाली वस्तु पर ₹50 प्रति किलोग्राम का शुल्क 50% टैरिफ का प्रतिनिधित्व करता है; हालाँकि, यदि कीमत घटकर ₹50 प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो प्रभावी टैरिफ दोगुना होकर 100% हो जाता है।

कई विकसित देश मुख्यतः अपने घरेलू कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट शुल्क लगाते हैं। हालाँकि, ऐसे शुल्क अक्सर विश्व व्यापार संगठन के पारदर्शिता मानकों को दरकिनार कर देते हैं, जो मुख्यतः यथामूल्य शुल्कों पर ज़ोर देते हैं। यूरोपीय संघ और जापान उन विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में शामिल हैं जो अपने कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट शुल्क लगाते हैं। यूरोपीय संघ और जापान जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए कृषि एक संवेदनशील क्षेत्र है, जो खेती को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील मानते हैं। विशिष्ट शुल्क—प्रति इकाई निश्चित शुल्क (उदाहरण के लिए, पनीर का प्रति किलोग्राम €X)— यथामूल्य शुल्कों की तुलना में कम पारदर्शी होते हैं और मूल्य में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए इन्हें समायोजित किया जा सकता है। कृषि के अलावा, कुछ औद्योगिक उत्पाद, जैसे कपड़ा या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, भी इन शुल्कों से सुरक्षित रहते हैं, जो कम लागत वाले आयातों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब शुल्क प्रति इकाई के आधार पर लगाए जाते हैं, तो उनका सुरक्षात्मक प्रभाव बाज़ार की कीमतों के साथ बदलता रहता है। यह परिवर्तनशीलता निगरानी को जटिल बनाती है और विश्व व्यापार संगठन की पारदर्शिता एवं अधिसूचना तंत्र के भीतर पारदर्शिता को कम करती है।यूरोपीय संघ की साझा कृषि नीति (CAP) ने ऐतिहासिक रूप से डेयरी, मांस और चीनी क्षेत्रों की रक्षा के लिए टैरिफ-दर कोटा और विशिष्ट शुल्कों का इस्तेमाल किया है। मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के संदर्भ में भी, ये शुल्क अक्सर "संवेदनशील" उत्पादों के लिए धीरे-धीरे समाप्त कर दिए जाते हैं या बरकरार रखे जाते हैं। जापान सूअर के मांस के लिए गेट मूल्य प्रणाली और चावल, गेहूँ और डेयरी उत्पादों के लिए राज्य व्यापार जैसी व्यवस्थाओं का उपयोग करता है, जो विशिष्ट शुल्कों को कोटा के साथ जोड़ती हैं। ये प्रणालियाँ विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकताओं का औपचारिक अनुपालन बनाए रखते हुए घरेलू उत्पादकों की प्रभावी रूप से रक्षा करती हैं। (कल्लुमल, 2015)

2. एकतरफा मुद्दे

वैश्विक व्यापार प्रशासन में एकतरफा व्यापार उपाय एक विवादास्पद मुद्दा बन गए हैं, खासकर जब विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत बहुपक्षवाद गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए एकतरफा टैरिफ, नियामक मानकों और गैर-टैरिफ बाधाओं को तेजी से लागू कर रही हैं। भारत जैसे देशों के लिए, इन उपायों का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है, जो अल्पकालिक व्यापार प्रवाह और निर्यात क्षेत्रों की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता, दोनों को प्रभावित करते हैं। यह अध्याय एकतरफा उपायों की तीन श्रेणियों की पड़ताल करता है: गैर-टैरिफ उपाय (एनटीएम), धारा 232 और धारा 301 की कार्रवाइयाँ, और पर्यावरण-लेबलिंग आवश्यकताएँ, साथ ही प्रत्येक से संबंधित भारत की विशिष्ट चिंताओं और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।

2.1. गैर-टैरिफ उपाय (एनटीएम)

पिछले बीस वर्षों में गैर-टैरिफ उपायों (एनटीएम) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो अक्सर व्यापार को विनियमित करने के प्राथमिक साधन के रूप में टैरिफ का स्थान ले लेते हैं। एनटीएम में अब उत्पाद मानक, लाइसेंसिंग, कोटा, लेबलिंग आवश्यकताएँ और प्रक्रियात्मक नियम शामिल हैं, जिन्हें अक्सर उपभोक्ता सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण जैसे कारणों से उचित ठहराया जाता है, लेकिन ये

अक्सर व्यापार में छिपी बाधाओं का काम करते हैं। (कल्लुममल, खोसला, और गुरुंग, 2024)। इनका एकतरफा और खंडित अनुप्रयोग विकासशील देशों के निर्यातकों पर असमान रूप से बोझ डालता है, जिससे अनुपालन लागत बढ़ती है और बाजार में अनिश्चितता पैदा होती है।

स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय, विशेष रूप से अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल), भारत के कृषि निर्यात को प्रभावित करने वाली सबसे कठोर एकतरफा बाधाओं में से एक बन गए हैं। विकसित देश अक्सर एमआरएल निर्धारित करते हैं जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस द्वारा स्थापित मानकों से अधिक होते हैं, जिससे बाजारों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ पैदा होती हैं। ये एसपीएस-आधारित एमआरएल फर्मों की लागत बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रयोगशालाओं की क्षमता से परे परीक्षण की आवश्यकता होती है, और चूँकि भारत छोटे खेतों से स्रोत प्राप्त करता है, इसलिए प्रत्येक को यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कड़े एमआरएल के लिए परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। (कल्लुममल, गुरुंग, और खोसला, 2025)। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के भीतर अनुमेय कीटनाशक अवशेष सीमाओं में अचानक बदलाव के कारण भारतीय बासमती चावल की खेपों को बार-बार अस्वीकार किया गया है, जिससे व्यापार घाटा हुआ है और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है। (कल्लुममल और गुरुंग, 2020)।

एसपीएस उपायों के साथ-साथ, तकनीकी व्यापार बाधाएं (TBT), जैसे लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन और उत्पाद सुरक्षा मानक, महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। विभिन्न क्षेत्राधिकारों में सामंजस्य का अभाव अनावश्यक और महंगी अनुपालन आवश्यकताओं को जन्म देता है। अनुभवजन्य आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त एसपीएस अधिसूचना कृषि निर्यात में 0.3% की कमी करती है, जबकि टीबीटी अधिसूचनाएं, हालांकि कभी-कभी व्यापार को बढ़ावा देती हैं, फिर भी अनुपालन लागत बढ़ाती हैं। (कल्लुममल, खोसला, कुंडू, और सिन्हा, 2024)। भारत के लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए, दोहरावदार अनुरूपता आकलन को संभालने के लिए आवश्यक वित्तीय और संस्थागत क्षमता अक्सर पहुंच से बाहर रहती है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है। एसपीएस और टीबीटी से परे, एकतरफा स्थिरता और पर्यावरणीय मानक, जिनमें इको-लेबल और कार्बन फुटप्रिंट प्रकटीकरण शामिल हैं, एनटीएम की नई परतें पेश कर रहे हैं। (कल्लुममल, गुरुंग, और खोसला, 2025)

यूरोपीय संघ का ग्रीन डील और उससे जुड़े उपाय इस दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) को एकतरफ़ा कम करके और पर्याप्त संक्रमण अवधि के बिना पर्यावरणीय मानकों को लागू करके, ये भारतीय निर्यातकों पर अनुपालन संबंधी अचानक चुनौतियाँ थोपते हैं। भारत ने स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS) और व्यापार में तकनीकी बाधाओं (TBT) समितियों के समक्ष इन चिंताओं को लगातार व्यक्त किया है, और तर्क दिया है कि ऐसे उपायों का इस्तेमाल गुप्त व्यापार प्रतिबंधों के रूप में किया जा रहा है।

भारत के लिए, गैर-शुल्क उपाय (NTMs) निर्यात वृद्धि की राह में सबसे जटिल बाधाओं में से एक हैं। कृषि निर्यात, श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र, और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) बढ़ती अनुपालन लागत और खंडित मानकों से असमान रूप से प्रभावित हैं। जब तक बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से सामंजस्य नहीं बढ़ाया जाता और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए घरेलू बुनियादी ढाँचे को मजबूत नहीं किया जाता, तब तक एनटीएम भारत के व्यापार लक्ष्यों के लिए एक बड़ी बाधा बने रहेंगे। (कल्लुममल, गुरुंग, और खोसला, 2025)। 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) और यूरोपीय संघ एफटीए को क्षेत्रीय पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRA) के माध्यम से इनमें से कुछ चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की आवश्यकता है।

2.2. इको-लेबलिंग

इको-लेबलिंग एक अन्य प्रमुख एकतरफा साधन के रूप में उभरा है जिसके माध्यम से विकसित देश वैश्विक व्यापार प्रवाह को आकार देते हैं। विशेष रूप से, यूरोपीय संघ (ईयू) ने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम), वनों की कटाई-मुक्त उत्पाद आवश्यकताएँ और स्थिरता प्रमाणन योजनाएँ जैसे उपाय शुरू किए हैं। हालाँकि इन्हें ज़िम्मेदार उपभोग और टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देने के उपकरण के रूप में तैयार किया गया है, लेकिन बहुपक्षीय ढाँचों के बाहर विकसित होने पर ये पहल अक्सर गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं के रूप में कार्य करने का जोखिम उठाती हैं।
इको-लेबल विशिष्ट पर्यावरणीय या स्थिरता मानकों के अनुपालन को प्रमाणित करते हैं, जिनमें कार्बन फुटप्रिंट में कमी, जैविक उत्पादन विधियाँ, या निष्पक्ष व्यापार प्रथाएँ शामिल हैं। शोध इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रमाणन और ट्रेसिबिलिटी आवश्यकताएँ विशेष

रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) पर महत्वपूर्ण बोझ डालती हैं, जो भारत के निर्यात आधार पर हावी हैं। (कल्लुममल, खोसला, कुंडू, और सिन्हा, 2024)।

भारत के लिए, इको-लेबलिंग का प्रसार तीन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। पहली, विभिन्न बाजारों में सामंजस्य का अभाव निर्यातकों को कई और अक्सर असंगत मानकों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है, जिससे भ्रम और दोहराव पैदा होता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान को आपूर्ति करने वाले समुद्री खाद्य उत्पादकों को अक्सर अतिव्यापी स्थिरता उद्देश्यों के बावजूद समानांतर प्रमाणन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। (बाजपेयी, 2024)। दूसरी, दस्तावेज़ीकरण, ऑडिट और प्रमाणन शुल्क सहित अनुपालन लागतें, कपड़ा, चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए प्रवेश बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं। (कल्लुमल और बनर्जी, 2023)। तीसरी, कई योजनाएँ विकासशील देशों से पर्याप्त इनपुट के बिना उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में डिज़ाइन की जाती हैं, जिनमें ऐसे मानदंड शामिल होते हैं जो छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिए तकनीकी या आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होते हैं। (खालिद, 1994)।

भारत ने विश्व व्यापार संगठन में एकतरफा इको-लेबलिंग आवश्यकताओं का लगातार विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि ये विकासशील देशों के लिए गैर-भेदभाव और विशेष एवं विभेदक व्यवहार के सिद्धांतों को कमजोर करती हैं। भारत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि इको-लेबलिंग पहलों को "हरित संरक्षणवाद" का साधन नहीं बनना चाहिए, जो स्थिरता की आड़ में बाज़ार तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है। ये चिंताएँ कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से तीव्र हैं, जहाँ यूरोपीय संघ की ट्रेसेबिलिटी और कार्बन-अकाउंटिंग आवश्यकताएँ छोटे किसानों पर अत्यधिक बोझ डालती हैं, जिनमें से कई के पास विस्तृत उत्सर्जन मापन के लिए आवश्यक तकनीक तक पहुँच नहीं है। (कल्लुमल और बनर्जी, 2023)।

भारत ने बहुपक्षीय संस्थाओं, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन की व्यापार एवं पर्यावरण समिति के माध्यम से पर्यावरण-लेबलिंग मानकों के सामंजस्य का भी आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापार समता को कम किए बिना पर्यावरणीय उद्देश्यों का पालन किया जाए। यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए समान मानकों की पारस्परिक मान्यता, क्षमता निर्माण सहायता और लचीली अनुपालन समय-सीमा की वकालत करता है। (सीआईईएल, 2005)। समावेशी, पारदर्शी और विज्ञान-आधारित प्रक्रियाओं में पर्यावरण-लेबलिंग को शामिल करके, वैश्विक दक्षिण के निर्यातकों को हाशिए पर डाले बिना वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों का पीछा किया जा सकता है।

अंततः, चुनौती यह सुनिश्चित करने में निहित है कि पर्यावरण-लेबलिंग समतापूर्ण व्यापार को कमजोर करने के बजाय उसका पूरक बने। हालाँकि भारत हरित प्रौद्योगिकियों और सतत उत्पादन में निवेश कर रहा है, लेकिन एकतरफा लेबलिंग उपायों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता के बिना इसकी बाजार पहुँच कम होने का खतरा है।

2.3. शुल्क और धारा 232 और 301

संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 और 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 जैसे क़ानूनों के तहत एकतरफ़ा व्यापार उपायों पर तेज़ी से निर्भर रहा है। धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा माने जाने वाले आयातों पर शुल्क लगाने को अधिकृत करती है, जबकि धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देती है (आदित्य, 2025)। हालाँकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इन उपायों को व्यापक रूप से संरक्षणवादी उपकरण के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ता है जो बहुपक्षीय व्यापार अनुशासन को दरकिनार करते हैं और विश्व व्यापार संगठन की विश्वसनीयता को कम करते हैं।

2018 से, अमेरिका ने भारत सहित, स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर धारा 232 के तहत शुल्क लगाए हैं। इन उपायों ने इनपुट लागत बढ़ा दी है और भारत के स्टील क्षेत्र, जो इसके विनिर्माण निर्यात का आधार है, की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमज़ोर कर दिया है। (बागिया और देविंदर, 2025)। अमेरिका को भारतीय इस्पात और एल्युमीनियम की आपूर्ति में भारी गिरावट आई है, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों को आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इन कार्रवाइयों ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एकतरफा व्यापार उपायों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को रेखांकित किया। विश्व व्यापार संगठन में, भारत ने तर्क दिया है कि ऐसे संदर्भों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनुच्छेद XXI का प्रयोग व्यापार नियमों का दुरुपयोग है और बढ़ते संरक्षणवाद के लिए खतरनाक मिसाल कायम करता है। (कल्लुमल, गुरुंग, और खोसला, 2025)।

धारा 301 का दायरा भी विस्तृत हो गया है। कभी बौद्धिक संपदा प्रथाओं के विरुद्ध इस्तेमाल होने वाला यह कानून अब डिजिटल सेवा करों और नियामक नीतियों, जिनमें भारत भी शामिल है, को निशाना बनाता है। 2019 में भारत की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) के लाभों को वापस लेना इन जोखिमों का उदाहरण है: अरबों डॉलर के निर्यात, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में, के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच को WTO तंत्रों का सहारा लिए बिना अचानक समाप्त कर दिया गया, जिससे MSME निर्यातक प्रभावित हुए। (बागिया और देविंदर, 2025)।

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत अमेरिकी कार्यकारी आदेशों ने टैरिफ कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। 2025 की शुरुआत से, चीन, कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 10-25% के व्यापक-आधारित टैरिफ को स्टील, एल्युमीनियम, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स सहित क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है। भारत के लिए, इन उपायों का चिकित्सा उपकरणों, समुद्री भोजन, वस्त्र और मसालों जैसे निर्यात पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अप्रैल 2025 तक, भारतीय निर्यात पर टैरिफ में 26% की वृद्धि हो चुकी थी, जिससे अमेरिकी व्यापार नीति में अचानक बदलाव के कारण इसके विविध निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है।

भारत इन एकतरफा उपायों को नियम-आधारित व्यापार प्रणाली को कमजोर करने वाला मानता है। धारा 232 के तहत "राष्ट्रीय सुरक्षा" का व्यापक उपयोग और धारा 301 का क्षेत्र-बाह्य अनुप्रयोग, गैर-भेदभाव और पूर्वानुमेयता के विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों को चुनौती देता है। एक कार्यशील विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय का अभाव इन उपायों का विरोध करने की भारत की क्षमता को और कमजोर करता है। (साहू, बिश्नोई, राव, और पाराशर, 2025)।

भारत की रणनीति दोहरी रही है: कूटनीतिक रूप से, यह विश्व व्यापार संगठन के मंचों पर आपत्तियाँ उठाते हुए बातचीत के माध्यम से अमेरिका से जुड़ता है; घरेलू स्तर पर, यह विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से लचीलापन चाहता है। (बागिया और देविंदर, 2025)। साथ ही, भारत विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।

धारा 232 और 301 के तहत अमेरिका द्वारा लगाए गए एकतरफा टैरिफ के साथ भारत का अनुभव विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऐसे उपायों के जोखिमों को दर्शाता है। ये उपाय तत्काल बाजार पहुँच को बाधित करते हैं और निर्यात के अवसरों को दूसरे देश के निर्णयों पर आधारित करके नीतिगत गुंजाइश को सीमित करते हैं। ये कदम वैश्विक व्यापार प्रशासन में संरचनात्मक विषमताओं को उजागर करते हैं, जहाँ बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ असमानुपातिक प्रभाव डालती हैं। भारत के लिए, चुनौती अपने निर्यातकों की रक्षा करते हुए बहुपक्षीय स्तर पर प्रणालीगत सुधारों पर ज़ोर देने की है।

3. व्यापार और पर्यावरणीय मुद्दे

जैसे-जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा अस्थिरता और औद्योगिक परिवर्तन जैसे संकटों के जवाब में सतत आर्थिक विकास की ओर बढ़ रही है, पर्यावरणीय चिंताएँ वैश्विक व्यापार और विकास का केंद्र बनती जा रही हैं। ये परिवर्तन "जलवायु-संरेखित व्यापार" की ओर एक बदलाव को दर्शाते हैं, जहाँ व्यापार और औद्योगिक नीतियाँ और जलवायु लक्ष्य तेज़ी से आपस में जुड़ते जा रहे हैं। जहाँ विकसित देश जलवायु संबंधी व्यापार नियमों को और सख्त बनाने पर ज़ोर दे रहे हैं, वहीं भारत सहित विकासशील देश 'साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों' के सिद्धांत के तहत समानता के महत्व पर ज़ोर दे रहे हैं। भारत का तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से उच्च उत्सर्जन वाले देशों को तुलनात्मक समानता बनाए रखने के लिए अधिक ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, और वैश्विक जलवायु उपायों में विभिन्न राष्ट्रीय क्षमताओं पर विचार किया जाना चाहिए। यह ऐसी जलवायु नीतियों की वकालत करता है जो वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लचीली कार्यान्वयन समय-सीमा के माध्यम से निष्पक्षता सुनिश्चित करें ताकि सभी के लिए एक न्यायसंगत और समावेशी हरित परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।

3.1 मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम

अगस्त 2022 में लागू किया गया मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम ('आईआरए'), संयुक्त राज्य अमेरिका का अब तक का सबसे व्यापक जलवायु कानून है। स्वच्छ ऊर्जा कर प्रोत्साहनों के लिए 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि और 369 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के समग्र जलवायु निवेश पैकेज के साथ, आईआरए का लक्ष्य 2030 तक अमेरिकी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 40% कम करना है (आईआरए अवलोकन, 2023)।

आईआरए की एक विशिष्ट विशेषता इसके इक्विटी-केंद्रित कार्यक्रम हैं, जैसे निम्न-आय समुदाय बोनस क्रेडिट, जो कम सेवा वाले क्षेत्रों, आदिवासी भूमि और ऐतिहासिक रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर क्षेत्रों में निवेश को लक्षित करता है (अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, 2023)। यह जलवायु महत्वाकांक्षा को आर्थिक समावेशन और रोजगार सृजन से जोड़ता है, जिसके अगले दशक में पूरे अमेरिका में 1.5 मिलियन से अधिक नए स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

हालाँकि इससे घरेलू उद्योग को मजबूती मिलती है, जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों का तर्क है कि ये प्रावधान विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, जिससे "हरित संरक्षणवाद" की आशंकाएँ बढ़ रही हैं। कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि IRA कई विश्व व्यापार संगठन प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर सकता है, जिनमें GATT अनुच्छेद । (सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र), अनुच्छेद III:4 (राष्ट्रीय व्यवहार), और सब्सिडी एवं प्रतिपूरक उपायों पर समझौता शामिल हैं। कनाडा और मेक्सिको में असेंबल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों को तरजीह देने और चीनी घटकों को बाहर रखने की भेदभावपूर्ण प्रकृति, संभावित विश्व व्यापार संगठन विवादों के लिए स्पष्ट आधार प्रदान करती है। (वांडुज़र, 2023)।

यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे विकसित बाजारों ने पारिस्थितिक स्थिरता और आर्थिक स्थानीयकरण पर ज़ोर देते हुए नई रणनीतियाँ अपनाई हैं। यूरोपीय संघ अपशिष्ट शिपमेंट निर्देश, सतत उत्पाद विनियमन के लिए पारिस्थितिक डिज़ाइन, पैकेजिंग और पैकेजिंग अपशिष्ट विनियमन, और कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे उपायों के माध्यम से हरित मानकों को आगे बढ़ाता है, ये सभी स्थानीय, सतत उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं। इसके विपरीत, अमेरिका बुनियादी ढाँचा निवेश और रोज़गार अधिनियम, चिप्स और विज्ञान अधिनियम, अमेरिकी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता अधिनियम, और धारा 232 और 301 टैरिफ के माध्यम से घरेलू विनिर्माण और आर्थिक राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देता है। ये नीतियाँ मिलकर विश्व व्यापार संगठन-युग के बहुपक्षवाद से हटकर राष्ट्रीय स्तर पर संचालित, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर एक बदलाव का प्रतीक हैं।

3.1.1 भारत के स्वच्छ ऊर्जा निर्यात पर प्रभाव

भारत व्यापक रूप से वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों का समर्थन करता है, लेकिन वह आईआरए के कुछ पहलुओं, विशेष रूप से घरेलू सब्सिडी संरचना और व्यापार बाधाओं को, संभावित रूप से भेदभावपूर्ण मानता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत का सौर निर्यात 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें से लगभग 97% अमेरिका को गया (गर्ग, 2024)। हालाँकि, आईआरए के अनुसार अमेरिकी सौर परियोजनाओं में 40-55% घटक, जिनमें स्टील भी शामिल है, अमेरिका में निर्मित होने चाहिए। चूँकि कई भारतीय मॉड्यूल चीनी इनपुट का उपयोग करते हैं, यह उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करता है और अमेरिकी बाजार तक उनकी पहुँच को कम कर सकता है।

चित्र 1

घरेलू बाजार में भारतीय कंपनियों द्वारा पी.वी. मॉड्यूल की वास्तविक आपूर्ति का पूर्वानुमान।

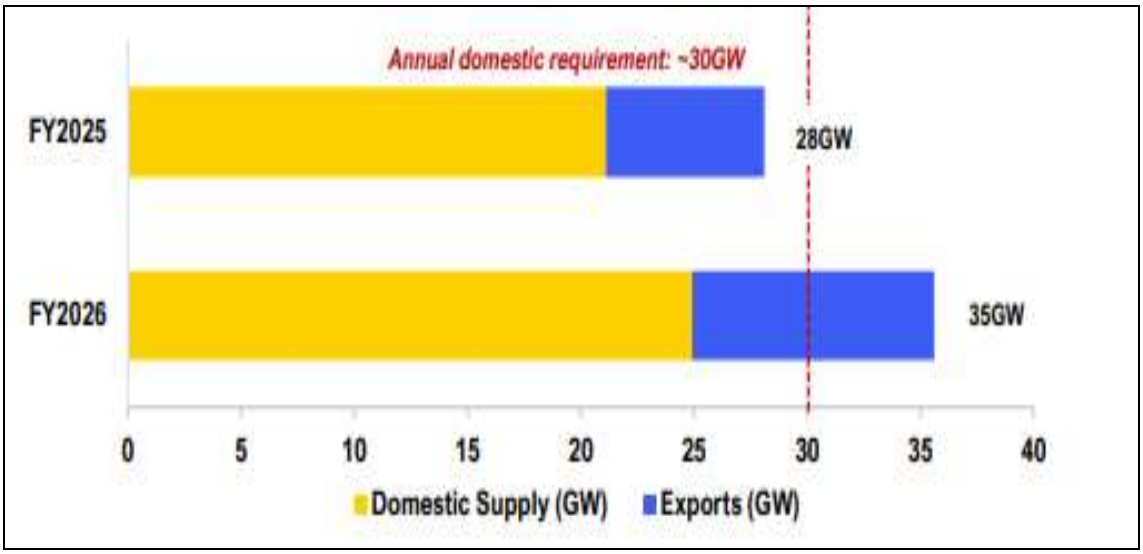

स्रोत: JMK रिसर्च

हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में, भारत ने 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसे लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर के नियोजित निवेश और 6 लाख नौकरियों के सृजन की संभावना से समर्थन प्राप्त है। (इन्वेस्ट इंडिया, 2025)। हालाँकि, अमेरिका IRA के तहत 3 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तक की सब्सिडी दे रहा है, जिससे वहाँ हाइड्रोजन की लागत 1 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से कम हो गई है—जिससे भारतीय हाइड्रोजन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है। ईवी क्षेत्र में, अमेरिकी खरीदार 7,500 अमेरिकी डॉलर तक का कर क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं यदि वाहन उत्तरी अमेरिका में बना है और स्वीकृत स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग करता है। (इलेक्ट्रिक वाहन और ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन कर क्रेडिट)। इसने कुछ भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहनों के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अमेरिका में उत्पादन स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए प्रेरित किया है। इनमें सौर और हाइड्रोजन निर्यात के लिए अस्थायी कार्बन मूल्य संकेत के रूप में अपनी निर्यात छूट योजना को अपनाना, IRA द्वारा संभावित व्यापार नियमों के उल्लंघन पर विश्व व्यापार संगठन में चिंता व्यक्त करना, और अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अपने निर्यात बाजारों का विस्तार करना शामिल है। भारत "मेक इन इंडिया" और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के तहत घरेलू स्वच्छ-तकनीक निर्माण को भी बढ़ा रहा है, और हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी सब्सिडी देने पर विचार कर रहा है।

3.2 कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम)

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र ('सीबीएएम') एक जलवायु-उन्मुख व्यापार नीति है जो स्टील, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली जैसे आयातों पर उनके उत्पादन के दौरान उत्पन्न उत्सर्जन के आधार पर कार्बन मूल्य लगाती है। इस तरह के रिसाव को रोकने के लिए आयात में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) पर कार्बन कर शामिल किया गया है। (कल्लुममल, खोसला और दहल, 2025)। हालाँकि इसका प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरणीय है, लेकिन सीबीएएम के विकासशील देशों, विशेष रूप से कार्बन-प्रधान उद्योगों वाले देशों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ भी हैं। 2023 में शुरू होने वाले संक्रमण चरण और 2026 में शुरू होने वाले वित्तीय दायित्वों के साथ, यह नीति निकट भविष्य में व्यापार और लागत संबंधी चुनौतियों के साथ-साथ स्वच्छ तकनीकों को अपनाने और उभरते वैश्विक जलवायु मानकों को पूरा करने के दीर्घकालिक अवसर भी प्रस्तुत करती है।

3.2.1 भारत के लिए CBAM क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत CBAM से काफी प्रभावित है क्योंकि यूरोपीय संघ को उसके निर्यात का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से इस्पात और एल्युमीनियम, इस नई नीति के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में आता है। 2022-2023 में, भारत ने यूरोपीय संघ को 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जो अब CBAM के अंतर्गत आती हैं, और इसमें से अधिकांश इस्पात और एल्युमीनियम का निर्यात होता है (द इकोनॉमिक टाइम्स, 2023)। समस्या यह है कि भारत में इन सामग्रियों के उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिसका मुख्य कारण कारखानों की कोयला-आधारित ऊर्जा पर निर्भरता और पुरानी उत्पादन विधियाँ हैं। उदाहरण के लिए, JSW स्टील जैसे प्रमुख इस्पात उत्पादक अभी भी ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं, और हिंडाल्को जैसे एल्यूमीनियम उत्पादक कोयले से चलने वाली बिजली पर निर्भर हैं, जिससे उनका उत्सर्जन प्रोफ़ाइल यूरोपीय संघ के मानकों से काफी अधिक है। ये संरचनात्मक विशेषताएँ भारतीय निर्यातकों को नुकसान में डालती हैं, क्योंकि CBAM उच्च अंतर्निहित उत्सर्जन के लिए वित्तीय दंड लगाता है (आरिफ, 2025)।

भारत में वर्तमान में यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के बराबर राष्ट्रीय कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली का अभाव है, जिससे निर्यातक सीबीएएम के तहत "समतुल्य कार्बन मूल्य" का दावा करने में असमर्थ हैं और यूरोपीय संघ की सीमा पर उनकी देनदारी बढ़ रही है। 2023 में, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) शुरू की, लेकिन यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अल्पकालिक प्रतिक्रिया के रूप में, भारत कार्बन मूल्य निर्धारण के प्रॉक्सी के रूप में निर्यात पर मौजूदा गैर-जीएसटी ऊर्जा और पर्यावरण करों का पुनः उपयोग कर सकता है। ये शुल्क, जो पहले से ही निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना में शामिल हैं, सीबीएएम के समतुल्यता प्रावधानों के तहत संक्रमणकालीन व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए प्रलेखित किए जा सकते हैं। भारत को यूरोपीय संघ पर अपने मौजूदा करों—जैसे कोयले पर क्षतिपूर्ति उपकर और आगामी सीसीटीएस—को अंतर्निहित कार्बन मूल्य निर्धारण के रूप में मान्यता देने के लिए भी दबाव डालना चाहिए,

सीबीएएम के प्रभाव को कम करने के लिए, भारतीय उद्योग कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रमुख रणनीतियाँ अपना सकते हैं। बिजली खरीद समझौतों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करने से मदद मिल सकती

है, हालाँकि ग्रिड तक पहुँच और विनियमन अभी भी बाधाएँ हैं। स्टील और एल्युमीनियम जैसे उत्सर्जन-भारी क्षेत्रों में, पुनर्चक्रित इनपुट पर स्विच करने के लिए बेहतर स्क्रैप पहुँच और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाइड्रोजन और बायोचार जैसे वैकल्पिक ईंधन आशाजनक हैं, लेकिन इन्हें और विकसित करने की आवश्यकता है। एमएसएमई को प्रभावी ढंग से कार्बन मुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता, ग्रीन लोन और डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) को शामिल करना वास्तविक आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। सीबीएएम या आईसीपीएफ को पीपीपी-समायोजित रूपांतरण कारक अपनाना चाहिए, जो पूर्ण आर्थिक भार समता को भी दर्शाएगा। ~4.6 का यूरो-आईएनआर पीपीपी कारक प्रभावी भार को ₹7086 से घटाकर ₹1526 कर देगा, जो सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (सीबीडीआर) के सिद्धांत के अनुरूप है। पीपीपी आर्थिक असमानता को पहचानता है और विकासात्मक रूप से प्रतिगामी कराधान को रोकता है, इसलिए यह स्थानीय आर्थिक वास्तविकताओं को समझने का सर्वोत्तम उपलब्ध साधन है। अनुसंधान संस्थानों और वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग से स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि सीबीएएम चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, फिर भी इसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका प्रभाव विकासशील और अल्पविकसित, दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर समान रूप से पड़े।

भारत का रुख जलवायु उद्देश्यों को व्यापार निष्पक्षता और विकास प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल देता है, तथा यह वकालत करता है कि पर्यावरण नीतियों को समावेशी रूप से तैयार किया जाना चाहिए ताकि वैश्विक स्तर पर न्यायोचित परिवर्तन को समर्थन मिल सके।

3.3 यूरोपीय संघ के सतत उत्पाद विनियमों (ईएसपीआर) के लिए इको-डिज़ाइन, अपशिष्टों के शिपमेंट पर विनियमन और ओईसीडी परिषद का निर्णय

कई अंतर्राष्ट्रीय पहल, समझौते और संधियाँ हुई हैं जिन्होंने इन पर्यावरणीय चिंताओं को सर्वोपरि रखा है और पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की माँग की है। सत्तर के दशक के प्रारंभ से ही यूरोपीय संघ ने पर्यावरण नीति को अपनी व्यापक विकास रणनीति में शामिल कर लिया था। तब से, यूरोपीय संघ ने उच्चतम पर्यावरणीय मानकों को सुनिश्चित करने वाले सशक्त कानूनों के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, यूरोपीय नीति अक्सर वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण और वैश्विक व्यापार, विशेष रूप से विकासशील देशों पर इन नीतियों के प्रभावों की अनदेखी करती है।

1. यूरोपीय संघ के पास 1993 से कचरे के शिपमेंट पर कानून है, जिसमें सीमाओं के पार कचरे के परिवहन के नियम भी शामिल हैं। इन्हें 1993 और 2006 में दो कानूनों में सीमा पार कचरे के नियंत्रण और उनके निपटान के रूप में सुनिश्चित किया गया था। यह OECD निर्णय (2001) के प्रावधानों को स्थानांतरित करता है, जो OECD क्षेत्र के भीतर पुनर्प्राप्ति के लिए अपशिष्ट शिपमेंट के लिए एक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करता है। अपशिष्ट शिपमेंट पर नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूरोपीय संघ अपने कचरे को तीसरे देशों को निर्यात न करे, पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान दे, अवैध अपशिष्ट शिपमेंट को रोकने के लिए प्रवर्तन को मजबूत करे, और अपशिष्ट शिपमेंट की ट्रेसबिलिटी बढ़ाए। नए अपशिष्ट शिपमेंट नियमन ने गैर-ईयू देशों को कचरे के निर्यात पर अधिक कड़े नियम निर्धारित किए

नए नियम (21 मई 2027 से प्रभावी) गैर-ओईसीडी देशों को यूरोपीय संघ के कचरे के निर्यात को तभी अनिवार्य करते हैं जब वे यूरोपीय संघ को ऐसे कचरे के आयात की अपनी इच्छा के बारे में सूचित करें और इसके लिए स्थायी प्रबंधन क्षमता रखते हों। यह गैर-ओईसीडी देशों को प्लास्टिक कचरे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाता है। निर्यात को प्रतिबंधित करने से, यह चिंता है कि यूरोपीय संघ अपने हरित-सूचीबद्ध कचरे के लिए एक "सिंकहोल" बन सकता है, क्योंकि यह वैश्विक दक्षिण और गैर-ओईसीडी देशों को निर्यात करने की क्षमता को सीमित करता है, जिससे संभवतः संसाधनों के अधिक दोहन और गैर-ओईसीडी देशों, विशेष रूप से भारत में कचरा प्रबंधन की उच्च लागत के कारण कार्बन फुटप्रिंट बढ़ सकता है। इन नियमों से निर्यातक देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों, की उत्पादन लागत बढ़ने की संभावना है, जिससे उनके निर्यात अप्रतिस्पर्धी हो सकते हैं और उन्हें उच्च यूरोपीय संघ मानकों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। साथ ही, ये नियम व्यापार प्रतिबंधात्मक हैं, जो GATT, अनुच्छेद 21 के स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत आ सकते हैं। (कल्लुमल एम., गुरुंग, खोसला, और कुंडू, 2024)

[1]https://environment.ec.europa.eu/news/new-regulation-waste-shipments-enters-force-2024-05-20_en

बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाओं, बेहतर पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमताओं, और नए नियमों के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता, गैर-ओईसीडी और विकासशील देशों के लिए एक गैर-टैरिफ बाधा बन सकती है। विकासशील देशों को इन नियमों का पालन करने हेतु अपने अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यूरोपीय संघ के नियमों में बदलाव के कारण विकासशील देश (भारत) पुरानी व्यवस्था के तहत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) से चूक सकते हैं, क्योंकि उन्हें उच्च अनुपालन लागत और उत्पादन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये नियम वैश्विक व्यापार को भी बाधित कर सकते हैं, खासकर उन देशों के लिए जो यूरोपीय संघ को अपशिष्ट या अपशिष्ट-संबंधी उत्पादों के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर हैं।
यूरोपीय संघ वन-कटान विनियमन (ईयूडीआर)

यूरोपीय संघ का वन-कटान विनियमन (ईयूडीआर), जिसे 2023 में अपनाया गया है, का उद्देश्य यूरोपीय संघ के बाज़ार से वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों को हटाना है। इसके लिए कंपनियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनकी वस्तुएँ, जैसे कॉफ़ी, पाम ऑयल, रबर और सोया, 2020 के बाद वनों की कटाई वाली भूमि से नहीं ली गई हैं। यह विनियमन निर्यातकों पर विस्तृत जाँच-पड़ताल और पता लगाने की क्षमता संबंधी आवश्यकताएँ लागू करता है, जिससे हाल ही में वनों की कटाई से जुड़े आयातों पर प्रभावी रूप से रोक लग जाती है (यूरोपीय आयोग, 2023)।

भारत के लिए, ईयूडीआर एक महत्वपूर्ण अनुपालन चुनौती प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए जिनके पास जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं को सत्यापित करने के लिए संसाधनों और तकनीकी क्षमता का अभाव है। अनुमान बताते हैं कि यूरोपीय संघ को भारत का कृषि और बागान निर्यात, जिसका मूल्य लगभग 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है, इन कठोर आवश्यकताओं के कारण बाधित हो सकता है। (भविष्यता, 2023)। कल्लुममल, खोसला और दहल (2025) द्वारा किए गए इसी प्रकार के विश्लेषण में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एमएसएमई के बीच आकार-संबंधी बाधाओं को दूर करने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए संगठित सहायता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

भारत ने ईयूडीआर की संभावित व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रकृति और विकासशील देशों के लिए इसके लचीलेपन की कमी को लेकर विश्व व्यापार संगठन के मंचों पर चिंता जताई है। भारत का कहना है कि यह विनियमन डेटा की सीमाओं के कारण अनजाने में स्थायी उत्पादकों के वैध उत्पादों को बाहर कर सकता है और निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा बाजार बहिष्कार से बचने के लिए अधिक संवाद की आवश्यकता पर बल देता है। (भविष्यता, 2023)। भारत इन चिंताओं में अकेला नहीं है; कई विकासशील देश अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर बल देते हैं और विकास स्तरों के आधार पर विभेदित उपचार की वकालत करते हैं। भारत बहुपक्षीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना जारी रखे हुए है, एक संतुलित दृष्टिकोण की तलाश में है जो पर्यावरणीय लक्ष्यों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के व्यापारिक हितों दोनों की रक्षा करे। सभी विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संघ देश-विशिष्ट परिस्थितियों को पहचाने और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थिरता मानक व्यापार में छिपी बाधा न बनें।

इसलिए, भारत का ध्यान अन्य प्रभावित देशों के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इस मुद्दे को उठाने पर होना चाहिए, और इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि EUDR सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN) और राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। EUDR की अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में निर्यातकों के बीच जागरूकता बढ़ाएँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मानकों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यूरोपीय संघ को अंगूर निर्यात के लिए APEDA द्वारा विकसित मौजूदा ब्लॉकचेन-सक्षम ट्रेसेबिलिटी प्रणाली का लाभ उठाएँ, और सभी संबंधित उत्पाद श्रेणियों में इसके अनुप्रयोग का उत्तरोत्तर विस्तार करें।

निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था तकनीकी व्यवधान और जलवायु संबंधी अनिवार्यताओं से प्रेरित परिवर्तन के दौर से गुज़र रही है, साथ ही बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बहुपक्षवाद के विघटन से भी प्रभावित हो रही है। विकासशील देशों के लिए, ये परिवर्तन विकास के नए अवसर पैदा करते हैं और हाशिए पर जाने का जोखिम भी बढ़ाते हैं। भारत इस विरोधाभास को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एक ओर, इसके जनसांख्यिकीय लाभ इसे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करते हैं। दूसरी ओर, कृषि, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे और समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों में मौजूदा कमज़ोरियाँ उभरते अवसरों का पूरा लाभ उठाने की इसकी क्षमता को सीमित करती हैं।

भारत की चिंताएँ—चाहे वे विश्व व्यापार संगठन की आम सहमति को ख़तरे में डालने वाले बहुपक्षीय प्रयासों के बारे में हों, कृषि सब्सिडी नियमों में असमानताओं के बारे में हों, विशेष और विभेदक उपचार के कमज़ोर होने के बारे में हों, या हरित संरक्षणवाद की पक्षपातपूर्ण प्रवृत्तियों के बारे में हों—अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि विकासशील देशों की व्यापक चिंताओं को दर्शाती हैं। ये मुद्दे वैश्विक व्यापार प्रशासन में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं ताकि स्थिरता और लचीलेपन के लक्ष्यों को संरक्षणवाद के औचित्य के रूप में इस्तेमाल होने से रोका जा सके, जिससे निष्पक्ष और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

गैर-टैरिफ उपायों (एनटीएम), धारा 232 और 301 के तहत सुरक्षा-संचालित टैरिफ, या इको-लेबलिंग आवश्यकताओं सहित एकतरफा व्यापार उपाय, भारत को उभरते व्यापार परिदृश्य के भीतर असममित कमजोरियों के लिए उजागर करते हैं। इस तरह के उपाय बाजार पहुंच को जटिल बनाते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर महत्वपूर्ण अनुपालन लागत लगाते हैं, और नियम-आधारित प्रणाली की स्थिरता को कमजोर करते हैं - विशेष रूप से एक कार्यशील डब्ल्यूटीओ विवाद समाधान तंत्र की अनुपस्थिति में। भारत के लिए, चुनौती न केवल इन उपायों के भेदभावपूर्ण प्रभावों के खिलाफ अपने निर्यातकों का बचाव करना है, बल्कि बहुपक्षीय मंचों में सामंजस्य, निष्पक्षता और क्षमता निर्माण के प्रयासों की वकालत के माध्यम से वैश्विक मानदंडों को सक्रिय रूप से आकार देना भी है।

वैश्विक व्यापार का क्षेत्र मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (आईआरए), कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम), पर्यावरण एवं सामाजिक नीति विनियम (ईएसपीआर), और यूरोपीय संघ के उचित परिश्रम विनियमन (ईयूडीआर) जैसे जलवायु-केंद्रित नियमों से तेजी से प्रभावित हो रहा है। ये उपाय अक्सर विकसित अर्थव्यवस्थाओं की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अनुपालन संबंधी गंभीर चुनौतियाँ और लागतें पैदा करते हैं। वैश्विक हरित परिवर्तन का समर्थन करते हुए अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए, भारत को दोहरी रणनीति अपनानी होगी: स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से घरेलू क्षमता को मजबूत करना, कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करना, और ट्रेसेबिलिटी प्रणालियाँ स्थापित करना; और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना कि जलवायु नीतियों का निष्पक्ष कार्यान्वयन हो, निष्पक्षता और सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों (सीबीडीआर) के सिद्धांतों को कायम रखना। व्यापार प्रतिस्पर्धा को सतत विकास के साथ जोड़ने के लिए यह संतुलित दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत के भविष्य के दृष्टिकोण में दो प्रमुख रणनीतियाँ शामिल हैं: बहुपक्षीय स्तर पर अपनी नीतिगत जगह की रक्षा करना और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, हरित परिवर्तन का समर्थन करने और संस्थागत क्षमता को मज़बूत करने के लिए घरेलू सुधारों में तेज़ी लाना। अन्य विकासशील देशों के साथ गठबंधन करके, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करके और नवीन व्यापार रणनीतियाँ विकसित करके, भारत बदलते वैश्विक परिदृश्य की उथल-पुथल से निपट सकता है। अभी लिए गए विकल्प भारत के मार्ग को आकार देंगे और वैश्वीकरण के भविष्य में वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को प्रभावित करेंगे।

निष्कर्षतः, भारत के सामने आने वाली अधिकांश छिपी हुई बाधाएँ मुख्यतः स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस) और व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के नियमों में पारदर्शिता की कमी से उत्पन्न होती हैं। हालाँकि प्रगति हुई है, फिर भी भारत में कई कृषि-प्रसंस्करण उद्योग और एमएसएमई अभी भी अधिसूचनाओं के बारे में अपर्याप्त या विलंबित जानकारी से जूझ रहे हैं, जिससे निर्यातकों के लिए तीसरे देशों द्वारा किए गए विचलनों पर प्रतिक्रिया देना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, नियामक पूर्वाग्रह अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि नए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में कभी-कभी विशिष्ट क्षेत्रों या देशों के पक्ष में प्रावधान शामिल होते हैं, जिससे भारतीय व्यवसायों के लिए छिपे हुए नुकसान पैदा होते हैं। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र में बढ़ते प्रतिबंध, जैसे कि उच्च एच1बी वीज़ा शुल्क, मूल्य श्रृंखला के भीतर अवसरों को सीमित करते हैं।

इनमें से अधिकांश चुनौतियाँ एसपीएस, टीबीटी और घरेलू विनियमों के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न होती हैं, जो उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं। भौतिक वस्तुओं के विपरीत, सेवाओं को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, निवास प्रतिबंधों और क्रेडिट रेटिंग पूर्वाग्रहों जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है - जिनमें से कई में एफटीए में पारदर्शिता या मानकीकरण का अभाव होता है। ये मुद्दे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के तहत विनिर्माण और सेवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने के भारत के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। सफलता भारत की बदलते व्यापार नियमों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की क्षमता पर निर्भर करती है। मुख्य चुनौती एफटीए द्वारा प्रदान किए गए लचीलेपन को डब्ल्यूटीओ मानदंडों की पूर्वानुमेयता के साथ संतुलित करना है - जबकि एक पेचीदा नियामक भूलभुलैया से बचना है।

वैश्विक स्तर पर, मौजूदा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (जीएसवी) से बदलने का प्रयास बढ़ रहा है।

संदर्भ

1. (2005, March). Retrieved from CIEL: https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/03/Ecolabeling_ WTO_ Mar05.pdf
2. (2023). Retrieved from European Commission: https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/ deforestation/regulation-deforestation-free-products_en
3. Aditya. (2025, August). *G*
4. *(2005, मार्च)। CIEL से प्राप्त: https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/03/Ecolabeling_WTO_ Mar05.pdf*
5. *(2023)। यूरोपीय आयोग से प्राप्त: https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en*
6. *आदित्य। (2025, अगस्त)।lobal Trends in SPS Measures and Stringent SPS-Based MRLs Notifications.* Retrieved from https://cleartax.in/s/us-tariff-on-india
7. Arif, A. (2025, March). *India vs. EU's CBAM: Trade Wars & Green Tariffs.* Retrieved from SPRF: https://sprf.in/india-vs-eus-cbam-trade-wars-green-tariffs/
8. Bacchetta, E. B. (2025). WORLD TRADE REPORT 2024. *WTO*.
9. Bagia, & Devinder. (2025, April). *Reciprocal Tariffs by the US: Impacts and strategies for India.* Retrieved from https://www.lakshmisri.com/insights/articles/reciprocal-tariffs-by-the-us-impacts-and-strategies-for-india/
10. Bajpai. (2024, July). *Eco-labels can help with responsible consumption, production.* Retrieved from DownToEarth: https://www.downtoearth.org.in/environment/eco-labels-can-help-with-responsible-consumption-production
11. Bhatnagar, M. (2025, March 26). Policy interventions to achieve a sustainable blue economy.
12. Bhavishyata. (2023, Dec). *EU's Deforestation Act and its Impact on India*. Retrieved from The Geostrata: https://www.thegeostrata.com/post/eu-s-deforestation-act-and-its-impact-on-india
13. Doshi, D. (2024). The Investment Facilitation Agreement: Resisting plurilateralism in global investment law. . *Observer Research Foundation*.
14. *Electric Vehicle and Fuel Cell Electric Vehicle Tax Credit.* (n.d.). Retrieved from US Department of Energy: https://afdc.energy.gov/laws/409
15. Forceget. (2025). Supply chain disruption 2025: Confronting complexity in global trade. *Forceget Supply Chain Logistics*.
16. Garg, V. (2024, November). *Solar PV export value from India surged 23 times between FY2022 and FY2024.* Retrieved from Institute for Energy Economics and Financial Analysis: https://ieefa.org/articles/solar-pv-export-value-india-surged-23-times-between-fy2022-and-fy2024
17. IEA. (2023). World Energy Investment 2023: Overview and key findings.
18. *Invest India.* (2025, June). Retrieved from India's Green Hydrogen Rise: https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/indias-green-hydrogen-rise-7-reasons-invest-2025#:~:text=Public%20sector%20hydrogen%20investment%20in%20India&text=The%20goal%20of%20the%20initiative,tons%20per%20annum%20by%202030.&text=The%20mission%20is%2
19. *IRA Overview.* (2023, January). Retrieved from EPA: https://www.epa.gov/system/ files/documents/ 2022-12/12%2009%202022_OAR%20IRA%20Overview_vPublic.pdf

20. Kallummal, M. (2015). North–South Imbalances in the Doha Round: The Use of Specific Duties as a Trade Policy Instrument. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 85–124. doi:https://doi.org/10.1177/2277976015574052
21. Kallummal, M., & Banerjee, S. (2023, February). *CRIT/ CWS Policy Brief No. 7*. Retrieved from CRIT/ CWS Policy Brief No. 7.
22. Kallummal, M., & Gurung, H. (2020). *CRIT/ CWS Working Paper No. 60*.
23. Kallummal, M., Gurung, H. M., Khosla, S., & Kundu, A. (2024). *CWS Note on European Union's Eco-design for Sustainable Products Regulations (ESPR).*
24. Kallummal, M., Gurung, H., & Khosla, S. (2025). *CRIT/ CWS Policy Brief No. 10*.
25. Kallummal, M., Khosla, S., & Gurung, H. (2024). *CRIT/CWS Working Paper No. 75*.
26. Kallummal, M., Khosla, S., Kundu, A., & Sinha, A. (2024). *CRIT/ CWS Working Paper No. 72*.
27. Khalid, A. (1994, September). *Unilateral Environmental Regulations and the Implications for International Commodity-Related Environmental Agreements.* Retrieved from https://nautilus.org/trade-and-environment/unilateral-environmental-regulations-and-the-implications-for-international-commodity-related-environmental-agreements-2/
28. Kumar, R. (2017). Fisheries subsidies negotiations at the WTO: The real catch . *CWS/CRIT Working Paper No. 45*.
29. Manak, I. (2025). How India Disrupts and Navigates the WTO. . *Council on Foreign Relations.*
30. Reisinger, H. (2025). Supply chain chaos in 2025: How geopolitics are rewriting the rules. *Palo Alto Networks Perspectives*.
31. Sahoo, Bishnoi, Rao, & Parashar. (2025, April). *Implications of US's Trade Policy on India.* Retrieved from Economic and Political Weekly: https://www.epw.in/journal/2025/15/special-articles/implications-uss-trade-policy-india.html
32. Sharma, S. K. (2024). Navigating agricultural domestic support, fisheries subsidies, and food security: A critical examination of the WTO rules . *CRIT/CWS Working Paper No. 71*.
33. *The Economic Times.* (2023, March 01). Retrieved from EU's carbon tax to impact India's metal exports: GTRI: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/eus-carbon-tax-to-impact-indias-metal-exports-gtri/articleshow/98332338.cms?from=mdr
34. *United States Environmental Protection Agency, EPA.* (2025, July). Retrieved from Summary of Inflation Reduction Act provisions related to renewable energy: https://www.epa.gov/green-power-markets/summary-inflation-reduction-act-provisions-related-renewable-energy
35. *US Treasury Department.* (2023, October). Retrieved from How the Inflation Reduction Act's Tax Incentives Are Ensuring All Americans Benefit from the Growth of the Clean Energy Economy: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1830
36. Vanduzer, J. A. (2023). Clean Vehicles Tax Credits under the US Inflation Reduction Act: Friend-Shoring Takes Centre Stage in US Policy. *The Indian Journal of International Economic Law*. Retrieved from Clean Vehicles Tax Credits under the US Inflation Reduction Act:: https://repository.nls.ac.in/cgi/viewcontent.cgi?article=1152&context=ijiel#:~:text=Although%20tailored%20as%20a%20market,the%20international%20economic%20law%20system.
37. WTO. (2025, September 16). Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_acceptances_e.htm
38. WTO. (n.d.). Special and differential treatment provisions. . *World Trade Organization*.

2024-25 में आईआईएफटी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां : त्वरित चित्र

मई 2024 में, IIFT ने ऐसे शिक्षण वातावरण का निर्माण करके उसका पोषण करने के अपने उद्देश्य का जश्न मनाया जो प्रतिभागियों को समाज के प्रति संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी बनने में सक्षम बनाता है। IIFT को अपने प्रदर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। ये IIFT के प्रत्येक प्रभाग और विभागों के उत्तरदायित्व साझा करने और निरंतर, सहयोगात्मक और परिश्रमी प्रयास करते रहने वाले दृष्टिकोण का परिणाम है।

संस्थान का वार्षिक दीक्षांत समारोह

आईआईएफटी का 57 वां दीक्षांत समारोह दिनांक 11 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान विभिन्न प्रबंधन कार्यक्रमओं कार्यक्रमों के कुल 978 छात्रों को डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किए गए। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (अमूल) के प्रबंध निदेशक डॉ. जयेन मेहता मुख्य अतिथि थे और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पदक, पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

दीक्षांत समारोह – बैच-वार विवरण

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	रैंक धारक	पुरस्कार से सम्मानित होने वालों की कुल संख्या
कैंपस में होने वाले कार्यक्रम			
1.	पीएचडी दिल्ली & कोलकाता	16	-
2.	एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 2022-24 दिल्ली	3	399
3.	एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 2022-24 कोलकाता		
4.	एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 2021 – 2024	3	48
5.	एमए (अर्थशास्त्र) दिल्ली	5	86
6.	एमए (अर्थशास्त्र) कोलकाता		
7.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा (सप्ताह अंत) 2022-23 दिल्ली	4	71
8.	ईपीजीडी-जीएचआरएम 2022-24 (सप्ताहांत) दिल्ली	3	09
9.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा (शीतकालीन) 2023-24 दिल्ली	4	39
10.	एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 2021-23 दिल्ली	-	01
11.	एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 2020 – 2023 (सप्ताह अंत) 2022-23 दिल्ली	-	04
12.	एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 2019-23 कोलकाता	-	01
13.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर डप्लोमा 2021-23 (सप्ताह अंत) दिल्ली	-	02
कुल संख्या		38	660
		698	

प्लेसमेंट्स का अंतिम चरण - एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 2023-25 बैच

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपने मुख्य कार्यक्रम एमबीए (आईबी) के 2023-25 बैच के लिए प्लेसमेंट्स का अंतिम चरण समाप्त किया। प्लेसमेंट चक्र में विविध क्षेत्रों और उद्योगों से 45 नए कॉर्पोरेट संघों सहित 135 प्रतिष्ठित भर्तीकर्ताओं ने भाग लिया। कठिन वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, आईआईएफटी ने ₹31.3 लाख रुपये प्रति वर्ष की औसत सीटीसी और ₹26.0 लाख रुपये प्रति वर्ष की मध्य सीटीसी के साथ अपना प्लेसमेंट पूरा किया। उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय सीटीसी ₹1.23 एलपीए पर उल्लेखनीय बनी रही, जबकि उच्चतम घरेलू सीटीसी ₹72.0 एलपीए तक पहुंची, जिससे बैच के 38% से अधिक छात्रों को प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) प्राप्त हुए। बैच के शीर्ष 25% छात्रों के लिए औसत सीटीसी ₹49.6 एलपीए था।

अंतिम प्लेसमेंट - एमबीए (बिजनेस एनालिटिक्स) 2023-25 बैच

आईआईएफटी ने अपने पहले एमबीए (बिजनेस एनालिटिक्स) प्रोग्राम के 2023-25 बैच के लिए अंतिम प्लेसमेंट सफलतापूर्वक संपन्न किया । इस प्लेसमेंट अभियान में 25 प्रतिष्ठित भर्तीकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैच ने ₹25.3 लाख प्रति वर्ष की प्रभावशाली औसत सीटीसी और ₹20.0 लाख प्रति वर्ष की औसत सीटीसी को हासिल किया। उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव ₹60 लाख प्रति वर्ष के असाधारण स्तर को छू गया, जबकि उच्चतम घरेलू प्रस्ताव ₹72.0 लाख प्रति वर्ष के शिखर पर जा पहुंचा । समूह के शीर्ष 25% ने उल्लेखनीय रूप से, ₹40.0 लाख प्रति वर्ष की औसत सीटीसी को हासिल किया।

ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट्स- एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 2024-28 बैच

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने अपने प्रमुख एमबीए (आई बी) कार्यक्रम के 2024-26 के बैच के लिए ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट का समापन किया। प्लेसमेंट चक्र में विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के 105 से अधिक प्रतिष्ठित भर्तीकर्ताओं ने भाग लिया । 2 महीने की अवधि के लिए औसत वजीफा ₹2.73 लाख और औसत मध्य वजीफा ₹2.50 लाख रहा।उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय वजीफा ₹6.00 लाख और उच्चतम घरेलू वजीफा ₹4.50 लाख रहा, जबकि 60 से ज़्यादा वजीफे ₹4.00 लाख से ऊपर के थे।

ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट - एमबीए (बिजनेस एनालिटिक्स) 2024-26 बैच

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने अपने दिल्ली परिसर में एमबीए बिज़नेस एनालिटिक्स बैच 2024-26 के लिए ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट का आयोजन किया। कुल 38 भर्तीकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और एनालिटिक्स, वित्त, परामर्श, उत्पाद, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री एवं विपणन, और सामान्य प्रबंधन में पदों की पेशकश की। अधिकतम वजीफा ₹4.00 लाख रहा, जिसमें औसत वजीफा ₹1.41 लाख और 2 महीने की इंटर्नशिप अवधि के लिए औसत वजीफा ₹1.10 लाख रहा।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, दिल्ली के एमडीपी विभाग ने विभिन्न स्तरों के के प्रबंधकों और कार्यपालकों के लिए 14 कार्यक्रमओं का संचालन किया. इनमें से 2 कार्यक्रम सभी क्षेत्रों से आने वालों के लिए परिसर में आयोजित खुले कार्यक्रम थे (जिनमें कोई भी या सकता था) और 12 प्रायोजित कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों (आईटीएस परिवीक्षार्थियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों सहित) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के लिए थे। इन कार्यक्रमों से कुल 397 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

श्रेणीवार कार्यक्रम विवरण:

कार्यक्रम	कार्यक्रम संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
प्रायोजित	12	318
परिसर में प्रमाणपत्र कार्यक्रम	02	79
कुल संख्या	14	397

कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) का कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम प्रभाग (ईएमपीडी) स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करता है। यह युवा पेशेवरों और मध्यम-स्तरीय वरिष्ठ प्रबंधकों को अत्याधुनिक ज्ञान और उद्योग की अंतर्दृष्टि देकर सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1. 11 नवंबर 2024 को 57वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ:

11 नवंबर 2024 को आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान कार्यकारी छात्रों को पीजी डिप्लोमा प्रदान किया गया।

क्रम संख्या	कार्यक्रम	पीजी डिप्लोमा प्राप्त छात्रों की संख्या
1	ईपीजीडीआईबी- 2023-24	71
2	ईपीजीडीआईबी-शीतकालीन2023-24	38
3	ईपीजीडी-जीएचआरएम 2022-24 (पहला बैच)	09
	कुल संख्या	**118**

2. ईएमपी प्रभाग द्वारा कार्यक्रमों का संचालन

निम्नलिखित कार्यकारी कार्यक्रम निर्धारित समय योजना के अनुसार सप्ताहांत में आयोजित किए गए थे ।

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम एवं अवधि	छात्रों की संख्या
1	ईपीजीडी-जीएचआरएम (डब्ल्यूई-ओसी) 2023-25 : 18 महीने	14
2	ईपीजीडीआईबी-ग्रीष्मकालीन (डब्ल्यूई-ओसी) 2023-25 : 18 महीने	97
3	ईपीजीडीआईबी-शीतकालीन 2024-25 : 18 महीने	42
4	पीजीसीएम (आईबी) 2025-25: 12 महीने – मार्च 2025 में शुरू हुआ	15

3. अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू अध्ययन दौरे/बंदरगाह दौरे

- एंटवर्प, बेल्जियम (5-8 नवंबर 2024): ईपीजीडीआईबी-ग्रीष्मकालीन बैच (31 प्रतिभागी) के लिए एंटवर्प/फ़्लैंडर्स बंदरगाह प्रशिक्षण केंद्र (एपीईसी) में प्रशिक्षण।

- वियतनाम (9-12 नवंबर 2024): ईपीजीडी-जीएचआरएम और ईपीजीडीआईबी छात्रों (33 प्रतिभागी) के लिए पूर्वी एशिया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ईएयूटी), हनोई के सहयोग से अध्ययन दौरा।

- विशाखापत्तनम, भारत (11-12 नवंबर 2024): 28 प्रतिभागियों के साथ विशाखापत्तनम कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड और वीसीटी-कंटेनर फ्रेट स्टेशन का बंदरगाह दौरा।

4. एंटवर्प/फ़्लैंडर्स पोर्ट (APEC), बेल्जियम के साथ समझौता ज्ञापन

भारत सरकार के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और फ़्लैंडर्स सरकार के राष्ट्रपति एवं फ़्लैंडर्स के अर्थव्यवस्था, नवाचार एवं उद्योग, विदेश मामले, डिजिटलीकरण एवं सुविधा प्रबंधन मंत्री महामहिम श्री मथायस डाइपेंडेले की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। IIFT और APEC - एंटवर्प/फ़्लैंडर्स पोर्ट, बेल्जियम के बीच समझौता ज्ञापन 3 मार्च, 2025 को वाणिज्य भवन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में में हस्ताक्षरित किया गया।

5. कार्यशालाएँ और विशेष व्याख्यान

- 7 दिसंबर 2024 को एमए (अर्थशास्त्र) के छात्रों सहित 139 प्रतिभागियों के साथ POSH कार्यशाला।
- 2 फ़रवरी 2025 को Cvent इंडिया के उपाध्यक्ष श्री संदीप नागपाल द्वारा मार्केटिंग टेक्नोलॉजी (MarTech) पर व्याख्यान।
- 22 फ़रवरी 2025 को मारुति सुजुकी के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह द्वारा आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल क्षमता विकास पर व्याख्यान।

दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई)

दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई) की स्थापना कार्यरत पेशेवरों को निरंतर व्यावसायिक विकास और कौशल संवर्धन पर केंद्रित आवश्यकता-आधारित ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मई 2021 में की गई थी। पिछले एक वर्ष में, केंद्र ने लचीले, इंटरैक्टिव ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से अपनी पहुँच का विस्तार किया है।

1. एमबीए (आईबी) ऑनलाइन कार्यक्रम

आईआईएफटी द्वारा प्रस्तुत यह स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर कार्यरत पेशेवरों को उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम अनुभवी प्रबंधकों को गहन ज्ञान, व्यावहारिक उपकरणों और रणनीतिक अंतर्दृष्टि से सशक्त बनाता है ताकि वे विशेष रूप से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त, विपणन, व्यापार और रणनीति के क्षेत्रों में जटिल व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान कर सकें।

वर्तमान बैच:

- 2022–24 बैच: 9 प्रतिभागी (जून 2025 में दीक्षांत समारोह)
- 2023–25 बैच: 11 प्रतिभागी (वर्तमान में सेमेस्टर IV में)

2. चार महीने के ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम

केंद्र, निर्यात-आयात प्रबंधन, वैश्विक व्यापार रसद और बंदरगाह संचालन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और व्यावसायिक विश्लेषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी प्रदान करता है।

वर्तमान बैच:

- बैच 01 (सितंबर 2024–फरवरी 2025): 32 प्रतिभागी (निर्यात-आयात प्रबंधन)
- बैच 02 (जनवरी 2025–मई 2025): 27 प्रतिभागी (निर्यात-आयात प्रबंधन)

3. व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)

यह प्रभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की निर्यात बंधु योजना के अंतर्गत 'निर्यात-आयात प्रबंधन की मूल बातें' पर एमओओसी कार्यक्रम संचालित करता है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्रतिभागियों को 134 प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

4. विकसित भारत@2047 वेबिनार

भारत सरकार की पहल - 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएँ/विकसित भारत@2047, के अंतर्गत प्रभाग ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान चार वेबिनार आयोजित किए।

5. उद्योग भ्रमण

विभाग ने एमबीए (आईबी) ऑनलाइन कार्यक्रम और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम के छात्रों के लिए औद्योगिक संचालन की व्यावहारिक समझ बढ़ाने हेतु दो, एक दिवसीय उद्योग भ्रमण आयोजित किए।

1) 3 जनवरी 2025 को, छात्रों ने मदर डेयरी प्लांट, पटपड़गंज का दौरा किया, जहाँ उन्होंने डेयरी प्रसंस्करण, पैकेजिंग और वितरण प्रणालियों की जानकारी प्राप्त की।

2) ऑटोमोबाइल उद्योग में विनिर्माण प्रक्रियाओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण से परिचित कराने के लिए 17 मार्च 2025 को, गुरुग्राम के मानेसर स्थित होंडा प्लांट का भ्रमण आयोजित किया गया।

एम.ए. (अर्थशास्त्र - व्यापार एवं वित्त में विशेषज्ञता)

एम.ए. (अर्थशास्त्र - व्यापार एवं वित्त में विशेषज्ञता) कार्यक्रम, जो 2018-19 में शुरू किया गया था, दिल्ली और कोलकाता दोनों परिसरों में उपलब्ध है। यह कार्यक्रम पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करता है, जिसमें सैद्धांतिक अर्थशास्त्र, अनुभवजन्य अनुप्रयोगों और उन्नत अर्थमितीय उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
IIFT का अर्थशास्त्र कार्यक्रम अब यूरोपीय संघ के इरास्मस मुंडस कार्यक्रम का हिस्सा है। IIFT अब EGEI का एक सहयोगी भागीदार है, जो सहयोग के नए रास्ते खोलता है (https://www.master-egei.eu/egei-associate-partners/)

IIFT के अर्थशास्त्र विभाग को रेपेक/आइडियाज़ इंडिया रैंकिंग (https://ideas.repec.org/top/top.india.html) के तहत भारत में 8वें सर्वश्रेष्ठ विभाग का दर्जा दिया गया है।

एम.ए. (अर्थशास्त्र) कार्यक्रम का छठा बैच (2023-25) वर्तमान में अपने चौथे सेमेस्टर में है, जिसमें 57 छात्र दिल्ली परिसर में और 52 छात्र कोलकाता परिसर में अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। सातवें बैच (2024-26) का उद्घाटन 27 अगस्त 2024 को दोनों परिसरों में किया गया था। उद्घाटन समारोह में इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के संस्थापक डीन प्रो. शुभाशीष गंगोपाध्याय ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बैच में वर्तमान में दिल्ली में 66 और कोलकाता में 54 छात्र हैं, जो इस कार्यक्रम के दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग संस्थान की तीन प्रमुख पत्रिकाओं, अर्थात् - फोकस डब्ल्यूटीओ (त्रैमासिक एवं आंतरिक पत्रिका), आईआईएफटी इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिव्यू (आईबीएमआर) (द्विवार्षिक पत्रिका और सेज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित), और फॉरेन ट्रेड रिव्यू (एफटीआर) (त्रैमासिक पत्रिका) पर कार्य करता है, साथ ही त्रैमासिक आईआईएफटी न्यूज़लेटर भी प्रकाशित करता है। ये तीनों पत्रिकाएँ शोधार्थियों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के पेशेवरों के लिए उभरते वैश्विक व्यापार मुद्दों से जुड़ने हेतु महत्वपूर्ण मंच, सूचना और सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करती हैं। प्रकाशन विभाग आईआईएफटी वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी) आदि का भी प्रबंधन करता है।

फॉरेन ट्रेड रिव्यू जर्नल: फॉरेन ट्रेड रिव्यू (FTR) एक समकक्ष-समीक्षित त्रैमासिक पत्रिका है, जो अकादमिक शोध जगत में साढ़े चार दशकों से अधिक समय से मौजूद है। यह पत्रिका SAGE पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह पत्रिका निम्नलिखित सार और अनुक्रमण डेटाबेस में शामिल है: SCOPUS, चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ बिजनेस स्कूल्स (ABS); ABDC-B, क्लेरिवेट एनालिटिक्स: इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स (ESCI)। यह पत्रिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय पर सैद्धांतिक और अनुभवजन्य शोध के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करने का इरादा रखती है। 2024-25 के दौरान, IIFT ने FTR खंड 59 संख्या 1, 2, और 3 के 4 अंक प्रकाशित किए हैं, और एक अंक खंड 60 संख्या 1 (मई, अगस्त, नवंबर 2024 और फरवरी 2025) है।

नया जर्नल 'आईआईएफटी इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिव्यू जर्नल': आईआईएफटी ने सेज पब्लिकेशंस के साथ मिलकर "इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिव्यू (आईआईएफटी-आईबीएमआर) जर्नल" नामक एक द्विवार्षिक समकक्ष-समीक्षित जर्नल प्रकाशित किया है। इस जर्नल का उद्देश्य प्रबंधकीय मुद्दों, प्रथाओं और नवाचारों को एकत्रित करना है जो दुनिया भर के विद्वानों, शिक्षकों, प्रबंधकों, उपभोक्ताओं, अन्य सामाजिक हितधारकों और नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी हैं। इसका उद्देश्य प्रबंधन अनुशासन की विषयवस्तु और सीमाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, साथ ही व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय दायरे को कवर करना है, जिसमें एशिया (श्रीलंका, जापान और थाईलैंड), रूस, अमेरिका आदि में फैले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन के विविध क्षेत्रों के प्रख्यात प्रोफेसर शामिल हैं। प्रकाशन विभाग ने दिसंबर 2024 में आईआईएफटी आईबीएमआर खंड 2 अंक 1 विशेषांक प्रकाशित किया है।

फोकस डब्ल्यूटीओ जर्नल: प्रकाशन विभाग फोकस डब्ल्यूटीओ (जर्नल ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड इंटरनेशनल बिजनेस) (प्रिंट और ऑनलाइन) नामक एक ब्लाइंड पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक जर्नल प्रकाशित करता है। फोकस डब्ल्यूटीओ, आईआईएफटी का एक आंतरिक प्रकाशन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन अनुसंधान पर लेख, शोध पत्र, परिप्रेक्ष्य लेख, केस स्टडी, मोनोग्राफ और

पुस्तक समीक्षाएँ प्रकाशित करता है। 2024-25 के दौरान, प्रकाशन विभाग फोकस डब्ल्यूटीओ खंड 26 के 3 अंक (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून और जुलाई-सितंबर 2024) प्रकाशित करेगा।

आईआईएफटी त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन: प्रकाशन विभाग आईआईएफटी त्रैमासिक न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है जिसमें संस्थान के विभिन्न प्रभागों की गतिविधियाँ शामिल होती हैं। 2024-25 के दौरान, प्रकाशन विभाग ने आईआईएफटी न्यूज़लेटर के 3 अंक (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून और जुलाई-सितंबर 2024) प्रकाशित किए हैं। आईआईएफटी वेबसाइट पर कुल 49 न्यूज़लेटर प्रकाशित और अपलोड किए जा चुके हैं।

वर्किंग पेपर/कार्याधीन शोधपत्र: आईआईएफटी की वर्किंग पेपर श्रृंखला का उद्देश्य संकाय सदस्यों को प्रकाशन-पूर्व चरण में अपने शोध निष्कर्षों को पेशेवर सहयोगियों के साथ साझा करने में मदद करना है। ये पेपर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाते हैं और आईआईएफटी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। आईआईएफटी वेबसाइट पर कुल पचहत्तर वर्किंग पेपर अपलोड किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता

ICCD प्रभाग, दुनिया भर के संस्थानों के साथ सहयोग करके, संस्थान के वैश्विक नेटवर्क के निर्माण हेतु विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करता है ताकि विभिन्न शैक्षणिक व्यवस्थाएँ संचालित की जा सकें। IIFT के शैक्षणिक सहयोग का प्रमुख आधार, छात्र और संकाय आदान-प्रदान है। यह प्रभाग, शैक्षणिक साझेदारी के अवसरों की खोज हेतु दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ निरंतर संवाद में संलग्न है। वर्तमान में, IIFT का दुनिया भर के 46 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सहभागिता में हैहै। इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों में से 21 यूरोप में, 13 एशिया में और 12 दुनिया के अन्य हिस्सों में हैं।

नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

- संस्थान ने 25 अप्रैल 2024 को तंजानिया के वित्त प्रबंधन संस्थान (आईएफएम तंजानिया) के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए एक सामान्य शैक्षणिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- संस्थान ने 26 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन के प्लायमाउथ विश्वविद्यालय के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए एक सामान्य शैक्षणिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- संस्थान ने 10 मई 2024 को ब्रिटेन के हडर्सफ़ील्ड विश्वविद्यालय के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए एक सामान्य शैक्षणिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- संस्थान ने सितंबर 2024 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के साथ 3 वर्षों की अवधि के लिए एक सामान्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- संस्थान ने 3 मार्च 2025 को बेल्जियम के एपेक एंटवर्प/फ़्लैंडर्स पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के साथ 4 वर्षों की अवधि के लिए एक सामान्य शैक्षणिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इनबाउंड

स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विभिन्न स्कूलों से तीन छात्र आईआईएफटी में आए:

क्रम संख्या	नाम	देश	विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	त्रैमासिक
1	सुश्री एलेक्सिया राचेले मैरी रोज़ काह्न	फ्रांस	रेनेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025
2	सुश्री अन्ना प्रशचारुक	रूस	GSEM UrFU, रूस	मार्च 2025
3.	श्री मिखाइल पेस्ट्री	रूस	GSEM UrFU, रूस	मार्च 2025

छात्र विनिमय कार्यक्रम 2024-25 IIFT

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) और डॉ. नीति नंदिनी चटनानी के नेतृत्व में इसके प्रभाग, ICCD, को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत 56 उत्कृष्ट छात्रों ने एक उल्लेखनीय और परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। इस शैक्षणिक वर्ष में, हमारा विशिष्ट समूह यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, फ़िनलैंड और रूस के प्रतिष्ठित और विश्व स्तर पर प्रशंसित बिज़नेस स्कूलों का हिस्सा होगा।

मान्यता और रैंकिंग (2024-25)

- IIFT ने प्रबंधन श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) इंडिया रैंकिंग - 2024 में भाग लिया है और 15वीं रैंक हासिल की है।
- IIFT ने PG मैनेजमेंट प्रोग्राम, MBA-IB (पूर्णकालिक) के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड (NBA) मान्यता प्रक्रिया हेतु आधिकारिक रूप से आवेदन किया है। विशेषज्ञ टीम का दौरा 30 अगस्त से 1 सितंबर, 2024 के दौरान आयोजित किया गया था।
- ICCD - मान्यता और रैंकिंग (A&R) प्रकोष्ठ ने 1 जुलाई 2024 को AACSB को एक सतत सुधार समीक्षा (CIR) आवेदन प्रस्तुत किया है।
- "अपनी मान्यता यात्रा शुरू करना" विषय पर AACSB सेमिनार का आयोजन IIFT द्वारा मान्यता और रैंकिंग प्रकोष्ठ के माध्यम से 18 सितंबर 2024 को किया गया था। सेमिनार के मुख्य संसाधन व्यक्ति डॉ. ज्योफ पेरी, कार्यकारी उपाध्यक्ष, वैश्विक मुख्य सदस्यता अधिकारी और एशिया प्रशांत AACSB के प्रबंध निदेशक थे।
- शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के सभी कार्यक्रमों के लिए एओएल माप रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रत्यायन एवं रैंकिंग सेल द्वारा एएसीएसबी एश्योरेंस ऑफ लर्निंग (एओएल) अभ्यास आयोजित किया जा रहा है।
- ICCD- प्रत्यायन एवं रैंकिंग प्रकोष्ठ ने बिज़नेस टुडे - MDRA बी स्कूल सर्वेक्षण 2024 के लिए डेटा प्रस्तुत किया है और 7वीं रैंक हासिल की है।
- IIFT ने फॉर्च्यून इंडिया बी-स्कूल रैंकिंग 2024 में 9वीं रैंक हासिल की है।
- IIFT को फॉर्च्यून इंडिया की सर्वश्रेष्ठ बी-स्कूल रैंकिंग 2024 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- IIFT को T.I.M.E बी-स्कूल रैंकिंग 2024 में 7वीं रैंक मिली है।
- IIFT को MBAUniverse.com रैंकिंग 2025 में 10वीं रैंक मिली है।
- ICCD - प्रत्यायन एवं रैंकिंग (A&R) प्रकोष्ठ ने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (MoE), भारत सरकार द्वारा आयोजित सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) पोर्टल पर डेटा प्रस्तुत किया है।
- क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) मान्यता द्वारा शुरू किए गए सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (एनएससीएसटीआई) सर्वेक्षण को आईसीसीडी - मान्यता और रैंकिंग (ए एंड आर) सेल द्वारा 14 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था।

आईआईएफटी सदस्यताएँ

आईसीसीडी, आईआईएफटी की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सदस्यता के लिए नोडल संपर्क रहा है। दुनिया भर के प्रतिष्ठित संगठन की सदस्यता से संबंधित सभी गतिविधियों का ध्यान आईसीसीडी द्वारा रखा जाता है। नीचे आईआईएफटी द्वारा ग्रहण की गई सदस्यताएँ दी गई हैं, और ये सदस्यताएं वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा रखती है।

1. **एसोसिएशन ऑफ एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस (AACSB):** AACSB इंटरनेशनल (AACSB), एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था, शिक्षकों, छात्रों और व्यवसायों को एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जोड़ती है: महान नेताओं की अगली पीढ़ी का निर्माण। 1916 से उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों का पर्याय, AACSB दुनिया भर में 1,850 से अधिक सदस्य संगठनों और 950 से अधिक मान्यता प्राप्त बिजनेस स्कूलों को गुणवत्ता आश्वासन, व्यावसायिक शिक्षा संबंधी जानकारी और शिक्षण एवं विकास सेवाएँ प्रदान करता है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी (AIB):** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी (AIB) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित विद्वानों और विशेषज्ञों का एक अग्रणी संघ है। 1959 में स्थापित, इसके लगभग 90 देशों में 3400 से अधिक सदस्य हैं। इसकी सदस्यता संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों के लिए भी खुली है।

3. **यूरोपियन फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (EFMD):** EFMD एक वैश्विक, गैर-लाभकारी, सदस्यता-आधारित संगठन है जो प्रबंधन विकास के लिए समर्पित है। इसे बिज़नेस स्कूलों, बिज़नेस स्कूल कार्यक्रमों और कॉर्पोरेट विश्वविद्यालयों के लिए एक मान्यता निकाय के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। शिक्षा, व्यवसाय, लोक सेवा और परामर्शदाता क्षेत्र के 30,000 प्रबंधन पेशेवरों के नेटवर्क के साथ, EFMD प्रबंधन शिक्षा के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

4. **भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU):** AIU उच्च शिक्षा के विकास और संवर्धन में सक्रिय रूप से संलग्न है। सभी प्रकार के विश्वविद्यालय AIU की सदस्य हैं, जैसे पारंपरिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, समविश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। भारतीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, बांग्लादेश,

भूटान, कजाकिस्तान गणराज्य, मलेशिया, मॉरीशस, नेपाल, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के 13 विश्वविद्यालय/संस्थान इसके सहयोगी सदस्य हैं।

5. **ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, भारत (GCN):** ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया (GCNI), संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट (UNGC), न्यूयॉर्क का भारतीय स्थानीय नेटवर्क, पूर्ण कानूनी मान्यता के साथ स्थापित होने वाला विश्व का पहला स्थानीय नेटवर्क है।

6. **एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स (AIMS):** एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स (AIMS) भारत में प्रबंधन शिक्षा के व्यावसायिक विकास और देश में बी-स्कूलों के हितों की रक्षा के लिए बी-स्कूलों का एक नेटवर्किंग निकाय है। यह भारत में और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय प्रबंधन स्कूलों का आधिकारिक प्रतिनिधि है। यह दुनिया में बी-स्कूलों के सबसे बड़े नेटवर्किंग निकायों में से एक है।

7. **भारतीय वित्त संघ (आईएफए):** आईआईएफटी ने अगस्त, 2023 में भारतीय वित्त संघ (आईएफए) की प्रतिष्ठित आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। आईएफए एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसका उद्देश्य वित्त और लेखांकन के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षाविदों और उद्योग जगत को कॉर्पोरेट वित्त, लेखांकन और कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्तीय बाजार और जोखिम प्रबंधन के मामलों पर बहस, शोध और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।

8. **अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए):** एआईएमए की स्थापना 1957 में हुई थी, जिसने देश में प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एआईएमए के 38,000 से अधिक सदस्य हैं और एआईएमए से संबद्ध 68 स्थानीय प्रबंधन संघों के माध्यम से लगभग 6,000 कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य हैं।

9. **भारतीय विपणन अकादमी (एआईएम):** 2009 में स्थापित, भारतीय विपणन अकादमी (एआईएम) अग्रणी प्रबंधन संस्थानों का एक संघ है जो डॉक्टरेट और समकक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियाँ प्रदान करता है।

10. **इरास्मस मुंडस:** आईआईएफटी "वैश्वीकरण और यूरोपीय एकीकरण का अर्थशास्त्र (ईजीईआई)" पर मास्टर कार्यक्रम के लिए एक सहयोगी भागीदार बन गया है।

आईआईएफटी की संस्थागत व्यवस्था

भारत के विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए, संस्थान बनाने के पंडित जवाहर लाल नेहरू के सपने को साकार करने के लिए 2 मई 1963 को विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना की गई। अपनी स्थापना के समय से संस्थान तेज़ी से विकसित हुआ और बड़े बदलावों से गुजरा । इसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी शैक्षिक गतिविधियों के आयाम और दायरे को बढ़ाया जिसने अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विस्तृत श्रेणी को अपने घेरे में ले रखा है. आज, संस्थान को अपने 62 वें साल में अपने संसाधन आधार, ज्ञान, अपनी गौरवशाली परंपरा एवं पूर्व छात्रों के मजबूत जाल तंत्र के लिए भारत और विदेश दोनों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है ।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जैसे संगठन की उत्पत्ति भीतर से होती है लेकिन केवल अपने परिवेश से पोषण लेने के बाद. आस पास की व्यवस्था जितनी ज्यादा कठिन चुनौतियां खड़ी करती हैं, नए एवं विशेष कार्यों को पूरा करने के स्तर तक आने का उतना ही अधिक प्रयास किया जाता है. विदेश व्यापार क्षेत्र की हमेशा विकसित होती रहने वाली गतिशीलता लगातार नए अवसर देती है और नई चुनौतियां खड़ी करती है. संस्थान अपनी गतिविधियों की रूपरेखा का पुनः रेखांकन करके, अपने तरीके से इनका सामना करने का प्रयास करता है ।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, अनुसंधान और शिक्षा को सुधारने एवं बढ़ावा देने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के पास वर्तमान में निम्नलिखित प्रभाग हैं :

(i) कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी)विभाग
(ii) प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम डी पी) विभाग
(iii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षमता विकास (आई सी आई सी डी) विभाग
(iv) प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) विभाग
(iv) अर्थशास्त्र विभाग
(v) अनुसंधान विभाग
(vi) पूर्व छात्र मामलों का विभाग
(vii) पत्रिका विभाग
(viii) दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई)

कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग

कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम प्रभाग का गठन, सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, उद्यमी, निर्यातकों, व्यवसायिक क्षेत्र और सभ्य समाज के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापारनीति पर पडने वाले उसके प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने को सुलभ बनाने हेतु किया गया । ईएमपीडी ने इस विचार के साथ कार्यक्रमओं की शुरुआत की कि ऐसा दृष्टिकोण, समझ विकसित कर और समकालीन व्यापार एवं आर्थिक मुद्दों पर विश्लेषण उत्पन्न किया जाए जो विभिन्न देशों के लिए रुचिकर हो खास कर विकासशील देशों के लिए।

प्रभाग जो कार्यकारी डिप्लोमा कार्यक्रम चलाता है उसके पाठ्यक्रम के मुख्य भाग इस प्रकार है:

- हर महीने के तीन सप्ताह अंत में क्लासेज, पाठ्यक्रम की अवधि 18 महीने
- हर सत्र के शुरू में संपर्क सप्ताह
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे शीघ्र विकसित होने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और व्यापार में से विशेषज्ञता प्राप्त करने के अवसर को चुनना
- संरचित अनुसंधान परियोजना के द्वारा अनुसंधान क्रियाविधि का खुलासा
- पठन सामग्री और अनुसंधान डेटाबेस की बड़े पैमाने पर ऑनलाइन उपलब्धता
- विश्व भर में उच्चपदस्थ पूर्व छात्रों के साथ मेलजोल बनाने का अवसर

प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग

संस्थान का प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, वित्त, आयात-निर्यात प्रबंधन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कूटनीतिक प्रबंधन, मानव संसाधन, आईटी, एसईजेड के लिए क्षमता निर्माण, डेटा विश्लेषण,

व्यापार विश्लेषण इत्यादि जैसे विषयों में पीएसयूज़, कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के कार्यक्षेत्रों के अधिकारियों/सरकारी कार्यकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर प्रस्तुत करता रहता है। आईएएस और अन्य अखिल भारतीय सेवा सहित भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों के लिये प्रभाग विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

आईआईएफटी भारतीय व्यापार सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए नौ महीने का आवासीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाला एक नोडल संस्थान है। इसके अतिरिक्त, संस्थान, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा इत्यादि के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

डीजीएफटी, भारत सरकार की निर्यात बंधु स्कीम के अंतर्गत देश भर के व्यवसाइयों और निर्यातकों के लिये "आयात-निर्यात व्यापार" पर भी यह संस्थान, ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यक्रम की श्रृंखला चला रहा है। अब तक, 1350 से अधिक निर्यातकों और व्यवसायियों को इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है. हाल ही में डीजीएफटी की पहल पर आईआईएफटी ने एमओओसी (विस्तृत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम) मंच द्वारा निर्यात बंधु कार्यक्रम आरंभ किया है।

इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग हाइब्रिड/ऑनलाइन/कैंपस में कक्षाओं के माध्यम से निम्नलिखित लंबी अवधि कार्यक्रम भी चलाता है;

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र कार्यक्रम
2. हाइब्रिड तरीके से आयात और निर्यात प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम
3. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रणनीतियों पर ईडीपी
4. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर ईडीपी
5. डीजीआर के माध्यम से सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षमता विकास (आई सी सी डी) विभाग

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षमता विकास (आईसीसीडी) विभाग, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ शैक्षिक संबंध बनाकर संयुक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमओं को शुरू करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थी और संकाय में होने वाला आदान-प्रदान शैक्षिक सहयोग का अभिन्न अंग है. प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सदस्यता प्राप्त करके, यह संस्थान, शैक्षिक सहयोग, विद्यार्थियों के बीच आदान प्रदान, अध्ययन के दौरे और संकाय में आदान प्रदान गतिविधियों को और सुदृढ़ करने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों में, विभाग संकाय की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है।

प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग

संस्थान का प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग, पूर्ण कालिक/लंबी अवधि कार्यक्रमो का प्रधान प्रभाग है। यह प्रभाग, प्रशासनिक एवं शैक्षिक सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त संस्थान के सप्ताह अंत एमबीए और प्रमाण पत्र कार्यक्रमओं मे प्रवेश की प्रक्रिया करता है। इस प्रभाग की ज़िम्मेदारी है कि वह सभी हितधारकों, जैसे संकाय, छात्र और अन्य सभी संबंधित, के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें।

अर्थशास्त्र प्रभाग

अर्थशास्त्र में एमए (अर्थशास्त्र- व्यापार और वित्त में विशेषज्ञता)

अर्थशास्त्र में एम ए (अर्थशास्त्र- व्यापार और वित्त में विशेषज्ञता) कार्यक्रम, शैक्षिक वर्ष 2018-19 में शुरू हुआ था. कार्यक्रम का संचालन दिल्ली और कलकत्ता में एक साथ किया जाता है। यह यह कार्यक्रम विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र विभागों के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को समाहित करता है। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नवीनतम विकास और उनके अनुभवजन्य अनुप्रयोगों पर बल दिया जाता है। कक्षा में अंतःक्रियाओं के अतिरिक्त, ट्यूटोरियल और समूह कक्षाओं में प्रत्येक छात्र पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है: शैक्षिक प्रयास करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उनमे जटिल समस्याओं का समाधान करने की योग्यता विकसित करना, कार्यक्रम में शामिल मॉडल के सूत्रीकरण और साथ ही साथ सैद्धांतिक मॉडल तैयार करने में योगदान देना. कार्यक्रम के दौरान नवीनतम अर्थमिति और सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाए।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कार्यक्रम अब यूरोपीय संघ के इरेस्मस मंडलास कार्यक्रम का भाग है. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, सहयोग के लिए पथ प्रशस्त करने वाले ईजीईआई का अब एक साझेदार है. (https:/ /www.master-egei.eu/egei-associate-partners/) रीपैक/आइडियास वैश्विक श्रेणीकरण के अंतर्गत भारत विदेश व्यापार संस्थान के अर्थशास्त्र विभाग को भारत में सबसे अच्छा विभाग होने के लिए छठा स्थान मिला है. https://ideas.repec.org/top/top.india.html).

उद्देश्य

एमए (अर्थशास्त्र- व्यापार और वित्त में विशेषज्ञता) कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य है:

1. विद्यार्थियों को उत्कृष्ट व्यापार नीती निर्माता और वित्तीय लेनदेन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित व्यापार मुद्दों पर प्रमुख रणनीतिकार बनने के लिए तैयार करना।
2. विद्यार्थियों को वे सभी साधन उपलब्ध कराना जो असली दुनिया की समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता कर सके।
3. विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और वित्त में विशिष्ट ज्ञान वाले पूर्ण कालिक शिक्षाविद बनने के लिए तैयार करना।

57 वां दीक्षांत समारोह

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 11 नवंबर 2024 को अपने 57 वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया । एमए (अर्थशास्त्र) और पीएच.डी. (अर्थशास्त्र) कार्यक्रम के निम्नलिखित बैचों को डिग्रियां प्रदान की गई :

क्रम संख्या	बैच	विद्यार्थियों की संख्या
1.	एम ए(अर्थशास्त्र) 2022-24 दिल्ली	51
2.	एमए (अर्थशास्त्र) 2022-24 कोलकाता	35
3.	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र) 2017 दिल्ली	02

शोध पद्धति कार्यशाला

अर्थशास्त्र विभाग ने 10-14 फ़रवरी 2025 के दौरान "सांख्यिकीय सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके डेटा विश्लेषण" विषय पर पाँच दिवसीय शोध पद्धति कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के युवा संकायों के साथ-साथ उद्योग जगत के शोधार्थियों और व्यवसायियों के लिए आयोजित की गई थी। कार्यशाला सफल रही और प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें यह कार्यशाला मूल्यवान और जानकारीपूर्ण लगी।

सीएमआईई डेटाबेस व्याख्यान श्रृंखला

अर्थशास्त्र प्रभाग ने 6, 9 और 18 दिसंबर 2024 को सीएमआईई डेटाबेस व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) प्राइवेट लिमिटेड के सहायक उपाध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी को छात्रों को आईआईएफटी, द्वारा सब्सक्राइब किए गए विभिन्न सीएमआईई डेटाबेस और आर्थिक डेटा विश्लेषण एवं अनुसंधान में उनके उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

प्लेसमेंट समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान

दिनांक	विषय	वक्ता	संगठन	उपस्थित रहने वाले
19 सितम्बर 2024	व्यापार परामर्श और कैरियर विकल्प	लक्ष्मण पांडे	संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी, विन्को कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विसेज	दिल्ली और कोलकाता
23 सितम्बर 2024	कल को आकार देना: अपनी पेशेवर यात्रा को भविष्य के लिए तैयार करना	अमित कुमारी	एवीपी, आईबीकेवाईसी ऑप्स इंडिया, डॉयचे बैंक	दिल्ली और कोलकाता
27 सितम्बर 2024	कॉर्पोरेट वास्तविकताओं से निपटना	ईमान चौधरी	एवीपी, एचएसबीसी	दिल्ली और कोलकाता
17 दिसंबर 2024	प्लेसमेंट साक्षात्कार में सफलता	खुशी आर्य	वरिष्ठ अनुप्रयुक्त डेटा विश्लेषक, डनहम्बी	दिल्ली और कोलकाता
24 जनवरी 2025	निवेश की मूल बातें और बाज़ार के उतार-चढ़ाव से निपटना	जय मेहता	सीएफए, अपस्टॉक्स	दिल्ली और कोलकाता

आईआईएफटी इकोनॉमिक्स सोसाइटी (आईईएस) द्वारा आयोजित व्याख्यान

दिनांक	विषय	वक्ता	उपस्थित रहने वाले
10 अप्रैल 2024	भारत में गिग-वर्क में कम कुशल महिला कार्यबल की स्थिति - एक खोजपूर्ण अध्ययन	डॉ मौसमी दास सहा. प्रोफ़ेसर बीजेबी ऑटोनॉमस कॉलेज, भुवनेश्वर	दिल्ली और कोलकाता
18 अप्रैल 2024	अर्थशास्त्र की पुनर्कल्पना: पारंपरिक प्रतिमान की एक नारीवादी आलोचना	डॉ रूपा पटवर्धन सहा. प्रोफ़ेसर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बैंगलोर	दिल्ली और कोलकाता
24 अप्रैल 2024	डिजिटल भुगतान और रोजगार संबंधी गतिविधियों में समय का उपयोग: एक लिंग-आधारित परिप्रेक्ष्य	डॉ. संध्या गर्ग सहायक प्रोफेसर, आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	दिल्ली और कोलकाता
30 अप्रैल 2024	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नए प्रतिमान: विश्व व्यापार संगठन से लेकर व्यापक मुक्त व्यापार समझौते तक	डॉ. प्रलोक गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर और सलाहकार विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र	दिल्ली और कोलकाता

5 अगस्त 2024	भारत में मौद्रिक नीति: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य	पामी दुआ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वरिष्ठ प्रोफेसर और पूर्व निदेशक	दिल्ली और कोलकाता
24 सितम्बर 2024	भारत में मौद्रिक नीति और हाल हाल ही में घटित घटनाक्रम	डॉ. संगीता मिश्रा निदेशक आरबीआई में मौद्रिक नीति विभाग	दिल्ली और कोलकाता
3 अक्टूबर 2024	प्रैक्सिस के सहयोग से वैश्विक संकट प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2024	-	दिल्ली और कोलकाता
6 फ़रवरी 2025	केंद्रीय बजट पैनल चर्चा	डॉ. राकेश मोहन जोशी कुलपति, आईआईएफटी डॉ. बिस्वजीत नाग प्रोफ़ेसर, आईआईएफटी डॉ. अर्पिता मुखर्जी प्रोफ़ेसर, आईसीआरआईईआर श्री एलन सीमन सलाहकार, आर्थिक नीति, ईवाई श्री शिशिर सिन्हा सह-संपादक, बिज़नेस लाइन	एमए, एमबीए और पीएचडी विद्वान
13 फ़रवरी 2025	कुशल नेतृत्व के लिए संचार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में निपुणता	डॉ. सी.वी. रामनन आईआईएफटी में विजिटिंग फैकल्टी	दिल्ली और कोलकाता
17 फ़रवरी 2025	IIFT से IES तक का सफर	अहाना सृष्टि भारतीय आर्थिक सेवा	दिल्ली और कोलकाता
17 अप्रैल 2025	ट्रम्पोनॉमिक्स और नई वैश्विक व्यवस्था-भारत पर प्रभाव	शिशिर सिन्हा एसोसिएट एडिटर, बिज़नेस लाइन	दिल्ली और कोलकाता

आईआईएफटी बिजनेस एनालिटिक्स क्लब द्वारा आयोजित व्याख्यान

दिनांक	विषय	वक्ता	उपस्थित रहने वाले
22 अप्रैल 2024	जनरेशन एआई के युग में डेटा-संचालित उत्पाद बनाना	स्निग्धा गुप्ता स्क्यूब एनालिटिक्स के सह-संस्थापक	दिल्ली और कोलकाता
25 सितम्बर 2024	प्रमुख परामर्श कौशलों को उजागर करना: रणनीतिक समस्या समाधान और संरचित सोच में अंतर्दृष्टि	रमन भाटिया संस्थापक, नेविगेटिंग एक्स कंसल्टिंग	दिल्ली और कोलकाता
29 सितम्बर 2024	क्रेडिट जोखिम और धोखाधड़ी विश्लेषण में मशीन लर्निंग पर अनुप्रयोग	अनिरबन सेनगुप्ता वरिष्ठ सहायक उपाध्यक्ष, वेल्स फ़ार्गो	दिल्ली और कोलकाता
29 नवंबर2024	डेटा को व्यावसायिक अंतर्दृष्टि में बदलना: आधुनिक निर्णय लेने में डेटा एनालिटिक्स की भूमिका	उज्जवल गुप्ता फ़्लोडाटा एनालिटिक्स के सह-संस्थापक	दिल्ली कोलकाता और काकीनाडा
6 दिसंबर 2024	सतत विकास में अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि: अनुसंधान के लिए कुछ मुद्दे	सब्यसाची साहा विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में एसोसिएट प्रोफेसर	दिल्ली और कोलकाता
15 & 22 दिसंबर	पायथन का उपयोग करके मशीन लर्निंग का	अनीश डे	दिल्ली और

2024	परिचय	सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गूगल	कोलकाता
16 & 23 फ़रवरी 2025	पायथन का उपयोग करके मशीन लर्निंग का परिचय	अनीश डे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गूगल	दिल्ली और कोलकाता
21 फ़रवरी 2025	बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में अर्थशास्त्रियों की भूमिका	युविका सिंघल क्वांट इको	दिल्ली

यूजीसी (नेट)

एमए (अर्थशास्त्र) 2024-26 बैच के दो छात्र और एमए (अर्थशास्त्र) 2023-25 बैच के एक छात्र ने 2024 में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।

अर्थशास्त्र में पीएच.डी. कार्यक्रम

संस्थान का पीएच.डी. (अर्थशास्त्र) कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय सहित अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टरेट अनुसंधान के अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम नए स्नातकों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षण संकाय के सदस्यों, और निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए है।

पीएचडी (अर्थशास्त्र) 2024 बैच का उद्घाटन 27 अगस्त 2024 को हुआ, जिसमें दो शोधार्थियों को दिल्ली परिसर में प्रवेश मिला। चार शोधार्थियों ने 2024 में अर्थशास्त्र विभाग में अपनी अंतिम पीएचडी थीसिस जमा की। इनमें से तीन छात्रों की थीसिस का अंतिम बचाव मार्च 2025 तक पूरा हो गया, और चौथे छात्र का शोधपत्र बचाव अप्रैल 2025 में हुआ। इसके अतिरिक्त, 2017 बैच के दो शोधार्थियों को 11 नवंबर 2024 को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई।

अर्थशास्त्र में अनुसंधान

अनुसंधान, संस्थान के विकास में बहुत महत्त्व रखता है क्योंकि ये प्रशिक्षण और ज्ञान की उत्पत्ति के दर्मियान मजबूत व्यापक मिलन बिंदु प्रदान करता है. उचित कॉर्पोरेट रणनीतियों को विकसित करने में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिदृश्यों का विश्लेषण करने में इसने परामर्श की मजबूत योग्यता विकसित की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की परियोजनाओं के लिए संस्थान सफलतापूर्वक बोली भी लगा रहा है। प्रभाग समय-समय पर, समकालीन विषयों पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है, जो दोनों बहुपक्षीय निकायों से, जैसे कि, प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों एवं सरकारी क्षेत्र से प्रख्यात विशेषज्ञों को एकत्रित करता है।

पूर्ण हो चुके अनुसंधान अध्ययन

1. "व्यापार करने में आसानी और भारतीय फर्मों का प्रदर्शन: उद्योगों और राज्यों में फर्म-स्तरीय अध्ययन।"
2. "बदलते वैश्विक परिवेश में यूके-भारतीय व्यापार और सीमा पार निवेश का भविष्य" पर आईसीएसएसआर-ईएसआरसी-यूकेआरआई सहयोगात्मक अनुसंधान ।

कार्याधीन अनुसंधान परियोजनाएँ

भारतीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) की फुटवियर एवं चमड़ा क्षेत्र उप-योजना में ब्रांड संवर्धन के अंतर्गत नामित एजेंसियों की नियुक्ति।

सम्मेलन, संगोष्ठी / कार्यशालाएँ

23 अप्रैल 2024 को भारत-यूके व्यापार एवं विकास सहयोग पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला इसी विषय पर चल रही परियोजना का एक हिस्सा थी, जिसका संचालन आईआईएफटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (दिल्ली विश्वविद्यालय), यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स बिजनेस स्कूल (यूके) और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (यूके) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह परियोजना आईसीएसएसआर (भारत) और ईएसआरसी (यूके) द्वारा प्रायोजित है।

यह परियोजना यूके-भारत एफटीए, जीएसपी के मूल्यांकन, व्यापार पर इसके प्रभाव और विकास पर इसके प्रभावों पर केंद्रित है। इंग्लैंड और भारत के उद्योग संघों ने भविष्य के उद्योग सहयोग के लिए इनपुट प्रदान किए।

अनुसंधान प्रभाग

अनुसंधान, संस्थान के विकास में बहुत महत्त्व रखता है, क्योंकि ये प्रशिक्षण और ज्ञान की उत्पत्ति के दर्मियान मजबूत व्यापक मिलन बिंदु प्रदान करता है. उचित कॉर्पोरेट रणनीतियों को उत्पन्न करने में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिदृश्यों का विश्लेषण करने में इसने परामर्श की मजबूत योग्यता विकसित की है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की परियोजनाओं के लिए संस्थान सफलतापूर्वक बोली भी लगा रहा है। प्रभाग समय-समय पर, समकालीन विषयों पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है जो दोनों बहुपक्षीय निकायों से, जैसे कि, प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों एवं सरकारी क्षेत्र से प्रख्यात विशेषज्ञों को एक साथ ले के आता है। प्रभाग द्वारा प्रस्तुत पीएचडी कार्यक्रम अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त करने वाला कार्यक्रम है।

पूर्व छात्र के मामला प्रभाग

बैंगलोर चैप्टर मीट

यह श्रृंखला 15 जून 2024 को बैंगलोर के भव्य पॉल होटल में बैंगलोर चैप्टर मीट 2024 के साथ शुरू हुई। विभिन्न उद्योगों और पृष्ठभूमियों से 70 से अधिक पूर्व छात्रों की रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति के साथ, यह एक शानदार शाम रही । जो बिछड़े साथियों से दोबारा से मिलने, हंसी-मज़ाक और साझी यादों से भरी रही ।

बैंगलोर चैप्टर मीट ने वर्ष के कार्यक्रमों के लिए एक उल्लेखनीय माहौल तैयार किया और देश भर में और उसके बाहर भी यादगार समारोहों की एक श्रृंखला का वादा किया।

चेन्नई चैप्टर मीट

चेन्नई के जीवंत शहर ने 22 जून, 2024 को चेन्नई चैप्टर मीट 2024 की मेजबानी की। यह एक अत्यंत उत्साहजनक और महत्वपूर्ण आयोजन था, क्योंकि इसमें 1976 से लेकर नवीनतम कक्षा 2024 तक के लगभग 30 पूर्व छात्र एकत्रित हुए। कोलकाता केंद्र के प्रमुख प्रो. के. रंगराजन ने प्रतिभागियों को संस्थान की नई पहल के बारे में जानकारी दी।

यह शाम पुरानी यादों, साझा अनुभवों और जीवंत वार्तालापों से भरी हुई थी, जिसने विभिन्न पीढ़ियों के आईआईएफटी छात्रों के बीच शाश्वत बंधन की पुष्टि की।

हैदराबाद चैप्टर मीट

6 जुलाई, 2024 को आयोजित हैदराबाद चैप्टर मीट में 1989 से 2023 तक के स्नातक कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 उत्साही पूर्व छात्र एकत्रित हुए। यह आयोजन सौहार्द और सार्थक ज्ञान के आदान-प्रदान के अपने उत्तम मिश्रण के लिए उल्लेखनीय रहा, जिसने न केवल स्मृतियों को बल्कि पेशेवर अंतर्दृष्टि और नेटवर्किंग के अवसरों को भी बढ़ावा दिया।
यह आईआईएफटी समुदाय की स्थायी भावना का प्रमाण था, जिसने भविष्य के पूर्व छात्रों के सहयोग की नींव को मजबूत किया।

दिल्ली चैप्टर मीट

दिल्ली एलुमनाई चैप्टर मीट 2024, 20 जुलाई 2024 को दक्षिण दिल्ली के प्रमुख आयोजन स्थलों में से एक, एसेक्स फार्म्स में आयोजित किया गया। आईआईएफटी के कुलपति प्रो. आर.एम. जोशी और कई वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। कई बैचों और कार्यक्रमों के 100 से अधिक पूर्व छात्र, पुरानी यादों से भरी बातचीत, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और रोमांचक नेटवर्किंग अवसरों से भरपूर एक शाम के लिए एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम ने आईआईएफटी के पूर्व छात्र नेटवर्क की मजबूती, गहराई और जीवंतता को रेखांकित किया और व्यापक पूर्व छात्र समुदाय में दिल्ली चैप्टर के महत्व की पुष्टि की।

वरिष्ठ पूर्व छात्रों का दौरा

9 अगस्त 2024 को, यूनिलीवर इंटरनेशनल के सीईओ और एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, श्री असीम पुरी ने आईआईएफटी दिल्ली परिसर का दौरा किया। उन्होंने एमबीए छात्रों को एक प्रेरक व्याख्यान दिया, जिसमें नेतृत्व, करियर विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसने छात्रों पर एक अमिट छाप छोड़ी।

कोलकाता चैप्टर मीट

10 अगस्त 2024 को उद्घाटित कोलकाता चैप्टर मीट 2024, पूर्व छात्र मामलों के विभाग की एक और उपलब्धि थी। यह शाम प्रेरक चर्चाओं और कुलपति के संबोधन से ऊर्जावान रही, जिनके शब्दों ने उपस्थित लोगों को आईआईएफटी के भविष्य के प्रति आशावादी और इसके बढ़ते वैश्विक समुदाय पर गर्वित महसूस कराया ।

यह सभा पूर्व छात्रों के बीच एकता की शक्ति और साझा दृष्टिकोण के अपार मूल्य का एक सशक्त स्मरण कराती थी।

कार्यकारी परिषद की बैठक

कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक उसी दिन, 10 अगस्त 2024 को आईआईएफटी कोलकाता परिसर में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख नेता और चैप्टर हेड्स एक साथ आए, जिससे पूर्व छात्र संबंधों की रूपरेखा और मजबूत हुई और आगामी पहलों के लिए रोडमैप तैयार हुआ।

मुंबई चैप्टर मीट

24 अगस्त 2024 को गोल्डफिंच मुंबई होटल में मुंबई चैप्टर मीट 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व छात्रों के बीच उत्साहपूर्ण भागीदारी और जीवंत आदान-प्रदान देखने को मिला, जो IIFT समुदाय की पहचान बन चुके जुड़ाव और सहयोग की भावना को दर्शाता है।

यूके चैप्टर मीट

यूके चैप्टर मीट 2024 का आयोजन 12 सितंबर 2024 को टरमरिक किचन, पार्क ग्रैंड लंदन केंसिंग्टन में किया गया। यूनाइटेड किंगडम में स्थित पूर्व छात्र पुरानी यादें ताज़ा करने, नेटवर्किंग करने और नए संबंध बनाने के लिए एक शाम के लिए एकत्र हुए, जहाँ जीवंत माहौल आईआईएफटी की वैश्विक उपस्थिति की स्थायी ताकत को दर्शाता है।

सिंगापुर चैप्टर मीट

इसके तुरंत बाद, सिंगापुर चैप्टर मीट 2024 का आयोजन 14 सितंबर 2024 को मुगल महल में हुआ। इस शाम में पुरानी यादों, पेशेवर बातचीत और भविष्य के सहयोग का एक बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला, जिसने दुनिया भर में अपने पूर्व छात्रों का समर्थन करने के लिए IIFT की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पूर्व छात्रों ने शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए संस्थान के निरंतर प्रयासों में सहयोग देने का भी संकल्प लिया।

विवान 10.0: मानव संसाधन सम्मेलन

विवान 10.0 के एक भाग के रूप में, कोलकाता परिसर ने 18-19 अक्टूबर 2024 को "*अशांत समय में नेतृत्व*" विषय पर अपने उद्घाटन मानव संसाधन सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिष्ठित नेताओं का एक पैनल एकत्रित हुआ, जिन्होंने अनिश्चितता के दौर में संगठनों के प्रबंधन पर अपने विचार साझा किए, जिसमें मानव संसाधन की उभरती भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया।
चर्चाओं में लचीलेपन, अनुकूलनशीलता और रणनीतिक दूरदर्शिता पर ज़ोर दिया गया, जिससे सभी उपस्थित लोगों को अमूल्य शिक्षा मिली।

ट्रेड विंड्स: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन - ट्रेड विंड्स का आयोजन 18-20 अक्टूबर 2024 को दिल्ली परिसर में "द ग्रेट रीसेट" विषय पर केंद्रित "21वीं सदी में डिजिटल विकास को उत्प्रेरित करना" विषय पर किया गया।

नेतृत्व पैनल ने डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से लचीली अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण पर गहन चर्चा की, जबकि डिजिटल पैनल ने भविष्य के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में डेटा और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाया।

यह एक दूरदर्शी, विचारोत्तेजक कार्यक्रम था जिसने वैश्विक व्यापार के भविष्य पर सार्थक बातचीत शुरू करवाई ।

कार्यकारी परिषद की बैठक और वार्षिक आम सभा

कार्यकारी परिषद की बैठक 16 नवंबर 2024 को दिल्ली परिसर में आईआईएफटी के कुलपति प्रो. राकेश मोहन जोशी के नेतृत्व में और पूर्व छात्र मामलों के प्रमुख प्रो. संजय रस्तोगी के संयोजन में आयोजित की गई। बैठक में सभी क्षेत्रीय अध्यायों के कार्यकारी परिषद सदस्यों के साथ-साथ विभागाध्यक्षों और छात्र निकायों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
इस बैठक में संस्थान के सहयोगात्मक जुड़ाव पर ज़ोर दिया गया और पूर्व छात्र नेटवर्क को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धताओं के साथ एक शानदार समापन हुआ।

भव्य पूर्व छात्र पुनर्मिलन

कार्यकारी समिति की बैठक के साथ आयोजित, भव्य पूर्व छात्र पुनर्मिलन वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण रहा, जिसमें विभिन्न बैचों के पूर्व छात्र, उत्सव और चिंतन के लिए एक साथ आए। इस कार्यक्रम ने, आईआईएफटी की अपने अतीत का सम्मान करते हुए, और भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने की प्रिय परंपरा को प्रतिबिंबित किया।

टोरंटो, कनाडा चैप्टर मीट

आईआईएफटी एलुमनी एसोसिएशन ऑफ कनाडा का औपचारिक शुभारंभ 30 नवंबर 2024 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता आईआईएफटी के कुलपति प्रो. राकेश मोहन जोशी ने की और मुख्य अतिथि सीजीआई कपिध्वज प्रताप सिंह उपस्थित थे। यह ऐतिहासिक आयोजन उत्तरी अमेरिका में आईआईएफटी के पूर्व छात्रों को एकजुट करने और आईआईएफटी के वैश्विक पूर्व छात्र जुड़ाव का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। समर्पित कार्यकारी सदस्यों को विशेष सम्मान दिया गया जिनके अथक प्रयासों से यह शुभारंभ संभव हो सका।

पूर्व छात्र समन्वयक और संयुक्त पूर्व छात्र समन्वयक चुनाव

पूर्व छात्र समन्वयक और संयुक्त पूर्व छात्र समन्वयक के चुनाव क्रमशः दिल्ली और कोलकाता परिसरों में सफलतापूर्वक संपन्न हुए। चयन प्रक्रिया में कई उम्मीदवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. इसमें साक्षात्कार की कठिन प्रक्रिया भी शामिल थी।
अंततः, 2024-26 के एमबीए (आईबी) बैच के आदित्य कुमार मिश्रा को दिल्ली परिसर के लिए पूर्व छात्र समन्वयक चुना गया, जबकि 2024-26 के एमबीए (आईबी) बैच के चिरायु श्रीमल्ल को कोलकाता के लिए संयुक्त पूर्व छात्र समन्वयक चुना गया।
दोनों समन्वयक आगामी शैक्षणिक वर्ष में अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे और आईआईएफटी में पूर्व छात्रों की भागीदारी को मज़बूत करने और सामुदायिक संबंधों को गहरा करने का संकल्प लेंगे।

30 वर्षों का पुनर्मिलन: एमपीआईबी बैच 1994

22 दिसंबर 2024 को, दिल्ली परिसर ने एमपीआईबी बैच 1994 के लिए 30-वर्षीय पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया। 30 से अधिक पूर्व छात्रों की उपस्थिति में, इस कार्यक्रम में कुलपति का एक प्रेरक संबोधन, भावपूर्ण भाषण, स्मृति चिन्ह वितरण और दोपहर के शानदार भोजन का आयोजन किया गया, जिसने पुरानी मित्रता को पुनर्जीवित किया एक साथ पूरी की गई एक लंबी यात्रा का जश्न मनाया ।

नेत्रत्व 2025

नेत्रत्व 2025 का आयोजन, 1 मार्च, 2025 को नेतृत्व संबंधी अंतर्दृष्टि और उद्यमशीलता संबंधी चर्चाओं के लिए एक जीवंत मंच के रूप में किया गया। इस पैनल में श्री सौरभ अग्रवाल, श्री मनु बजाज, सुश्री कनुप्रिया सालदी, सुश्री मीनाक्षी कौल और श्री नवीन गुप्ता सहित कई प्रतिष्ठित वक्ता शामिल थे।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ और आईआईएफटी की त्रैमासिक पूर्व छात्र पत्रिका, एलुमिनाती का औपचारिक विमोचन किया गया।

नेत्रत्व, आईआईएफटी समुदाय के भीतर नेतृत्व सहभागिता के एक प्रमुख मंच के रूप में अपनी विरासत को कायम रखे हुए है।

ग्रीष्मकाल की ओर

मार्च 2025 में आयोजित ग्रीष्मकाल की ओर पहल ने आईआईएफटी में पूर्व छात्रों के मार्गदर्शन की अटूट भावना को प्रदर्शित किया। विभिन्न उद्योगों के कई पूर्व छात्र वर्तमान छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए आगे आए और उनकी ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप की तैयारियों में अमूल्य सहायता प्रदान की।

टीएएस, गोदरेज, जेपी मॉर्गन एंड चेज़, फोनपे, ट्राइडेंट, एक्सिस बैंक और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत मार्गदर्शन सत्र, रिज्यूमे समीक्षा और मॉक इंटरव्यू अभ्यास प्रदान किए। इस पहल ने वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों के बीच की कड़ी को मजबूत किया और आईआईएफटी परिवार को वापस देने की स्थायी भावना को प्रतिबिंबित किया।

पूर्व छात्र संबंध समिति (एआरसी) 2024-25 की विदाई

वरिष्ठ पूर्व छात्र संबंध समिति 2024-25 के लिए 21 मार्च 2025 को दिल्ली परिसर में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। पूर्व छात्र मामलों के प्रमुख डॉ. संजय रस्तोगी की उपस्थिति में समिति के वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों को सम्मान चिह्न प्रदान किए गए।

कोलकाता परिसर की गतिविधियाँ

शोध गतिविधियाँ

1) आईआईएफटी कोलकाता के अर्थशास्त्र प्रभाग ने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules Of Origin) पर एक शोध परियोजना पूरी कर ली है।
2) पश्चिम बंगाल सरकार के एमएसएमई विभाग के अंतर्गत चार विभिन्न एमएसएमई क्लस्टरों के मूल्य श्रृंखला मानचित्रण और विश्लेषण पर चार शोध परियोजनाएँ पूरी की गईं। क्लस्टरों के नाम इस प्रकार हैं:
   क. सिंगूर का नकल आभूषण क्लस्टर
   ख. मगरहाट का सिल्वर फिलिग्री क्लस्टर
   ग. जयनगर का मोया क्लस्टर
   घ. चंदननगर का स्वीटमीट क्लस्टर।
3) डीजी शिपिंग, मुंबई के लिए दो शोध परियोजनाएँ पूरी करी ।
   क)"भारतीय घरेलू कानून को शामिल करने के लिए अमेरिका के 2022 के महासागर नौवहन सुधार अधिनियम का अध्ययन"
   ख) शिपिंग लाइनों द्वारा पोत साझाकरण समझौते
4) शेफेक्सिल संस्थान के लिए "बांग्ला पान के लिए जीआई टैग प्राप्त करने पर अध्ययन" नामक एक शोध परियोजना पूरी की।
5) शेफेक्सिल संस्थान के लिए "ग्वार मील पर बाजार पहुंच अध्ययन: चीन को निर्यात" विषय पर एक शोध परियोजना पूरी की।
6) आईआईएफटी, कोलकाता ने 26-27 सितंबर, 2024 के दौरान प्रबंधन डॉक्टरल और शोधकर्ता संगोष्ठी का अपना चौथा संस्करण आयोजित किया।
7) आईआईएफटी – कोलकाता ने 12-13 दिसंबर 2024 को ईआईआईटीएफ सम्मेलन का आयोजन किया।
8) आईआईएफटी-के ने 15-18 जनवरी 2025 के दौरान विश्वव्यापी प्रतिष्ठित INDAM सम्मेलन का आयोजन किया और मेजबानी की।
9) आईआईएफटी कोलकाता ने दामोदर घाटी निगम के लिए "डीवीसी अधिकारियों के लिए प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा और संशोधन" पर एक शोध अध्ययन पूरा किया।

संकाय आउटरीच

1. डॉ. बिबेक राय चौधरी को विद्यासागर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा 21 मार्च, 2024 को एक विशेष व्याख्यान कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था।
2. डॉ. के. रंगराजन को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 22.07.2024 को निर्धारित 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रसद' पर बीजीबीएस सेक्टर समिति की बैठक में सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था।
3. डॉ. के. रंगराजन को 30.07.2024 को कैपेक्सिल द्वारा आयोजित वेबिनार में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसका विषय था "कैपेक्सिल उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण: चुनौतियां, संभावित बाजार और ईएसजी पहल"।
4. 23 अगस्त, 2024 को,पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक व्यापार रणनीति - वीयूसीए पर्यावरण में चुनौतियां विषय पर डॉ. के. रंगराजन को एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
5. डॉ. रंगराजन को 3 और 10 अगस्त, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी - दक्षिण एशिया चैप्टर द्वारा बी-स्कूलों के संकाय के लिए "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रणनीति कैसे सिखाएँ" विषय पर ऑनलाइन सत्र आयोजित करने के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया था।
6. डॉ. रंगराजन को 19.08.2024 को उन्नत शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के 2024 बैच के अभिविन्यास कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
7. डॉ. रंगराजन को सीआईआई द्वारा 20.08.2024 को पूर्वी क्षेत्र से निर्यात: क्षमता और रणनीति पर आयोजित एक्जिम सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
8. डॉ. सैकत बनर्जी को एआईएमए, एआईएम और एआईएमएस के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कोलकाता (स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कोलकाता, भारत) के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा 13 सितंबर, 2024 को डॉक्टरल रिसर्च कॉलोक्वियम (डीआरसी-2024) के रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया गया था।
9. डॉ. दीपांकर सिन्हा को 22 अक्टूबर, 2024 को सदस्यों और उद्योग नेतृत्व को व्यापक आर्थिक अवलोकन प्रदान करने के लिए सीआईआई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
10. डॉ. रंगराजन को आईएफएससीए, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर के सहयोग से एफपीएसबी इंडिया कॉन्क्लेव के लिए मॉडरेटर के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसका शीर्षक 'इंडिया फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्क्लेव 2024' था, जो शुक्रवार, 4 अक्टूबर, 2024 को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में आयोजित किया गया था।

11. डॉ. रंगराजन को दिनांक 25.10.24 को भारतीय फाउंड्रीमैन संस्थान में राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन केंद्र के उद्घाटन के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
12. डॉ. ओइंद्रिला डे को आईआईएम कोलकाता द्वारा 28.11.24 को समकालीन शोध मुद्दों पर एक विशेष व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था।

13. डॉ. देबाशीष चक्रवर्ती और डॉ. रणजॉय भट्टाचार्य को हेरिटेज कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 28 नवंबर, 2024 को आयोजित "ओपन इकोनॉमी मैक्रोइकॉनॉमिक्स: थ्योरी से प्रैक्सिस तक" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
14. डॉ. पी.के.दास को आईआईएम (रायपुर) इंडिया फाइनेंस कॉन्फ्रेंस 2024 में 16.12.24 को सत्रों की अध्यक्षता करने के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया था।
15. डॉ. के. रंगराजन को 27 फरवरी, 2025 को FIEO निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार के 9वें और 10वें सेट में जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया।
16. डॉ. रंगराजन को दिनांक 05.02.2025 को बैंक ऑफ इंडिया, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, कोलकाता के स्थापना दिवस समारोह में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा "उत्कृष्टता के स्तर पर एक प्रशिक्षण केंद्र विकसित करना" विषय पर बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

एक्ससेल - निर्यात सुविधा केंद्र (पूर्व में CeNest)

1. आईआईएफटी, कोलकाता ने छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से छत्तीसगढ़ में एक ईएफसी की स्थापना की।
2. एसईएफसी, पश्चिम बंगाल ने उद्यमियों तक व्यापक पहुंच और कवरेज के लिए जिलावार एमएफसी और उत्पाद विशिष्ट ईएफसी को एसईएफसी के साथ एकीकृत किया है।
3. निर्यात सहायता प्रकोष्ठ ने असम के पांच चयनित उत्पादों - मुगा सिल्क, किंग मिर्च, असम नींबू, चाय और अगरवुड के मूल्य श्रृंखला मानचित्रण विश्लेषण और निर्यात संभावनाओं का संचालन किया।
4. ईएसी असम ने असम के उद्यमियों और डीआईसीसी अधिकारियों के लिए निर्यात पर ज्ञान सत्र और प्रश्न समाधान सत्र के साथ आठ निर्यात शिविरों की एक श्रृंखला आयोजित की।
5. राज्य निर्यात सुविधा केंद्र, पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल में परिधान-टेक्सटाइल पार्क और अंकुरहाटी रत्न एवं आभूषण पार्क में उत्पाद विशिष्ट ईएफसी विकसित किए।
6. एक्ससेल के अंतर्गत एक ईएफसी, एसईएफसी पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में 11 विभिन्न तालमेल शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में जिलों के लगभग 235 उद्यमियों को लाभ पहुँचाया गया।
7. एसईएफसी पश्चिम बंगाल ने उद्यमियों को निर्यात के प्रति प्रेरित करने के लिए डीआईसी कार्यालयों, क्लस्टरों और उद्योग संघों में लगभग दस निर्यात जागरूकता अभियान चलाए। एसईएफसी, पश्चिम बंगाल द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित ऑनलाइन निर्यात क्लिनिक, राज्य के हर कोने तक डिजिटल रूप से पहुँचने में मदद करता है। इस ऑनलाइन निर्यात क्लिनिक ने अब तक विभिन्न जिलों के लगभग 350 उद्यमियों को सुविधा और मार्गदर्शन प्रदान किया है।
8. एक्ससेल को सिक्किम सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से कार्य आदेश प्राप्त हुआ और उसने सिक्किम में एक निर्यात सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की।
9. ईएसी सिक्किम ने 18.02.25 को गंगटोक में 45 प्रतिभागियों के लिए निर्यात प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण पर एक दिवसीय बूटस्ट्रैप कार्यक्रम आयोजित किया।

व्यापार सुविधा और रसद केंद्र

1. व्यापार सुविधा एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र, सीटीएफएल, आईआईएफटी ने गुजरात में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास के लिए गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, जीआईडीबी, अहमदाबाद के साथ परिचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. व्यापार सुविधा एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र, सीटीएफएल, व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों के अध्ययन और सुझावों के लिए फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संबद्ध है।
3. व्यापार सुविधा एवं रसद केंद्र, सीटीएफएल, भारतीय बंदरगाहों में खाद्यान्नों के संचालन में बंदरगाह अवसंरचना और नियामक सुधारों के आकलन के लिए विकासशील देशों के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था एवं संपर्क अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली केंद्र के साथ संबद्ध है।

4. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), कोलकाता को सीटीएफएल के माध्यम से निष्पादित आरएफपी में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामलों पर शिपिंग महानिदेशालय (डीजीएस) को संस्थागत समर्थन देने के लिए चुना गया है।
5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की उत्पाद और प्रक्रिया दक्षता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता के लिए मापन और बेंचमार्किंग

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

1. आईआईएफटी कोलकाता ने 6 से 7 मई 2024 तक दामोदर घाटी निगम के लिए सीएसआर प्रभाव बढ़ाने पर डीवीसी के सीएसआर अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया।
2. 04–05.06.2024 को ग्राहक केंद्रितता बढ़ाने पर डीवीसी अधिकारियों के लिए 2-दिवसीय एमडीपी का आयोजन किया गया
3. आईआईएफटी कोलकाता ने 6 से 10 मई 2024 तक अरुणाचल प्रदेश के संभावित निर्यातकों के लिए 5 दिवसीय हैंड होल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
4. 20 जुलाई 2024 को सीआईआई के लिए "निर्यात व्यवसाय के लिए एमएसएमई की तैयारी" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
5. आईआईएफटी कोलकाता ने जनवरी-फरवरी, 2025 के दौरान डीवीसी अधिकारियों के 4 बैचों के लिए 'योग्यता संवर्धन' पर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
6. 17-21 मार्च, 2025 के दौरान व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के संभावित उद्यमियों के लिए 5 दिवसीय निर्यात संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
7. 24 से 26 मार्च 2025 के दौरान नागालैंड सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के लिए निर्यात संवर्धन पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

छात्र गतिविधियाँ

1. आईआईएफटी, कोलकाता ने 18 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक आईआईएफटी कोलकाता के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन विवान 10.0 का आयोजन किया, जिसका विषय था "अशांत समय में नेतृत्व"
2. "नेट ज़ीरो" पर भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, मिशन लाइफ यूनिट के अनुरूप छात्रों की भागीदारी से स्थिरता क्लब का गठन किया गया है।

काकीनाडा परिसर

आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश) भारत के शीर्ष पाँच निर्यातक राज्यों में से एक है, जहाँ समुद्री उत्पादों, कृषि और वस्त्र उद्योग में उत्कृष्टता प्राप्त है। तटीय शहर काकीनाडा अपने रणनीतिक स्थान और अप्रयुक्त प्रतिभा के कारण एक व्यापार केंद्र बनने की क्षमता रखता है। आंध्र प्रदेश औद्योगिक और विदेशी निवेश में अग्रणी है। सरकार अनुसंधान एवं विकास पर ज़ोर देती है और विकास के लिए IIFT जैसे संस्थानों से योगदान की अपेक्षा करती है।
आईपीएम (बीबीए + एमबीए - 2024-29) के तीसरे बैच के लिए क्रमशः 6 सितंबर, 2024 को उद्घाटन और अभिविन्यास कार्यक्रम तथा 13 सितंबर, 2024 को अभिविन्यास कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया है।

आईपीएम 2024 बैच के उद्घाटन ने आईआईएफटी काकीनाडा के लिए एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत की। यह कार्यक्रम आशावाद से भरा था, जिसने शिक्षा, विकास और उपलब्धियों से भरे एक नए वर्ष की नींव रखी। छात्र और संकाय सदस्य नए बैच का स्वागत करने के लिए एक साथ आए, जिससे शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता और भी पुष्ट हुई।

अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और नेटवर्किंग अवसरों के लिए प्रसिद्ध भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) काकीनाडा ने आईपीएम 2024-29 बैच के लिए 13 सितंबर, 2024 को एक प्रेरणादायक समापन समारोह के साथ ओरिएंटेशन सप्ताह का समापन किया।

निम्नलिखित अतिथियों/पूर्व छात्रों ने ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन और समापन समारोह में भाग लिया और छात्रों को आशावादी, आत्मविश्वासी और दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अनुकरणीय प्रबंधक और पूर्ण विकसित व्यक्ति बनने की दिशा में काम करते हैं:

1. श्री सत्यकी मश्चरक, प्रबंधक क्षमता निर्माण, WWCS, अमेज़न में सिंगल थ्रेडेड लीडर;
2. प्रो. राकेश मोहन जोश, कुलपति, IIFT-दिल्ली;
3. प्रो. केवीएसजी मुरली कृष्ण, कुलपति, जेएनटीयू-काकीनाडा;
4. श्री रत्नेश कुमार, कार्यकारी निदेशक और परिसंपत्ति प्रबंधक, ONGC, काकीनाडा;
5. श्री राजेंद्र राव जुव्वाडी, ऑरोरे लाइफ साइंसेज के सीईओ और IIFT के पूर्व छात्र।

ओरिएंटेशन सप्ताह ने आईपीएम 2024-29 बैच के लिए एक आशाजनक यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने आईआईएफटी काकीनाडा में अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास के लिए उच्च मानक स्थापित किए।

काकीनाडा परिसर की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

(i) ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)

आईआईएफटी-काकीनाडा में "18 से 22 नवंबर, 2024 के दौरान उन्नत समय श्रृंखला विश्लेषण" विषय पर एक ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) का आयोजन किया गया, जिसका समन्वयन सहायक प्राध्यापक डॉ. मिक्लेश प्रसाद यादव, डॉ. सौरव दाश और डॉ. रश्मि रस्तोगी ने किया।

41 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और कार्यक्रम में भाग लिया। यह एफडीपी अत्यधिक प्रयोगात्मक और संवादात्मक है जिसमें व्याख्यान, चर्चाएँ और आर स्टूडियो व अन्य सॉफ़्टवेयर के उपयोग के साथ व्यावहारिक सत्र शामिल हैं। इसने प्रतिभागियों को विभिन्न मॉडलों जैसे कि यूनीवेरिएट टाइम सीरीज़ मॉडल, ARCH-GARCH, टाइम सीरीज़ रिग्रेशन, कोइंटीग्रेशन और वेक्टर-ऑटो रिग्रेशन का उपयोग करके टाइम सीरीज़ डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम बनाया है।

(ii) संस्थान नवाचार परिषद (आईआईसी)

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के नवाचार प्रकोष्ठ (एमआईसी) ने वर्ष 2018 में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के लिए एआईसीटीई के सहयोग से संस्थान नवाचार परिषद (आईआईसी) कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में नवाचार और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देना है। आईआईसी की भूमिका बड़ी संख्या में संकाय सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों को विभिन्न नवाचार और उद्यमिता संबंधी गतिविधियों जैसे विचार, समस्या समाधान, डिजाइन थिंकिंग, आईपीआर, परियोजना संचालन और प्री-इन्क्यूबेशन/इन्क्यूबेशन चरण में प्रबंधन आदि में शामिल करना है, ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित और स्थिर हो सकें।

आईआईएफटी-काकीनाडा में अप्रैल, 2024 में संस्थान नवाचार परिषद (आईआईसी) का गठन किया गया और संकाय एवं छात्रों के लाभ के लिए नवाचार, इंटर्नशिप, आईपीआर, स्टार्टअप, एनआईआरएफ, सोशल मीडिया, एआरआईआईए, स्टार्टअप/पूर्व छात्र उद्यमी और इनक्यूबेशन केंद्र जैसी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(क) एनैक्टस प्रतियोगिता

एनैक्टस के सहयोग से आईआईएफटी-काकीनाडा की इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) । एनैक्टस एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जो जरूरतमंद लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उद्यमशीलता की गतिविधियों का उपयोग करता है और छात्रों, शैक्षणिक और व्यावसायिक नेताओं के एक वैश्विक नेटवर्क को बढ़ावा देता है। इसे पहले SIFE (स्टूडेंट्स इन फ्री एंटरप्राइज) के नाम से जाना जाता था।

आईआईएफटी-काकीनाडा ने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने हेतु नवीन विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 06.12.2024 को एक व्यवसाय योजना (बी-प्लान) प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई और यह ग्रामीण चुनौतियों से निपटने के लिए छात्रों को रचनात्मक और प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत करने का एक मंच है।

बी-प्लान प्रतियोगिता ने छात्रों को ग्रामीण समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए समस्या-समाधान और उद्यमशीलता की सोच में संलग्न होने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया। इस आयोजन ने नवोन्मेषी और सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार नेताओं को विकसित करने के लिए आईआईएफटी काकीनाडा की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया।

(ख) आईआईएफटी, काकीनाडा की इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) ने 08.12.2024 को "एक सफल व्यवसाय योजना कैसे बनाएँ" विषय पर एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

यह एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम था जिसमें छात्रों को एक प्रभावी और व्यवहार्य व्यवसाय योजना बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। यह सत्र आकर्षक, प्रेरणादायक और हमारे युवा नवप्रवर्तकों को ऊँचे लक्ष्य और बड़ी सोच के लिए प्रोत्साहित करने वाला रहा।

श्री अरुण पंडित को एक रोचक और ज्ञानवर्धक सत्र के लिए आमंत्रित किया गया है। वे हाइफ़न एससीएस और डोंट गिव अप के संस्थापक, एआईएमए वाईएलसी के उपाध्यक्ष, वाईएस टेक30, डी एंड बी एसटी, व्हार्टन आईएससी, टीजीएस100, गिनीज, डब्ल्यूआर फेलो: सीएससी2023, ओडीएक्स, एमसीआईएल, फिक्की, एसोचैम, एआईटीडब्ल्यूए, डब्ल्यूएआई, एडीआईएफ, टीआईई और पूर्व छात्र: आईआईएफटी, जीजेडएससीईटी और एसएसएसटीएच के विजेता हैं।

उनकी अविश्वसनीय उद्यमशील यात्रा से प्राप्त उनके विशेषज्ञ मार्गदर्शन ने हमारे छात्रों को प्रभावशाली पिच डेक तैयार करने के लिए अमूल्य ज्ञान और आत्मविश्वास से सुसज्जित किया है।

(ग) व्यवसाय में एआई की भूमिका पर कार्यशाला:

आईआईएफटी, काकीनाडा की इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) ने 28.03.2025 को आईपीएम कार्यक्रम के छात्रों के लिए प्रसिद्ध एआई विशेषज्ञ, उद्यमी और स्टार्टअप मेंटर श्री अभिजीत मजूमदार द्वारा एक विशेष कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह ज्ञानवर्धक सत्र व्यावसायिक विचार-मंथन, बाजार सत्यापन और रणनीतिक विस्तार में एआई की भूमिका पर गहन चर्चा करेगा, जिससे महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सफलता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सशक्त बनाया जा सकेगा।

(घ) विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस पर निबंध लेखन प्रतियोगिता:

विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस के अवसर पर, आईआईसी ने छात्रों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। "रचनात्मक चिंगारी: शब्दों के माध्यम से नवाचार का प्रसार" शीर्षक से यह कार्यक्रम 21.04.2025 को आयोजित किया गया और इसमें छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

(ड़) TEDx IIFT काकीनाडा:

4 मई, 2025 को प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उद्यमिता पर एक संगोष्ठी। इसका उद्देश्य युवा व्यावसायिक नेताओं को एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना था।

कॉर्पोरेट संबंध और प्लेसमेंट प्रभाग (सीआरपीडी), आईआईएफटी काकीनाडा ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कई गतिविधियाँ आयोजित की।

सीआरपीडी ने नवंबर, 2024 के महीने में निम्नलिखित 3 वक्ता सत्र आयोजित किए:

1. 06.11.2024 को UX और यह कैसे विकास और ग्राहक गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, पर सुश्री मधुमिता गुप्ता द्वारा एक सत्र आयोजित किया गया। सुश्री मधुमिता गुप्ता उपयोगकर्ता अनुभव (UX) और उत्पाद डिज़ाइन की विशेषज्ञ हैं।

2. श्री राघवन पिचुमानी द्वारा 13.11.2024 को "स्टार्टअप की यात्रा: विचार से क्रियान्वयन तक" विषय पर एक उद्यमिता सत्र आयोजित किया गया। वे आयुष के संस्थापक और सीईओ हैं और उद्यमिता एवं वित्तीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उद्योग जगत का अनुभव रखते हैं।

3. 25.11.2024 को श्री कौस्तव सिल द्वारा 'भविष्य के लिए वित्त में करियर' पर एक सत्र। वे वर्तमान में रीटर में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और नवाचार एवं परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हुए व्यावसायिक विकास के अनुरूप वित्तीय रणनीतियाँ बनाते हैं।

सीआरपीडी ने श्री राघवन पिचुमानी द्वारा अपनी कंपनी आयुष में मार्केटिंग भूमिकाओं के लिए और श्री कौस्तव सिल द्वारा प्रदान किए गए इंटर्नशिप अवसर की जानकारी प्रसारित की। रीटर में वित्त और मानव संसाधन के क्षेत्र में इंटर्नशिप के दो अवसर हैं।

पूर्व छात्र संबंध समिति (एआरसी) और सीआरपीडी ने 17.02.2025 को संयुक्त रूप से एलिवेटएक्स के सहयोग से शैक्षणिक शिक्षा को आवश्यक व्यावसायिक कौशल के साथ जोड़ने के उद्देश्य से एक इंटरैक्टिव उद्योग कार्यशाला का आयोजन किया।

एलिवेटएक्स एक व्यावहारिक, इंटरैक्टिव कार्यशाला है जिसे उद्योग ज्ञान के साथ आवश्यक व्यावसायिक कौशल को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत में कार्यरत लोगों समेत चार प्रतिष्ठित वक्ता शामिल होंगे, जो छात्रों को केस-आधारित शिक्षण के माध्यम से मार्गदर्शन देंगे और विशेषज्ञ प्रशिक्षक कौशल-निर्माण सत्रों का नेतृत्व करेंगे।
इस प्रतिष्ठित कार्यशाला में, प्रबंधन परामर्श, विपणन, बिक्री और वित्त क्षेत्र के निम्नलिखित चार प्रतिष्ठित उद्योग नेताओं ने कैरियर विकास, उद्योग के रुझान और आवश्यक पेशेवर कौशल पर अपनी विशेषज्ञता साझा की।

1. श्री अभिषेक गुप्ता, जेबपे, मुंबई, महाराष्ट्र में मानव संसाधन प्रमुख
2. श्री अंकुर हांडा, यूटीआई म्यूचुअल फंड में वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 और क्षेत्रीय प्रमुख, बैंकिंग और राष्ट्रीय वितरण
3. श्री संजय गोपीनाथ, मैथवर्क्स, बैंगलोर, कर्नाटक में मार्किंग और संचार प्रमुख
4. श्री रोहित गर्ग, प्रबंधक, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, नई दिल्ली

इंटरैक्टिव चर्चाओं, केस स्टडीज़ और नेटवर्किंग के अवसरों के माध्यम से, छात्रों को कक्षा से परे व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। "एलिवेटएक्स एक मूल्यवान मंच है जो शिक्षा और उद्योग जगत को जोड़ता है, और छात्रों को वास्तविक दुनिया के कौशल से लैस करता है।

महत्वपूर्ण बैठकें

वर्ष के दौरान, प्रबंधन बोर्ड की चार बैठकें 28 मई 2024, 18 जून 2024, 30 सितंबर 2024 और 18 मार्च 2025 को आयोजित की गईं: वित्त समिति की दो बैठकें 2 जुलाई 2024 और 19 सितंबर 2024 को आयोजित की गईं।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण

प्रबंधन में स्नातकोत्तर अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग, आईआईएफटी के प्रमुख कार्यक्रम, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए, के अलावा, व्यावसायिक विश्लेषण में एमबीए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सप्ताहांत एमबीए का संचालन करता है। जीएसएम का उद्देश्य आईआईएफटी के कार्यक्रमों के संचालन की निगरानी करते हुए उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता और समसामयिकता सुनिश्चित करना है। जीएसएम प्रभाग कार्यक्रम प्रबंधन, पाठ्यक्रम निर्धारण, सत्र नियोजन, संकाय आवंटन, परीक्षाओं का संचालन, शोध-प्रबंध परियोजनाओं, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों और छात्रों की गैर-शैक्षणिक गतिविधियों एवं मौखिक परीक्षाओं पर भी कार्य करता है। छात्र संबंध और अनुशासन सहित सभी छात्र मामले, जीएसएम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जीएसएम बंदरगाह भ्रमण, औद्योगिक भ्रमण, अतिथि व्याख्यान, कार्यशालाएँ, सेमिनार और छात्र विनिमय कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:

(i) दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए (आईबी) 2024-26 और एमबीए (बीए) 2024-26 कार्यक्रम

एमबीए (आईबी) 2024-26 के 59वें बैच और एमबीए (बीए) 2024-26 के दूसरे बैच का पंजीकरण और उद्घाटन 16 जुलाई 2024 को हुआ। मुख्य अतिथि श्री सुनील बर्थवाल, वाणिज्य सचिव और आईआईएफटी के कुलाधिपति ने व्यवसाय में नवाचार और नैतिकता पर प्रकाश डाला। कुलपति प्रो. राकेश मोहन जोशी ने कड़ी मेहनत और समकालीन कौशल पर जोर दिया, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व स्तरीय उत्कृष्टता के लिए आईआईएफटी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉ. शीबा कपिल, प्रमुख, जीएसएम प्रभाग, दिल्ली ने नए बैच का स्वागत किया और उन्हें अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रो. जयंत कुमार सील, प्रमुख, जीएसएम प्रभाग, कोलकाता ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

एमबीए (आईबी) 2024-26 कार्यक्रम के लिए 211 छात्रों ने पंजीकरण कराया और एमबीए (बीए) 2024-26 कार्यक्रम के लिए 46 छात्रों ने पंजीकरण कराया।

(ii) ढाई वर्षीय एमबीए (आईबी) 2024-27 - सप्ताहांत कार्यक्रम

ढाई वर्षीय एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) 2024-27 - सप्ताहांत का 25वाँ बैच, 5 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ। निबंध लेखन के आधार पर अट्ठाईस छात्रों को इस कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया और भौतिक रूप से एक्सटेम्पोर और व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किए गए। स्नातक अध्ययन प्रबंधन प्रभाग की प्रमुख डॉ. शीबा कपिल ने उद्घाटन भाषण दिया। उद्घाटन कार्यक्रम में आईआईएफटी के संकाय, छात्र और कर्मचारी उपस्थित थे।

सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

2005 में स्थापित सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थान के एमबीए (आईबी) पूर्णकालिक कार्यक्रम के छात्रों को सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों से परिचित कराना और समाज के वंचित वर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना है। चूँकि कॉर्पोरेट क्षेत्र कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के नियामक प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व रखता है, इसलिए वे इस कार्यक्रम के तहत हमारे छात्रों को दिए जाने वाले अनुभव को महत्व देते हैं।

पाठ्यक्रम में इस कार्यक्रम के महत्व पर ज़ोर देने के लिए, 3 क्रेडिट का भारांक निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को गैर-सरकारी संगठनों/कॉर्पोरेट घरानों द्वारा सौंपे गए एक वास्तविक जीवन के प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, जिसके लिए बाद में उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक 3,500 से ज़्यादा छात्र इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें छात्रों को संबंधित एनजीओ/संगठन द्वारा सौंपे गए एक लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है। हमारे छात्र जिन प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं, उनमें पर्यावरण एवं सामुदायिक विकास, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण, साक्षरता, स्वच्छता, एचआईवी/एड्स जागरूकता, बच्चों की शिक्षा, वंचित वृद्धजनों का कल्याण, स्वास्थ्य, बेघरों के लिए आश्रय, सामुदायिक विकास, विकलांगता, महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, शिशु दत्तकग्रहण आदि शामिल हैं।

इस वर्ष, एमबीए (आईबी) और एमबीए (बीए) 2024-26 कार्यक्रमों के छात्रों को दिल्ली परिसर में लगभग 18 गैर-सरकारी संगठनों में भौतिक रूप से प्रतिनियुक्त किया गया। आईआईएफटी अपने पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध है।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

2024-25 के दौरान, IIFT दिल्ली के MDP प्रभाग ने विभिन्न स्तरों के प्रबंधकों और कार्यपालकों के लिए 14 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें से दो कार्यक्रम सभी क्षेत्रों के लिए खुले ऑन-कैंपस कार्यक्रम थे, और 12 सरकारी अधिकारियों (ITS परिवीक्षाधीनों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों सहित) और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यपालकों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम थे। इन कार्यक्रमों से कुल 397 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

श्रेणीवार कार्यक्रम विवरण

कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
प्रायोजित	12	318
ऑन-कैंपस सर्टिफिकेट प्रोग्राम	02	79
कुल	14	397

(I).प्रायोजित कार्यक्रम

1. आईटीएस परिवीक्षार्थियों के लिए "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय" पर ग्यारह महीने का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (फरवरी 2024 से जनवरी 2025)

आईटीएस परिवीक्षार्थियों के लिए फरवरी 2024 से जनवरी 2025 तक चलने वाला"अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय" पर ग्यारह महीने का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, अपने प्रतिभागियों की पेशेवर यात्रा में एक आधारशिला की तरह है। प्रतिष्ठित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), दिल्ली द्वारा आयोजित और निपुण डॉ. चारु ग्रोवर द्वारा निर्देशित, इस कार्यक्रम ने तीन प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें एक गहन शिक्षण अनुभव प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय में भावी नेतृत्वकर्ताओं के विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम को वैश्विक व्यापार नीतियों और वार्ताओं से लेकर बाजार विश्लेषण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तक, विभिन्न विषयों को शामिल करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। सैद्धांतिक व्याख्यानों, व्यावहारिक कार्यशालाओं और वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज़ के माध्यम से,

प्रतिभागियों को वैश्विक बाज़ार की जटिलताओं को कुशलता से समझने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया गया। डॉ. ग्रोवर के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में, उन्होंने अपनी विश्लेषणात्मक कुशाग्रता को निखारा और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता की गहरी समझ विकसित की। जैसे-जैसे कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ा, यह अपने प्रतिभागियों पर एक अमिट छाप छोड़ता रहा, तथा उन्हें निरंतर विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय परिदृश्य में कुशल और दूरदर्शी नेताओं के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनने में योगदान देता गया ।

2. टीवीएस मोटर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्कृष्टता में ग्यारह महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम (जनवरी से दिसंबर 2024)

टीवीएस मोटर्स के लिए जनवरी से दिसंबर 2024 तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्कृष्टता पर ग्यारह महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिष्ठित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) दिल्ली द्वारा आयोजित और डॉ प्रीति टाक द्वारा निर्देशित है। टीवीएस मोटर्स में कार्यरत अधिकारियों के ज्ञान को उन्नत करने और उनकी परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्कृष्टता में एक प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं का गहन ज्ञान महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा निर्यात विपणन गतिविधियों में लगे अधिकारियों के लिए चुनौतियां

पैदा करती है। जब तक वे खुद को नए विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं में तेजी से बदलाव और प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई गई नवीन विपणन रणनीतियों से अवगत नहीं रखते, निर्यात अधिकारी उपलब्ध या उभरते बाजार के अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ नहीं उठा सकते।

3. सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन में 6 माह/24 सप्ताह का पाठ्यक्रम, डीजीआर द्वारा प्रायोजित (बैच 15) (12 फ़रवरी से 29 जुलाई 2024)

सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार और पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा प्रायोजित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन में 6 माह/24 सप्ताह का पाठ्यक्रम, पेशेवर विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। प्रतिष्ठित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) दिल्ली द्वारा आयोजित और प्रतिष्ठित डॉ. आंचल अरोड़ा द्वारा निर्देशित, बैच 15 ने 12 फ़रवरी से 29 जुलाई 2024 तक एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। 50 प्रतिभागियों की उपस्थिति के साथ, इस कार्यक्रम को सैन्य अधिकारियों को वैश्विक वाणिज्य में निहित बारीकियों और जटिलताओं की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। प्रतिभागियों ने सैद्धांतिक ढाँचों, केस स्टडीज़ और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के एक सुव्यवस्थित मिश्रण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों, बाज़ार विश्लेषण और रणनीतिक निर्णय लेने के विषयों का गहन अध्ययन किया।

4. सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रबंधन में 6 महीने/24 सप्ताह का पाठ्यक्रम, डीजीआर द्वारा प्रायोजित (बैच 16) (11 मार्च से सितंबर 2024)

सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार और पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा प्रायोजित 6 महीने/24 सप्ताह का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रबंधन पाठ्यक्रम पेशेवर उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिष्ठित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) दिल्ली द्वारा आयोजित और सम्मानित डॉ सुगंधा हुरिया द्वारा निर्देशित यह कार्यक्रम 11 मार्च से सितंबर 2024 तक चला, जिसमें 34 समर्पित प्रतिभागियों ने भाग लिया। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रबंधन की पेचीदगियों को समझने के लिए सैन्य अधिकारियों को आवश्यक कौशल और रणनीतियों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पाठ्यक्रम में खरीद और सूची प्रबंधन से लेकर परिवहन रसद और वितरण रणनीतियों तक के विषयों पर चर्चा की गई। सैद्धांतिक व्याख्यानों, व्यावहारिक अभ्यासों और उद्योग केस स्टडी के माध्यम से, प्रतिभागियों ने आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को अनुकूलित करने, जोखिमों को कम करने और विविध हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की। बैच 16 के समापन के साथ ही, यह पाठ्यक्रम एक स्थायी विरासत छोड़ता है, जो सशस्त्र बलों के अधिकारियों के एक ऐसे समूह को आकार देता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रबंधन में कुशल नेताओं के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

5. सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन (मानव संसाधन और वित्त) में 6 महीने/24 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स (बैच 17) (12 अगस्त 2024 से 24 जनवरी 2025)

सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन (मानव संसाधन एवं वित्त) में 6 महीने/24 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स, बैच 17, 12 अगस्त 2024 से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया और उल्लेखनीय रुचि दिखाई। कार्यक्रम निदेशक डॉ. प्रियंका जायसवाल थीं। सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव संसाधन और वित्त में उनके प्रबंधकीय कौशल को बढ़ाना था, जो उनकी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों के नेतृत्व में, इस पाठ्यक्रम में रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय विश्लेषण, बजट और संगठनात्मक नेतृत्व सहित विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान किया गया। व्याख्यानों, केस स्टडी और व्यावहारिक अभ्यासों के संयोजन के माध्यम से, प्रतिभागियों ने आधुनिक व्यवसाय प्रबंधन की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से समझने के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक कौशल प्राप्त

किए। इस कार्यक्रम ने उनकी व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाया और प्रतिभागियों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और नेटवर्किंग के लिए अनुकूल एवं सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया। बैच 17 के समापन पर, अधिकारी उन्नत क्षमताओं से सुसज्जित होकर सशस्त्र बलों के भीतर और बाहर महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हुए।

6. आईईएस के अधिकारियों के लिए विश्व व्यापार संगठन और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (27-31 मई 2024)

भारतीय आर्थिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए 27-31 मई 2024 तक आयोजित विश्व व्यापार संगठन और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ने 17 प्रतिभागियों के लिए वैश्विक व्यापार नियमों और बौद्धिक संपदा अधिकारों की बारीकियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। डॉ. विजया कट्टी के विशेषज्ञ निर्देशन में, इस कार्यक्रम ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के ढाँचे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके प्रभावों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान किया, साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और तंत्रों का गहन अन्वेषण भी किया। व्याख्यानों, केस स्टडी और संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से, प्रतिभागियों ने व्यापार नीतियों को आकार देने में विश्व व्यापार संगठन समझौतों की भूमिका और नवाचार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की। डॉ. कट्टी के मार्गदर्शन और विशेषज्ञता ने एक गतिशील शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया, जिससे प्रतिभागियों को इन जटिल मुद्दों के बारे में अपनी समझ को गहरा करने में मदद मिली और उन्हें वैश्विक व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकारों के उभरते परिदृश्य को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया गया।

7. सोनालीका ट्रैक्टर्स के अधिकारियों के लिए गैर-वित्त अधिकारियों हेतु वित्त पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (26-27 जुलाई 2024)

सोनालीका ट्रैक्टर्स के अधिकारियों के लिए 26-27 जुलाई 2024 तक वित्त पर, गैर-वित्त अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसका नेतृत्व डॉ. जैकलीन सिम्स ने किया। इसका उद्देश्य गैर-वित्त पेशेवरों को प्रमुख वित्तीय अवधारणाओं की स्पष्ट समझ प्रदान करना था। इन सत्रों में एक पूर्व-मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी, वित्त और वित्तीय विवरणों की मूल बातें, वित्तीय अनुपात और विश्लेषण, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, मुद्रा जोखिम प्रबंधन, और निर्यात वित्त एवं वित्तपोषण विकल्पों का परिचय शामिल था। प्रशिक्षण में निर्यात रणनीति के साथ वित्त को एकीकृत करने पर भी ज़ोर दिया गया और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और व्याख्या पर एक व्यावहारिक सत्र भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन-पश्चात प्रश्नोत्तरी के साथ हुआ।

8. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) के लिए 6-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (20 अगस्त से 25 सितंबर 2024)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) के लिए 12-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 अगस्त को शुरू हुआ। यह 25 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ, जिसने 30 प्रतिभागियों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा को चिह्नित किया। कार्यक्रम निदेशक डॉ. विजया कट्टी थीं। उनके प्रशासनिक कौशल को निखारने और सरकारी प्रक्रियाओं की उनकी समझ को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए इस कार्यक्रम में लोक प्रशासन, नीति विश्लेषण, कानूनी ढाँचे और संचार रणनीतियों सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। अनुभवी प्रशिक्षकों और विषय विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों ने सहायक अनुभाग अधिकारियों को प्रभावी शासन के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक अभ्यास प्रदान किए। इंटरैक्टिव चर्चाओं, केस स्टडी और सिमुलेशन के माध्यम से, प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से सीखने में भाग लिया, अपनी समझ को गहरा करने के लिए अनुभवों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान किया। जैसे-जैसे कार्यक्रम समाप्त होने के करीब आया, एएसओ बढ़ी हुई क्षमताओं और उद्देश्य की नई भावना के साथ उभरे, जो शासन में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मिशन में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए तैयार थे।

9. एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, देश व्यापार: भारतीय डाक सेवाओं के लिए ब्रांडिंग और विपणन (4 सितंबर 2024)

विदेश व्यापार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: भारतीय डाक सेवाओं के लिए ब्रांडिंग और विपणन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया। डॉ. रोहित मेहतानी द्वारा निर्देशित इस कार्यक्रम में कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य विदेशी व्यापार और उसके विपणन पहलुओं की समझ को बढ़ाना था। इन सत्रों में भारत में विदेशी व्यापार प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा की गई और ई-कॉमर्स पर केंद्रित देश की विदेश व्यापार नीति की जानकारी प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विपणन रणनीतियों के साथ-साथ प्रमुख विपणन सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में ब्रांडिंग अवधारणाओं का भी परिचय दिया गया और वैश्विक बाजारों में ब्रांड निर्माण और प्रचार के तरीकों पर चर्चा की गई। कुल मिलाकर, प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को भारतीय डाक के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई-कॉमर्स जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करना था।

10. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के अधिकारियों के लिए "निर्यात आयात प्रबंधन" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (18-20 दिसंबर 2024)

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के अधिकारियों के लिए 18-20 दिसंबर 2024 तक "निर्यात-आयात प्रबंधन" पर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 प्रतिभागियों का एक केंद्रित समूह शामिल हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए उत्सुक था। कार्यक्रम के निदेशक डॉ. रोहित मेहतानी थे। जहाज निर्माण उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए इस कार्यक्रम में निर्यात-आयात प्रबंधन के आवश्यक पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उद्योग के दिग्गजों और अकादमिक विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों में व्यापार नियमों, रसद, दस्तावेज़ीकरण, जोखिम प्रबंधन और बाजार विश्लेषण पर गहन चर्चा की गई। व्याख्यानों,

केस स्टडी और इंटरैक्टिव कार्यशालाओं के माध्यम से, प्रतिभागियों ने वैश्विक व्यापार गतिशीलता की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और रणनीतिक दृष्टिकोण प्राप्त किए। कार्यक्रम के अंतरंग परिवेश ने प्रतिभागियों के बीच गहन चर्चा और ज्ञान साझा करने में मदद की, जिससे उनकी समझ बढ़ी और एक सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम के समापन पर, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में प्रभावी योगदान देने के लिए तैयार, प्रतिभागी, कौशल और एक नए दृष्टिकोण के साथ रवाना हुए।

11. ईसीजीसी के कार्यालयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (6-8 फरवरी 2025)

ईसीजीसी के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 6-8 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का निर्देशन डॉ. विजया कट्टी ने किया और इसका उद्देश्य प्रतिभागियों की वैश्विक व्यापार और वार्ता रणनीतियों के प्रमुख पहलुओं की समझ को बढ़ाना था। सत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भविष्य के रुझानों, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), व्यापार दस्तावेजीकरण और शिपिंग लॉजिस्टिक्स शामिल थे। अन्य विषयों में व्यावसायिक संचार, व्यापार वित्त, भारत की विदेश व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम प्रबंधन शामिल थे। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लॉजिस्टिक्स और धन शोधन विरोधी उपायों पर भी चर्चा की गई। इसने उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए व्यावहारिक कौशल का एक व्यापक अवलोकन प्रदान किया।

12. वाणिज्य विभाग के सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय पर छह-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (18 फ़रवरी से 24 मार्च 2025)

वाणिज्य विभाग (डीओसी) के सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) के लिए छह-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 फ़रवरी को शुरू हुआ और 24 मार्च 2024 को संपन्न हुआ। यह डॉ. विजया कट्टी द्वारा निर्देशित, आठ प्रतिभागियों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतीक था। प्रतिभागियों के प्रशासनिक कौशल को निखारने और सरकारी प्रक्रियाओं की उनकी समझ को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए इस कार्यक्रम में लोक प्रशासन, नीति विश्लेषण, कानूनी ढाँचे और संचार रणनीतियों सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। अनुभवी प्रशिक्षकों और विषय विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों ने सहायक अनुभाग अधिकारियों को प्रभावी शासन के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने हेतु सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक अभ्यास प्रदान किए। इंटरैक्टिव चर्चाओं, केस स्टडी और सिमुलेशन के माध्यम से, प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से सीखने में भाग लिया, अपनी समझ को गहरा करने के लिए अनुभवों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान किया। जैसे-जैसे कार्यक्रम समाप्त होने के करीब आया, एएसओ बढ़ी हुई क्षमताओं और उद्देश्य की नई भावना के साथ उभरे, जो शासन में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मिशन में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए तैयार थे।

13. निर्यात और आयात प्रबंधन (हाइब्रिड) में चार महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम: बैच 21, जनवरी से मई 2024 तक

जनवरी से मई 2024 तक आयोजित, निर्यात और आयात प्रबंधन (हाइब्रिड) में चार महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, बैच 21, ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पेचीदगियों को समझने के लिए 54 उत्सुक प्रतिभागियों के एक विविध समूह को आकर्षित किया।

डॉ. आशीष गुप्ता ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ऑनलाइन और व्यक्तिगत सत्रों को मिलाकर, कार्यक्रम ने आवश्यक निर्यात और आयात प्रबंधन पहलुओं को कवर करने वाला एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान किया। उद्योग विशेषज्ञों और शैक्षणिक पेशेवरों के नेतृत्व में सत्रों में व्यापार नियमों, रसद, दस्तावेज़ीकरण, जोखिम प्रबंधन और बाजार विश्लेषण पर गहन चर्चा की गई। व्याख्यानों, केस स्टडी और व्यावहारिक अभ्यासों के मिश्रण के माध्यम से, प्रतिभागियों ने वैश्विक व्यापार गतिशीलता की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और रणनीतिक दृष्टिकोण प्राप्त किए। कार्यक्रम के हाइब्रिड प्रारूप ने लचीलेपन और सुलभता की अनुमति दी, प्रतिभागियों के विविध कार्यक्रमों को समायोजित करते हुए जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा दिया।

14. जुलाई से दिसंबर 2024 के दौरान निर्यात और आयात प्रबंधन पर चार महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम (बैच-2)

जुलाई से दिसंबर 2024 तक आयोजित निर्यात और आयात प्रबंधन (ऑन कैंपस) पर चार महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, बैच 2, वैश्विक व्यापार की पेचीदगियों को समझने के लिए 25 उत्साही प्रतिभागियों के एक विविध समूह को आकर्षित किया। डॉ. आशीष गुप्ता ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम ने एक गहन शिक्षण अनुभव प्रदान किया, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अंतर्दृष्टि के साथ मिलाकर प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया गया। अनुभवी उद्योग पेशेवरों और शैक्षणिक विशेषज्ञों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में व्यापार नियम, बाजार विश्लेषण, लॉजिस्टिक्स और दस्तावेज़ीकरण सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। व्याख्यानों, केस स्टडी और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से, प्रतिभागियों ने निर्यात और आयात प्रक्रियाओं और वैश्विक बाज़ार में सफलता के लिए आवश्यक रणनीतिक विचारों को व्यापक रूप से समझा। कार्यक्रम के सहयोगात्मक माहौल ने प्रतिभागियों के बीच नेटवर्किंग के अवसरों और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी सीखने की यात्रा समृद्ध हुई। कार्यक्रम के समापन पर, प्रतिभागी बढ़ी हुई विशेषज्ञता और आत्मविश्वास के साथ उभरे, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गतिशील क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए तैयार हुए।

कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं	कार्यक्रम	कार्यक्रम की अवधि	कार्यक्रम निदेशक का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
I ओपन प्रोग्राम				
1.	निर्यात और आयात प्रबंधन में चार महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम (जनवरी से मई 2024), बैच 21	4 महीने/150 घंटे	डॉ आशीष गुप्ता	54
2.	निर्यात और आयात प्रबंधन में चार महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम (बैच 2) (जुलाई से दिसंबर 2024)	4 महीने/150 घंटे	डॉ आशीष गुप्ता	25
	कुल संख्या			79
II प्रायोजित एमडीपी				
1	आईटीएस परिवीक्षार्थियों के लिए 11 महीने का व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2024-25 (फरवरी 2024 से जनवरी 2025)	11 महीने	डॉ. चारु ग्रोवर	3
2.	टीवीएस मोटर्स के लिए 11 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम (जनवरी से दिसंबर 2024)	1 वर्ष	डॉ. प्रीति, टाक	33

3.	डीजीआर बैच 15 के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन में 24 सप्ताह/6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स (12 फरवरी से 29 जुलाई 2024)	6 महीने/24 सप्ताह	डॉ आंचल अरोड़ा	50
4.	डीजीआर बैच 16 (11 मार्च से सितंबर 2024) के अधिकारियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 24 सप्ताह/6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स	6 महीने/24 सप्ताह	डॉ. सुगंधा हुरिया	34
5.	डीजीआर बैच 17 (12 अगस्त 2024 से 24 जनवरी 2025) के अधिकारियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट (एचआर और वित्त) में 24 सप्ताह/6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स	6 महीने/24 सप्ताह	डॉ प्रियंका जयसवाल	46
6.	**आईआईएफटी परिसर में आईईएस के लए 5 दिवसीय एमडीपी**	5 दिन/ 30 घंटे	डॉ. विजया कट्टी	17
7.	सोनालीका ट्रैक्टर्स के गैर-वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	26-27 जुलाई 2024	डॉ. जैकलीन सिम्स	23
8.	डीओसी के एएसओ के लिए 12-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	20 अगस्त से 25 सितंबर 2024 तक	डॉ. विजया कट्टी	30
9.	भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	4 सितंबर 2024	डॉ रोहित मेहतानी	25
10.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के अधिकारियों के लिए निर्यात प्रबंधन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	18-20 दिसम्बर 2024	डॉ रोहित मेहतानी	20
11.	ईसीजीसी के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	6-8 फ़रवरी 2025	डॉ. विजया कट्टी	29
12.	वाणिज्य विभाग के सहायक सचिवों (एएसओ) के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैच 2023	18 फ़रवरी से 24 मार्च तक 2025	डॉ. विजया कट्टी	8
	कुल			**318**
	सकल कुल			**397**

(अंतर्राष्ट्रीय वार्ता केंद्र)

वर्ष 2024-25 के दौरान, IIFT दिल्ली में CIN ने सरकारी अधिकारियों के लिए पाँच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों से कुल 125 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

1. आईआईएफटी परिसर में ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (19-21 सितंबर 2024)

ईसीजीसी अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 19-21 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. रोहित मेहतानी द्वारा निर्देशित इस कार्यक्रम में वैश्विक व्यापार गतिशीलता, व्यापार दस्तावेज़ीकरण, शिपिंग लॉजिस्टिक्स, भारत की विदेश व्यापार नीति, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध प्रबंधन, व्यावसायिक संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसमें समूह प्रस्तुतियाँ और प्रस्तुतियों पर प्रतिक्रियाएँ भी शामिल थीं और भविष्य के रुझानों पर भी चर्चा की गई । इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन और वार्ता रणनीतियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना, उनके व्यावसायिक विकास में योगदान देना और वैश्विक व्यापार परिवेश में ईसीजीसी के उद्देश्यों का समर्थन करना था।

2. आईओसीएल परिसर में आईओसीएल के अधिकारियों के लिए निर्यात-आयात प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (24-26 सितंबर 2024)

आईओसीएल अधिकारियों के लिए निर्यात-आयात प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 24-26 सितंबर 2024 तक आईओसीएल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. रोहित मेहतानी ने इस कार्यक्रम का निर्देशन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें बाज़ार में प्रवेश की रणनीतियाँ, INCOTERMS, व्यापार वित्त और निर्यात-आयात अनुबंध शामिल हैं। प्रतिभागियों ने जोखिम प्रबंधन, वैश्विक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, उन्नत लॉजिस्टिक्स और अंतर-सांस्कृतिक वार्ता कौशल का भी अध्ययन किया। प्रभावी संचार और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के मूल सिद्धांतों पर ज़ोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को वैश्विक व्यापार परिवेश में संचालन के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान और रणनीतिक अंतर्दृष्टि से लैस करना था।

3. भारतीय विमानन अकादमी में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के लिए भूमि बंदरगाहों और सीमा पार व्यापार सुविधा पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (18-22 नवंबर 2024)

भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के लिए भूमि बंदरगाहों और सीमा पार व्यापार सुविधा पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 18-22 नवंबर 2024 तक, भारतीय विमानन अकादमी में आयोजित किया गया, जिसमें 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. रोहित मेहतानी द्वारा निर्देशित इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढाँचे, क्षेत्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार सुविधा तंत्र और बहुविध परिवहन सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। प्रमुख सत्रों में सीमावर्ती अवसंरचना, अंतर-सांस्कृतिक वार्ता, लिंग और व्यापार, तथा व्यापार डेटा विश्लेषण पर चर्चा की गई। एक क्षेत्रीय भ्रमण ने व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार व्यापार प्रक्रियाओं और क्षेत्रीय एकीकरण के बारे में प्रतिभागियों की समझ को मजबूत करना था।

4. ग्लोब-एक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, उनके परिसर बीईएल, बैंगलोर में (25-29 नवंबर 2024)

25-29 नवंबर 2024 तक, 24 प्रतिभागियों के साथ, बीईएल, बैंगलोर में पाँच दिवसीय ग्लोब-एक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. रोहित मेहतानी के कार्यक्रम में विदेश व्यापार नीति, निर्यात वित्तपोषण विकल्प, व्यापार दस्तावेज़ीकरण और जोखिम प्रबंधन जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया। इसमें बहुपक्षीय व्यापार

ढाँचों, भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA), अंतर-सांस्कृतिक वार्ताओं और बाज़ार में प्रवेश की रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अतिरिक्त सत्रों में INCOTERMS, व्यापार वित्त और भारत के भुगतान संतुलन पर चर्चाएँ शामिल थीं। कार्यक्रम में केस स्टडी, समूह गतिविधियाँ और प्रतिभागियों की वैश्विक व्यापार गतिशीलता और वार्ताओं की समझ को बढ़ाने के लिए एक समापन समारोह शामिल था।

5. आईआईएफटी परिसर में ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (23-25 जनवरी 2025)

ईसीजीसी अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वार्ता पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 23-25 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. विजया कट्टी द्वारा निर्देशित इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भविष्य के रुझान, व्यापार दस्तावेजीकरण, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और भारत की विदेश व्यापार नीति सहित कई प्रमुख विषयों को शामिल किया गया। अन्य सत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व व्यापार संगठन, अनुबंध प्रबंधन, व्यापार वित्त और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने धन शोधन विरोधी प्रथाओं, संगठनात्मक व्यवहार और व्यावसायिक संचार पर भी चर्चा की। कार्यक्रम का समापन, विदाई समारोह और समापन भाषण के साथ हुआ, जिससे प्रतिभागियों के वैश्विक व्यापार और वार्ता कौशल में वृद्धि हुई।

कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	कार्यक्रम निदेशक का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1	आईआईएफटी परिसर में ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच 1)	19-21 सितम्बर 2024	डॉ रोहित मेहतानी	28
2	आईओसीएल के अधिकारियों के लिए उनके परिसर में निर्यात-आयात प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	24-26 सितम्बर 2024	डॉ रोहित मेहतानी	23
3	भारतीय विमानन अकादमी में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के लिए भूमि परिवहन और सीमा पार व्यापार सुविधा पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	18-22 नवंबर 2024	डॉ रोहित मेहतानी	25
4	ग्लोब-एक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, बीईएल, बैंगलोर के परिसर में	25-29 नवंबर 2024	डॉ रोहित मेहतानी	24
5	आईआईएफटी परिसर में ईसीजीसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्ता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच 2)	23-25 जनवरी 2025	डॉ. विजया कट्टी	25
	कुल			**125.00**

आईआईएफटी में अनुसंधान

अनुसंधान प्रभाग की गतिविधियों का उद्देश्य आईआईएफटी की दृश्यता बढ़ाना है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार और वित्त में अनुसंधान के लिए एक थिंक टैंक के रूप में उभरा है। प्रभाग की अनुसंधान गतिविधियाँ प्रबंधन अनुशासन के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित हुई हैं। संस्थान के विकास में अनुसंधान गतिविधि का बहुत महत्व है, क्योंकि यह अनुसंधान और प्रशिक्षण के बीच एक मजबूत और व्यापक अंतरापृष्ठ प्रदान करती है। सरकार और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित अध्ययनों के अलावा, संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भी सफलतापूर्वक बोली लगा रहा है।

1.प्रक्रियाधीन अनुसंधान अध्ययन

- **कॉर्पोरेट प्रदर्शन पर ईएसजी स्कोर और फर्म गुणवत्ता का प्रभाव: एशियाई बाजारों के लिए एक अध्ययन**

आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित

प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

i. ईएसजी के परिभाषात्मक और माप संबंधी पहलुओं पर विचार करना और फंड मैनेजरों का सर्वेक्षण करके प्रभाव निवेश में इसके ईएसजी को समझना
ii. ईएसजी स्कोर, स्टॉक रिटर्न और स्टॉक अस्थिरता के बीच संबंधों की अनुभवजन्य जाँच करना
iii. ईएसजी-आधारित निवेश रणनीति और अन्य विशेषता-आधारित रणनीतियों के बीच संबंधों की जाँच करना ईएसजी और बॉन्ड विशेषताओं के बीच संबंधों का परीक्षण करना
iv. ईएसजी के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों के लिए नीतिगत सुझाव।
v. झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना का कार्यान्वयन - सौर छतों को अपनाने के प्रेरकों और बाधाओं की जाँच

आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित

प्रस्तावित अध्ययन झारखंड, भारत में आदिवासी परिवारों द्वारा सौर छत प्रणालियों को अपनाने की जाँच करता है, और अपनाने की दरों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-जनसांख्यिकीय, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। झारखंड, अपनी महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी और विविध भौगोलिक विशेषताओं के साथ, इन गतिशीलताओं की जाँच के लिए एक अनूठा संदर्भ प्रदान करता है।

अध्ययन के व्यापक उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. सामाजिक-जनसांख्यिकीय प्रभाव का आकलन करना
2. आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना
3. पर्यावरणीय परिस्थितियों की जाँच करना
4. तकनीकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना
5. नीति और संस्थागत समर्थन की समीक्षा करना
6. सामुदायिक गतिशीलता की जाँच करना
7. केस स्टडीज़ का संचालन करना
8. दीर्घकालिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना

9. अनुकूलित हस्तक्षेपों का प्रस्ताव करना
10. नीति और व्यवहार को सूचित करना

- **दक्षिण बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सूर्य घर: सौर बिजली योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक और स्थिरता कारकों का एक व्यापक अध्ययन**

आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित

इस अध्ययन का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण दक्षिण बिहार में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक और सतत कारकों का पता लगाना है, जिसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री सूर्य घर: सौर बिजली योजना कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सौर ऊर्जा अपनाने में सुधार और क्षेत्र में ऊर्जा पहुँच की चुनौतियों का समाधान करने हेतु प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करने के लिए इन गतिशीलताओं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निम्नलिखित पाँच व्यापक उद्देश्य इस शोध के विशिष्ट लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं:

1. अपनाने के स्तर और जनसांख्यिकी का मूल्यांकन
2. सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की जाँच
3. सौर ऊर्जा अपनाने को प्रभावित करने वाले स्थिरता कारकों का आकलन
4. नीतिगत ढाँचों और सामुदायिक भागीदारी का विश्लेषण
5. लैंगिक गतिशीलता की जाँच
6. रोज़गार सृजन और आर्थिक अवसरों का आकलन
7. रोजगार सृजन और आर्थिक अवसरों का आकलन करना

2. पीएच.डी. कार्यक्रम

- **पीएच.डी. कार्यक्रम (प्रबंधन) 2024 का उद्घाटन, 18 अक्टूबर 2024 को हुआ। दिल्ली परिसर में 18 छात्र (12 पूर्णकालिक और 6 अंशकालिक) इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फिलहाल, पाठ्यक्रम प्रगति में है।**
- **11 नवंबर 2024 को आयोजित संस्थान के 57वें दीक्षांत समारोह में 12 छात्रों को प्रबंधन में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई।**
- **पीएच.डी. (प्रबंधन) कार्यक्रम 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है।**

3. कार्यशालाएँ/ शोध वार्ताएँ/ पत्रिकाएँ

शोध वार्ता

- 12 मार्च 2024 को डॉ. अर्पिता जोआर्डर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबंधन एवं विपणन, चार्लटन कॉलेज ऑफ बिजनेस द्वारा दायित्व और लाभ: उद्यमिता के दृष्टिकोण से विदेशी मुद्रा के दो पहलुओं की जाँच।
- 3 जून 2024 को डॉ. अर्पण कर, प्रोफेसर, आईआईटी दिल्ली द्वारा बिग डेटा संचालित अध्ययनों के साथ प्रबंधन में सिद्धांत निर्माण।
- 18 सितंबर 2024 को प्रोफेसर आलोक कुमार, आईआईएम विशाखापत्तनम द्वारा बहु-मानदंड निर्णय-निर्माण का उपयोग करके एक समग्र स्थिरता सूचकांक का निर्माण विषय पर शोध वार्ता।
- 28 अक्टूबर 2024 को डॉ. अर्घो बंधोपाध्याय, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लॉ, आरएमआईटी विश्वविद्यालय, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रकाशन प्रक्रिया और शोध-पत्र लेखन तथा थीसिस लेखन के बीच संतुलन स्थापित करना।
- 5 मार्च 2025 को प्रो. प्रेम व्रत, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद द्वारा उत्पादकता बढ़ाने की रणनीतियाँ और डॉक्टरेट-बहुविषयक अनुसंधान का मापन।

- 25 मार्च 2025 को प्रो. गुरमीत सिंह, प्रमुख, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, द यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक द्वारा कार्य प्रौद्योगिकी फिट सिद्धांत, सामाजिक पूंजी सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के एकीकृत सैद्धांतिक लेंस के माध्यम से मेटावर्स: एसएमई का मामला।

4. पत्रिका "रिसर्च पल्स"

आईआईएफटी का अनुसंधान प्रभाग उच्च-गुणवत्ता वाले शोध परिणाम प्रस्तुत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, और "रिसर्च पल्स" पीएचडी शोधार्थियों के बीच गुणवत्तापूर्ण शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक ऐसा ही प्रयास है। 2024-25 के दौरान रिसर्च पल्स के निम्नलिखित अंक जारी किए गए:

1. रिसर्च पल्स: वॉल्यूम I का दूसरा अंक 1 अक्टूबर 2024 को जारी किया जाएगा।
2. रिसर्च पल्स: वॉल्यूम II का पहला अंक 27 मार्च 2025 को जारी किया जाएगा।

खंड II के पहले अंक में विशेष विचार, विचार धारा, शोध झलक, संवाद, मनन और प्रकाशन-शोध समापन आदि की कई श्रेणियों के तहत विभिन्न लेख शामिल हैं। इस अंक में पुरस्कार, मान्यता और समाचार (समाचार में आईआईएफटी) भी शामिल हैं।

5. विकसित भारत के निर्माण में एमएसएमई निर्यात की भूमिका पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

"वकसत भारत के निर्माण में एमएसएमई निर्यात की भूमका" वषय पर 10 जनवरी 2025 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कया गया। वभन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, एमएसएमई संघों, कॉर्पोरेट्स, स्टार्ट-अप मालकों और शोधाथयों सहित लगभग 75 प्रतिभागयों ने संगोष्ठी में भाग लया और चर्चा को समृद्ध बनाया।

संगोष्ठी में "भारत से निर्यात बढ़ाने में एमएसएमई की क्षमता" वषय पर एक पैनल चर्चा भी शामल थी। चूँक देश 2047 तक एक वकसत राष्ट्र बनने की दिशा में प्रयासरत है, इस लए यह माना गया क 2030 के लए निर्धारित महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लए निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाना आवश्यक होगा।

6. वैश्विक व्यापार अनुसंधान सम्मेलन (जीबीआरसी 2025)

"सीमाओं से परे: वैश्वीकृत विश्व में अनुसंधान की पुनर्कल्पना" विषय पर तीन दिवसीय वैश्विक व्यापार अनुसंधान सम्मेलन (जीबीआरसी 2025) 26-28 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया।

संस्थान को दुनिया भर के संकाय सदस्यों और शोध विद्वानों से 185 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से निम्नलिखित सात ट्रैकों से 112 शोध पत्र स्वीकार किए गए:

1. वैश्विक व्यापार एवं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता
2. वित्तीय प्रबंधन
3. अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक नीति
4. विपणन प्रबंधन
5. सामान्य प्रबंधन एवं रणनीति
6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं विश्लेषण
7. संचालन एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

निम्नलिखित पूर्व-सम्मेलन कार्यशालाएँ आयोजित की गईं:

1. "व्यापार और नीति अनुसंधान में जनरेटिव एआई का उपयोग", प्रोफेसर माइकल डॉवलिंग द्वारा, डीसीयू बिजनेस स्कूल, डबलिन में वित्त के प्रोफेसर।
2. "व्यावसायिक अनुसंधान में प्रायोगिक विधियाँ" प्रोफेसर शिल्पा मदन, मार्केटिंग प्रोफेसर, सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय द्वारा।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री राजर्षि गुप्ता, जीबीआरसी'25 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे।

जीबीआरसी'25 में "संपादकों से मिलिए" सत्र भी शामिल था जहाँ विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादकों ने अपने अनुभव साझा किए और युवा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अलावा, इसमें "आर्थिक व्यवधानों से निपटना: लचीलेपन की रणनीतियाँ" विषय पर एक पूर्ण सत्र भी शामिल था।

दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई)

आईआईएफटी, दिल्ली स्थित दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई प्रभाग) की स्थापना मई 2021 में कार्यरत पेशेवरों के कौशल विकास एवं संवर्धन हेतु आवश्यकता-आधारित ऑनलाइन शिक्षण के अवसर प्रदान करने हेतु की गई थी।

पिछले एक साल में, केंद्र ने आधुनिक शिक्षार्थियों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए विविध ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत करके अपनी शैक्षिक पहुँच का उल्लेखनीय विस्तार किया है। इंटरैक्टिव लाइव व्याख्यानों और आकर्षक मल्टीमीडिया सामग्री के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने व्यापक दर्शकों को लचीले और सुलभ शिक्षण के अवसर सफलतापूर्वक प्रदान किए हैं।

केंद्र वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम चला रहा है:

1. एमबीए (आईबी) ऑनलाइन कार्यक्रम

आईआईएफटी द्वारा प्रस्तुत यह स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर कार्यरत पेशेवरों को उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम अनुभवी प्रबंधकों को गहन ज्ञान, व्यावहारिक उपकरण और रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ताकि वे जटिल व्यावसायिक चुनौतियों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त, विपणन, व्यापार और रणनीति, से निपटने में सक्षम हो सकें।

वर्तमान बैच:

1. एमबीए (आईबी) ऑनलाइन बैच 2022-2024: 9 प्रतिभागी; जून 2025 में दीक्षांत समारोह के लिए निर्धारित।
2. एमबीए (आईबी) ऑनलाइन बैच 2023-2025: 11 प्रतिभागी; वर्तमान में सेमेस्टर IV में।

2. **चार महीने का ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम**

केंद्र निर्यात-आयात प्रबंधन, वैश्विक व्यापार रसद और बंदरगाह संचालन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और व्यावसायिक विश्लेषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रदान करता है।

वर्तमान बैच:

1. 32 प्रतिभागियों के साथ, निर्यात-आयात प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम (बैच 01): सितंबर 2024 - फरवरी 2025
2. 27 प्रतिभागियों के साथ, निर्यात-आयात प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम (बैच 02): जनवरी 2025 - मई 2025

3. निर्यात-आयात प्रबंधन की मूल बातों पर व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम

यह प्रभाग, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की निर्यात बंधु योजना के अंतर्गत 'निर्यात-आयात प्रबंधन की मूल बातें' पर एमओओसी कार्यक्रम संचालित करता है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक प्रतिभागियों को एक सौ चौंतीस प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

4. विकसित भारत@2047 वेबिनार

प्रभाग ने "भारत सरकार की पहल - 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएँ/विकसित भारत@2047" के अंतर्गत अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चार वेबिनार आयोजित किए।

5. उद्योग भ्रमण

डिवीजन ने एमबीए (आईबी) और ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम के छात्रों के लिए औद्योगिक संचालन की व्यावहारिक समझ बढ़ाने हेतु, दो एक दिवसीय उद्योग भ्रमण का आयोजन किया।

1. 3 जनवरी 2025 को, छात्रों ने डेयरी प्रसंस्करण, पैकेजिंग और वितरण प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मदर डेयरी प्लांट, पटपड़गंज का दौरा किया।

2. 17 मार्च 2025 को, ऑटोमोबाइल उद्योग में विनिर्माण प्रक्रियाओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण की जानकारी प्रदान करने के लिए, गुरुग्राम के मानेसर में होंडा प्लांट का दौरा आयोजित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आईआईएफटी का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग, विभिन्न शैक्षणिक व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने के लिए दुनिया भर के संस्थानों के साथ सहयोग करके संस्थान के वैश्विक नेटवर्क के निर्माण हेतु गतिविधियाँ संचालित करता है। छात्र और संकाय आदान-प्रदान, आईआईएफटी के शैक्षणिक सहयोग का प्रमुख आधार है।

आईसीसीडी प्रभाग एएसीएसबी, ईएफएमडी और एआईबी जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संघों की सदस्यता के माध्यम से अपने वैश्विक संबंधों को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। इस तरह के जुड़ावों के माध्यम से संयुक्त शैक्षणिक पहलों के लिए मंच तैयार होता है। अपनी वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करने के अपने प्रयासों के क्रम में, प्रभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही स्तरों पर प्रासंगिक प्रत्यायन और रैंकिंग में भाग लेने की ज़िम्मेदारी भी लेता है।

क्षमता विकास आईसीसीडी प्रभाग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। यह प्रभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और चर्चाओं में भागीदारी के माध्यम से आईआईएफटी संकाय की उन्नति के लिए उपयुक्त दिशानिर्देशों को परिभाषित और कार्यान्वित करना सुनिश्चित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आईसीसीडी प्रभाग, IIFT के शैक्षणिक सहयोग का प्रमुख आधार है। यह प्रभाग, शैक्षणिक साझेदारी के अवसरों की खोज हेतु दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ निरंतर संवाद में संलग्न है। वर्तमान में, IIFT दुनिया भर के 46 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सहयोग करता है। इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों में से 21 यूरोप में, 13 एशिया में और 12 दुनिया के अन्य हिस्सों में हैं।

नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

- संस्थान ने 25 अप्रैल 2024 को वित्त प्रबंधन संस्थान, तंजानिया (आईएफएम तंजानिया) के साथ 5 वर्षों के लिए एक सामान्य शैक्षणिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- संस्थान ने 26 अप्रैल 2024 को यूके के प्लायमाउथ विश्वविद्यालय के साथ 5 वर्षों के लिए एक सामान्य शैक्षणिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- संस्थान ने 10 मई 2024 को यूके के हडर्सफ़ील्ड विश्वविद्यालय के साथ 5 वर्षों के लिए एक सामान्य शैक्षणिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- संस्थान ने सितंबर 2024 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के साथ 3 वर्षों के लिए एक सामान्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- संस्थान ने 3 मार्च 2025 को एपीईसी एंटवर्प/फ़्लैंडर्स पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, बेल्जियम के साथ 4 वर्षों के लिए एक सामान्य शैक्षणिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

आईआईएफटी में विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

आईसीसीडी में वर्ष भर विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से आते रहते हैं। ये दौरे आईआईएफटी को नेटवर्क बनाने और नए सहयोग स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं।

क्रम संख्या	नाम	विश्वविद्यालय	यात्रा की तिथि	आईआईएफटी सदस्य	उद्देश्य
1	सुश्री एरीना टिंकोवा	RUDN, रूस	16 अप्रैल 2024	*डॉ. सतिंदर भाटिया, पूर्व कुलपति,* *डॉ. नीति नंदिनी चटनानी,* *प्रमुख- आईसीसीडी*	भविष्य के उद्यम पर चर्चा करने के लिए
2	सुश्री तारा पाठक- प्रथम सचिव (पीआईसी एवं शिक्षा)	नीदरलैंड स्थित दूतावास (वाणिज्य दूतावास)	7 मई 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी* *प्रमुख- आईसीसीडी,* *डॉ. तुहीना मुखर्जी* *सहेयक प्रोफेसर*	शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए
3	प्रो. जोसेफैट डैनियल लोट्टो, रेक्टर, प्रो. तादेओ एंड्रयू सट्टा, बाह्य संपर्क सलाहकार, डॉ. बर्नार्ड एलीज़र मन्ज़ावा, विभागाध्यक्ष,	आईएफएम, तंजानिया	10 मई 2024	*डॉ. सतिंदर भाटिया पूर्व-वीसी,* *डॉ. पी.के. गुप्ता पूर्व रजिस्ट्रार,* *डॉ. नीति नंदिनी*	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु

	बाह्य संपर्क			*चटनानी, प्रमुख-आईसीसीडी, डॉ. श्वेता एस. मल्ला प्रमुख-जीएसएमडी, आईसीसीडी संकाय*	
4	सुश्री ओल्गा कलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय विभाग	आईएएएस एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान, रूस	29 मई 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख-आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	शैक्षणिक गतिशीलता पर चर्चा करने के लिए (ऑनलाइन बैठक)
5	सुश्री लिचमीरा डोरोटा, अंतर्राष्ट्रीय विकास प्रबंधक	ईएम नॉर्मंडी, फ्रांस	5 जून 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख-आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	छात्र विनिमय कार्यक्रम (ऑनलाइन बैठक) पर चर्चा करने के लिए
6	डॉ. डेविड मथुवा, एसोसिएट डीन, एंथोनी एमबांदी, विकास निदेशक	स्ट्रैथमोर विश्वविद्यालय, नैरोबी, केन्या	16 जुलाई 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख-आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	सहयोग और अतिथि व्याख्यान (ऑनलाइन बैठक) पर चर्चा करने के लिए
7	डॉ. मून यंग किम, सहायक प्रोफेसर	सोलब्रिज विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया	2 अगस्त 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख-आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	छात्र विनिमय कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान/वार्ता और सहयोगात्मक अनुसंधान गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए (ऑनलाइन बैठक)
8	सुश्री जूलिया सेनी, कार्यक्रम प्रबंधक	सारलैंड विश्वविद्यालय, जर्मनी	8 अगस्त 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख-आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	एसईपी छात्रों द्वारा कम क्रेडिट पूरा करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई, उद्यमिता के छात्रों के लिए एक अल्पकालिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन (ऑनलाइन बैठक)
9	डॉ. अतुल मिश्रा, रणनीतिक प्रबंधन (शिक्षा) के व्याख्याता, प्लायमाउथ विश्वविद्यालय	प्लायमाउथ विश्वविद्यालय, यूके	9 अगस्त 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख-आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	अल्पकालिक अध्ययन कार्यक्रम/दौरे, संयुक्त अनुसंधान सहयोग और कार्यकारी कार्यक्रमों के विकास पर चर्चा करना
10	सुश्री एनेटे विंसेंट, वरिष्ठ भर्ती सलाहकार-दक्षिण एशिया	एबरिस्टविथ विश्वविद्यालय, यूके	12 अगस्त 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख-आईसीसीडी और आईसीसीडी*	समझौता ज्ञापन के सक्रियण के लिए (ऑनलाइन बैठक)

				संकाय	
11	प्रो. एकातेरिना डेमचेंको, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय प्रमुख, जीएसईएम	जीएसईएम, यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	13 अगस्त 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	छात्र विनिमय कार्यक्रम पर चर्चा (ऑनलाइन बैठक)
12	डॉ. इल्गाज़अरीकन, प्रोफेसर- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रणनीतिक प्रबंधन, केंट स्टेट यूनिवर्सिटी	केंट स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए	4 सितम्बर 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण (ऑनलाइन बैठक)
13	सुश्री टोवा ब्लोमक्विस्ट, विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और गतिशीलता	हेंकेन विश्वविद्यालय, फ़िनलैंड	11 सितम्बर 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	छात्र विनिमय कार्यक्रम पर चर्चा (ऑनलाइन बैठक)
14	विक्टर फर्नांडो, अध्यक्ष, एसओआईके इन्वेस्टमेंट्स, अंगोला, जोआकिम पिपा, निदेशक, संचालन, एसओआईके इन्वेस्टमेंट्स, अंगोला, सिल्वियो नेवेस बैप्टिस्टा, प्रबंधक, एसओआईके इन्वेस्टमेंट्स, अंगोला, एल्मिरा ममाडोवा, युकसेलिश पीसी, अज़रबैजान में मानव संसाधन और परीक्षण विभाग के प्रमुख, चिनारा बाबायेवा, युकसेलिश पीसी, अज़रबैजान में पीआर विभाग की प्रमुख, लव अग्रवाल, भारत, जोआओ मातोसो हेनरिक्स, सीईओ-एसडीजी, पुर्तगाल, व्याचेस्लाव शॉपटेंको, उप निदेशक, रानेपा, रूस, अल्लाटुपिकोवा, उप निदेशक रानेपा, रूस, अलेक्जेंडर सोलोविएव,	जीएमसी इवेंट	28 सितम्बर 2024	डॉ. राकेश मोहन जोशी वीसी- आईआईएफटी, डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी, डॉ. राम सिंह प्रमुख-सीडीओई, डॉ. रोहित मेहतानी प्रमुख - एमडीपी, डॉ. आशीष पांडे प्रमुख - अनुसंधान, डॉ. आशीष गुप्ता सहायक प्रोफेसर, आईआरसी टीम और आईसीसीडी स्टाफ	विभिन्न देशों के प्रवक्ताओं के साथ बातचीत बैठक

	परियोजना निदेशक, रानेपा, रूस, एलेजांद्रो सेगुरा डी ला कैल, प्रेसिडेंट, स्पेन				
15	माइकल लो - उप निदेशक, पाठ्यक्रम विकास एवं डिजिटलीकरण लिम ताऊ वी, सहायक निदेशक केवेन टैन, वरिष्ठ विश्लेषक चोंग वेन हान, शोध अध्येता पून यू केओंग, कार्यक्रम प्रबंधक	सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय अकादमी (SMU)	10 अक्टूबर 2024	डॉ. राकेश मोहन जोशी वीसी-आईआईएफटी, डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी), डॉ. रविशंकर, प्रोफेसर, डॉ. श्वेता मल्ल प्रमुख (जीएसएमडी), *श्री अमित कुमार चनपुरिया* *उप कुलसचिव, शैक्षणिक*	अधिकारियों के पुनर्कौशल/उन्नयन पर केंद्रित कार्यक्रमों के लिए एसएमयूए और आईआईएफटी के बीच सहयोग पर चर्चा हुई। विशेष रूप से, इस बात पर सहमति हुई कि हाल ही में स्थापित दुबई केंद्र में, आईआईएफटी और एसएमयूए संयुक्त रूप से दुबई में स्थित अधिकारियों के लिए एमडीपी कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं।
16	सुश्री एलिसा स्टेपानोवा-अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कार्यालय की प्रमुख, जीएसईएम, एसपीएसयू	सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी रूस	11 अक्टूबर 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी* *प्रमुख आईसीसीडी,* *डॉ. र वशंकर* *प्रोफेसर*	भावी सहयोग और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बारे में चर्चा
17	श्री केन हाउतेवेल्ट्स, प्रमुख खाता भारतीय उपमहाद्वीप	एंटवर्प/ फ़्लैंडर्स पोर्ट प्रशिक्षण केंद्र, बेल्जियम	14 अक्टूबर 2024	डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी), डॉ. राम सिंह प्रमुख (सीडीओई), डॉ. प्रयंका जयसवाल सहायक. प्रोफ़ेसर. (ईएमपीडी)	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संबंधी चर्चा
18	प्रो. अल्बर्टो ओनेट्टी, उद्यमिता और प्रबंधन के प्रोफेसर	इंसुब्रिया विश्वविद्यालय, इटली	18 अक्टूबर 2024	डॉ. रवि शंकर प्रोफेसर, डॉ. आशीष गुप्ता और आईसीसीडी टीम	छात्र विनिमय पर चर्चा
19	प्रो. निगेल होल्ट,	एबरिस्टविथ	22 नवंबर	डॉ. रवि शंकर,	संवदात्मक बैठक

	एसोसिएट प्रो वीसी प्रो. निगेल कोपनर, विभागाध्यक्ष, एबरिस्टविथ बिज़नेस स्कूल श्री ज़फीर आलम-प्रबंधक	विश्वविद्यालय	2024	डॉ. आशीष गुप्ता, डॉ. तुहीना मुखर्जी और आईसीसीडी स्टाफ	
20	सुश्री शर्लिन और सुश्री नम्रता बचानी आयोजक, एएससीआई अकादमी	भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई)	2 दिसम्बर 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी) एवं आईसीसीडी संकाय*	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद बातचीत बैठक (ऑनलाइन बैठक)
21	प्रो. एकातेरिना, एसोसिएट प्रोफेसर और सुश्री वेलेरिया, छात्र विनिमय समन्वयक	जीएसईएम, यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	12 दिसम्बर 2024	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	स्प्रिंग स्कूल कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पर चर्चा (ऑनलाइन बैठक)
22	प्रो. एकातेरिना, एसोसिएट प्रोफेसर और सुश्री वेलेरिया, छात्र विनिमय समन्वयक	जीएसईएम, यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	17 दिसम्बर 2024	डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी), आईसीसीडी संकाय और आईआरसी	स्प्रिंग स्कूल कार्यक्रम पर चर्चा (ऑनलाइन बैठक)
23	प्रो. एकातेरिना, एसोसिएट प्रोफेसर और यूआरएफयू छात्र	जीएसईएम, यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	26 दिसम्बर 2024	डॉ. अरुणिमा राणा, सुश्री रितिका कोहली	यूआरएफयू छात्रों के लिए स्प्रिंग स्कूल प्रोग्राम पीपीटी की प्रस्तुति (ऑनलाइन बैठक)
24	श्री तरुण शर्मा, सीओओ, नोकिया वेंचर्स	नोकिया वेंचर्स	4 जनवरी 2025	अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति (आईआरसी) और एमबीए आईबी छात्र	अतिथि व्याख्यान
25	सुश्री विल्मा पॉल, क्षेत्रीय प्रबंधक- दक्षिण एशिया	प्लायमाउथ विश्वविद्यालय	16 जनवरी 2025	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	
26	प्रो. माइकल लो, विभागाध्यक्ष, प्रो. चोंग वेन हान, शोध अध्येता प्रो. पून यू केओंग, कार्यक्रम प्रबंधक	सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय अकादमी (SMUA)	22 जनवरी 2025	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	संयुक्त कार्यक्रम पर चर्चा (ऑनलाइन बैठक)
27	प्रो. रजनीश नरूला, निदेशक, जॉन एच. डनिंग चेयर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस रेगुलेशन, हेनले बिजनेस स्कूल	रीडिंग विश्वविद्यालय, यूके	27 जनवरी 2025	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी और आईसीसीडी*	सहयोग पर चर्चा

				संकाय	
28	श्री मैथ्यू ली, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय श्री ताऊ वी लिम, सहायक निदेशक सुश्री मैगाडलीन चान, प्रबंधक	सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय अकादमी (SMUA)	3 फ़रवरी 2025	डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी), डॉ. विश्वजीत नाग प्रमुख (ईएमपीडी), डॉ. राम सिंह प्रमुख (सीडीओई), डॉ. रविशंकर और आईसीसीडी स्टाफ	कार्यकारी एवं ऑनलाइन एमबीए के साथ सहयोग के लिए चर्चा।
29	प्रो. रजनीश नरूला, निदेशक - हेनले बिजनेस स्कूल	रीडिंग विश्वविद्यालय, यूके	18 फ़रवरी 2025	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख-आईसीसीडी*	सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा (ऑनलाइन बैठक)
30	प्रोफेसर हंस रामो, प्रोफेसर प्रो निशांत कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रो. मार्टिन जोहानसन, एसोसिएट प्रोफेसर	स्टॉकहोम बिजनेस स्कूल, स्टॉकहोम विश्वविद्यालय, स्वीडन	24 फ़रवरी 2025	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख-आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	भविष्य के उद्यमों पर चर्चा
31	प्रोफेसर डेविड वेरेडास, और प्रो. मैरियन डेब्रुइन	वेलेरिक बिजनेस स्कूल - बेल्जियम आर्थिक मिशन	3 मार्च 2025	डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी) एवं डॉ. तुहीना मुखर्जी सहायक प्रोफेसर, आईसीसीडी स्टाफ	भविष्य के उद्यमों पर चर्चा
32	3 मार्च 2025 को, डॉ. नीति एन. चटनानी, प्रमुख (आईसीसीडी), डॉ. तुहीना मुखर्जी, सहायक प्रोफेसर और आईसीसीडी प्रभाग के अन्य सदस्यों ने वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में एपीईसी एमओयू (एंटवर्प/फ्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर), बेल्जियम के लिए एमओयू हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया।				
33	सुश्री तारा पाठक, काउंसलर (पीआईसी और शिक्षा), भारतीय दूतावास सुश्री तारा पाठक, काउंसलर (पीआईसी एवं शिक्षा), भारतीय दूतावास रेका लाइकलामा ए निजेहोल्ट, वरिष्ठ नीति सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीयकरण, छात्र एवं शैक्षिक मामले	व्रीजे विश्वविद्यालय, नीदरलैंड	17 मार्च 2025	डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी) डॉ. वी. रवीन्द्र सारधी प्रमुख (काकीनाडा), आईसीसीडी संकाय एवं कर्मचारी	शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए (ऑनलाइन बैठक)

	प्रो. बर्न्ड हेइडरगॉट, संचालन विश्लेषण डॉ. ई.पी. ग्रैमन्स, प्रबंधन एवं संगठन वभाग में संस्कृति एवं नेतृत्व के सहायक प्रो.				
34	सुश्री लिचमीरा डोरोटा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग में विकास प्रबंधक, सुश्री रिया, प्रशासनिक सहायक	ई एम नॉर्मंडी बिजनेस स्कूल, फ्रांस	24 मार्च 2025	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी*	दो-तरफ़ा छात्र गतिशीलता पर चर्चा
35	सुश्री रेका लिक्लामा ए निजेहोल्ट, वरिष्ठ नीति सलाहकार अंतर्राष्ट्रीयकरण, छात्र एवं शैक्षिक मामले	व्रीजे विश्वविद्यालय, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड	26 मार्च 2025	*डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख- आईसीसीडी और आईसीसीडी संकाय*	शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए
36	प्रो. माइकल डाउलिंग	डीसीयू बिजनेस स्कूल, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, आयरलैंड	26 मार्च 2025	डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी) डॉ. आशीष पांडे प्रमुख (अनुसंधान), डॉ. अरुणिमा राणा, और आईसीसीडी स्टाफ	शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए
37	प्रो. एलेना स्पासोवा- डीन	हेनले बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूके	27 मार्च 2025	प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी कुलपति, डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी) डॉ विश्वजीत नाग प्रमुख (अर्थशास्त्र) डॉ. रोहित मेहतानी प्रमुख (एमडीपी), डॉ. आशीष पांडे प्रमुख (अनुसंधान), डॉ बिबेक रे चौधरी, आईसीसीडी संकाय एवं कर्मचारी	सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा

38	अमेय पास्कल- एसोसिएट निदेशक अंतर्राष्ट्रीय संबंध	IESEG स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस	27 मार्च 2025	डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी) डॉ. अरुणिमा राणा, और आईसीसीडी स्टाफ	समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण पर चर्चा करने के लिए
39	ऑगस्टो वेन्सेस्लाउ, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार और साझेदारी उत्प्रेरक, अंतर्राष्ट्रीयकरण विभाग, FAAP- आर्मंडो अल्वारेसपेंटेडो फाउंडेशन मोनिका दा कोस्टा हेइलब्रॉन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निदेशालय, DIRCINT - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यालय, UERJ - रियो डी जनेरियो स्टेट यूनिवर्सिटी डाल्मोमंडेली, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कार्यालय, यूएफएबीसी - एबीसी संघीय विश्वविद्यालय इसाबेला बेराल्डीएस्पेरंडियो, उप-समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीयकरण कार्यालय, यूएफसीएसपीए - पोर्टो एलेग्रे के स्वास्थ्य विज्ञान के संघीय विश्वविद्यालय फेलिप फ़र्टाडो गुइमारेस, भाषा प्रभाग (डीएल), अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय (एसआरआई), यूएफईएस - संघीय विश्वविद्यालय एस्पिरिटो सैंटो के प्रमुख बारबरा मालवीरा ओफ़र्नो, सहायक निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय, यूएफएमजी - मिनस गैरैस के संघीय विश्वविद्यालय लिसे विएरा दा कोस्टा तुपियासु मर्लिन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध	ब्राज़ीलियाई उच्च शिक्षा संस्थान और प्रतिनिधि, ब्राज़ील और भारत: उच्च शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के मार्ग	28 मार्च 2025	प्रो. राकेश मोहन जोशी कुलपति डॉ. नीति नंदिनी चटनानी अध्यक्ष - आईसीसीडी, डॉ. राम सिंह, अध्यक्ष - सीडीओई, डॉ. रोहित मेहतानी अध्यक्ष - एमडीपी, डॉ. बी.के. साहू, अध्यक्ष - अर्थशास्त्र प्रभाग और आईसीसीडी संकाय	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर चर्चा

	कार्यालय, यूएफपीए - संघीय पारा विश्वविद्यालय एथोस मुन्होज़ मोरेरा दा सिल्वा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उप डीन, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, यूएफआरजीएस - रियो ग्रांडे डो सुल के संघीय विश्वविद्यालय लुइस एडुआर्डो बोवोलाटो, अध्यक्ष, राष्ट्रपति कार्यालय, यूएफटी - टोकांटिंस संघीय विश्वविद्यालय जोस सेल्सो फ्रेयर जूनियर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एसोसिएट प्रोवोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, यूएनईएसपी - साओ पाउलो स्टेट यूनिवर्सिटी राफेल डी ब्रिटो डायस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, यूनिकैंप - स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैम्पिनास लॉरा एंकोना लोपेज़ फ्रेयर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए उप-रेक्टर और इरास्मस कार्यक्रम की समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, यूएनआईपी - यूनिवर्सिटी पॉलिस्ता				
40	सुश्री ल्यान ई.जे. प्लूमेन – निदेशक अंतर्राष्ट्रीय संबंध	मास्ट्रिच विश्वविद्यालय, बिजनेस और अर्थशास्त्र स्कूल	28 मार्च 2025	डॉ. नीति नंदिनी चटनानी प्रमुख (आईसीसीडी), डॉ. पूजा लखनपाल प्रमुख (सीआरपीडी), आईसीसीडी संकाय एवं कर्मचारी	भविष्य के उपक्रमों पर चर्चा करने के लिए

आईआईएफटी द्वारा आयोजित वैश्विक प्रबंधन चुनौती (जीएमसी) - 2024-25 में आईआईएफटी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां - एक झलक

हाल ही में, पुर्तगाल के सिमुलाडोर्स ई मॉडल्स डी गेस्टाओ द्वारा आयोजित ग्लोबल मैनेजमेंट चैलेंज (जीएमसी) ने 27-28 सितंबर 2024 को, आईआईएफटी दिल्ली परिसर में विश्व सेमीफाइनल और फाइनल की मेजबानी करने के लिए आईआईएफटी को अकादमिक भागीदार के रूप में चुना। यह एक वैश्विक आयोजन था जिसमें दुनिया भर के लगभग 12 विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन ने हमारे संस्थान को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने और विभिन्न वैश्विक बी-स्कूलों के टीम प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। यह आयोजन AIOE-ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स (FICCI का एक सहयोगी निकाय) के सहयोग से आयोजित किया गया था। आयोजन की कुछ झलकियाँ यहाँ संलग्न हैं।

छात्र विनिमय कार्यक्रम

आगमन

छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्कूलों से तीन छात्र आईआईएफटी आए:

क्रम संख्या	नाम	देश	विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	त्रैमासिक
1	सुश्री एलेक्सिया राचेले मैरी रोज़ कहन	फ्रांस	रेनेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025
2	सुश्री अन्ना प्रश्चारुक	रूस	GSEM UrFU, रूस	मार्च 2025
3.	श्री मिखाइल पेस्त्री	रूस	GSEM UrFU, रूस	मार्च 2025

छात्र विनिमय कार्यक्रम 2024-25 IIFT आउटबाउंड छात्र MBA (IB) 2024-26 बैच और MBA(BA) 2024-26 बैच IIFT से अंतर्राष्ट्रीय/वैश्विक साझेदार स्कूल/विश्वविद्यालय

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) और डॉ. नीति नंदिनी चटनानी की अध्यक्षता में संस्थान की एक शाखा, आईसीसीडी, को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि 56 उत्कृष्ट छात्रों ने छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत एक उल्लेखनीय और परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। इस शैक्षणिक वर्ष में, हमारा प्रतिष्ठित समूह फ्रांस, जर्मनी, फ़िनलैंड और रूस सहित यूरोप के प्रतिष्ठित और विश्व स्तर पर प्रशंसित बिज़नेस स्कूलों का हिस्सा होगा।

मूल्यांकन वर्ष 2024-25 में, छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत आईआईएफटी से विभिन्न वैश्विक विश्वविद्यालयों तक दो-तरफ़ा छात्र गतिशीलता में लगभग 53 छात्र शामिल हुए हैं।

क्रम संख्या	नाम	आवंटित विश्वविद्यालय	देश	त्रैमासिक	पाठ्यक्रम
1	जय कृष्ण कुमार एस.	ईएम नॉर्मंडी बिजनेस स्कूल, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
2	तनुष बीजू	ईएम नॉर्मंडी बिजनेस स्कूल, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
3	कुलदीप वाला	ईएम नॉर्मंडी बिजनेस स्कूल, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)

4	शिवांग पारीक	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
5	निशिता पाली	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
6	यश गोयल	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
7	अजिंक्य योगेश सुरवाडे	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
8	अवनि सूद	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
9	स्वप्निल संजय मंगलोरकर	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
10	पुलकित डागा	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
11	आदित्य अग्रवाल	ग्रेनोबल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
12	ध्वनि कुमार	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
13	साहिल राज सिंह	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
14	सुसरला साईं सुमेधा	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
15	नेहल शरण चंदू	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
16	मोहम्मद काशिफ़	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
17	जसकीरत सिंह कोहली	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
18	उत्कर्ष सिंह	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
19	तृषा शर्मा	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
20	विजय सिंह	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
21	अंकन रॉय	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
22	चैतन्य कुमार	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
23	मोहम्मद अदनान	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
24	अविक दास	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)

25	भुवनगिरि वसुधा	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
26	उमाशंकर एस.	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
27	मुहम्मद सिनान के.पी.	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
28	वेदांत अनिल मोरे	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
29	श्रेयश विष्णुदास तिरुक	जीएसईएम यूराल संघीय विश्वविद्यालय, रूस	रूस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
30	शुभम प्रजापति	हैंकेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिनलैंड, हेलसिंकी	फिनलैंड	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
31	मानस चड्ढा	हैंकेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिनलैंड, हेलसिंकी	फिनलैंड	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
32	अनिरुद्ध सुरसे	स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
33	शताक्षी डोगरा	IESEG स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
34	करण मल्होत्रा	IESEG स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
35	रौनक बनर्जी	सारलैंड विश्वविद्यालय, जर्मनी	जर्मनी	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
36	आद्या पांडे	ग्रेनोबल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
37	अभिषेक भार्गव	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
38	सार्थक सिंह	ईएम स्ट्रासबर्ग बिजनेस स्कूल, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
39	करूब सिंह	IESEG स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
40	दिवांशु गुप्ता	हैंकेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिनलैंड	फिनलैंड	जनवरी-मार्च 2025	MBA (IB) एमबीए (आईबी)
41	वेदांत	हैंकेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिनलैंड	फिनलैंड	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
42	सौरभ मान	IESEG स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
43	विवेकवर्धिनी मायका	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
44	जैतिक नागपाल	IESEG स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
45	सिद्धार्थ चौधरी	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
46	आर्य शिरीष पुरोहित	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	) एमबीए (आईबी)
47	सक्षम जैन	ईएम नॉर्मंडी बिजनेस स्कूल, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)

48	करण ठकराल	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
49	शिवम कुमार	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
50	मयंक गुप्ता	ईएससी रेन्नेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
51	अमित भारद्वाजइरागवरपु	सारलैंड विश्वविद्यालय, जर्मनी	जर्मनी	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
52	वरुण गोयल	ईएम नॉर्मंडी बिजनेस स्कूल, फ्रांस	फ्रांस	जनवरी-मार्च 2025	एमबीए (आईबी)
53	शुभम सौरव सिंह	रेनेस स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्रांस	फ्रांस	17-27 जून 2025	एमबीए (आईबी) सप्ताहांत 22-25

आगंतुक छात्रों छात्रों और आईआरसी 2024-25 को विदाई

20 मार्च 2025 को दिल्ली परिसर में इनबाउंड छात्रों और वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति (आईआरसी) 2024-25 के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। डॉ. नीति नंदिनी चटनानी, प्रमुख (आईसीसीडी) और आईसीसीडी संकाय सदस्यों की उपस्थिति में प्रशंसा चिह्न प्रदान किए गए।

संकाय विकास कार्यक्रम

वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, संकाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आईआईएफटी संकाय की भागीदारी नीचे दी गई है:

	सम्मेलन	प्रशिक्षण/प्रमाणन कार्यक्रम
राष्ट्रीय	**3**	**1**
अंतरराष्ट्रीय	**2**	**2**

प्रत्यायन एवं रैंकिंग प्रकोष्ठ गतिविधियाँ (2024-25)

- आईआईएफटी ने प्रबंधन श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) भारत रैंकिंग - 2024 में भाग लिया है और 15वीं रैंक प्राप्त की है।

- IIFT ने पीजी मैनेजमेंट प्रोग्राम, एमबीए (आईबी) फुल-टाइम के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) की मान्यता प्रक्रिया के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन कर दिया है। विशेषज्ञों की टीम का दौरा 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक चला। निम्नलिखित 10 मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर एनबीए तकनीकी संस्थानों के कार्यक्रमों को मान्यता देता है।
  - विज़न, मिशन और कार्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्य
  - शासन, नेतृत्व और वित्तीय संसाधन
  - कार्यक्रम के परिणाम और पाठ्यक्रम के परिणाम
  - पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रक्रिया
  - छात्र गुणवत्ता और प्रदर्शन
  - संकाय विशेषताएँ और योगदान
  - उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क
  - बुनियादी ढाँचा
  - पूर्व छात्रों का प्रदर्शन और संपर्क
  - निरंतर सुधार
- आईसीसीडी - प्रत्यायन एवं रैंकिंग (ए एंड आर) प्रकोष्ठ ने 1 जुलाई 2024 को एएसीएसबी को एक सतत सुधार समीक्षा (सीआईआर) आवेदन प्रस्तुत किया है।
- "अपनी प्रत्यायन यात्रा की शुरुआत" विषय पर एएसीएसबी सेमिनार का आयोजन आईआईएफटी द्वारा प्रत्यायन एवं रैंकिंग प्रकोष्ठ के माध्यम से 18 सितंबर 2024 को किया गया था। सेमिनार के मुख्य संसाधन व्यक्ति डॉ. ज्योफ पेरी, कार्यकारी उपाध्यक्ष, वैश्विक मुख्य सदस्यता अधिकारी और एशिया प्रशांत एएसीएसबी के प्रबंध निदेशक थे।
- आईसीसीडी - प्रत्यायन एवं रैंकिंग (एएंडआर) प्रकोष्ठ ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित एएसीएसबी सर्वेक्षणों के लिए डेटा प्रस्तुत किया है।
- कर्मचारी मुआवज़ा एवं जनसांख्यिकी सर्वेक्षण (एससीडीएस) सर्वेक्षण
- वार्षिक बिजनेस स्कूल प्रश्नावली (बीएसक्यू) कार्यक्रम मॉड्यूल सर्वेक्षण।
- वार्षिक बिजनेस स्कूल प्रश्नावली (बीएसक्यू) वित्त मॉड्यूल सर्वेक्षण।
- शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सभी कार्यक्रमों के लिए एओएल माप रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रत्यायन और रैंकिंग सेल द्वारा एएसीएसबी एश्योरेंस ऑफ लर्निंग (एओएल) अभ्यास आयोजित किया जा रहा है।
- आईसीसीडी- प्रत्यायन एवं रैंकिंग सेल ने बिजनेस टुडे - एमडीआरए बी स्कूल सर्वेक्षण 2024 के लिए डेटा प्रस्तुत किया है और 7वीं रैंक हासिल की है।
- आईआईएफटी ने फॉर्च्यून इंडिया बी-स्कूल रैंकिंग 2024 में 9वां स्थान हासिल किया है।
- फॉर्च्यून इंडिया की सर्वश्रेष्ठ बी-स्कूल रैंकिंग 2024 में, विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएफटी को पहला स्थान मिला है।
- IIFT को T.I.M.E बी-स्कूल रैंकिंग 2024 में 7वां स्थान दिया गया है।
- IIFT को MBAUniverse.com रैंकिंग 2025 में 10वां स्थान दिया गया है।
- आईसीसीडी - प्रत्यायन और रैंकिंग (ए एंड आर) सेल ने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार द्वारा आयोजित सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) पोर्टल पर डेटा प्रस्तुत किया है।
- 14 फरवरी 2025 को क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) मान्यता द्वारा शुरू किए गए सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (एनएससीएसटीआई) सर्वेक्षण को आईसीसीडी - मान्यता और रैंकिंग (ए एंड आर) सेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

आईआईएफटी सदस्यताएँ

आईआईएफटी की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सदस्यता के लिए आईसीसीडी, नोडल संपर्क रहा है। आईसीसीडी दुनिया भर के प्रतिष्ठित संगठनों में सदस्यता से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन करता है। नीचे आईआईएफटी द्वारा अपनाई गई सदस्यताएँ दी गई हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर गहरी प्रतिष्ठा है।

1. **एसोसिएशन ऑफ एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस (AACSB):** AACSB इंटरनेशनल (AACSB), एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है, जो एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षकों, छात्रों और व्यवसायों को जोड़ती है, ताकि महान नेताओं की अगली पीढ़ी का निर्माण हो सकें । 1916 से उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों का पर्याय, AACSB दुनिया भर में 1,850 से अधिक सदस्य संगठनों और 950 से अधिक मान्यता प्राप्त बिजनेस स्कूलों को गुणवत्ता आश्वासन, व्यावसायिक शिक्षा बुद्धिमत्ता और शिक्षण एवं विकास सेवाएँ प्रदान करता है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी (एआईबी):** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी (एआईबी) अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विद्वानों और विशेषज्ञों का संघ है। 1959 में स्थापित, इसके लगभग 90 देशों में 3400 से अधिक सदस्य हैं। इसकी सदस्यता संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों के लिए भी खुली है।

3. **यूरोपीय प्रबंधन विकास फाउंडेशन (EFMD):** EFMD एक वैश्विक, गैर-लाभकारी, सदस्यता-आधारित संगठन है, जो प्रबंधन विकास के लिए समर्पित है। इसे व्यावसायिक स्कूलों, कार्यक्रमों और कॉर्पोरेट विश्वविद्यालयों के लिए एक मान्यता निकाय के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। शिक्षा, व्यवसाय, लोक सेवा और परामर्शदाता क्षेत्र के 30,000 प्रबंधन पेशेवरों के नेटवर्क के साथ, EFMD प्रबंधन, शिक्षा के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण को आकार देने में केंद्र की भूमिका निभाता है।

4. **भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू):** एआईयू उच्च शिक्षा के विकास और संवर्धन में सक्रिय रूप से संलग्न है। एआईयू के सदस्यों में सभी प्रकार के विश्वविद्यालय शामिल हैं, जैसे पारंपरिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, समविश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। भारतीय विश्वविद्यालयों के अलावा, बांग्लादेश, भूटान, कज़ाकिस्तान गणराज्य, मलेशिया, मॉरीशस, नेपाल, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के 13 विश्वविद्यालय/संस्थान इसके सहयोगी सदस्य हैं।

5. **ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, इंडिया (जीसीएनआई):** संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट (यूएनजीसी), न्यूयॉर्क का भारतीय स्थानीय नेटवर्क, ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया (जीसीएनआई) पूर्ण कानूनी मान्यता के साथ, विश्व स्तर पर स्थापित होने वाला पहला स्थानीय नेटवर्क है।

6. **भारतीय प्रबंधन विद्यालय संघ (AIMS):** भारतीय प्रबंधन विद्यालय संघ (AIMS), भारत में प्रबंधन शिक्षा के व्यावसायिक विकास और देश के बी-स्कूलों के हितों की रक्षा हेतु बी-स्कूलों का एक नेटवर्किंग निकाय है। यह भारत में भारतीय प्रबंधन विद्यालयों का आधिकारिक प्रतिनिधि है और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थित रहता है। यह दुनिया के बी-स्कूलों के सबसे बड़े नेटवर्किंग निकायों में से एक है।

7. **भारतीय वित्त संघ (आईएफए):** आईआईएफटी ने अगस्त 2023 में भारतीय वित्त संघ (आईएफए) की प्रतिष्ठित आजीवन सदस्यता ग्रहण कर ली है। आईएफए एक गैर-लाभकारी संस्था है जो वित्त और लेखांकन में काम करने वाले शिक्षाविदों और उद्योग को कॉर्पोरेट वित्त, लेखांकन और कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्तीय बाजार और जोखिम प्रबंधन पर शोध पर चर्चा करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

8. **अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (AIMA):** AIMA की स्थापना 1957 में हुई थी और इसने देश में प्रबंधन क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। AIMA के सदस्यों की संख्या 38,000 से अधिक है और AIMA से संबद्ध 68 स्थानीय प्रबंधन संघों के माध्यम से लगभग 6,000 कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य हैं।

9. भारतीय वपणन अकादमी **(एआईएम):** 2009 में स्था पत, भारतीय वपणन अकादमी (एआईएम) अग्रणी प्रबंधन संस्थानों का एक संघ है जो डॉक्टरेट और समकक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से वश्व स्तरीय प्रबंधन शक्षा और अनुसंधान गति व धयों की पेशकश करता है।

10. इरास्मस मुंडस: आईआईएफटी "वैश्वीकरण और यूरोपीय एकीकरण का अर्थशास्त्र (ईजीईआई)" पर मास्टर कार्यक्रम के लए एसो सएट पार्टनर बन गया है।

कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम

कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों और व्यापार नीति पर उनके प्रभावों की व्यापक समझ को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों/बैंकों और सरकारी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) का कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम प्रभाग (ईएमपीडी) पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करता है। यह युवा पेशेवरों और मध्यम-स्तरीय वरिष्ठ प्रबंधकों को अत्याधुनिक ज्ञान और उद्योग की अंतर्दृष्टि से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1. ईएमपी प्रभाग द्वारा कार्यक्रमों का संचालन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सप्ताहांत में निम्नलिखित कार्यकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम एवं अवधि	छात्रों की संख्या
1	ईपीजीडी-जीएचआरएम (डब्ल्यूई-ओसी) 2023-25 : 18 महीने	14
2	ईपीजीडीआईबी-ग्रीष्मकालीन (डब्ल्यूई-ओसी) 2023-25 : 18 महीने	97
3	ईपीजीडीआईबी-शीतकालीन 2024-25: 18 महीने	42
4	पीजीसीएम (आईबी) 2025-25: 12 महीने - मार्च 2025 में प्रारंभ	15

2 अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू अध्ययन दौरा/बंदरगाह दौरा - सफलतापूर्वक आयोजित

(i) एंटवर्प, बेल्जियम (5-8 नवंबर 2024): ईपीजीडीआईबी-ग्रीष्मकालीन 2023-25 बैच के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार संचालन पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें 31 प्रतिभागी और 1 संकाय सदस्य शामिल थे। यह प्रशिक्षण एंटवर्प/फ़्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर (एपीईसी) में 5 से 8 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया।

(ii) वियतनाम, (9 से 12 नवंबर 2024): (वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ईपीजीडी-जीएचआरएम) 2023-25 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ईपीजीडीआईबी-ग्रीष्म 2023-25)। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में 33 छात्रों और 1 संकाय सदस्य के एक समूह के लिए सफलतापूर्वक अध्ययन दौरा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण पूर्वी एशिया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ईएयूटी), नाम तू लिएम, हनोई, वियतनाम द्वारा 9 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में निम्नलिखित स्थानों का दौरा भी शामिल था।

(iii) विजाग, भारत, (11 से 12 नवंबर 2024): ईपीजीडीआईबी-ग्रीष्म 2023-25 बैच के लिए 11 से 12 नवंबर 2024 के दौरान 28 प्रतिभागियों के साथ विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड और वीसीटी- कंटेनर फ्रेट स्टेशन, विजाग का घरेलू बंदरगाह दौरा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

उपरोक्त सभी दौरे और प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिससे प्रतिभागियों को विभिन्न देशों और उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार संचालन और मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।

3. व्याख्यान: POSH

ईएमपी प्रभाग ने 7 दिसंबर, 2024 को ईएमपी प्रभाग के कार्यकारी कार्यक्रमों के छात्रों के लिए "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) और लैंगिक संवेदनशीलता" विषय पर एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसके अतिरिक्त,

एम.ए. अर्थशास्त्र कार्यक्रम के छात्रों ने भी कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में कुल 139 छात्रों ने भाग लिया और छात्रों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

व्याख्यान: "मार्केटिंग टेक्नोलॉजी (मार-टेक)"

ईएमपी प्रभाग द्वारा 2 फ़रवरी, 2025 को कार्यकारी बैच के सभी छात्रों के लिए "मार्केटिंग टेक्नोलॉजी (मार-टेक)" पर एक विशेष व्याख्यान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह व्याख्यान सीवेंट इंडिया के उपाध्यक्ष एवं मार्केटिंग प्रमुख श्री संदीप नागपाल द्वारा दिया गया।

आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल क्षमता विकास: कंपनियों को लाभदायक बनाने का रोडमैप विषय पर व्याख्यान

ईएमपी प्रभाग द्वारा 22 फरवरी 2025 को कार्यकारी बैच के सभी छात्रों के लिए "आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल क्षमता विकास: कंपनियों को लाभदायक बनाने का रोडमैप" विषय पर एक विशेष व्याख्यान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह व्याख्यान मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष, श्री शैलेंद्र सिंह द्वारा दिया गया।

आईआईएफटी और एपेक के बीच समझौता ज्ञापन

भारत सरकार के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद और फ़्लैंडर्स सरकार के राष्ट्रपति एवं फ़्लैंडर्स के अर्थव्यवस्था, नवाचार एवं उद्योग, विदेश मामले, डिजिटलीकरण एवं सुविधा प्रबंधन मंत्री, महामहिम श्री मथायस डिपेंडेले की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईआईएफटी और एपेक - एंटवर्प/फ़्लैंडर्स पोर्ट, बेल्जियम के बीच समझौता ज्ञापन, 3 मार्च, 2025 को वाणिज्य भवन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संपन्न हुआ।

12 महीने के स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (पीजीसीएम-आईबी) का शुभारंभ:

पीजीसीएम (आईबी) 2025-26 के पहले बैच का उद्घाटन 28 मार्च, 2025 (शुक्रवार) को सफलतापूर्वक दिल्ली परिसर में 17 प्रतिभागियों के साथ हुआ। डॉ. विश्वजीत नाग, प्रमुख (ईएमपीडी) द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया, जिसके बाद आईआईएफटी के माननीय कुलपति, प्रो. राकेश मोहन जोशी ने विशेष भाषण दिया।

आईआईएफटी में उत्कृष्टता केंद्र

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र

संस्थान में स्थित विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र, व्यापार नीति में रुचि रखने वाली शोध करने वाली एक इकाई है, जो व्यापार वार्ताओं से संबंधित ज्ञान और दस्तावेज़ीकरण के एक स्थायी भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा, व्यापार नीति में भी रुचि रखती है। भारत सरकार द्वारा इसे नियमित रूप से अनुसंधान करने और स्वतंत्र विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करने के लिए कहा जाता रहा है ताकि विश्व व्यापार संगठन और अन्य मंचों, जैसे मुक्त एवं अधिमान्य व्यापार समझौते (एफटीए/पीटीए) और व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) में, अपनी विभिन्न व्यापार वार्ताओं में अपनी स्थिति विकसित करने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, केंद्र अपने आउटरीच और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके उद्योग और सरकारी इकाइयों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क स्थापित कर रहा है, जिससे हितधारकों और नीति-निर्माताओं के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर रहा है।

डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का उद्देश्य निम्नलिखित पांच व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करना है - (i) अनुसंधान और विभिन्न सहायक गतिविधियों के माध्यम से डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं और नियमित डब्ल्यूटीओ कार्य कार्यक्रम में प्रभावी रूप से भाग लेने में भारत के व्यापार वार्ताकारों और नीति निर्माताओं की सहायता करना; (ii) एफटीए और अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं में प्रभावी रूप से भाग लेने में भारत के व्यापार वार्ताकारों और नीति निर्माताओं की सहायता करना; (iii) डीओसी अधिकारियों के बीच उभरते व्यापार मुद्दों की समझ को बढ़ाना; (iv) आउटरीच और प्रसार गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच प्रमुख व्यापार मुद्दों की समझ को बढ़ाना; (v) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से डब्ल्यूटीओ और अन्य व्यापार-संबंधी मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए भारत और अन्य विकासशील देशों में क्षमता विकसित करना; और (vi) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ पहलुओं पर वैश्विक आख्यान को प्रभावित करने का प्रयास करना।

2023-24 के दौरान, केंद्र ने वाणिज्य विभाग और सरकार के अन्य हितधारकों/विभागों को विश्लेषण और परामर्श प्रदान किए। संकायों और कर्मचारियों ने विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर 100 से अधिक संक्षिप्त नोट्स और अन्य तकनीकी प्रकाशन प्रकाशित किए। सीडब्ल्यूएस के संकाय और शोधकर्ता नौ एफटीए वार्ताओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों का सहयोग किया। इसमें कई आंतरिक पृष्ठभूमि नोट्स, नीतिगत संक्षिप्त विवरण और अर्थव्यवस्थाओं एवं क्षेत्रों का मात्रात्मक विश्लेषण तैयार करना शामिल था। इस अवधि के दौरान सीडब्ल्यूएस ने 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और बैठकें आयोजित कीं; और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 25 घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों, हितधारक बैठकों आदि के आयोजन में शामिल रहा। निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाना आवश्यक है:

- विकासशील देशों के 89 अधिकारियों और अन्य प्रतिभागियों ने विदेश मंत्रालय के आईटीईसी के तत्वावधान में आयोजित तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।
- सीडब्ल्यूएस ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे और लखनऊ में भारत के मुक्त व्यापार समझौतों पर पाँच उद्योग हितधारक परामर्श आयोजित किए।
- केंद्र ने 22-26 मई 2023 के दौरान नेपाल के मंत्रालय के अधिकारियों के लिए काठमांडू में एक परिचयात्मक स्तर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नीति कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद दिसंबर 2023 में सप्ताह भर चलने वाले दो उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।
- विश्व व्यापार संस्थान (बर्न) के साथ साझेदारी में, केंद्र ने 5-30 जून 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और नीति पर डब्ल्यूटीआई-सीडब्ल्यूएस संयुक्त अकादमी का आयोजन किया।
- सीडब्ल्यूएस ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से 27 अप्रैल 2023 को व्यापार समझौतों से उभरते अवसर - उद्योग परिप्रेक्ष्य पर एक क्षमता निर्माण सत्र का आयोजन किया।
- सीडब्ल्यूएस ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से 16 जून 2023 को व्यापार सुविधा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 200 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

- यूएई सरकार के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो अबू धाबी, यूएई में आयोजित डब्ल्यूटीओ एमसी13 के बाद की तैयारी में उनकी मदद करेगा।
- भूटान की शाही सरकार के 25 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो थिम्पू, भूटान और नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूटीओ परिग्रहण के लिए उन्हें तैयार करेगा।
- जून 2023 में आईएएस परिवीक्षार्थियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, नई दिल्ली
- मार्च 2023 में डीओसी अधिकारियों के लिए ट्रेड नेगोशिएशन कोर्स, नई दिल्ली
67

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) को आईआईएफटी के दो केंद्रों, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र और व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र, के संयुक्त आवेदन के आधार पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अध्यक्ष कार्यक्रम (डब्ल्यूसीपी) के तीसरे चरण में भारत अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डब्ल्यूटीओ अध्यक्ष कार्यक्रम 2010 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा की जाने वाली व्यापार संबंधी शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित और समर्थन देकर विकासशील और अल्पविकसित देशों के शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं के बीच ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना और बढ़ाना है। डब्ल्यूसीपी गतिविधियों के एक भाग के रूप में, केंद्र ने भारत के व्यापार और निवेश विधि शिक्षाविदों के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विधि मुद्दों में शिक्षण-शिक्षाशास्त्र' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्घाटन अगस्त 2022 में आईआईएफटी परिसर में किया गया। पहली कार्यशाला 10 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून में पद्धतिगत मुद्दे: दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य का एकीकरण विषय पर एक अन्य कार्यशाला दिसंबर 2022 में केरल में आयोजित की गई।

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र, 1995 से 2021 तक 164 सदस्यों द्वारा विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित स्वच्छता, पादप स्वच्छता और व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं संबंधी उपायों पर एक अनूठा ऑनलाइन डेटाबेस रखता है। ये दोनों डेटाबेस 66,000 से अधिक अधिसूचनाओं में से 100 प्रतिशत के लिए अत्यंत आवश्यक व्यापार लिंक (HSN) प्रदान करते हैं। ये किसी भी उपयोगकर्ता के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं और वेब लिंक इस प्रकार हैं: एसपीएस ऑनलाइन डेटाबेस: https://cc.iift.ac.in/sps/index.asp; टीबीटी ऑनलाइन डेटाबेस: https://cc.iift.ac.in/tbt/index.asp.

भारत सरकार द्वारा की जा रही द्विपक्षीय वार्ताओं के मद्देनजर, सीडब्ल्यूएस वाणिज्य विभाग (डीओसी) को भारत-यूके, भारत-ऑस्ट्रेलिया, भारत-ईयू, भारत-पेरू, भारत-ओमान, भारत ईएईयू, भारत-ईपीटीए सहित कई व्यापार वार्ताओं के लिए तकनीकी, आर्थिक और कानूनी सहायता प्रदान करता रहा है। इन सभी वार्ताओं में, केंद्र ने सरकारी खरीद, उत्पत्ति के नियम, एसपीएस और टीबीटी, कृषि, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, माल, मत्स्य पालन, डिजिटल व्यापार और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान की है।

व्यापार एवं निवेश कानून विधि केंद्र (CTIL)

व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र (CTIL) की स्थापना वर्ष 2017 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के अंतर्गत की गई थी। केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संबंधित मंत्रालयों एवं सरकारी एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश विधि एवं नीति से संबंधित कानूनी मुद्दों का ठोस एवं गहन विश्लेषण प्रदान करना है। CTIL व्यापार एवं निवेश विधि संबंधी सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसके पास व्यापक संसाधन उपलब्ध हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विधि संबंधी मुद्दों पर उभरते विमर्श में भाग लेने और उसे प्रभावित करने के लिए भारत में एक अग्रणी मंच के रूप में भी कार्य करता है।

सीटीआईएल विश्व व्यापार संगठन के विवादों, एफटीए वार्ताओं और औद्योगिक नीति के मामलों सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून के मुद्दों पर भारत सरकार को लगातार तकनीकी जानकारी प्रदान करता रहा है। अपनी स्थापना के बाद से, केंद्र द्वारा वाणिज्य विभाग को महत्वपूर्ण व्यापार मुद्दों पर 850 से अधिक सलाहकार राय प्रदान की गई हैं, जिनमें भारत की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत व्यापार संवर्धन योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की व्याख्या और विश्लेषण, भारत को उसकी चल रही व्यापार वार्ताओं में सहायता के लिए अनुसंधान और जानकारी प्रदान करना, यूरोपीय संघ के व्यापार संबंधी स्थिरता उपाय, सेवाओं में घरेलू विनियमन, ई-कॉमर्स नीति, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कराधान के मामले, रॉयल्टी का अधिरोपण, और भारत की व्यापार प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करने वाले घरेलू कानूनों का विकास शामिल हैं।

सीटीआईएल ने एक व्यापार उपचार सलाहकार प्रकोष्ठ (टीआरएसी) की भी स्थापना की है, जिसका उद्देश्य आवेदन तैयार करने, प्रासंगिक जानकारी या डेटा एकत्र करने और व्यापार उपचार महानिदेशालय के समक्ष व्यापार उपचारात्मक जाँच के लिए कानूनी

सलाह प्रदान करने में घरेलू उद्योग को समग्र सहायता प्रदान करना है। टीआरएसी अपनी सलाहकार सेवाएं इस उद्देश्य से प्रदान करता है कि भारत में एमएसएमई निर्माता वित्तीय प्रभाव के बिना व्यापार सुधारात्मक उपायों का लाभ उठा सकें।
सीटीआईएल ने अपनी वैश्विक भागीदारी और नीतिगत प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारियों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। इसने सहयोगी पहलों को बढ़ावा देने और उद्योग-अकादमिक-नीति संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, सीटीआईएल ने संयुक्त अनुसंधान, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के मुद्दों पर गहन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन और ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (आईएचईआईडी), जिनेवा के साथ सहयोग किया।

सीटीआईएल प्रतिष्ठित डब्ल्यूटीओ चेयर प्रोग्राम (डब्ल्यूसीपी) भी चलाता है, जिसमें सीडब्ल्यूएस डब्ल्यूसीपी इंडिया चेयर (आईआईएफटी) के अधीन है और सीटीआईएल प्रमुख भारत के अध्यक्ष हैं। इंडिया चेयर डब्ल्यूसीपी के तत्वावधान में तीन स्तंभों के तहत गतिविधियों का संचालन कर रहा है:

अपने अधिदेश के एक भाग के रूप में, सीटीआईएल भारत के राष्ट्रीय विधि विद्यालयों और अन्य अग्रणी संस्थानों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विधि के क्षेत्र में उनकी क्षमता का गहन विकास करता है। सीटीआईएल राष्ट्रीय विधि विद्यालयों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यापार एवं निवेश कानून पर गैर-क्रेडिट और क्रेडिट पाठ्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार, चर्चाएँ जैसे संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने और छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विधि के मूलभूत कानूनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार सहयोग करता रहा है। सीटीआईएल में, हम नैदानिक कानूनी शिक्षा के महत्व को समझते हैं और इसलिए, केंद्र भारत के विभिन्न राष्ट्रीय विधि विद्यालयों और अन्य प्रमुख संस्थानों में ट्रेडलैब (जिनेवा) विधि क्लीनिक आयोजित करता रहा है।

किए गए प्रमुख अध्ययन
अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान

व्यावसायिक सेवाओं पर नीति आयोग के लिए अध्ययन:

व्यावसायिक सेवाएँ भारत के लिए निर्यात हित का एक प्रमुख क्षेत्र होने के नाते, यह अध्ययन व्यापार सुगमता सुधारों के एक भाग के रूप में भारतीय नियामक ढाँचे में सुधारों के लिए व्यावहारिक कदमों का प्रस्ताव करता है और व्यावसायिक सेवाओं में भारतीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं की निर्यात क्षमता का निर्माण भी करता है। यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी विचार करता है और भारतीय संदर्भ के लिए अधिक उपयुक्त सरल एवं व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का प्रभाव आकलन अध्ययन:

यह अध्ययन सीटीआईएल द्वारा प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के सहयोग से किया गया था। लौह एवं इस्पात तथा एल्युमीनियम क्षेत्रों पर केंद्रित, यह अध्ययन यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन विनियमन से भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन सीबीएएम के चरणबद्ध कार्यान्वयन के आधार पर प्रभाव पर प्रकाश डालता है और 2034 तक सीबीएएम के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद, विशेष रूप से लौह एवं इस्पात क्षेत्र में, सीबीएएम से आच्छादित उत्पादों के पहुँच मूल्य का अनुमान प्रदान करता है।

भारत की सरकारी खरीद व्यवस्था और अन्य देशों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों से संबंधित अध्ययन:

"भारत की सरकारी खरीद व्यवस्था और अन्य देशों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों" पर अध्ययन, आर्थिक कानून प्रथाओं द्वारा व्यापार और निवेश कानून केंद्र के सहयोग से, विश्व व्यापार संगठन अध्यक्ष कार्यक्रम के लिए शोध कार्य के एक भाग के रूप में किया गया था। यह अध्ययन केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी खरीद के लिए भारत के घरेलू कानूनी ढांचे का विश्लेषण प्रदान करता है, और चुनिंदा देशों - यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया - के खरीद बाजारों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के सामने आने वाली संभावित बाजार पहुँच बाधाओं की भी पहचान करता है। अध्ययन कुछ सिफारिशों के साथ समाप्त होता है, जिनमें घरेलू स्तर पर एक एकीकृत खरीद कानून बनाने, खरीद प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों को संस्थागत बनाने की आवश्यकता, आदि शामिल हैं।

भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत औद्योगिक/निर्मित वस्तुओं के लिए भौगोलिक संकेतकों के अनुप्रयोग और कवरेज पर एक अध्ययन:

इसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि भारत के 14 हस्ताक्षरित और 12 मौजूदा एफटीए भौगोलिक संकेतकों (जीआई) को कैसे संबोधित करते हैं और क्या वे कृषि वस्तुओं से परे, विशेष रूप से औद्योगिक जीआई के लिए, सुरक्षा का विस्तार करने के साधन के रूप में काम कर सकते हैं। इसका उद्देश्य उन संभावित औद्योगिक उत्पादों की पहचान करना है जिन्हें जीआई सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और उन्हें विशिष्ट हार्मोनाइज्ड सिस्टम नामकरण (एचएसएन) कोड दिए जा सकते हैं ताकि उनकी व्यापार मान्यता को सुगम बनाया जा सके।

यूरोपीय संघ के वन-कटान विनियमन में संशोधनों का अध्ययन:

यह अध्ययन यूरोपीय संघ के वन-कटान विनियमन (ईयूडीआर) की अनुपालन आवश्यकताओं की जाँच करता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि क्या भारतीय कानून भारतीय निर्यातकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं। यह ईयूडीआर की विश्व व्यापार संगठन के कानून के साथ संगति की भी जाँच करता है और विश्व व्यापार संगठन में विवाद शुरू करने के संभावित दावों पर प्रकाश डालता है।

यूरोपीय संघ के हरित दावा निर्देश पर अध्ययन:

यह अध्ययन विश्वसनीय और सत्यापन योग्य दावों को स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ के हरित दावा निर्देश के तहत आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। यह उपभोक्ताओं को ग्रीनवाशिंग से रोकने के लिए संबंधित भारतीय कानून का भी मानचित्रण करता है।

यूरोपीय संघ का अपशिष्ट शिपमेंट विनियमन:

यह अध्ययन यूरोपीय संघ के अपशिष्ट शिपमेंट विनियमन के अंतर्गत आवश्यकताओं की जाँच करेगा और इस बात पर प्रकाश डालेगा कि क्या अपशिष्ट प्रसंस्करण पर वर्तमान भारतीय घरेलू कानून, यूरोपीय संघ द्वारा भारत को गैर-खतरनाक अपशिष्ट निर्यात जारी रखने के लिए विनियमन के अंतर्गत अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त हैं।

अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान व्यापार और निवेश कानून केंद्र द्वारा किया गया शोध

क्र. सं.	कार्यभार
1.	इस बात का विश्लेषण कि क्या भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते को GATT के अनुच्छेद XXIV या सक्षमकारी खंड के तहत स्थापित किया जाना चाहिए
2.	लघु मत्स्य पालन का विश्लेषण
3.	डिजिटल व्यापार के मापन पर विश्व व्यापार संगठन-अंकटाड हैंडबुक पर टिप्पणी
4.	आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या NSEZO/R/T/24/00002 का उत्तर
5.	187वीं स्थायी समिति की रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों पर राय
6.	भारत-ईएईयू व्यापार समझौते के संदर्भ की शर्तों पर इनपुट
7.	वाईपी/सहयोगी/परामर्शदाताओं के लिए दिशानिर्देशों में प्रतिभा प्रतिधारण पर प्रावधानों/अनुच्छेदों पर इनपुट
8.	एईओ पर एमआरए के लिए ब्रिक्स के बीच संयुक्त कार्य योजना पर इनपुट
9.	यूरोपीय संघ एफटीए में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए समान परिभाषा पर इनपुट
10.	भारत-यूरोपीय संघ एफटीए टीएसडी अध्याय में निवेश संदर्भों पर राय

11.	कुछ प्रोत्साहनों की विश्व व्यापार संगठन अनुकूलता के आकलन पर टिप्पणी
12.	सेवाओं के डीआर परिणामों पर जेएसआई के आलोक में ऑस्ट्रेलिया के प्रमाणन अनुरोध पर राय और ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित पत्र जिसमें समझौते शामिल हैं
13.	ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 14वीं बैठक की संयुक्त घोषणा पर टिप्पणियाँ
14.	एसपीएस समझौते की छठी समीक्षा पर बेलीज के प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ
15.	विश्लेषण W278 पाठ
16.	प्रवासी रोज़गार शुल्क
17.	भारत और AFCFTA के बीच समझौता ज्ञापन
18.	भारत और AFCFTA (डिजिटल व्यापार) के बीच समझौता ज्ञापन
19.	अमेरिकी E1 और E2 वीज़ा के लिए भारत का 'संधि देश' का दर्जा
20.	व्यापार और निवेश पर राष्ट्रमंडल कार्य समूह की प्रस्तावित कार्य योजना - 2024-2026 पर टिप्पणियाँ
21.	कृषि पर ब्राज़ील संचार पर राय
22.	बंदरगाह राज्यों के उपायों पर समझौते के अनुपालन हेतु भारतीय नियामक व्यवस्था का मूल्यांकन
23.	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते के प्रारूपण दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ
24.	पूर्व अधिसूचना में शामिल राज्यों का मानचित्रण और एससीएम समझौते के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना
25.	अनुच्छेद 25 एससीएम समझौते के आधार पर सब्सिडी का मानचित्रण, 2022 के लिए भारत अधिसूचना
26.	एससीएम समझौते के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रारूप 2024 अधिसूचना में नई सब्सिडी, 2022 अधिसूचना की तुलना में
27.	2024 से प्राप्त जानकारी और 2022 में अधिसूचित सब्सिडी के आधार पर सब्सिडी की सूची
28.	यूएसएनओएए द्वारा सूचना संग्रहण हेतु प्रारूप अधिसूचना पर टिप्पणियाँ
29.	डब्ल्यूटीओ में संयुक्त वक्तव्य पहल (जेएसआई) पर गैर-पत्र: आगे भारत की स्थिति
30.	ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने गैट्स कार्यक्रम में प्रस्तावित संशोधन पर ऑस्ट्रेलिया के साथ मध्यस्थता की मांग के संबंध में प्रश्न, जिसमें डीआर विषयों पर जेएसआई को एकीकृत करने की मांग की गई है
31.	आईएफडी एमएफएन प्रावधान के संबंध में प्रश्न
32.	के संचालन पर कानूनी राय नवीनतम जेएसआई ई-कॉमर्स पाठ
33.	आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौता निकायों के लिए संदर्भ की शर्तों पर भारत के इनपुट
34.	मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के लिए अध्यक्ष के नवीनतम पाठ के अंतर्गत सीबीडीआर-आरसी पर भारत की स्थिति
35.	यूके सीबीएएम, विश्व व्यापार संगठन में ब्रिटेन के राजदूत का पत्र
36.	क्षेत्र की परिभाषा पर ध्यान दें
37.	भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) से संबंधित राज्य स्तरीय नीतियाँ और कानून
38.	वर्तमान में लागू PLI योजनाओं का विश्लेषण
39.	ब्रिक्स संघ के ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय अनाज व्यापार मंच स्थापित करने के रूस के प्रस्ताव पर राय
40.	जेएसआई ई-कॉमर्स ड्राफ्ट अध्यक्ष के पाठ पर टिप्पणियाँ - 6 मई 2024
41.	कृषि मंत्रियों की 14वीं ब्रिक्स बैठक पर टिप्पणियाँ
42.	भारत-चिली में वित्तीय सेवाओं के लिए टीओआर के फुटनोट की संशोधित भाषा पर राय
43.	स्तंभ II - IV पर आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय वक्तव्य पर टिप्पणियाँ (सिंगापुर जून 2024)

44.	आरवीसी (नेट ज़ीरो इंडस्ट्रीज) पर भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी डब्ल्यूजी3 नॉन-पेपर्स पर इनपुट
45.	पीएमओ के समक्ष एफटीए वार्ता के लिए सरकारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर वाणिज्य सचिव के लिए चर्चा के बिंदु
46.	आईपीईएफ पी2 संदर्भ की शर्तों पर भारत की स्थिति पर टिप्पणियाँ
47.	हीरे के व्यापार पर जी7 प्रतिबंधों की डब्ल्यूटीओ संगति
48.	भारत सीपीटीपीपी में क्यों शामिल नहीं हुआ, इस पर राय
49.	श्रम मानकों की चिंताओं के संबंध में ऑस्ट्रेलिया की संसदीय रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते में
50.	TEPA के श्रम प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण
51.	संयुक्त राज्य अमेरिका के उन्नत स्वच्छ ऊर्जा (क्रिटिकल मैटीरियल ट्रेस) विधेयक 2024 की महत्वपूर्ण सामग्री पारदर्शिता और रिपोर्टिंग का विश्लेषण
52.	यूरोपीय संघ द्वारा अपने इस्पात सुरक्षा उपायों के प्रस्तावित विस्तार पर इनपुट
53.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य पर इनपुट
54.	कृषि में व्यापार सुगमता पर ब्रिक्स सिद्धांतों पर इनपुट
55.	इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य पर इनपुट
56.	अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर इनपुट
57.	जीडीपीआर के तहत यूरोपीय संघ की डेटा पर्याप्तता स्थिति पर इनपुट
58.	प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के बीच नए शामिल ब्रिक्स देशों के लिए समझौता ज्ञापन के विस्तार के संबंध में इनपुट
59.	ट्रेसेबिलिटी और ट्रैकेबिलिटी पर नोट
60.	इराक के प्रवेश पर टिप्पणियाँ
61.	चीन के विकास पत्र पर टिप्पणियाँ
62.	रूस के GATS अनुसूची के प्रमाणन से संबंधित टिप्पणियाँ
63.	CBAM विवाद शुरू करने के लिए कानूनी फर्मों को नियुक्त करने हेतु संदर्भ की शर्तें
64.	व्यापार संबंधी सतत विकास उपायों के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए G20 सिद्धांतों के पहले मसौदे पर टिप्पणियाँ
65.	यूरोपीय संघ योग्यता - TiS
66.	एस/एल/80 के अंतर्गत मध्यस्थों के चयन पर टिप्पणियाँ
67.	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणियाँ
68.	प्रस्तावित मध्यस्थों की रूपरेखा-पीएमआई
69.	ट्रिप्स परिषद के मसौदा एजेंडे पर टिप्पणियाँ
70.	डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 269/2024 - एग्रोस्टोस थियोस बनाम यूओआई एवं अन्य में एसपीएस-संबंधित अनुच्छेदों पर टिप्पणियाँ।
71.	पीई प्रस्तावना अंतरसत्र सीटीआईएल टिप्पणियाँ
72.	भारत में मान्यता भाषा के संचालन पर पाठ्य सामग्री - यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
73.	भारत में श्रम बाजार पहुँच पर पाठ्य सामग्री - यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
74.	एफएसआर और नेट ज़ीरो उद्योग अधिनियम पर जानकारी

75.	भारत में श्रम बाज़ार पहुँच के विशिष्ट तत्वों पर डीओसी के प्रस्तावित आगे के मार्ग पर टिप्पणियाँ - यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
76.	सेवाओं में व्यापार और प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही अध्याय के लिए प्रस्तावित पाठ पर टिप्पणियाँ
77.	आईपीआर अध्याय के अंतर्गत प्रवर्तन दायित्वों से संबंधित यूरोपीय संघ के पाठ पर टिप्पणियाँ
78.	ईआरएम अध्याय और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता के अन्य अध्यायों में प्रस्तावित तत्वों के बीच ओवरलैप पर टिप्पणी।
79.	यूरोपीय संघ-भारत ईआरएम के लिए चर्चा के बिंदु
80.	भारत के एफटीए में महत्वपूर्ण खनिज ट्रैक की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी
81.	इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर प्रस्तावित पाठ पर टिप्पणियाँ - यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता
82.	कौशल और गतिशीलता पर प्रस्तावित पाठ पर टिप्पणियाँ - यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता
83.	ईआरएम अध्याय पर डीएस अध्याय का अनुप्रयोग
84.	यूरोपीय संघ संशोधित अपशिष्ट शिपमेंट विनियमन पर टिप्पणी
85.	एसएसीयू संदर्भ की शर्तों पर टिप्पणियाँ
86.	स्तंभ IV समझौते के फुटनोट 9 का विश्लेषण
87.	आईपीईएफ जून मंत्रिस्तरीय वक्तव्य पर टिप्पणियाँ
88.	भारत-यूएई सीईपीए के अनुच्छेद 2.4 पर टिप्पणियाँ
89.	मूल्य सीमा तंत्र और प्रयुक्त वस्तुओं पर टिप्पणी
90.	भारत-चिली सीईपीए के लिए संदर्भ की शर्तों में लंबित मुद्दों पर टिप्पणियाँ
91.	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता - पारदर्शिता पर अध्याय के क्षैतिज अनुप्रयोग से उत्पन्न मुद्दों पर टिप्पणी
92.	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते के सहयोग अध्याय में चुनिंदा प्रावधानों पर टिप्पणी
93.	यूके-भारत एफटीए दूरसंचार पाठ पर दूरसंचार विभाग की चिंताओं पर टिप्पणी
94.	राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) पर संक्षिप्त टिप्पणी (आईएन-एयूएस सीईसीए का ट्रैक)
95.	कृषि और पशुपालन प्रौद्योगिकी पर पृष्ठभूमि टिप्पणी (आईएसीईसीए का ट्रैक)
96.	खरीद प्रक्रिया से उत्पन्न शिकायतों की घरेलू समीक्षा के लिए भारत की कानूनी व्यवस्था पर नोट।
97.	जन विश्वास अधिनियम, 2023 के अनुसरण में चाय बोर्ड, प्रजाति बोर्ड और रबर बोर्ड से प्राप्त मसौदा नियमों की समीक्षा।
98.	स्थिति - मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता - बौद्धिक संपदा, भौगोलिक संकेत, नवाचार और प्रौद्योगिकी
99.	पीएम-आशा से संबंधित डीसीएन पर राय
100.	अनुच्छेद 25 एससीएम समझौते के तहत भारत की अधिसूचना के लिए कुछ राज्य योजनाओं की डब्ल्यूटीओ अनुकूलता का आकलन और चयनित योजनाओं की समीक्षा
101.	डेटा उपयोग लेख के निर्माण पर राय
102.	एफटीए में भारत के सामने आने वाले एसपीएस मुद्दों पर टिप्पणी
103.	रिट याचिका पर टिप्पणी
104.	डीएस सुधार: पारस्परिक प्रतिशोध पर कोलंबियाई प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ
105.	डीएस सुधार: पारस्परिक प्रतिशोध पर कोलंबियाई प्रस्ताव पर चर्चा के बिंदुओं पर टिप्पणियाँ
106.	थियाक्लोप्रिड पर यूरोपीय संघ के मसौदा विनियमन पर टिप्पणियाँ
107.	मध्यस्थों की नई सूची-एस/एल/80
108.	मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते के तहत अधिसूचना टेम्पलेट्स पर टिप्पणियाँ
109.	10-11 जुलाई को ट्रिप्स परिषद की बैठक के लिए भारत की स्थिति और एजेंडा पर इनपुट 2024
110.	यूनाइटेड किंगडम स्टील सुरक्षा उपाय पर राय
111.	आईआईडीएम भोपाल पर टिप्पणियाँ - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) की योजना के लिए

	तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने हेतु रिपोर्ट
112.	भारतीय ध्वजवाहक पोत द्वारा उच्च समुद्र में पकड़ी गई मछलियों की उत्पत्ति का निर्धारण
113.	मत्स्य पालन से संबंधित जी20 कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) मंत्रिस्तरीय घोषणा के मसौदे के प्रासंगिक अनुच्छेदों पर इनपुट
114.	शुद्ध शून्य उद्योग अधिनियम
115.	संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मसौदे पर खान मंत्रालय द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर टिप्पणियाँ
116.	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद और दोहा, आभूषण एवं घड़ियाँ आयोजन समिति के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे पर टिप्पणियाँ
117.	चर्चा का अभिलेख - लघु समूह बैठक पर अतिरिक्त प्रावधान - दूसरा समूह - दोपहर 2:30 बजे (आईएसटी) सत्र
118.	चर्चा का अभिलेख - लघु समूह बैठक पर अतिरिक्त प्रावधान - तीसरा समूह - शाम 6:30 बजे (आईएसटी) सत्र
119.	ईयूडीआर पर जाँच बिंदु
120.	समझौता ज्ञापन के मसौदे पर संशोधित टिप्पणियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग पर (एमओयू)
121.	महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विस्तार और विविधता के लिए अमेरिका और भारत के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस)-भारत वाणिज्यिक वार्ता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी।
122.	कानूनी राय: इस बात की जाँच कि क्या डीआर परिणाम पर जेएसआई को शामिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने कार्यक्रम में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में डब्ल्यूटीओ विवाद शुरू करने का कोई कानूनी आधार मौजूद है।
123.	विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध 4 के अंतर्गत मत्स्य पालन सब्सिडी पर अतिरिक्त प्रावधानों को एक बहुपक्षीय समझौता बनाया जा सकता है या नहीं, इस पर सुझाव
124.	S/L/80 GATS प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यस्थता निकाय के गठन हेतु ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तावित विकल्पों पर सुझाव
125.	S/L/80 GATS प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यस्थता निकाय के गठन हेतु अतिरिक्त विकल्पों पर सुझाव
126.	चर्चा का अभिलेख - 24.07.2024 को सामान्य परिषद की बैठक
127.	भारत-ऑस्ट्रेलिया पारंपरिक चिकित्सा संबंधी पत्र
128.	EU TSD अध्याय का EU ERM अध्याय के साथ ओवरलैप
129.	S/L/80 JSI-DR मध्यस्थता में मध्यस्थता निकाय के गठन हेतु DoC द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर टिप्पणियाँ
130.	परिधान/वस्त्र, मेड-अप और वस्त्र सहायक उपकरणों के लिए PLI योजना हेतु संशोधित कैबिनेट नोट के मसौदे की WTO अनुकूलता पर राय
131.	FDI/IFD EU स्क्रीनिंग तंत्र
132.	FDI/IFD कनाडा स्क्रीनिंग तंत्र
133.	महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग पर अमेरिका के प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर प्रश्नों के उत्तर।
134.	अज़रबैजान का प्रवेश
135.	चीन से चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के बहिर्वाह के आंकड़े
136.	एफडीआई/आईएफडी यूएसए स्क्रीनिंग तंत्र
137.	व्यापार संवर्धन संगठनों के बीच एससीओ सहयोग पर सीटीआईएल इनपुट
138.	नए आर्थिक संवाद विकसित करने के लिए एससीओ सहयोग कार्यक्रम पर इनपुट
139.	एससीओ एमएस का आर्थिक वरीयता आधार बनाने के लिए एससीओ अवधारणा पर इनपुट
140.	रचनात्मक अर्थव्यवस्था विकास के लिए एससीओ ढांचे पर इनपुट
141.	घरेलू सार्वजनिक खरीद के अनुबंधों में मध्यस्थता और मध्यस्थता के लिए दिशानिर्देशों पर इनपुट
142.	विश्व बैंक की बी-रेडी हैंडबुक पर इनपुट
143.	अनुच्छेद 24.1 ईपीसी उपनियमों पर इनपुट
144.	आईपीईएफ स्तंभ IV पर इनपुट

145.	पारंपरिक चिकित्सा सेवा आपूर्तिकर्ताओं पर संशोधित अनुलग्नक पर टिप्पणियाँ
146.	आईएफडी समझौते के जीएटीएस के साथ इंटरफेस पर अनुवर्ती प्रश्न पर टिप्पणियाँ
147.	अनुच्छेद पर वैकल्पिक भाषा X.2 और X.7 - EU TSD
148.	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत के मसौदा अध्याय के लिए SMD ऊर्जा अनुशंसाओं पर नोट
149.	ऑस्ट्रेलिया-भारत ECTA तथ्यात्मक प्रस्तुति के संबंध में स्पष्टीकरण
150.	भारत-वियतनाम डिजिटल साझेदारी पर समझौता ज्ञापन के लिए प्रस्तावित तत्व और पाठ
151.	गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था और अमेरिकी एवं भारतीय कानून के तहत इसकी स्थिति पर टिप्पणी
152.	विश्व व्यापार संगठन में भूटान के प्रवेश पर भारत के प्रभाव पर टिप्पणी
153.	सेवाओं में व्यापार के परिप्रेक्ष्य से पारदर्शिता अध्याय पर टिप्पणियाँ
154.	LRAB - IPEF स्तंभ II के TOR पर इनपुट
155.	G20 सिद्धांतों पर टिप्पणियाँ
156.	अमेरिकी CHIPS अधिनियम पर टिप्पणी
157.	JSI-DR पर संक्षिप्त और प्रमुख तर्क
158.	DGTR नोट पर टिप्पणियाँ
159.	महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन के संबंध में अमेरिकी संपादनों पर टिप्पणियाँ
160.	पारस्परिक मान्यता समझौतों पर टिप्पणी
161.	अमेरिकी महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर
162.	SCM अधिसूचना पर मास्टर टेबल
163.	आसियान-भारत सेवा व्यापार समीक्षा और एक संयुक्त समिति की स्थापना पर टिप्पणियाँ
164.	COO जारी करने के लिए OCP की व्याख्या पर APTA नियम 4.1 पर इनपुट
165.	थियाक्लोप्रिड पर यूरोपीय संघ के मसौदा विनियमन पर भारत के STC पर यूरोपीय संघ से प्राप्त उत्तर पर टिप्पणियाँ
166.	जी20 सिद्धांतों पर टिप्पणियाँ (संबंधित संस्करण)
167.	अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर मसौदा समझौता ज्ञापन में गोपनीयता प्रावधान पर इनपुट
168.	कालीनों और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग के आयात पर इंडोनेशिया के सुरक्षा उपायों के जवाब में तुर्की द्वारा उपायों के निलंबन पर राय।
169.	तटस्थ तत्वों पर यूरोपीय संघ के आरओओ की राय
170.	अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर मसौदा समझौता ज्ञापन में भारत द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक गोपनीयता प्रावधान में अमेरिकी परिवर्धन पर इनपुट
171.	G20 महिला सशक्तिकरण में वार्ता के अधीन मंत्रिस्तरीय घोषणा के मसौदे पर टिप्पणियाँ
172.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिलाओं की प्राथमिकता पर G20 ब्राज़ील 2024 के मसौदा अनुच्छेद पर इनपुट
173.	IN-EU DS अध्याय पर टिप्पणियाँ (आठवें दौर के बाद का पाठ)
174.	DS अध्याय में ADR के लिए EU के समझौता प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ
175.	TiG, SOE और ERM अध्यायों में आयात और निर्यात एकाधिकार से संबंधित अतिव्यापी प्रावधानों पर कानूनी राय
176.	पारदर्शिता अध्याय पर TiG ट्रैक के लिए इनपुट
177.	TiS के अंतर्गत कार्यक्षेत्र और परिभाषा प्रावधानों पर इनपुट
178.	CS-DG बैठक - DS अध्याय के लिए वार्ता बिंदु इनपुट
179.	CS-DG बैठक - पारदर्शिता अध्याय के लिए वार्ता बिंदु इनपुट
180.	IN-EU पारदर्शिता अध्याय पर CTIL इनपुट
181.	यूरोपीय संघ पारदर्शिता अध्याय पर यूरोपीय संघ एसपीएस अध्याय के अंतर्गत संबंधित दायित्वों के संबंध में टिप्पणियाँ

182.	घरेलू उद्योग पर एआईटीआईजीए के प्रभाव पर टिप्पणी
183.	आईएन-एसएल टीआईएस पर राय
184.	सेवा सब्सिडी के लिए भाषा विकल्पों सहित टिप्पणी
185.	पीपीपी-एमआईआई आदेश संशोधन पर टिप्पणियाँ
186.	आसियान एससीएलआईआई - मानचित्रण तालिका
187.	यूरोपीय संघ आरक्षणों की रैंकिंग और विश्लेषण
188.	निर्माण सेवाओं में संभावित लाभों का विश्लेषण
189.	वित्तीय सेवाओं में संभावित लाभों का विश्लेषण
190.	स्वास्थ्य और पर्यटन सेवाओं में संभावित लाभों का विश्लेषण
191.	भारत मलेशिया सीईसीए के दूरसंचार पर सेवा व्यापार अध्याय और अनुलग्नक की समीक्षा
192.	भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए जीपी अध्याय के लिए वैकल्पिक भाषा सूत्रीकरण
193.	"सामान्य समीक्षा" लेख में ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियाँ
194.	आईपीईएफ पर पीएमओ द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर
195.	आईपीईएफ स्तंभ IV के अंतर्गत विदेशी रिश्वत दायित्वों पर टिप्पणी
196.	अंतरिम समीक्षा के दायरे पर अनौपचारिक प्रस्ताव पर राय
197.	एफटीडीआर अधिनियम 1992 में नए अध्याय के प्रस्तावित परिचय पर राय
198.	एपीआई पर भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी गैर-पत्र पर इनपुट
199.	आईपीईएफ पृष्ठ 4 पर लेख की समीक्षा
200.	रुचिरा शुक्ला द्वारा भारत की स्वच्छ अर्थव्यवस्था और जलवायु प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश को उत्प्रेरित करने में आईपीईएफ स्तंभ II और स्तंभ III की भूमिका पर लेख की समीक्षा
201.	जीटीआरआई द्वारा आईपीईएफ स्तंभ IV के संबंध में टिप्पणी के लिए प्रेस संक्षिप्त समीक्षा
202.	"कम राख धातुकर्म कोक" के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध के रूप में सुरक्षा उपाय लागू करने हेतु व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मांगे गए इनपुट।
203.	दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए एकीकृत पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पर टिप्पणी
204.	16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 'शून्य मसौदा कज़ान घोषणापत्र' के अनुच्छेद 68 पर इनपुट और वैकल्पिक सूत्रीकरण
205.	भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी डब्ल्यूजी3 (व्यापार और निवेश कार्य समूह), लचीली मूल्य श्रृंखलाओं के लिए उप-समूह के अंतर्गत स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी
206.	भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी डब्ल्यूजी3 (व्यापार और निवेश कार्य समूह), लचीली मूल्य श्रृंखलाओं के लिए उप-समूह के अंतर्गत कृषि-खाद्य क्षेत्र में आरवीसी पर गैर-पत्र पर इनपुट
207.	आईपीईएफ पी2 एलआरएबी टीओआर भारत इनपुट
208.	एआईटीआईजीए एससीएलआईआई जीडीआईपी अध्याय पर टिप्पणियाँ
209.	एआईटीआईजीए एससीएलआईआई प्रस्तावना पर टिप्पणियाँ
210.	एआईटीआईजीए एससीएलआईआई जीपीई अध्याय पर टिप्पणियाँ
211.	AITIGA SCLII संस्थागत व्यवस्था अध्याय पर टिप्पणियाँ
212.	AITIGA SCLII अंतिम प्रावधान अध्याय पर टिप्पणियाँ
213.	IPEF P2 LRAB TOR CN चर्चा बिंदु
214.	कुछ उत्पादों के लिए गतिशील सीमा शुल्क संरचना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर राय
215.	मिनी व्यापार सौदों पर टिप्पणी
216.	LRAB प्रतिनिधित्व और IPEF समझौते के अनुपालन से संबंधित चिंताएँ
217.	अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार समझौतों के तहत कोटा आवंटन
218.	EU द्वारा इस्पात सुरक्षा उपायों के विस्तार के विरुद्ध प्रस्तावित प्रतिशोधात्मक उपायों पर जानकारी।
219.	ASEAN के साथ सेवा समझौतों के संदर्भ में 2014 से अब तक की उपलब्धियों पर जानकारी

220.	TVPRA
221.	रबर बोर्ड द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच क्लोन एक्सचेंज पर हस्ताक्षरित किए जाने वाले मसौदा समझौता ज्ञापन पर टिप्पणियाँ
222.	LRAB पर CN चर्चा बिंदु
223.	गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं, धारा 301, कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडी पर टिप्पणी
224.	EPCH के संशोधित उपनियमों का मानचित्रण
225.	वाणिज्य पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर टिप्पणियाँ
226.	विश्व व्यापार संगठन को भारत की मत्स्य पालन सब्सिडी अधिसूचना पर टिप्पणी
227.	एमए अधिसूचना और पीक्यूओ पर ब्राज़ील दूतावास के पत्र पर इनपुट
228.	गैर-प्रतिस्पर्धा खंड और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के संबंध में स्वतंत्र सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वचन पर राय
229.	एपीडा और एमओसीसीएई (यूएई) के बीच मसौदा समझौता ज्ञापन पर टिप्पणियाँ
230.	ईएसपीआर विनियमन पर इनपुट
231.	स्लैग वूल और रॉक वूल पर इंडोनेशिया के सुरक्षा उपायों के माध्यम से रियायतों के निलंबन पर इनपुट
232.	प्लास्टिक संधि - गैर-कागज़ी
233.	सऊदी अरब शुद्धिपत्र- जेएसआई एसडीआर
234.	कुछ इस्पात उत्पादों पर यूरोपीय संघ के सुरक्षा उपायों के विरुद्ध भारत के प्रस्तावित प्रतिशोध उपायों पर राय
235.	ऑस्ट्रेलियाई एफटीए का मानचित्रण
236.	डीएसयू अनुच्छेद 27.2 प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ
237.	भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) के संशोधित एओए का मानचित्रण
238.	ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद के संशोधित एओए का मानचित्रण (WWEPC)
239.	अनुरूपता मूल्यांकन प्रमाणन चिह्नों पर नोट
240.	अमेरिका के लघु व्यापार सौदों की WTO संगति पर नोट
241.	एपीडा और एमओसीसीएई के बीच समझौता ज्ञापन पर विदेश मंत्रालय की टिप्पणियाँ
242.	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर पर तुर्की के सुरक्षा उपायों पर इनपुट
243.	सुगम्यता पर शून्य मसौदे पर टिप्पणियाँ
244.	कोलंबिया के पारस्परिक प्रतिशोध प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ
245.	यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा इस्पात सुरक्षा उपायों को लागू करने के विरुद्ध भारत के जवाबी उपायों पर राय।
246.	ऑस्ट्रेलिया में सरकारी कंपनियों का विश्लेषण
247.	डीएएचडी और न्यूजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर इनपुट
248.	अपील/समीक्षा तंत्र में "तथ्यात्मक त्रुटियों" पर टिप्पणियाँ
249.	अंतरिम समीक्षा के उपयोग को बढ़ाने पर टिप्पणियाँ
250.	कार्यान्वयन पर भौतिक प्रभाव पर टिप्पणियाँ
251.	अपील/समीक्षा तंत्र में "समय-सीमाओं के पालन" पर टिप्पणियाँ
252.	लघु समूह 2 के लिए आरओडी - मत्स्य पालन सब्सिडी पर अतिरिक्त प्रावधान
253.	कृषि-खाद्य क्षेत्र में लचीली मूल्य श्रृंखला पर गैर-कागज़ी इनपुट
254.	स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लचीली मूल्य श्रृंखला पर गैर-कागज़ी इनपुट
255.	प्रस्तावित सीमा कर समायोजन पर इनपुट उपाय
256.	ऑस्ट्रेलिया द्वारा समर्थित "आईपीईएफ भागीदार देशों के लिए यूएनसीएसी के कार्यान्वयन का समर्थन - आईपीईएफ भागीदारों के बीच यूएनसीएसी कार्यान्वयन का मानचित्रण" शीर्षक वाली यूएनओडीसी की परियोजना की जाँच पर इनपुट, क्या यह टीएसीबी ढाँचे सहित आईपीईएफ स्तंभ IV समझौते के प्रावधानों के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

257.	आईपीईएफ ने पी2 एलआरएबी टीओआर के लिए नोट जारी किया
258.	चीन में औद्योगिक सब्सिडी पर पारदर्शिता की कमी से संबंधित संसदीय प्रश्न पर इनपुट।
259.	एपीआई क्षेत्र में लचीली मूल्य श्रृंखला पर गैर-पत्र पर इनपुट (संशोधित)
260.	आईपीईएफ पी2 एलआरएबी टीओआर के पैरा 5.2 पर राय
261.	पारस्परिकता अधिनियम पर इनपुट
262.	आईसीटी के लिए रोजगार बाजार तक पहुँच पर टिप्पणियाँ
263.	भारत और फिजी के बीच संयुक्त व्यापार समिति पर 2005 के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद V पर इनपुट
264.	एफटीए पर पीएमओ के लिए पीपीटी हेतु निवेश संबंधी कार्यों पर इनपुट: स्थिति और रणनीतियाँ
265.	भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर इनपुट
266.	शिपिंग बिलों पर इनपुट
267.	एसपीएस टीबीटी पोर्टल के शुभारंभ के लिए प्रेस नोट
268.	भारत से पीएसएफ आयात पर तुर्की के सुरक्षा उपायों पर इनपुट
269.	पारदर्शिता संबंधी प्रावधानों को शामिल करने के लिए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तिका में संशोधन की मांग करने वाले दस्तावेजों पर टिप्पणियाँ
270.	अधिनियम: व्यापार हित (संवर्धन और संरक्षण) अधिनियम, 2025 का मसौदा
271.	निर्यात संवर्धन परिषद के उपनियमों का प्रारूपण
272.	यूरोपीय संघ के ड्रेगी पर वाणिज्य सचिव के समक्ष इनपुट और प्रस्तुति रिपोर्ट
273.	इंडोनेशिया के कोटा की विश्व व्यापार संगठन की स्थिरता का विश्लेषण
274.	ऑस्ट्रेलिया-यूएई निवेश समझौते और संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण
275.	स्टील सुरक्षा उपायों की यूरोपीय संघ द्वारा कार्यशील समीक्षा शुरू करने का विश्लेषण
276.	पीएसएच अधिदेश पर राय
277.	प्रतिपूरक अंतरराष्ट्रीय सब्सिडी: यूरोपीय आयोग द्वारा दो जांचों का एक संक्षिप्त केस स्टडी
278.	डब्ल्यूईएफ, दावोस में अनौपचारिक डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए एचसीआईएम वार्ता बिंदु
279.	उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उत्तरदायी प्रसार हेतु अमेरिकी नियामक ढाँचे पर टिप्पणी
280.	आईएसीईसीए में "ऑस्ट्रेलिया के प्रथम राष्ट्र के लोगों" से संबंधित प्रावधानों पर कानूनी राय
281.	भारत-ऑस्ट्रेलिया जीपी अध्याय अंतर्वेशन के लिए इनपुट
282.	चीन-मालदीव निवेश अध्याय की तुलना
283.	भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए के तहत अग्रिम प्राधिकरण और शुल्क-मुक्त आयात प्राधिकरण से संबंधित प्रावधान की व्यवहार्यता
284.	डीएएचडी (भारत) और कृषि मंत्रालय (डोमिनिकल रिपब्लिक) के बीच समझौता ज्ञापन पर टिप्पणियाँ
285.	व्यापार सौदों पर डब्ल्यूटीओ अनुशासन पर इनपुट
286.	अमेरिकी धारा 301 के समान संशोधन प्रस्ताव, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आपातकालीन शक्तियाँ आदि।
287.	अमेरिकी कार्यकारी आदेशों पर टिप्पणी
288.	आरवीसी (कृषि) पर भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी डब्ल्यूजी3 गैर-पत्रों पर इनपुट खाद्य)
289.	भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और कृषि-तकनीकी प्रस्तावों के लिए अस्वीकरण
290.	एसपीएस-टीबीटी पोर्टल के लिए मास्टर एक्सेल शीट (मुद्दों का विश्लेषण)
291.	व्यापार और निवेश पर IND-BAH TWG के लिए संशोधित TOR
292.	भारत-ऑस्ट्रेलिया FTA CECA वार्ता में एकतरफा पर्यावरणीय उपायों की भाषा के संबंध में राय।
293.	ब्रिक्स विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना पर प्रोटोकॉल के मसौदे पर टिप्पणियाँ
294.	मासिक संक्षिप्त विवरण पर टिप्पणी - दृश्य-श्रव्य और आईटी क्षेत्र
295.	MPIA पर टिप्पणी
296.	SL80 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रमाणित कार्यक्रम पर विवाद का आधार

297.	संशोधन के लिए AITIGA कानूनी प्रारूप
298.	IEEPA के तहत अमेरिकी कार्रवाइयों पर टिप्पणी
299.	व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन पर टिप्पणियाँ
300.	ToR के लिए GATT के अनुच्छेद XI के साथ CBAM संगतता
301.	पारस्परिक तरीके से टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति
302.	प्रस्तावित अमेरिकी स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ पर टिप्पणी
303.	सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्युटिकल उत्पादों और दूरसंचार क्षेत्र पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण उपाय
304.	भारत-EAEU FTA: डिजिटल व्यापार का व्यवहार्यता विश्लेषण, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (CEPC) के संशोधित AOA और मॉडल उपनियमों का अध्याय मानचित्रण।
305.	अमेरिकी धारा 232 में उपाय शामिल हैं
306.	माराकेश समझौते के अनुबंध 4 में जेएसआई ई-कॉमर्स समझौते को शामिल करने पर राय
307.	जेएसआई ई-कॉमर्स समझौते के पाठ पर अद्यतन टिप्पणियाँ
308.	फरवरी 2025 के संयुक्त राज्य अमेरिका के धारा 232 स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ की विश्व व्यापार संगठन-संगति का आकलन
309.	भारत-अमेरिका एमएएस पर सीटीआईएल का प्रारंभिक विश्लेषण
310.	सोमालिया के प्रवेश पर इनपुट
311.	भारत-यूरोपीय संघ आरओओ के मसौदा पाठ के तहत पूरी तरह से प्राप्त या उत्पादित उत्पादों पर संचयन लागू है या नहीं, इस पर राय
312.	भारत-अमेरिका टीबीटी मुद्दों पर प्राप्त हितधारक इनपुट पर टिप्पणियाँ
313.	भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता मसौदा संदर्भ की शर्तें (टीओआर)
314.	भारत और अमेरिका के बीच संभावित सीमित व्यापार समझौते के लिए मसौदा टीओआर
315.	क्षेत्रीय शर्तों की मान्यता के लिए नियामक आलोचनाओं का नोट
316.	यूरोपीय संघ-मर्कोसुर टीएसडी मुद्दों पर राय
317.	अपने व्यापारिक साझेदारों के विरुद्ध संभावित अमेरिकी कार्रवाइयों (समयसीमा सहित) पर इनपुट - अमेरिका प्रथम व्यापार नीति और अन्य प्रासंगिक कानूनों का मानचित्रण
318.	धारा 301 में चीन द्वारा समुद्री, रसद और जहाज निर्माण क्षेत्रों को प्रभुत्व के लिए लक्षित करने की जाँच पर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई का विश्लेषण
319.	यूरोपीय संघ के स्वच्छ औद्योगिक समझौते पर एक संक्षिप्त विवरण
320.	अमेरिकी कानूनी प्रणाली के तहत टैरिफ लगाने की शक्ति पर टिप्पणी
321.	"भारत गणराज्य की सरकार" और "भारत गणराज्य" के प्रयोग पर विश्लेषण
322.	विश्व व्यापार संगठन आरओओ उपसमिति में थाईलैंड द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के आरओओ प्रावधान की व्याख्या पर कानूनी राय
323.	अमेरिका-जापान व्यापार समझौते पर संक्षिप्त विवरण
324.	मूल्य वर्धित कर पर टिप्पणी
325.	आईएन ईयू एफटीए में प्रतिस्पर्धा अध्याय के अनुच्छेद 2 पर टिप्पणी
326.	मसौदा पाठ पर इनपुट
327.	विश्व व्यापार संगठन सुधार पर इनपुट/चर्चा बिंदु/टिप्पणी
328.	भारत-मालदीव एफटीए के लिए टीओआर पर टिप्पणियाँ
329.	क्यूसीटीडी मसौदा निर्माण
330.	टिप्पणियाँ भारत-जीसीसी सीईपीए के लिए टीओआर
331.	व्यापार नीति पर अमेरिकी संवैधानिक ढांचा
332.	प्राकृतिक रबर के लिए बाउंड रेट में संशोधन पर टिप्पणी

333.	भारत-यूएस बीटीए पर प्रश्न
334.	एमएसपी पर प्रतिक्रिया
335.	यूएसटीआर टिप्पणियों पर सारांश नोट
336.	मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की निगरानी और बेहतर उपयोग हेतु तंत्र और प्राधिकरण
337.	GATT के अनुच्छेद 24 का विकास
338.	NAFTA के संभावित ToR पर टिप्पणियाँ
339.	संयुक्त राज्य अमेरिका के धारा 232 शुल्कों के विरुद्ध भारत की प्रतिशोध रणनीति और लागू प्रक्रियाओं पर टिप्पणी
340.	अमेरिका-चीन चरण एक समझौते पर टिप्पणी
341.	SAFTA देशों से महत्वपूर्ण कम कीमतों वाले आयातों के संबंध में भारतीय उद्योग द्वारा वाणिज्य विभाग को दिए गए प्रतिनिधित्व पर इनपुट
342.	दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ पर कानूनी टिप्पणी और भारत और SACU के बीच मुक्त व्यापार समझौते के कानूनी प्रारूप के लिए संभावित आगे का रास्ता
343.	कोलंबिया और भारत के बीच एक संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) की स्थापना के माध्यम से सतत निवेश और व्यापार के विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर राय
344.	BIMSTEC पर टिप्पणियाँ
345.	BRICS डेटा अर्थव्यवस्था शासन समझ पर मसौदा
346.	AITIGA के लिए CPTF पर टिप्पणियाँ
347.	SME अध्याय के मसौदा पाठ पर संशोधन
348.	AITIGA- SCLII AITIGA-NTMA द्वारा मांगी गई टिप्पणियों का उत्तर
349.	NTMA के लिए NTMA के मसौदा पाठ में संशोधन AITIGA
350.	AITIGA के लिए ECOTECH के प्रारूप पाठ में संशोधन
351.	मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की निगरानी और बेहतर उपयोग हेतु तंत्र और प्राधिकरण
352.	GATT के अनुच्छेद 24 का विकास
353.	NAFTA के संभावित ToR पर टिप्पणियाँ
354.	संयुक्त राज्य अमेरिका के धारा 232 शुल्कों के विरुद्ध भारत की प्रतिशोध रणनीति और लागू प्रक्रियाओं पर टिप्पणी
355.	अमेरिका-चीन चरण एक समझौते पर टिप्पणी
356.	SAFTA देशों से महत्वपूर्ण कम कीमतों वाले आयातों के संबंध में भारतीय उद्योग द्वारा वाणिज्य विभाग को दिए गए प्रतिनिधित्व पर इनपुट
357.	दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ पर कानूनी टिप्पणी और भारत और SACU के बीच मुक्त व्यापार समझौते के कानूनी प्रारूप के लिए संभावित आगे का रास्ता
358.	कोलंबिया और भारत के बीच एक संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) की स्थापना के माध्यम से सतत निवेश और व्यापार के विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर राय
359.	BIMSTEC पर टिप्पणियाँ
360.	BRICS डेटा अर्थव्यवस्था शासन समझ पर मसौदा
361.	AITIGA के लिए CPTF पर टिप्पणियाँ
362.	SME अध्याय के मसौदा पाठ पर संशोधन
363.	AITIGA- SCLII AITIGA-NTMA द्वारा मांगी गई टिप्पणियों का उत्तर
364.	NTMA के लिए NTMA के मसौदा पाठ में संशोधन AITIGA
365.	AITIGA के लिए ECOTECH के प्रारूप पाठ में संशोधन
366.	मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की निगरानी और बेहतर उपयोग हेतु तंत्र और प्राधिकरण
367.	GATT के अनुच्छेद 24 का विकास
368.	NAFTA के संभावित ToR पर टिप्पणियाँ

369.	संयुक्त राज्य अमेरिका के धारा 232 शुल्कों के विरुद्ध भारत की प्रतिशोध रणनीति और लागू प्रक्रियाओं पर टिप्पणी
370.	अमेरिका-चीन चरण एक समझौते पर टिप्पणी
371.	SAFTA देशों से महत्वपूर्ण कम कीमतों वाले आयातों के संबंध में भारतीय उद्योग द्वारा वाणिज्य विभाग को दिए गए प्रतिनिधित्व पर इनपुट
372.	दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ पर कानूनी टिप्पणी और भारत और SACU के बीच मुक्त व्यापार समझौते के कानूनी प्रारूप के लिए संभावित आगे का रास्ता
373.	कोलंबिया और भारत के बीच एक संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) की स्थापना के माध्यम से सतत निवेश और व्यापार के विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर राय
374.	BIMSTEC पर टिप्पणियाँ
375.	BRICS डेटा अर्थव्यवस्था शासन समझ पर मसौदा
376.	ईयू एफटीए में एफएस अनुलग्नक में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेख पर इनपुट
377.	आईएन-ईयू डीएस अध्याय पर टिप्पणियाँ (राउंड VII पाठ)
378.	आईएन-पीई प्रस्तावना टिप्पणियाँ
379.	भारत में सेवा क्षेत्रों में एसएमबीडी/स्थानीय उपस्थिति आवश्यकता का आकलन
380.	पूंजी संचलन पर गैर-पत्र
381.	राउंड 8- अपवाद-ईयू-भारत एफटीए
382.	आईएन-पीई डीएस: राउंड VIII से पहले आईएन के नए एट्रिब्यूशन पर नोट
383.	ऊर्जा और कच्चे माल अध्याय के मूल और संशोधित पाठ की तुलना और उनके निहितार्थ | ईयू-भारत मुक्त व्यापार समझौता
384.	गैर-टैरिफ उपायों और सीबीएएम पर ईयू को भारत के पाठ्य प्रस्ताव पर तुलनात्मक नोट
385.	एसपीएस अध्याय की कला तक पहुँच। यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत XX सामान्य अपवाद
386.	एसपीएस अध्याय में यूरोपीय संघ के संशोधित प्रस्तावों पर टिप्पणियाँ
387.	सीबीएएम पर यूरोपीय संघ को भारत के प्रस्ताव पर टिप्पणी
388.	आईपीईएफ स्तंभ 2 परिषद की संदर्भ शर्तों पर सीटीआईएल की टिप्पणियाँ
389.	विवाद निपटान अध्याय पर यूरोपीय संघ आर7 संक्षिप्त विवरण
390.	आईएन-पीई विवाद निपटान अध्याय की विशेषताएँ
391.	एफटीए में मरम्मत किए गए सामान की परिभाषा की तुलना
392.	भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते पर जीपी अध्याय में यूके और भारत द्वारा दी गई रियायतों के संक्षिप्त विवरण की जाँच
393.	यूरोपीय संघ जीपी में बाजार पहुँच पर भारत के प्रस्ताव पर टिप्पणी
394.	एससी-एनटीएमसीए बैठक एआईटीआईजीए पर टिप्पणी
395.	यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता टीआईजी अध्याय-सीवीए
396.	एससी-एससीएलआई बैठक एआईटीआईजीए पर टिप्पणी
397.	ईयू-भारत एफटीए टीआईजी अध्याय-स्थानीय सामग्री आवश्यकता
398.	भारत-यूएई सीईपीए तथ्यात्मक प्रस्तुति प्रश्नों पर इनपुट
399.	जीसीसी के लिए संदर्भ की शर्तें
400.	ईआरएम अध्याय वार्ता पर टिप्पणी - यूरोपीय संघ में एफटीए
401.	आईएन-ईयू एफटीए डीएस अध्याय के लिए यूरोपीय संघ रोस्टर प्रणाली पर टिप्पणी
402.	जी20 नेताओं की घोषणा और आईपीईएफ स्तंभ III की तुलना
403.	पारदर्शिता अध्याय पर यूरोपीय संघ आर7 संक्षिप्त विवरण
404.	अपवाद अध्याय पर यूरोपीय संघ आर7 संक्षिप्त विवरण

405.	एआईटीआईजीए एसपीएस वार्ता पर व्यापक संक्षिप्त विवरण
406.	टीआईजी (भारत-पेरू एफटीए) के लिए गैर-पत्र
407.	आईएन-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए आर7 आरओडब्ल्यूपी पर टिप्पणियाँ
408.	आईएन-ईएफटीए टीईपीए की शीघ्र अधिसूचना
409.	ईयू-भारत एफटीए टीआईजी अध्याय - आयात-निर्यात एकाधिकार
410.	एआईटीआईजीए-आरसीईपी टीआईजी
411.	आईएन-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए आरओडब्ल्यूपी
412.	भारत-पेरू एफटीए (वरीयता मार्जिन की परिभाषा)
413.	भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए - स्थिति अद्यतन
414.	यूरोपीय संघ मध्यस्थता अनुभाग के मानचित्रण पर इनपुट और एडीआर पर भारत लेख
415.	जीआई संरक्षण पर पेरू के पाठ पर इनपुट
416.	टीकेजीआर पर पेरू के पाठ पर इनपुट
417.	आईएन-पीई प्रारंभिक प्रावधानों (अंतर-सत्रीय) पर आईएन मार्कअप
418.	आसियान के लिए वस्तुओं के व्यापार अध्याय
419.	भारत-पेरू एफटीए में सहयोग अध्याय पर भारत के आरोप
420.	आईएन-पीई डीएस अध्याय: उद्देश्य और रेडलाइन
421.	राउंड VII से पहले IN-PE DS अध्याय पाठ में भारत के संशोधित योगदान
422.	वस्तुओं के व्यापार अध्याय के संबंध में पूर्व-स्क्रब इनपुट। भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता
423.	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) ट्रैक पर संक्षिप्त नोट
424.	भौगोलिक संकेतों पर पेरू पाठ पर टिप्पणियाँ
425.	मोड 4 पर भाषा प्रस्ताव - अपवाद दृष्टिकोण
426.	मोड 4 पर भाषा प्रस्ताव - स्थिर और रैचेट दृष्टिकोण
427.	मोड 4 पर भाषा प्रस्ताव - सुरक्षा दृष्टिकोण
428.	मोड 4 पर भाषा प्रस्ताव - एकतरफा उपाय दृष्टिकोण
429.	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते के लिए चर्चा का रिकॉर्ड - सहयोग - दौर 7
430.	यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते अभ्यास में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए वार्षिक राजस्व आधारित सीमा पर प्रावधानों की तालिका
431.	आईएसीईसीए के कृषि और पशुपालन प्रौद्योगिकी ट्रैक पर संक्षिप्त नोट
432.	पेरू टीआईजी-लैंडिंग ज़ोन
433.	डब्ल्यूटीओ को भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते की अधिसूचना
434.	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते के लिए चर्चा का रिकॉर्ड - विवाद निपटान - दौर 7
435.	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौते के लिए चर्चा का रिकॉर्ड - एल एंड आई और अंतिम प्रावधान अध्याय - दौर 7
436.	प्रशासन और RoWP का मानचित्रण
437.	संयुक्त समिति - भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA/CECA के लिए RoWP पर भारत का मार्कअप
438.	संयुक्त समिति - भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA/CECA के लिए RoWP हेतु भारत का संशोधित प्रस्ताव
439.	यूरोपीय संघ में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व आधारित परिभाषाओं पर कानूनी प्रावधानों का संकलन
440.	GP पर अध्याय के लिए चल रही भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते वार्ता की स्थिति अद्यतन
441.	आईपीईएफ पी2 टीओआर बैठक का आरओडी
442.	भारत-पेरू एफटीए के लिए चर्चा का रिकॉर्ड - सहयोग - अंतर-सत्रीय पोस्ट राउंड 7
443.	विवाद समाधान अध्याय में प्रमुख मुद्दे: यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता

444.	अपवाद अध्याय में प्रमुख मुद्दे: यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता
445.	पारदर्शिता अध्याय में प्रमुख मुद्दे: यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता
446.	यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में विभिन्न राष्ट्रीयता/सीआर आवश्यकताओं का मानचित्रण
447.	दिन 1- यूरोपीय संघ-भारत टीआईजी नोट्स राउंड 8
448.	आईएन पीई प्रस्तावना अंतर-सत्र आरओडी
449.	दिन 2- यूरोपीय संघ-भारत टीआईजी नोट्स राउंड 8
450.	दिन 3- यूरोपीय संघ-भारत टीआईजी नोट्स राउंड 8_एमए_एग्री
451.	भारत-पेरू एफटीए में सहयोग अध्याय पर प्रगति रिपोर्ट
452.	भारत-यूरोपीय संघ पारदर्शिता
453.	एआईटीआईजीए समीक्षा - एआईटीआईजीए डीएसयू और भारत-सिंगापुर सीईसीए की तुलना
454.	ऑस्ट्रेलिया सरकार खरीद व्यवस्था पर टिप्पणी
455.	आसियान चर्चा पत्र पर टिप्पणियाँ
456.	यूके, ऑस्ट्रेलिया को प्रस्तावित और यूके के साथ सहमत अध्याय की तुलना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
457.	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भुगतान एवं हस्तांतरण (पूंजी संचलन) प्रावधानों पर टीआईएल टिप्पणियाँ और मसौदा भारतीय संदर्भों
458.	'कृषि निर्यात सब्सिडी' पर इनपुट
459.	आईपीईएफ पी2 एससीसी टीओआर विकास पर एचसीआईएम के लिए संक्षिप्त नोट
460.	आईपीईएफ पी2 सीआरएन टीओआर विकास पर एचसीआईएम के लिए संक्षिप्त नोट
461.	आर्थिक सहयोग पर टिप्पणियाँ
462.	घरेलू समीक्षा पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर
463.	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए स्थिरता-संचालित गैर-टैरिफ उपायों पर भारत के गैर-पत्र और प्रस्तावित पाठ पर स्लाइड्स
464.	भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के अनुच्छेद 14.4 (सामान्य समीक्षा) पर एयू संपादनों पर सीटीआईएल इनपुट
465.	यूरोपीय संघ के लिए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में ईआरएम अध्याय के लिए भारत के प्रतिप्रस्ताव का सीटीआईएल मसौदा
466.	पूंजी संचलन अध्याय पर भारतीय इनपुट
467.	मॉडल पाठ का विश्लेषण
468.	श्रीलंका टीआईजी के लिए लैंडिंग ज़ोन
469.	यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते (पेटेंट द्वारा प्रदत्त सुरक्षा अवधि का विस्तार)
470.	भारत में खरीद की समयावधि
471.	पशुपालन ट्रैक में टीआरक्यू को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जोड़ने के लिए भाषा
472.	आईएन-ईयू मुक्त व्यापार समझौते में सेवा सब्सिडी प्रावधान के मसौदा निर्माण पर इनपुट
473.	ऑस्ट्रेलिया की खरीद नीतियों पर प्रश्न
474.	आईएन-ईयू पारदर्शिता अध्याय पर टिप्पणियाँ
475.	समुद्री कैबोटेज के निर्माण पर इनपुट
476.	के लिए मसौदा रूपरेखा भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत ऊर्जा और कच्चे माल पर भारत का गैर-पत्र
477.	भारत-पेरू सहयोग पाठ में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए सुझावों का समावेश
478.	भारत-पेरू सहयोग अध्याय पर पृष्ठभूमि नोट
479.	भारत-एयू अंतरिक्ष सहयोग अध्याय पर पृष्ठभूमि नोट
480.	भारत-एयू अंतरिक्ष सहयोग अध्याय में लंबित मुद्दे

481.	आईएमसी बैठक के लिए पारदर्शिता अध्याय पर पीपीटी
482.	डिजिटल व्यापार अध्याय में पूर्व-प्राधिकरण, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
483.	टीआईएस के अंतर्गत समान परिस्थितियों पर इनपुट
484.	टीआईएस से जीपी बहिष्करण पर पाठ्य प्रस्ताव
485.	श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के टीआईजी की कानूनी पाठ तुलना
486.	यूरोपीय संघ की खरीद नीतियों पर प्रश्न
487.	आरओडी पारदर्शिता अध्याय R9 यूरोपीय संघ में
488.	दिन 4- यूरोपीय संघ-भारत टीआईजी नोट्स राउंड 8_एमए_नामा
489.	आसियान टीआईजी पाठ पर टिप्पणियाँ
490.	पीई अंतर-सत्रीय आरओडी, एफपी में
491.	कौशल और गतिशीलता साझेदारी पर भारत के प्रस्तावित अध्याय के लिए पृष्ठभूमि नोट
492.	आईपीईएफ पी2 सीआरएन टीओआर पर विदेश मंत्रालय के प्रश्नों का डीओसी उत्तर
493.	एआईटीआईजीए समीक्षा - मसौदा वस्तु पाठ के कुछ लेखों पर टिप्पणियाँ
494.	21 जून 2024 की आईपीईएफ सीएन बैठक के लिए आरओडी
495.	ईयू पारदर्शिता अध्याय R8 में आरओडी
496.	ईयू टीएल पारदर्शिता अध्याय R8 के लिए मसौदा ईमेल
497.	भारत-श्रीलंका के लिए वैकल्पिक लेख एफटीए
498.	टीआईजी (भारत-श्रीलंका एफटीए) के लिए लेखों पर राय
499.	प्रमुख यूरोपीय संघ विनियमों का संक्षिप्त सारांश
500.	भारत में ईआरएम अध्याय के लिए भारत के प्रतिप्रस्ताव का सीटीआईएल मसौदा - संबंधित मंत्रालयों के लिए यूरोपीय संघ एफटीए
501.	आसियान टीआईजी पाठ की भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए पाठ से तुलना
502.	सीएन स्तर पर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय बैठक का आरओडी
503.	भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए और भारत-पेरू एफटीए के लिए तैयार किए गए महत्वपूर्ण खनिजों पर मसौदा पाठ की तुलना
504.	खनन क्षेत्र में पेरू के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर टिप्पणी
505.	एआईटीआईजीए पाठ के लिए भाषा निर्माण
506.	भारत-यूएई एफटीए में संबंधित मंत्रालयों के लिए ईआरएम अध्याय के लिए भारत के प्रतिप्रस्ताव का सीटीआईएल मसौदा- II
507.	टीआईएस अध्याय के लिए कार्य बिंदुओं की तैयारी
508.	टीआईएस अध्याय के लिए संयुक्त रिपोर्ट
509.	जीपी बाजार पहुँच पर पावरग्रिड द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर इनपुट
510.	सीएन के लिए टीआईएस अध्याय पर ट्रैक लीड रिपोर्ट
511.	भारत के नए अध्याय का अन्य यूरोपीय संघ एफटीए अध्यायों के साथ मानचित्रण
512.	भारत-आसियान एफटीए समीक्षा के लिए सहयोग अध्याय पर संशोधित टिप्पणियाँ
513.	भारत-यूएई सीईपीए के लागू होने के बाद भारतीय उद्योग के सामने आने वाली व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं पर टिप्पणी
514.	एसएमई अध्याय पर टिप्पणियाँ
515.	ईआरएम अध्याय और अन्य अध्यायों के बीच ओवरलैप का अद्यतन सारणीकरण भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का
516.	जीपी अध्याय के अंतर्गत आपत्तिजनक प्रश्नों का सारणीयन
517.	एसएमई और ईकोटेक का संशोधित मसौदा पाठ

518.	संयुक्त ईकोटेक और एसएमई अध्याय पर भारत के आरोप
519.	एआईटीआईजीए पर संशोधित सीटीआईएल टिप्पणियाँ
520.	टैरिफ उदारीकरण के तौर-तरीकों के निर्धारण हेतु आसियान मुक्त व्यापार समझौते की तुलना
521.	यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में यूरोपीय संघ की माँग_श्रेणियाँ
522.	यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में यूरोपीय संघ की माँग_श्रेणियाँ- माल ट्रैक
523.	आसियान के लिए संशोधित एनटीएमए पाठ
524.	आक्रामक और रक्षात्मक माँग में ईकोटेक अध्याय
525.	भारत-यूरोपीय संघ विवाद निपटान अध्याय - वार्ता के 9वें दौर के बाद की स्थिति
526.	आयात-निर्यात एकाधिकार
527.	संयुक्त एसएमई अध्याय पर इनपुट
528.	संयुक्त ईकोटेक अध्याय पर इनपुट
529.	आर्थिक और तकनीकी सहयोग अध्याय पर एससीएलआईआई के इनपुट
530.	एसएमई अध्याय पर एससीएलआईआई के इनपुट
531.	भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के मसौदे के तथ्यात्मक प्रस्तुतीकरण पर भारत की टिप्पणियों पर सचिवालय के उत्तर पर इनपुट
532.	एसएमई अध्याय पर भारत के रुख पर इनपुट
533.	आसियान द्वारा प्रस्तावित एनटीएमए पाठ पर इनपुट
534.	एआईटीआईजीए - एससीएलआईआई प्रस्तुतीकरण
535.	आसियान एससीएलआईआई - मानचित्रण तालिका (अंतिम प्रावधान)
536.	आसियान एससीएलआईआई - मानचित्रण तालिका (सामान्य प्रावधान और अपवाद)
537.	एआईटीआईजीए में रियायत की समीक्षा और संशोधन पर इनपुट
538.	आसियान के गैर-पत्र पर भारत की प्रतिक्रिया
539.	अनुच्छेद 2.3 (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) के लिए प्रस्तावित सूत्रीकरण
540.	आईपीईएफ स्तंभ-IV के अंतर्गत सहमत प्रतिबद्धताओं के संबंध में यूएनओडीसी प्रस्ताव पर इनपुट
541.	अनुच्छेद X.8 - घरेलू विनियमन के पैरा 18 और 19 पर इनपुट
542.	IND - AU CECA के नवाचार अध्याय के अंतर्गत 'ऑस्ट्रेलियाई प्रथम राष्ट्रों के लोगों और व्यवसायों' के संदर्भ में इनपुट
543.	ऑस्ट्रेलियाई CECA में आधार दर पर इनपुट
544.	वित्तीय सेवाओं और घरेलू विनियमन प्रावधान पर अनुलग्नक में पारदर्शिता प्रावधानों पर इनपुट
545.	अंतरिक्ष सहयोग अध्याय की अद्यतन स्थिति पर इनपुट
546.	अंतरिक्ष सहयोग अध्याय के लिए CN के लिए मसौदा वार्ता बिंदु
547.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए प्रश्नों की सूची
548.	TIS अध्याय में घरेलू समीक्षा प्रावधान के पैराग्राफ 10 और 11 के लिए यूरोपीय संघ के प्रस्ताव की स्वीकृति पर इनपुट।
549.	IN-AU CECA वार्ता के अंतर्गत भारतीय पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं पर अनुलग्नक XX पर टिप्पणियाँ
550.	आर्थिक एवं सहयोग अध्याय हेतु मसौदा निर्माण
551.	IN-EU TiS के अंतर्गत हवाई सेवाओं पर इनपुट
552.	6 दिसंबर 2024 के EU-मर्कोसुर साझेदारी समझौते पर टिप्पणी
553.	AITIGA समीक्षा (SCLII): कानूनी दस्तावेजों में पुष्टि प्रावधानों पर राय
554.	भारत के FTA में GDIP प्रावधान
555.	भारत के FTA में संयुक्त समिति प्रावधान
556.	भारत के FTA में अंतिम प्रावधान
557.	IN AU CECA के लिए संयुक्त CN संक्षिप्त का सारांश

558.	IN AU CECA के लिए CS संक्षिप्त हेतु PPT
559.	EU भारत आयात निर्यात एकाधिकार ओवरलैप
560.	यूरोपीय संघ-मर्कोसुर FTA सरकारी खरीद अध्याय पर टिप्पणियाँ
561.	यूरोपीय संघ-मर्कोसुर विवाद निपटान अध्याय पर प्रस्तुति
562.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए प्रश्नों की सूची
563.	यूरोपीय संघ-मर्कोसुर मुक्त व्यापार समझौते में ईआरएम क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं पर प्रारंभिक जानकारी
564.	भारतीय कानून में 'राज्य व्यापार उद्यम' शब्द के प्रयोग का विश्लेषण।
565.	भारत-फिलीपींस पीटीए के लिए टीओआर पर टिप्पणियाँ
566.	एमएसएमई के लिए मसौदा तैयार करना
567.	यूएसएमसीए के अंतर्गत विवाद निपटान तंत्र पर टिप्पणी
568.	ईयू-मर्कोसुर और आईएन-ईयू टीआईएस अध्याय की तुलनात्मक तालिका
569.	संशोधित अपील/समीक्षा तालिकाओं पर डीएस सुधार सीटीआईएल इनपुट (18 नवंबर 2024)
570.	भारत द्वारा पूर्व में उठाए गए एसटीसी - भारत की उन चिंताओं को उजागर करते हैं जिनका संबंधित सदस्य देश द्वारा समाधान नहीं किया गया है
571.	अन्य देशों द्वारा पूर्व में उठाए गए एसटीसी जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं
572.	मलावी के लिए प्रश्न, चौथा टीपीआर
573.	ईयू एमडीआर और अपशिष्ट शिपमेंट विनियमन एसटीसी पर टिप्पणी - भारतीय उद्योग पर प्रभाव
574.	संशोधित अपील/समीक्षा तालिकाओं पर डीएस सुधार सीटीआईएल इनपुट, 18 अक्टूबर 2024 की बैठक में उठाए जाने वाले प्रश्नों के साथ
575.	टीबीटी समिति में भारत द्वारा उठाए गए एसटीसी के लिए वक्तव्य, नवंबर 2024
576.	21 अक्टूबर 2024 की बैठक के लिए AB/समीक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर
577.	DS फंड पर अवधारणा नोट
578.	पार-प्रतिशोध पर अवधारणा नोट
579.	मुकदमेबाजी लागतों के लिए प्रतिपूर्ति मॉडल पर अवधारणा नोट
580.	भारत द्वारा WTO SPS समिति के समक्ष उठाए जाने वाले STCs
581.	STCs के लिए वक्तव्य TBT समिति में भारत के प्रतिक्रिया वक्तव्य, नवंबर 2024
582.	SPS समझौते की छठी समीक्षा पर SPS समिति की सिफारिशों में पाठ्य संपादन
583.	SPS समझौते की छठी समीक्षा के विषय 1, 3, 7, 8 पर भारत की स्थिति
584.	SPS समझौते की छठी समीक्षा के विषय 2, 4, 5, 6, 9 पर भारत की स्थिति
585.	नाइजीरिया की छठी TPR पर प्रश्न
586.	SPS समिति में भारत का वक्तव्य
587.	13वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणामों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवाओं के व्यापार से संबंधित भारत द्वारा सुझाए गए विषयों पर टिप्पणियाँ
588.	विषयगत सत्र पर भारत का मसौदा प्रस्ताव क्षेत्रीयकरण पर
589.	RoD - DS सुधार सूचना सत्र - JOB/DSB/8
590.	IFD समन्वयकों द्वारा दिए गए सारांश उत्तरों पर टिप्पणियाँ
591.	विश्व व्यापार संगठन सचिवालय द्वारा साझा किए गए एसपीएस विषयगत सत्रों के प्रारूप कार्यक्रम पर टिप्पणियाँ
592.	संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद प्रस्ताव पर सीटीआईएल की टिप्पणियाँ
593.	एनवीएनआई से संबंधित गैट/विश्व व्यापार संगठन विवादों की तालिका
594.	आईएन-यूके और ईयू-मर्कोसुर अपवाद अध्याय के साथ आईएन-ईयू अपवाद अध्याय का तुलनात्मक विश्लेषण
595.	वियतनाम-ईएईयू एफटीए - वाणिज्यिक उपस्थिति और एमओएनपी अध्याय का सीटीआईएल मानचित्रण

596.	आईएन-यूके, ईयू-मेक्सिको और ईयू-मर्कोसुर एसओई अध्याय का तुलनात्मक विश्लेषण
597.	आईएन-यूके पाठ के साथ संरेखित आईएन-ईयू एसपीएस अध्याय में आईएन के नए गुण
598.	एआईटीआईजीए के लिए एनटीएमए पाठ के लिए नए गुण
599.	ईएईयू में सरकारी खरीद के दायरे का आकलन
600.	एआईटीआईजीए एसपीएस अध्याय के लिए मसौदा ईआईसी अनुलग्नक
601.	एआईटीआईजीए के एनटीएमए पाठ के लिए विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त इनपुट के आधार पर संशोधित गुण
602.	पवन और सौर ऊर्जा में संभावित सहयोग पर एमएनआरई के लिए प्रश्नों सहित सीटीआईएल नोट
603.	नोट यूरोपीय संघ की रोस्टर प्रणाली पर
604.	भारत-ब्रिटेन, यूरोपीय संघ-मेक्सिको और यूरोपीय संघ-मर्कोसुर सब्सिडी अध्याय का तुलनात्मक विश्लेषण
605.	भारत-यूरोपीय संघ डीएस अध्याय: आईएमसी के लिए विचारणीय मुद्दे
606.	ओमान में सेवाएँ
607.	एनटीएमए पाठ पर संदर्भ
608.	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में ईआरएम अध्याय के लिए मसौदा सूत्रों के साथ नोट
609.	मुख्य वार्ताकार (कृषि तकनीक अध्याय) के लिए व्यापक संक्षिप्त विवरण
610.	आईएसीईसीए के कृषि तकनीक अध्याय पर एचसीआईएम के लिए सारणीबद्ध सारांश
611.	भारत-ईएईयू जीपी अध्याय के मसौदे का विश्लेषण
612.	भारत-ईएईयू आईपी अध्याय के मसौदे का विश्लेषण
613.	सीडब्ल्यूएस द्वारा साझा किए गए ईआरएम उत्पादों पर निर्यात/आयात आंकड़ों का सारांश
614.	ईएईयू में प्रतिस्पर्धा के दायरे का आकलन अध्याय
615.	यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में पारदर्शिता अध्याय
616.	अमेरिका में बीटीए टीआईएस विश्लेषण - आक्रामक और रक्षात्मक प्रश्न
617.	अमेरिका में बीटीए टीआईएस विश्लेषण - यूएस जीएटीएस विश्लेषण
618.	अमेरिका में बीटीए टीआईएस विश्लेषण - टीआईएस अध्याय के लिए अमेरिकी दृष्टिकोण
619.	अमेरिका में बीटीए - आईपीईएफ वार्ता पर विश्लेषणात्मक संक्षिप्त विवरण, सेवा प्राधिकरण उपायों के विकास और प्रशासन पर पाठ
620.	आईपीईएफ डिजिटल व्यापार पर कवर नोट
621.	आसियान एफटीए में संस्थागत प्रावधान
622.	ऊर्जा और कच्चे तेल के अंतर्गत उत्पाद कवरेज यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर सामग्री अध्याय
623.	ऑस्ट्रेलिया के जीपी प्रस्ताव में भाषा का विश्लेषण
624.	भारत के जीपी प्रस्ताव के लिए बहिष्करण भाषा विकल्प
625.	ऊर्जा एवं कच्चे माल अध्याय में निर्यात मूल्य निर्धारण संबंधी प्रावधान के विश्व व्यापार संगठन के सुसंगतता विश्लेषण पर राय
626.	भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते के लिए एसपीएस/टीबीटी पर मसौदा पत्र
627.	भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते के लिए एटीएसएम पर मसौदा पत्र
628.	भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के संबंध में थाईलैंड द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर
629.	टीआईजी वैकल्पिक पाठ आईएन-ईयू एफटीए
630.	पारदर्शिता तुलना अभ्यास आईएन-ईयू, आईएन-यूके, ईयू मर्कोसुर
631.	इंड-ईयू एफटीए के अंतर्गत आईपी अध्याय - भारत-यूके एफटीए और ईयू-मर्कोसुर के अंतर्गत आईपी अध्याय पाठ के साथ संरेखण का सारणीकरण
632.	सेवा अनुसूची में एयू को भारत के संशोधित प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ
633.	इंड-ईयू एफटीए के अंतर्गत आईपी अध्याय (संरेखण का सारांश)

634.	भारत-ओमान एफटीए के लिए निवेश प्रोत्साहन पर मसौदा पत्र
635.	वियतनाम-ईएईयू एफटीए का मानचित्रण
636.	भारत के पिछले एफटीए में विवाद निपटान प्रावधान
637.	माल व्यापार भारत के पिछले एफटीए
638.	सेवा व्यापार - आईपीईएफ डीआर और यूएसएमसीए की तुलना
639.	सेवाओं में व्यापार - आईपीईएफ डीआर और आईएन की पिछली प्रथाओं की तुलना
640.	डिजिटल व्यापार - भारत के एफटीए के साथ अमेरिका-भारत डिजिटल व्यापार समझौते की तुलना
641.	सेवाओं में व्यापार: भारत के पिछले मुक्त व्यापार समझौते
642.	भारतीय मुक्त व्यापार समझौतों में सरकारी खरीद अध्यायों की मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) तुलना
643.	भारतीय मुक्त व्यापार समझौतों में डिजिटल व्यापार अध्यायों की मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) तुलना
644.	सेवाओं में व्यापार - पारस्परिक व्यापार और शुल्कों पर यूएसटीआर ज्ञापन और सार्वजनिक टिप्पणियाँ
645.	भारत-चिली सीईपीए वार्ता दिशानिर्देश
646.	भारत-ऑस्ट्रेलिया सरकारी खरीद अध्याय: प्रस्तावित भाषा के लिए भाषा प्रस्ताव
647.	कानूनी जाँच - विकास पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की जीसी को भारत द्वारा प्रस्तुत मसौदा
648.	एसपीएस समझौते की छठी समीक्षा पर सचिवालय की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ
649.	यूरोपीय संघ के बहुपक्षीय व्यापार समझौते (एमआरएल) के विरुद्ध सेंटेग्रो और एसटीसी द्वारा लिखे गए पत्रों पर टिप्पणियाँ
650.	विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय पहलों के लिए मसौदा ढाँचा
651.	कनाडा व्यापार नीति (टीपीआर) के लिए प्रश्न
652.	भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए की तथ्यात्मक प्रस्तुति का मसौदा
653.	चीन व्यापार नीति (टीपीआर) के लिए प्रश्न
654.	18 जुलाई को विश्व व्यापार संगठन में रक्षा मंत्रालय की औपचारिक बैठक के लिए आरओडी
655.	17 जुलाई को विश्व व्यापार संगठन में रक्षा मंत्रालय की सूचना सत्र के लिए आरओडी
656.	कानूनी जाँच - वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए औद्योगिक सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों पर विश्व व्यापार संगठन के मसौदा अधिसूचना के लिए भारत की मसौदा अधिसूचना
657.	आईएफडी से संबंधित मुद्दों पर भारत का प्रत्युत्तर
658.	डीएस सुधार: अपील/समीक्षा तालिकाओं पर सीटीआईएल इनपुट
659.	विश्व व्यापार संगठन की एसपीएस समिति में भारत द्वारा उठाए जाने वाले एसटीसी
660.	तृतीय पक्ष अधिकारों पर पत्र
661.	कज़ाकिस्तान के लिए टीपीआर प्रश्न

अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र द्वारा आयोजित विवाद, संशोधन समीक्षा

1. पैनल कार्यवाही पर टिप्पणियाँ - अध्याय II
2. DS588 (ICT) - चीनी ताइपे के प्रस्ताव पर CTIL की राय
3. पैनल कार्यवाही पर टिप्पणियाँ - अध्याय III
4. शीर्षक IV अनुपालन पर सारणीबद्ध CTIL टिप्पणियाँ
5. विवाद निपटान सुधार पर अनौपचारिक सूचना बैठक पर टिप्पणी
6. DS सुधारों के लिए वार्ता बिंदु - 30 मई को विभागाध्यक्ष की बैठक

7. मध्यस्थता के लिए मसौदा अनुरोध
8. मध्यस्थता के लिए वैकल्पिक संदर्भ शर्तें
9. चीनी ताइपे द्वारा प्रदान किए गए MAS स्पष्टीकरणों पर राय
10. मध्यस्थता निकाय की कार्य प्रक्रियाओं की समीक्षा
11. SL80 के तहत मध्यस्थता के लिए भारत के मसौदा लिखित प्रस्तुतियों पर टिप्पणियाँ ऑस्ट्रेलिया
12. ऑस्ट्रेलिया के साथ SL80 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए भारत के मसौदा लिखित प्रस्तुतियों पर टिप्पणियाँ [द्वितीय समीक्षा]
14. SL80 मध्यस्थता के अंतर्गत अतिरिक्त प्रश्नों की समीक्षा
15. SL80 मध्यस्थता के अंतर्गत अतिरिक्त प्रश्नों पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरों पर टिप्पणियाँ
16. SL80 मध्यस्थता के अंतर्गत अतिरिक्त प्रश्नों पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरों पर भारत की टिप्पणियों की समीक्षा
17. विभागाध्यक्ष की बैठक, DS सुधार ROD (संक्षिप्त)
18. विभागाध्यक्ष की बैठक, DS सुधार ROD (संक्षिप्त)
19. ICT विवाद पर EU के मौखिक नोट पर टिप्पणी
20. भारत-ऑस्ट्रेलिया SL80 मध्यस्थता पर इनपुट
21. SL80 मध्यस्थता के अंतर्गत अतिरिक्त प्रश्नों पर भारत के उत्तरों पर ऑस्ट्रेलिया की टिप्पणियों पर टिप्पणियाँ
22. मेक्सिको में USMCA पैनल रिपोर्ट पर केस नोट्स - आनुवंशिक रूप से इंजीनियर मक्का
23. WTO विवाद निपटान के लिए वैकल्पिक सुझाव - मसौदा कार्य प्रगति पर
24. विवाद निपटान खंड पर CTIL की राय नर्सिंग और देखभाल सेवाओं पर एमआरए के गैर-निष्कर्ष के लिए आईजेसीईपीए. SL80 मध्यस्थता के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तुतियों का खंडन

अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान व्यापार और निवेश कानून केंद्र द्वारा आयोजित/प्रायोजित/भागीदारी वाला कार्यक्रम

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम का नाम
1.	24-25 अगस्त 2024	सम्मेलन- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लैंगिक आयाम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: मुद्दे, चुनौतियाँ और संभावनाएँ।
2.	02 अगस्त 2024	सीटीआईएल का 7वाँ वार्षिकोत्सव
3.	27-28 सितंबर 2024	"बदलती वैश्विक व्यवस्था के लिए लचीले और उत्तरदायी व्यापार को बढ़ावा देना" विषय पर एशियाई और अफ्रीकी अध्यक्षों के लिए डब्ल्यूसीपी क्षेत्रीय सम्मेलन
4.	5-6 अक्टूबर 2024	कानून, अर्थव्यवस्था और एआई पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
5.	5 अक्टूबर 2024	भारत में निवेश पर कानून और नीति पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. जेम्स नेदुयमपारा का मुख्य अतिथि संबोधन: मुद्दे और चुनौतियाँ
6.	26 अक्टूबर 2024	व्यापार और निवेश कानून केंद्र ने 26 अक्टूबर 2024 को सुबह 11:15 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी (आईएसआईएल) द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मेलन में एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।
7.	13-14 दिसंबर 2025	अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक ट्रेडलैब सम्मेलन, 2024

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम का नाम
8.	11 - 12 जनवरी 2025	
9.	06 फरवरी 2025	डब्ल्यूसीपी नेपाल - तीसरा वार्षिक सम्मेलन - जलवायु परिवर्तन और व्यापार एवं स्थिरता
10.	17-19 जनवरी 2025	पैनल 1: महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियाँ: भारत थिंक टैंक फोरम में शक्ति, पहुँच और समानता
11.	10-11 फरवरी 2025	भविष्य की दिशा: औद्योगिक नीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता
12.	28 फरवरी 02 मार्च 2025	बंदरगाह राज्य उपाय समझौते पर कार्यशाला (पीएसएमए) कोचीन, केरल में आयोजित
13.	28-29 मार्च 2025	कानून और नैतिकता, समावेशिता और स्थिरता के आर्थिक विश्लेषण पर 8वां जीएनएलयू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
14.	15 फरवरी 2025	सीटीआईएल-जीएनएलयू-जीएमयू-सेलन महासागर शासन पर सम्मेलन
15.	21-23 फरवरी 2025	मूट कोर्ट प्रतियोगिता लुई ब्राउन मोस्टेन ग्राहक परामर्श प्रतियोगिता
16.	07-10 मार्च 2025	जेएचजेएमसीसी पश्चिम एशिया दौर
17.	31 जुलाई 2024	कार्यक्रम वैश्विक निवेश नीति विकास - एएफसीएफटीए निवेश प्रोटोकॉल और विवाद निवारण पर ध्यान केंद्रित
18.	10 जनवरी 2025	टीएसडी उपायों पर कार्यशाला
19.	10 - 14 फरवरी 2025	पीएसएमओ कार्यक्रम - बंगाल की खाड़ी - मत्स्य पालन विभाग
20.	06 फरवरी 2025	"विकसित भारत की ओर @2047: अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और कानून का सुदृढ़ीकरण" विषय पर सम्मेलन
21.	15 फरवरी 2025 (JJN)	निवेश सम्मेलन - जे. इंदु मल्होत्रा
22.	05 मार्च 2025	पुस्तक लोकार्पण: प्रभास रंजन पुस्तक लोकार्पण
23.	26 मार्च 2025	स्थायित्व, लिंग और एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सत्र और बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ओएफडीआई), एआई और मीडिया, मनोरंजन और एवीजीसी सेवा क्षेत्र पर सत्र।
24.	11-15 फ़रवरी 2025	बैठक - 7वीं आसियान-भारत संयुक्त सलाहकार समूह बैठक और वार्ता दौर
25.	12 फ़रवरी 2025	विशेषज्ञ सलाहकार समूह की बैठक
26.	10-14 मार्च 2025	भारत - यूरोपीय संघ एफटीए (10वां दौर)
27.	19-21 मार्च 2025	व्यापार वार्ता पर पाठ्यक्रम
28.	26 मार्च 2025	मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र की वार्षिक आम बैठक

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम का नाम
29.	27 अगस्त 2024	व्यापार वार्ता "नए भू-राजनीतिक संघर्ष के समय में अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के शस्त्रीकरण" पर विशेषज्ञ वार्ता
30.	4-6 अक्टूबर 2024	का परिचय ट्रेडलैब, अतिथि व्याख्यान और पायलट परियोजना एवं एसीए हस्ताक्षर
31.	23 अक्टूबर 2024	डॉ. जेम्स जे. नेदुम्परा द्वारा तिरुचिरापल्ली में सम्मेलन भाषण
32.	19-22 नवंबर 2024	छठी जेसी एआईटीआईजीए बैठक पर सम्मेलन (समीक्षा वार्ता)
33.	26-28 नवंबर 2024	व्यापार, निवेश और प्रतिस्पर्धा कानून में स्थिरता प्राप्त करने हेतु बहु-विषयक दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
34.	12 दिसंबर 2024	व्यापार समझौतों में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
35.	16-18 दिसंबर 2024	सेलन सम्मेलन
36.	2 जुलाई-2 अगस्त 2024	प्रशिक्षण कार्यक्रम: मानकों, विनियमों और विश्व व्यापार संगठन के एसपीएस और टीबीटी उपायों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
37.	24-25 अगस्त 2024	डीएनएलयू जबलपुर के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लैंगिक आयामों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: मुद्दे, संभावनाएँ और चुनौतियाँ शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सह-आयोजन किया।
38.	30 अगस्त 2024	सीआईआई और एम्फोरी, ब्रुसेल्स के साथ व्यापार और स्थिरता पर सम्मेलन का सह-आयोजन किया।
39.	13 सितंबर 2024	डब्ल्यूटीओ सार्वजनिक मंच जिनेवा में ट्रेडलैब पैनल चर्चा
40.	7-9 अक्टूबर 2024	व्यापार वार्ता पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम
41.	26-27 दिसंबर 2024	पारो में 26-27 दिसंबर को विश्व व्यापार संगठन और संबंधित मामलों पर क्षमता निर्माण कार्यशाला। भूटान के व्यापार विभाग, उन्नत एकीकृत ढाँचे और विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित
42.	2 अगस्त 2024	अध्ययन फाउंडेशन फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून" पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में "एसपीएस और टीबीटी समझौते और उनका तुलनात्मक विश्लेषण" पर व्याख्यान
43.	22 अगस्त 2024	पैनल चर्चा: लॉयड लॉ कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून पर पैनल चर्चा
44.	25 अगस्त 2024	स्केडेन एफडीआई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मूट कोर्ट प्रतियोगिता के दक्षिण एशिया दौर के तीसरे-चौथे स्थान के लिए निर्णायक
45.	22-25 अगस्त 2024	ग्रेटर नोएडा स्थित लॉयड विश्वविद्यालय के सहयोग से सीटीआईएल द्वारा प्रायोजित एफडीआई मूट कोर्ट प्रतियोगिता के लिए मध्यस्थ
46.	23 अक्टूबर 2024	हरित अर्थव्यवस्था (साओ पाउलो) पर पैनल चर्चा
47.	12 नवंबर 2024	एमएसएमई आउटरीच और एफटीए उपयोग वडोदरा

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम का नाम
48.	20-22 नवंबर 2024	सीओपी 29 - "हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना और इसके निहितार्थ: अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जलवायु परिवर्तन जवाबदेही" पर पैनल चर्चा
49.	05-14 फ़रवरी 2025	विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उभरते मुद्दों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
50.	18 फ़रवरी से 24 मार्च 2024)	भारत सरकार के वाणिज्य विभाग (डीओसी) के सहायक अनुभाग अधिकारियों के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय' पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम प्रभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम
51.	25 फ़रवरी 2025	
52.	28 फ़रवरी 2025	सीएसईपी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित निवेश समझौते के प्रति भारत का दृष्टिकोण
53.	16-17 मई 2024	ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, कोलकाता द्वारा आयोजित एआई के लोकतंत्रीकरण पर कार्यशाला
54.	12-13 जून 2024	चिंतन शिविर - एफटीए रणनीति और व्यापार वार्ता के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर दो दिवसीय चिंतन शिविर

अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान हितधारक परामर्श

क्र.सं	हितधारक
1.	खान मंत्रालय के लिए सीबीएएम अध्ययन के प्रभाव पर सीटीआईएल अध्ययन के एक भाग के रूप में भारतीय सीमेंट उद्योग के लिए सीटीआईएल प्रश्नावली
2.	यूरोपीय संघ के एसपीएस अध्याय पर नियामकों के लिए प्रश्नावली
3.	डब्ल्यूबी बी-रेडी प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों पर टिप्पणियाँ
4.	एफटीए के मूल सिद्धांत और सीआईआई के साथ एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता
5.	एसपीएस-टीबीटी पोर्टल के लिए उपयोग की शर्तों/अस्वीकरण सूचना का मसौदा तैयार करना

अप्रैल 2024-मार्च 2025 के दौरान व्यापार और निवेश कानून केंद्र द्वारा प्रकाशन

क्र.सं	वर्ष एवं माह प्रकाशन	शीर्षक/प्रकाशक
शोध पत्र		
1	जून 2025	"बांग्लादेश में बाल-नेतृत्व वाली जलवायु मुकदमेबाजी की आवश्यकता: भारत और पाकिस्तान से सबक"
2	अप्रैल 2024	अपशिष्ट के शिपमेंट पर यूरोपीय संघ का विनियमन: लौह और इस्पात क्षेत्र में भारतीय एमएसएमई पर चुनौतियाँ और प्रभाव
3	दिसंबर 2024	कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव (सीएसडीडीडी) के विशिष्ट संदर्भ में निजी अभिनेताओं के कॉर्पोरेट उद्देश्य के साथ स्थिरता आयामों का एकीकरण" 7 से 9 दिसंबर 2024 तक "विकास, स्थिरता और लचीलेपन का संगम" विषय पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा आयोजित भारत प्रबंधन अनुसंधान सम्मेलन में।

4	दिसंबर 2024	एक स्थायी भविष्य की रूपरेखा: अति-क्षमता और अति-मत्स्य पालन पर विषयों के सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम" 16 से 18 दिसंबर 2024 तक कोलंबो, श्रीलंका में SAIELN के चौथे द्विवार्षिक सम्मेलन में "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून के प्रति स्थानीय दृष्टिकोण" विषय पर।	
5	अक्टूबर 2024	आपराधिक न्याय में एआई-संचालित परिवर्तन: नैतिक दुविधाएँ और व्यावहारिक अनुप्रयोग	
पेपर प्रस्तुति / प्रकाशन			
6	अक्टूबर 2024	"अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और शासन में खाद्य सुरक्षा बनाम खाद्य सुरक्षा से सतत खाद्य प्रणालियों तक" पर नीति संक्षिप्त, T20 ब्राज़ील	प्रो. मार्कस वैगनर, सुश्री विशाखा श्रीवास्तव, और श्री आशुतोष कश्यप.पीपी. 189-197
7	जनवरी 2025	अध्याय VIII: व्यापार उपाय और एबी संकट: एमपीआईए के अंतर्गत कानूनी व्यवस्था की भविष्यवाणी - पृष्ठ 165-179	
8	अगस्त 2024		कैलाश चौहान एवं मोहित यादव द्वारा
9	अगस्त 2024	कोलंबिया एफडीआई परिप्रेक्ष्य: सामयिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुद्दों पर परिप्रेक्ष्य	
10	अगस्त 2024		जेम्स जे. नेदुम्पारा द्वारा
11	मार्च 2025	भारत की द्विपक्षीय निवेश संधियाँ 2.0: धारणाएँ, उभरते रुझान और संभावित संरचना, स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर	अर्णव शर्मा, आशुतोष कश्यप द्वारा
सामग्री			
12	जून 2024	व्यापार समझौतों में सतत विकास में 'विकास' की भूमिका	जेम्स जे नेदुम्परा द्वारा
13	मार्च 2024	एक समृद्ध भविष्य का निर्माण: आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते के लाभों का अनावरण (स्तंभ II)	आशुतोष कश्यप द्वारा
14	अगस्त 2024	निवेश संधियों में स्थिरता: भविष्य में क्या है?	शाइनी प्रदीप द्वारा

कॉर्पोरेट संबंध और प्लेसमेंट प्रभाग

एमबीए (आईबी) 2023-25 बैच के अंतिम प्लेसमेंट

आईआईएफटी ने अपने प्रमुख एमबीए (आईबी) कार्यक्रम के 2023-25 बैच के लिए अंतिम प्लेसमेंट का समापन किया। प्लेसमेंट चक्र में विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों से 45 नए कॉर्पोरेट संघों सहित 135 प्रतिष्ठित भर्तीकर्ताओं ने भाग लिया। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, आईआईएफटी ने ₹31.3 लाख प्रति वर्ष की औसत सीटीसी और ₹26.0 लाख प्रति वर्ष की औसत सीटीसी के साथ अपने प्लेसमेंट का समापन किया। उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय सीटीसी उल्लेखनीय ₹1.23 लाख प्रति वर्ष रहा, जबकि उच्चतम घरेलू सीटीसी ₹72.0 लाख प्रति वर्ष तक पहुँच गया, जिसमें 38% से अधिक बैच को प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) प्राप्त हुए। बैच के शीर्ष 25% के लिए औसत सीटीसी ₹49.6 लाख प्रति वर्ष था।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) अपनी कठोर शिक्षा पद्धति, मज़बूत उद्योग संपर्क और भावी वैश्विक नेताओं को आकार देने में 62 वर्षों से अधिक की विरासत के कारण, विशिष्ट भर्तीकर्ताओं के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मज़बूत कर रहा है। इस वर्ष, एकॉर्डियन, एक्सस, अफ्रीकन इंडस्ट्रीज, एग्रोकॉर्प, ब्लिंकिट, सेलेबल टेक्नोलॉजी, क्यूरेटेक, ग्रांट थॉमटन, इंफोसिस सीएसजी, जावा, माइकल पेज, ओएफआई, रॉकवाफथ, सी6 एनर्जी और एसएमबीसी सहित कई प्रतिष्ठित ब्रांडों के साथ नए सहयोग स्थापित हुए।

संस्थान के कुलपति, प्रो. डॉ. राकेश मोहन जोशी ने इस वर्ष के उत्कृष्ट प्लेसमेंट परिणामों पर अत्यधिक गर्व व्यक्त किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि कॉर्पोरेट जगत का निरंतर विश्वास आईआईएफटी छात्रों की असाधारण प्रतिभा, व्यावसायिकता और वैश्विक तत्परता को दर्शाता है। उन्होंने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि शैक्षणिक उत्कृष्टता और व्यावहारिक अनुभव के प्रति संस्थान का एकीकृत दृष्टिकोण स्नातकों को विभिन्न उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है।

सबसे ज़्यादा मांग वाले रणनीति और परामर्श क्षेत्र में कुल प्रस्तावों का 22% हिस्सा रहा। उल्लेखनीय संगठनों में एकॉर्डियन, ब्लैकस्टोन, कैपजेमिनी, सेलेबल टेक्नोलॉजी, डेलॉइट एडवाइज, डेलॉइट कंसल्टेंट, ईवाई, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ स्ट्रैटेजी, ग्रांट थॉर्नटन, इंडिगो, इंफोसिस सीएसजी, आईओसीएल, जेपीएमसी, मैकिन्से, मैक्लॉड्स, माइकल पेज, पीडब्ल्यूसी, रॉकसर्च, टाइगर एनालिटिक्स, विप्रो, डब्ल्यूएनएस और जेडएस एसोसिएट्स शामिल हैं। एकॉर्डियन, सेलेबल टेक्नोलॉजी और माइकल पेज जैसे नए प्रवेशकों ने इस क्षेत्र में अवसरों को और विविधता प्रदान की।

बिक्री और विपणन क्षेत्र ने कुल प्रस्तावों में 21% का योगदान दिया, जो इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा। सम्मानित भर्तीकर्ताओं में एबीएफआरएल, एबीएफआरएल, एशियन पेंट्स, बीरा91, डियाजियो, एली लिली, कोडरेज़ कलर्स्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हेलियन, हीरो मोटोकॉर्प, एचटी मीडिया, आईटीसी, जावा, मारुति सुजुकी, रेकिट, रॉकवर्थ, रॉकवर्थ, सैमसंग, स्प्रिंटो, टीएएस, टीसीपीएल, टाइटन, टाइटन, वरुण बेवरेजेस और वेदांता शामिल थे।

वित्त क्षेत्र 19% प्रस्तावों के साथ एक मज़बूत स्तंभ बना रहा, जिसमें कॉर्पोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट और फ़र्मटेक में प्रतिष्ठित भूमिकाएँ शामिल थीं। प्रतिष्ठित भर्तीकर्ताओं में आदित्य बिड़ला कैपिटल, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, क्रिसिल, क्यूरेटक, डेज़र्व इन्वेस्टमेंट्स, ईटीजी, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई, आईडीएफसी फ़र्स्ट बैंक, आईबीडीआईसी, जिंदल स्टेनलेस, जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी, रॉकवर्थ, एसएमबीसी, टाटा एआईए, टाटा एआईए, ट्रेसविस्टा और वेदांता शामिल थे।

एथर, एक्सिस बैंक, ब्लिंकिट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, इंडिगो, इंडिजीन, आईओसीएल, आईओसीएल, जेएसडब्ल्यू, एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी6 एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, टीएएस और ट्राइडेंट जैसे संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों में सामान्य प्रबंधन क्षेत्र का योगदान 14% रहा, जिसमें विभिन्न उद्योगों के प्रतिष्ठित नेतृत्व कार्यक्रम भी शामिल थे।

ट्रेड एवं ऑपरेशंस में 13% ऑफर आए, जिनमें अदानी विल्मर, अफ्रीकन इंडस्ट्रीज, एग्रोकॉर्प, अमेज़न, डीटीडीसी, ईट्रेड, गेल, एचपीसीएल, एचपीसीएल, एलडीसी, ओएफआई, सी6 एनर्जी, सीशेल लॉजिस्टिक्स और टाटा स्टील जैसी कंपनियों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमुख भूमिकाएँ प्रदान कीं।
आईटी/एनालिटिक्स और उत्पाद प्रबंधन क्षेत्र, जो कुल ऑफर का 11% है, में एकॉर्डियन, अमेज़न, बजाज फिनसर्व, ब्लूमबर्ग, डीटीडीसी, एक्सपीरियन, आईपीकार्ट, जूसपे, जूसपे, लोव्स इंडिया, एलटीआई माइंडट्री, एमएई सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट और टैफे की मजबूत भागीदारी देखी गई।

एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, अमेज़न, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, ब्लूमबर्ग, कैपजेमिनी, डेलोइट, आई, फ्लिपकार्ट, गोदरेज, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, मेर्सक, मारुति सुजुकी, फिलिप्स, पीडब्ल्यूसी, रिलायंस, सैमसंग, टाटा ग्रुप, टाइटन और ट्राइडेंट जैसे पुराने भर्तीकर्ताओं ने एक बार फिर आईआईएफटी के प्रतिभा पूल में अपना विश्वास प्रदर्शित किया, तथा विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों की एक बड़ी संख्या का चयन किया।

आईआईएफटी में कॉर्पोरेट संबंध एवं प्लेसमेंट विभाग की प्रमुख डॉ. पूजा लखनपाल ने सभी सहयोगी संगठनों के अटूट विश्वास के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने दीर्घकालिक कॉर्पोरेट संबंध बनाने पर संस्थान के फोकस पर प्रकाश डाला और छात्रों के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। डॉ. लखनपाल ने आगे कहा कि इस वर्ष के प्रस्तावों की गुणवत्ता और पैमाने ने आईआईएफटी को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले एक शीर्ष-स्तरीय बिजनेस स्कूल के रूप में स्थापित किया है।

प्रथम बिजनेस एनालिटिक्स (बीए) 2023-25 बैच के लिए अंतिम प्लेसमेंट

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) को अपने प्रथम एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम, 2023-25 कक्षा के अंतिम प्लेसमेंट के सफल समापन की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। इस ऐतिहासिक प्लेसमेंट चक्र में 25 से अधिक नए कॉर्पोरेट संघों और विविध उद्योगों के कई प्रतिष्ठित भर्तीकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अग्रणी बैच ने अच्छे परिणाम प्राप्त करके एक नया मानदंड स्थापित किया है जो आईआईएफटी की शिक्षा पद्धति की गुणवत्ता और इसके छात्रों की असाधारण प्रतिभा को रेखांकित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा-संचालित निर्णय लेने के युग में, इस बैच का मजबूत प्रदर्शन बिजनेस एनालिटिक्स-केंद्रित पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करता है।

बदलते आर्थिक परिदृश्य के बावजूद, बीए बैच ने उल्लेखनीय परिणाम दिए। उच्चतम घरेलू सीटीसी सराहनीय ₹72.0 LPA रहा। औसत सीटीसी ₹25.3 LPA रहा, जिसका औसत सीटीसी ₹20.0 LPA रहा। बैच के शीर्ष 25% छात्रों का औसत सीटीसी ₹40.0 LPA तक पहुँच गया, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शीर्ष स्तरीय विश्लेषणात्मक प्रतिभा की प्रबल माँग को दर्शाता है। बीए प्रोग्राम के नवीन पाठ्यक्रम, कठोर शैक्षणिक प्रशिक्षण और केस स्टडीज़ व परियोजनाओं के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव ने इसे विशिष्ट भर्तीकर्ताओं के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। इस वर्ष, आर्केसियम, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, एलडीसी, फास्ट रिटेलिंग, एसबीआई लाइफ, फ्लिपकार्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और विप्रो सहित कई अन्य प्रमुख ब्रांडों के साथ नए सहयोग स्थापित हुए।

प्लेसमेंट में विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाओं का व्यापक वितरण देखा गया, जिससे बीए प्रोग्राम के स्नातकों की बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ: आईटी और एनालिटिक्स: यह सबसे अधिक मांग वाला क्षेत्र था, जो कुल प्रस्तावों का 28% था। इस डोमेन के लिए भर्तीकर्ताओं में आर्केसियम, एक्सट्रिया, डनहम्बी, आईजीटी सॉल्यूशंस, मारुति सुजुकी, एनएबी और डब्ल्यूएनएस शामिल थे।

बिक्री एवं विपणन: कुल प्रस्तावों में 27% का योगदान देते हुए, यह क्षेत्र दूसरे स्थान पर रहा। प्रमुख भर्तीकर्ताओं में बोरोसिल, हीरो फिनकॉर्प, लोकोफास्ट, एमएक्यू सॉफ्टवेयर, क्वालकॉम, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, स्प्रिंटो, ट्राइडेंट, वेदांता और विप्रो शामिल थे, जिन्होंने ब्रांड प्रबंधन, प्रमुख खाता प्रबंधन और बिक्री में पदों की पेशकश की।

रणनीति एवं परामर्श: कुल प्रस्तावों में इस क्षेत्र का योगदान 22% था, जो रणनीतिक प्रतिभाओं की उच्च मांग को दर्शाता है। भर्तीकर्ताओं में अफ्रीकन इंडस्ट्रीज, कॉग्निजेंट, डीटीडीसी, ईवाई, फास्ट रिटेलिंग, हीरो फिनकॉर्प और हीरो मोटोकॉर्प जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल थे।

व्यापार एवं संचालन: कुल प्रस्तावों में इस क्षेत्र का योगदान 13% था। छात्रों को फ्लिपकार्ट, एलडीसी और टाटा स्टील जैसी अग्रणी कंपनियों में प्लेसमेंट मिला, जहाँ आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भूमिकाएँ प्रदान की गईं।

वित्त: वित्त क्षेत्र ने 10% प्रस्तावों का योगदान दिया। प्रतिष्ठित भर्तीकर्ताओं में ब्लैकस्टोन, आईडीबीआई और एसबीआई लाइफ शामिल थे, जिन्होंने कॉर्पोरेट बैंकिंग और धन प्रबंधन में प्रतिष्ठित पदों की पेशकश की।

आईआईएफटी के कुलपति प्रो. (डॉ.) राकेश मोहन जोशी ने इस वर्ष के प्लेसमेंट परिणामों पर संतोष व्यक्त किया और आईआईएफटी के छात्रों पर निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट भागीदारों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग उद्योग-अकादमिक सहयोग को मज़बूत करने और छात्रों को बहुमूल्य शिक्षण अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आईआईएफटी में कॉर्पोरेट संबंध एवं प्लेसमेंट प्रभाग की प्रमुख डॉ. पूजा लखनपाल ने सभी सहयोगी संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "उद्योग जगत का अटूट विश्वास और ज़बरदस्त प्रतिक्रिया वाकई बेहद सराहनीय है। हम इन संबंधों को मज़बूत करने और पहले दिन से ही योगदान देने के लिए तैयार प्रतिभाओं का एक समूह प्रदान करने के लिए तत्पर हैं।" इस वर्ष के प्रस्तावों की गुणवत्ता और व्यापकता आईआईएफटी के कार्यक्रम को महत्वाकांक्षी व्यावसायिक नेताओं के लिए एक प्रमुख विकल्प के रूप में स्थापित करती है।

एमबीए (आईबी) 2024-26 बैच के ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने अपने प्रमुख एमबीए (आईबी) कार्यक्रम के 2024-26 बैच के लिए ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 105 से अधिक संगठनों ने भाग लिया। चुनौतीपूर्ण बाजार परिवेश के बावजूद, संस्थान ने दो महीने की इंटर्नशिप अवधि के लिए ₹2.73 लाख का औसत वजीफा और ₹2.50 लाख का औसत वजीफा दर्ज किया। उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय वजीफा ₹6.00 लाख था, जबकि उच्चतम घरेलू वजीफा ₹4.50 लाख था। उल्लेखनीय रूप से, 60 से अधिक छात्रों को ₹4.00 लाख से अधिक के ऑफर मिले।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने अपने समृद्ध शिक्षण पद्धति, व्यापक पाठ्यक्रम और कॉर्पोरेट प्रतियोगिताओं में सफलता के प्रभावशाली इतिहास के कारण प्रतिष्ठित भर्तीकर्ताओं के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। 62 वर्षों से भी अधिक की विरासत के साथ, आईआईएफटी व्यावसायिक जगत के भावी नेताओं को आकार देने में एक स्तंभ के रूप में खड़ा है। आईआईएफटी ने एयरटेल, ब्रिटानिया, बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी, क्रैनमोर पार्टनर्स, देहात, डूम, केनव्यू, लिशियस, मास्टरकार्ड, नोमुरा, परफेटी वैन मेले, पतंजलि, पब्लिसिस ग्रुप स्टैंडर्ड चार्टर्ड, टैफे और प्रतिष्ठित इंडिगो एस्पायर लीडरशिप प्रोग्राम सहित कई प्रतिष्ठित ब्रांडों के साथ नए संबंध स्थापित किए हैं, जो ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आईआईएफटी के कुलपति प्रो. (डॉ.) राकेश मोहन जोशी ने इस वर्ष के ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप परिणामों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा आईआईएफटी के छात्रों पर निरंतर भरोसा उनकी प्रबल प्रतिभा और क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि ये परिणाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने, छात्रों को उद्योग में बेहतर प्रदर्शन करने और सफल होने के लिए तैयार करने की संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
बिक्री और विपणन सबसे अधिक मांग वाले क्षेत्र के रूप में उभरे, जिनकी कुल पेशकशों में 34% हिस्सेदारी रही। उल्लेखनीय कंपनियों में आदित्य बिड़ला फैशन रिटेल, एशियन पेंट्स, ब्लूमबर्ग, डाबर, डियाजियो, गैलडर्मा, गोदरेज, हैलियन, एचटी मीडिया, आईटीसी, एलएंडटी, मैरिको, मार्स, मारुति सुजुकी, फिलिप्स, फोनपे, प्यूमा, सैमसंग, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाइटन आदि शामिल हैं।

इस क्षेत्र में एयरटेल, अमूल, ब्रिटानिया, हैवेल्स, इंडिगो, एचयूएल, केनव्यू, लिशियस, पतंजलि, परफेटी वैन मेले, पब्लिसिस, टैफे और यूनिक्लो जैसी भर्ती कंपनियों के साथ नए जुड़ाव भी स्थापित हुए।

छात्रों ने कॉर्पोरेट ट्रेजरी, निवेश बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, धन प्रबंधन, इक्विटी अनुसंधान और फिनटेक जैसी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त करके वित्त क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित की, जो इस बैच को मिले प्रस्तावों का 21% था। इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित भर्ती कंपनियों में आदित्य बिड़ला कैपिटल, बैंक ऑफ अमेरिका, क्रैनमोर पार्टनर्स, क्रिसिल, डीई शॉ, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, डेलॉइट यूएसआई, गोदरेज, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, एलएंडटी, नोमुरा, परफेटी वैन मेले और स्टैंडर्ड चार्टर्ड आदि शामिल हैं।
इस प्लेसमेंट सीज़न में महत्वाकांक्षी रणनीति और परामर्श क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में ऑफर आए। रणनीति और परामर्श क्षेत्र में भूमिकाएँ प्रदान करने वाली कंपनियों में एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, अमेज़न, एक्सिस बैंक, कैपजेमिनी, डेलॉइट यूएसआई, गोदरेज, जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी, पब्लिसिस ग्रुप, वीमेंटर.एआई और थिंक थ्रू कंसल्टिंग शामिल थीं, जिन्हें कुल ऑफरों का 10% मिला।

प्रतिष्ठित सामान्य प्रबंधन क्षेत्र में 13% ऑफर के साथ उल्लेखनीय हिस्सेदारी देखी गई, जिसमें एक्सिस बैंक, एचटी मीडिया, इंडिगो, जेएसडब्ल्यू, मारुति सुजुकी, प्रीमियर इन्फोअसिस्ट, रिलायंस, सारा इंटरनेशनल, टीएएस, ट्राइडेंट ग्रुप जैसी कंपनियों से ऑफर आए। प्लेसमेंट सीज़न में कंपनियों ने अपनी प्रतिष्ठित नेतृत्व भूमिकाओं के लिए भर्ती की, जैसे इंडिगो - एस्पायरिंग लीडर्स प्रोग्राम, टाटा समूह में टीएएस- लीडरशिप प्रोग्राम, जिंदल समूह में जेएसडब्ल्यू- लीडरशिप प्रोग्राम और रिलायंस समूह में रिलायंस- लीडरशिप प्रोग्राम।

ट्रेड और ऑपरेशंस ने कुल प्लेसमेंट में 12 साल की हिस्सेदारी दर्ज की, जिसमें मैनेजमेंट इंटर्न के लिए ऑफर शामिल थे। अमेज़न, अमूल, अनाकिन, बीडी, देहात, गोल्डन एग्री-रिसोर्सेज, डीसीएम श्रीराम, फ्लिपकार्ट, केनव्यू, एलएंडटी, एलडीसी, मेर्सक, मारुति सुजुकी, सीस्टारक, टाटा स्टील और यूनिक्लो जैसी प्रतिष्ठित भर्ती कंपनियों ने इन क्षेत्रों में कई पदों के लिए आवेदन किया।

आईटी/एनालिटिक्स और उत्पाद प्रबंधन क्षेत्र कुल प्रस्तावों के 9% के साथ आकर्षक बने रहे। इनमें पुराने भर्तीकर्ताओं और पहली बार जुड़ने वाले लोगों की भागीदारी देखी गई। आईआईएफटी को अमेज़न, ब्लूमबर्ग, कैपजेमिनी, डूम, फ्लिपकार्ट, फ्रॉस्ट एंड सुलिवन, लिशियस, मास्टरकार्ड, फोनपे, सोशल पायलट, टैफे और कई अन्य कंपनियों की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला। हमने आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, अमेज़न, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, कैपजेमिनी, डाबर, डीई शॉ, डेलॉइट यूएसआई, डियाजियो, फ्लिपकार्ट, गोदरेज, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, मेर्सक, मार्स, फिलिप्स, फोनपे, पब्लिसिस ग्रुप, प्यूमा, रिलायंस, सैमसंग, टाटा ग्रुप, टाइटन और ट्राइडेंट जैसी दिग्गज भर्ती कंपनियों को बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन करते देखा, जो आईआईएफटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले छात्रों की गुणवत्ता का प्रमाण है।

आईआईएफटी में कॉर्पोरेट संबंध और करियर एडवांसमेंट प्रभाग की प्रमुख डॉ. पूजा लखनपाल ने इस वर्ष की भर्ती प्रक्रिया के लिए आईआईएफटी के साथ भागीदारी करने वाली कंपनियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सार्थक, दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता के बारे में बात की, जो उनके अनुसार इसकी प्लेसमेंट सफलता का आधार है। डॉ. लखनपाल ने छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और कॉर्पोरेट जगत में कदम रखने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि वे जहां भी जाएंगे, सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।
IIFT ने दिल्ली परिसर के लिए MBA (BA) 2024-26 बैच के ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट का समापन किया

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) ने अपने दिल्ली परिसर में MBA बिज़नेस एनालिटिक्स बैच 2024-26 के लिए ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट का समापन किया। इस प्रक्रिया में एनालिटिक्स, वित्त, परामर्श, उत्पाद, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री एवं विपणन, और सामान्य प्रबंधन में पदों की पेशकश करने वाले 38 संगठनों ने भाग लिया। अधिकतम प्रस्तावित वजीफा 4.00 लाख रुपये था, जिसमें औसत वजीफा ₹1.41 लाख और दो महीने की इंटर्नशिप अवधि के लिए औसत वजीफा ₹1.10 लाख था। IIFT के MBA (बिजनेस एनालिटिक्स) कार्यक्रम में 100% ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट दर्ज किए गए, जिसमें भर्तीकर्ताओं ने एनालिटिक्स, वित्त, परामर्श, संचालन और विपणन जैसे क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए। कार्यक्रम ने अपने पहले वर्ष के अंतिम प्लेसमेंट में भी उत्साहजनक परिणाम देखे हैं, जिसका औसत CTC देश के कई प्रमुख B-विद्यालयों के बराबर है।

प्लेसमेंट सीज़न की मुख्य बातें

- बिक्री, विपणन और सामान्य प्रबंधन 34% प्रस्तावों के साथ शीर्ष योगदानकर्ता के रूप में उभरे। प्यूमा, ट्राइडेंट, प्लाडिस, मेडट्रॉनिक जैसी कंपनियों ने बाजार विस्तार, रणनीति और ग्राहक अंतर्दृष्टि में भूमिकाएँ प्रदान कीं।

- वित्त क्षेत्र में 21% प्रस्ताव आए, जबकि जे.पी. मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी, गोल्डमैन सैक्स, आदित्य बिड़ला कैपिटल, क्रिसिल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका और ऑरम इक्विटी जैसी प्रतिष्ठित फर्मों ने धन प्रबंधन, इक्विटी अनुसंधान और जोखिम विश्लेषण में भूमिकाएँ प्रदान कीं।

- उत्पाद प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 16% प्रस्ताव आए। क्वालकॉम, मेडट्रॉनिक, एसएबीआईसी, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, ट्रेव मोबिलिटी, डूम, एनाकिन, सीस्टार इंटरनेशनल और मर्कडोस एनर्जी जैसी कंपनियों ने व्यावसायिक बुद्धिमत्ता, उत्पाद रणनीति और विश्लेषण में पदों के लिए नियुक्तियाँ कीं।

- व्यापार, संचालन एवं आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में भी 16% प्रस्ताव आए, जिनमें गोल्डन एग्री, एलडीसी, डीसीएम श्रीराम, बीडी और सीके लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों ने लॉजिस्टिक्स विश्लेषण, माँग पूर्वानुमान और संपूर्ण संचालन में पदों की पेशकश की।

- रणनीति एवं परामर्श के क्षेत्र में 8% प्रस्ताव आए, जिनमें व्यावसायिक रणनीति, विश्लेषण परिवर्तन और परामर्श-आधारित डिजिटल सक्षमता जैसे क्षेत्र शामिल थे।

- सामान्य प्रबंधन की भूमिकाएँ बैच के कुल पदों का 5% थीं, जो उन संगठनों द्वारा प्रस्तावित की गईं जो क्रॉस-फ़ंक्शनल निष्पादन में सक्षम नेतृत्व-ट्रैक इंटर्न की तलाश में थे।

नेतृत्व संबंधी टिप्पणियाँ

आईआईएफटी के कुलपति प्रो. डॉ. राकेश मोहन जोशी ने कहा, "एमबीए (बिजनेस एनालिटिक्स) जैसे नए ज़माने के कार्यक्रम के लिए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रतिष्ठित भर्तीकर्ताओं द्वारा जताया गया भरोसा हमारे पाठ्यक्रम, हमारे संकाय और सबसे बढ़कर, हमारे छात्रों की मज़बूती को दर्शाता है।"

कॉर्पोरेट संबंध एवं प्लेसमेंट विभाग की प्रमुख डॉ. पूजा लखनपाल ने कहा, "प्लेसमेंट का यह परिणाम उद्योग-तैयार एनालिटिक्स लीडर्स तैयार करने के हमारे मिशन की पुष्टि करता है। हम अपने सभी कॉर्पोरेट भागीदारों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आगामी बैचों के साथ नई ऊँचाइयों को छूने के लिए तत्पर हैं।"

छात्र गतिविधियाँ 2024-25

दिल्ली परिसर

2024-25 शैक्षणिक वर्ष एक बार फिर आईआईएफटी दिल्ली के छात्रों के लिए बहुत फलदायी रहा है। दो साल से ज़्यादा समय तक कार्यक्रमों के ऑनलाइन आयोजित होने के बाद, सभी कार्यक्रम धूमधाम से ऑफ़लाइन आयोजित किए गए। कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेड विंडज़
2. यूडब्ल्यूएल
3. मैराथन
4. बिग फाइट
5. एड्रेनालाईन
6. निवेश
7. अंतरंग
8. प्रोदसाहन
9. क्को वादिस
10. टेडएक्स

ट्रेड विंड्स (17-19 अक्टूबर 2024)

मुख्य अतिथि: श्री अभिषेक अग्रवाल (सीआईओएटईईएसएल और सीईएसएल)

ट्रेड विंड्स, आईआईएफटी का वार्षिक व्यावसायिक सम्मेलन है, जो छात्रों को उद्योग जगत के अग्रणी पेशेवरों के साथ जुड़ने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। इस वर्ष के सम्मेलन में वित्त से लेकर मानव संसाधन तक, आठ विविध शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनका मुख्य विषय "द ग्रेट रीसेट: कैटेलाइज़िंग डिजिटल ग्रोथ फॉर द 21वीं सेंचुरी" था। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के दिग्गजों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे ज्ञानवर्धक चर्चाएँ और सार्थक नेटवर्किंग के अवसर पैदा हुए।

यूडब्ल्यूएल - अल्टीमेट वॉरियर्स लीग (4-8 नवंबर 2024)

आईआईएफटी का अनूठा परिसर-व्यापी खेल आयोजन, खेलों के रोमांच को प्रबंधन के मूल सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। यह आयोजन विपणन, वित्त, संचालन, रणनीति और मानव संसाधन प्रबंधन के पहलुओं को एकीकृत करता है, जिससे छात्रों को कक्षा के बाहर एक व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्राप्त होता है। प्रतिस्पर्धी बोली दौरों की एक श्रृंखला के बाद, शीर्ष चार बोलीदाता अपनी टीमों को सुरक्षित करते हैं और ब्रांड प्रबंधकों की नियुक्ति करते हैं, जिससे खिलाड़ियों की गहन नीलामी का मंच तैयार होता है। इसके बाद छात्र क्रिकेट, फुटसल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खेल प्रश्नोत्तरी और शतरंज सहित विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और अपनी एथलेटिक क्षमता, रणनीतिक और प्रबंधकीय कौशल का प्रदर्शन करते हैं।

आईआईएफटी मैराथन (24 नवंबर 2024)

आईआईएफटी मैराथन 2024 नवंबर में आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों, फिटनेस प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक साथ लाया गया जो वास्तव में महत्वपूर्ण है - महिला सुरक्षा। आईआईएफटी के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव, क्वो वादिस 2025 के पूर्वाभ्यास के रूप में आयोजित इस मैराथन का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बातचीत को गति देना था।

300 से ज़्यादा धावकों की भागीदारी के साथ, इस आयोजन में छात्रों और व्यापक समुदाय का उल्लेखनीय उत्साह देखा गया। मैराथन में कई दौड़ श्रेणियों में भाग लिया गया और इसे उन सम्मानित अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो महिला अधिकारों और सुरक्षा के पक्षधर रहे हैं।

बिग फाइट - सेक्शन वॉर्स (7-10 जनवरी 2025)

जनवरी में IIFT दिल्ली के सभी सेक्शनों के बीच एक रोमांचक, जोशीले और प्रतिस्पर्धी माहौल में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। IIFT दिल्ली की सांस्कृतिक समिति - मेलेंज - द्वारा संचालित और आयोजित बिग फाइट में एमबीए की यात्रा के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, नेतृत्व और संचार कौशल शामिल थे। कई कार्यक्रमों, खेलों और गतिविधियों के बाद, सेक्शन ए विजयी हुआ और उसे सेक्शन वॉर्स 2025 का विजेता घोषित किया गया।

आईआईएफटी का प्रमुख खेल टूर्नामेंट, जो खेल समिति द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इस वर्ष बेहद सफल रहा, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में टीमों और कॉलेजों ने भाग लिया। विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं में, खिलाड़ियों और टीमों ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में चैंपियन का खिताब जीतने के लिए कड़ी टक्कर दी। इस आयोजन में संस्थान के पूर्व छात्रों ने भी भाग लिया, जिन्होंने एक बार फिर आईआईएफटी का प्रतिनिधित्व करते हुए इस लीग की भावना और विरासत को और भी मज़बूत किया।

निवेश - मॉक स्टॉक प्रतियोगिता (8 फ़रवरी 2025)

8 फ़रवरी 2025 को, कैपिटल - आईआईएफटी दिल्ली का वित्त एवं निवेश प्रकोष्ठ - ने निवेश'25 नामक एक अंतर-महाविद्यालय ऑफ़लाइन मॉक स्टॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया के बाज़ारों का एक रोमांचक सिमुलेशन दिया गया, जिसमें उनकी वित्तीय सूझबूझ, निर्णय लेने के कौशल और दबाव में लचीलापन का परीक्षण किया गया। निवेश ने प्रतिभागियों की सहज प्रवृत्ति और सीमित समय में जानकारी को समझने और उस पर अमल करने की क्षमता को चुनौती दी, जिससे एक गहन और आकर्षक अनुभव प्राप्त हुआ।

अंतरंग (16 फ़रवरी 2025)

आईआईएफटी दिल्ली का राष्ट्रीय विज्ञापन सम्मेलन, ब्रांडवैगन - आईआईएफटी के मार्केटिंग क्लब द्वारा आयोजित, 16 फ़रवरी 2025 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य छात्रों को गतिशील विज्ञापन जगत से परिचित कराना था, जिससे उन्हें उद्योग की अंतर्दृष्टि और अनुभवों से प्रत्यक्ष रूप से सीखने का अवसर मिले। इस कार्यक्रम में एड-डिकोड, एड-मैड्स, एड-फ़िएस्टा और मेगा एड क्विज़ बैटल जैसी आकर्षक गतिविधियाँ शामिल थीं, जिससे प्रतिभागियों को एक व्यापक और इंटरैक्टिव शिक्षण मंच मिला।

प्रोडसाहन (प्रोडक्ट हेतु प्रोत्साहन) (15 फ़रवरी 2025)

प्रोडसाहन (प्रोडक्ट हेतु प्रोत्साहन), आईआईएफटी दिल्ली के आईटी कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और ई-कॉमर्स क्लब, सिस्टमिक्स का प्रमुख कार्यक्रम है। यह छात्रों को अपने उत्पाद प्रबंधन कौशल का प्रदर्शन करने, नई अवधारणाओं को सीखने, भूलने और फिर से सीखने तथा उत्पाद प्रबंधन और ई-कॉमर्स के नवीनतम रुझानों से अपडेट रहने का एक मंच प्रदान करता है।

प्रोडसाहन में इस वर्ष कई रोमांचक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पीएम बोर्डरूम चैलेंज, पीएम वर्कशॉप और पीएम प्रोडक्ट पिच रिले चैलेंज शामिल हैं, जिससे प्रतिभागियों को एक समग्र और समृद्ध अनुभव प्राप्त हुआ।

क्को वादिस - 25 (21-23 फ़रवरी 2025)

आईआईएफटी दिल्ली का वार्षिक प्रबंधन और सांस्कृतिक उत्सव, क्को वादिस, बौद्धिक दृढ़ता और रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक गतिशील मिश्रण है। यह उत्सव देश भर के प्रमुख बी-स्कूलों के प्रतिभागियों को आकर्षित करता है, और विभिन्न प्रबंधन प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शन कला कार्यक्रमों की पेशकश करता है। प्रेरक केस प्रतियोगिताओं और व्यावसायिक प्रश्नोत्तरी से लेकर ऊर्जावान नृत्य, संगीत और नाटक प्रदर्शनों तक, क्को वादिस छात्रों को अपनी प्रबंधकीय कुशलता और कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो आईआईएफटी में समग्र विकास की भावना को मूर्त रूप देता है।

TEDx IIFT दिल्ली (9 मार्च 2025)

TEDx IIFT दिल्ली एक स्वतंत्र रूप से आयोजित TED कार्यक्रम है जो विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों, नवप्रवर्तकों और परिवर्तनकर्ताओं को IIFT समुदाय के साथ अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए साथ लाता है। केंद्रीय विषय पर प्रत्येक वर्ष आयोजित, इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक सीमाओं से परे सोचने और ऐसे विचारों से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है जो जिज्ञासा को जगाते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं । प्रभावशाली

और सार्थक संवादों के साथ, TEDxIIFTDelhi परिसर में सीखने, चिंतन करने और प्रेरणा देने की संस्कृति को बढ़ावा देता रहता है।

अंतिम विदाई - विदाई 2025

आईआईएफटी दिल्ली में वदाई समारोह एक हार्दिक परंपरा है, जो स्नातक बैच को गर्मजोशी, कृतज्ञता और उत्सव के साथ वदाई देता है। आईएमएफ द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पुरानी यादों और आनंद का मश्रण है, जिसमें प्रस्तुतियाँ, भाषण और यादें शा मल हैं जो जाने वाले छात्रों के सफ़र को दर्शाती हैं। यह संस्थान में उनके योगदान का सम्मान करने और उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश करने पर उन्हें शुभकामनाएँ देने का एक अवसर है।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आईआईएफटी के छात्रों द्वारा जीते गए पुरस्कार

कोलकाता परिसर

क्लब और सेल गतिविधियाँ

क्लब/सेल	तिथि	गतिविधि	विवरण
क्विज़ार्डरी	02 फरवरी	"क्विज़ क्विज़ होता है"	2023 और 2024 के बैच के लिए एक मजेदार मूवी क्विज़ का आयोजन किया गया।
	20 फरवरी	"ब्रांडवाइज़र"	अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन चमत्कारों संबंधी विपणन प्रश्नोत्तरी।
	02 मार्च	"पॉप-ए-राज़ी"	"अद्वैत 23" के दौरान आयोजित एक पॉप संस्कृति प्रश्नोत्तरी।
कोशिश	23 से 27 फरवरी	वस्त्र दान अभियान	ट्विल्स के सहयोग से एक कपड़ा दान अभियान चलाया गया और लगभग 40 बक्से एकत्र किए गए।
ईआरसी	23 फरवरी	"फ्यूचर्स एंड ऑप्शनस" पर सत्र	ईआरसी द्वारा एमबीए आईबी और एमए इको बैचों के लिए इक्विटी मार्केट, इंडिकेटर्स, ऑप्शंस और फ्यूचर्स विषय पर ज्ञान हस्तांतरण सत्र आयोजित किया गया।

खेलकूद गतिविधियां

दिनांक	गतिविधि	विवरण
17 जनवरी	"देसी खेल"	पोंगल, सक्रांति और लोहड़ी के त्योहारों के उत्सव के साथ-साथ मेल खाने वाले मज़ेदार खेलों और गतिविधियों का आयोजन जैसे: खो-खो, पिठू (सितोलिया) , मटका फोड़ इत्यादि खेल।
5 फरवरी	"ऑनलाइन फीफा टूर्नामेंट"	प्रसिद्ध फुटबॉल खेल फीफा 22 का ऑनलाइन टूर्नामेंट।
13-19 फरवरी	सेक्शन वार्स	आईआईएफटी कोलकाता की वार्षिक फ्लैगशिप इंट्रा-कॉलेज खेल प्रतियोगिता 7 दिनों तक आयोजित की गई, जिसमें 5 खेलों और 4 प्रतिस्पर्धावर्गों का आयोजन हुआ ।
7 मार्च	महिला दिवस	महिला दिवस के अवसर पर एक बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक थ्रोबॉल खेल का आयोजन किया गया ।

टोस्टमास्टर्स कार्यक्रम

9 मार्च 2024 को, टोस्टमास्टर्स क्लब की 74वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर भाषण दिए गए। सभी भाषण बिना तैयारी के तुरंत दिए गए और इसमें हमारे 1995-97 बैच के पूर्व छात्र श्री सौम्य उपाध्याय ने भाग लिया।

विवान 9.0

विवान 9.0, 10-12 अक्टूबर 2023 के दौरान "स्थायी डिजिटल परिवर्तनों द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण" विषय पर आयोजित होने वाला वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन है।

यह ऐसे समय में आया है जब दुनिया अभूतपूर्व बदलावों का सामना कर रही है। कोविड-19 महामारी ने विभिन्न उद्योगों में डिजिटल तकनीकों को अपनाने में तेज़ी ला दी है, जिससे व्यवसायों को अपनी रणनीतियों और संचालन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने और एक अधिक समतापूर्ण भविष्य बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई है।

इन बदलावों के मद्देनजर, विवान 9.0 का उद्देश्य स्थायी डिजिटल परिवर्तनों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्संबंध पर गहन चर्चा और अंतर्दृष्टि के लिए एक मंच प्रदान करना है। हमारा लक्ष्य यह पता लगाना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, हरित तकनीक और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसी नवीन प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार आर्थिक विकास को गति प्रदान कर रही हैं और साथ ही पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान भी कर रही हैं।

अद्वैत

1. कोलकाता परिसर के छात्रों ने 2-3 मार्च 2024 को अपना वार्षिक कॉलेज उत्सव, अद्वैत 2024, आयोजित किया।

2. आईआईएफटी, कोलकाता के छात्रों ने स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 किलोमीटर की मैराथन 1.0 दौड़ का भी आयोजन किया। 220 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और विभिन्न श्रेणियों में वितरित पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा की। इस आयोजन को प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से भी लाभ हुआ, जिससे हमारे आउटरीच प्रयासों को बल मिला। स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के साथ रचनात्मक साझेदारी ने आयोजन के सुचारू संचालन और अंतिम सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ मिलकर, हमने जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक समर्थन को बढ़ावा देने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया।

उद्योग, व्यापार और वाणिज्य जगत संबंधी संपर्क

आईआईएफटी उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञों को अपने समृद्ध अनुभव और ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत करने, कॉर्पोरेट जगत की बेहतर समझ हासिल करने और अपने सीखने के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इस वर्ष आईआईएफटी परिसर में आने वाले कुछ प्रख्यात वक्ता थे:

नाम	पदनाम	संगठन
प्रो. अभिषेक मित्तल	निदेशक एम एंड ए	मेर्सक सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
अभिषेक मित्तल	निदेशक एम एंड ए	मेर्सक सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
प्रो. अनिरुद्ध घोष	फैकल्टी	आईसीएफएआई बिजनेस स्कूल, गुरुग्राम
डॉ. अनीता सिंह	वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक	एमडीआई, गुड़गांव
प्रो. अंकिता नागपाल	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
डॉ. अर्घो बंद्योपाध्याय	व्याख्याता	आरएमआईटी मेलबर्न
डॉ. अरुण के. पांडे	संस्थापक और प्रबंध निदेशक	संपरी कंसल्टेंसी
प्रोफेसर अरुण पांडे	प्रोफेसर	संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक SANPRI कंसल्टेंसी, ह्यूस्टन, टेक्सास (अमेरिका)
प्रोफेसर आशीष द्विवेदी	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो. बिप्लब भट्टाचार्य	सह - प्राध्यापक	विजिटिंग फैकल्टी
बिप्लब भट्टाचार्य	सह - प्राध्यापक	विजिटिंग फैकल्टी
प्रोफेसर चन्द्रशेखर भुवनगिरी	प्राध्यापक	डीकिन विश्वविद्यालय, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर (गुजरात) में विजिटिंग फैकल्टी
चन्द्रशेखर भुवनगिरी	प्राध्यापक	डीकिन विश्वविद्यालय, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर (गुजरात) में विजिटिंग फैकल्टी
प्रो. दिशांत पोपली	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
डॉ गौरव कुमार	सहायक प्रोफेसर	एनआईटी जालंधर
प्रो. हर्षवर्धन	प्राध्यापक	विभिन्न प्रसिद्ध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर
डॉ हर्षवर्धन	प्राध्यापक	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय
हर्षवर्धन	प्राध्यापक	विभिन्न प्रसिद्ध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर
डॉ. जीता सरकार	सहायक प्रोफेसर	जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
प्रो कुमार गौरव	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी

डॉ. एम.पी. सिंह	निदेशक	एसएमआई, दुबई
प्रो. मनप्रीत कौर	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
डॉ. नलिन जैन	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रोफेसर नवीन कुमार	संकाय	संस्थापक और प्रबंध साझेदार, नवीन एंड नवीन
प्रो.नीरज गेहानी	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो नीता त्रिपाठी	व्यावसायिक विशेषज्ञता	अतिथि संयोजक
प्रो. नितिन सेठ	निदेशक	उन्नत अनुसंधान संवर्धन के लिए भारत-फ्रांसीसी केंद्र
डॉ. परवेश अघी	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
डॉ. राहुल मिश्रा	प्राध्यापक	आईआईएलएम, नई दिल्ली
प्रो राहुल प्रताप सिंह कौरव	संकाय	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
प्रोफेसर राकेश सेठ	संस्थापक निदेशक	नेतृत्व के विषय में प्रो. सेठ के कथन
प्रोफेसर रमेश बहल	प्रोफेसर एवं निदेशक	आईएमआई, नई दिल्ली
प्रो. रिक पॉल	संकाय	बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय
डॉ. साहिल गुप्ता	सह - प्राध्यापक	जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस
प्रो.संजीव नंदवानी	प्रधान सचिव	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
प्रो.संजीव शंकर दुबे	प्राध्यापक	भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रसिद्ध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर
प्रो. सरबजीत बुटालिया	प्रशिक्षण सलाहकार	वीशिप्स (यूके)
प्रो. शशांक शेखर शर्मा	सीईओ और संस्थापक	ब्रेनपैन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
शशांक शेखर शर्मा	सीईओ और संस्थापक	ब्रेनपैन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
प्रो. शिखर रंजन	निदेशक	एशियाई अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन दिल्ली
डॉ. शिलादित्य दासगुप्ता	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो. सुनीता डैनियल	सह - प्राध्यापक	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
सुनीता डेनियल	सह - प्राध्यापक	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
प्रो. तमन्ना चतुर्वेदी	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो. तरुण केहैर	सीए	सीए तरुण केहैर एंड कंपनी
प्रो. विपुलेश शारदेव	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो. योगेश कुमार वर्मा	सीईओ	मैनेजमेंट परफेक्ट स्क्वायर

विदेश व्यापार पुस्तकालय

विदेश व्यापार पुस्तकालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक परिवेश पर सूचना संसाधनों के एक संगठित संग्रह का ज्ञानकोष है। यह पाठकों के संदर्भ या उधार के लिए मुद्रित या ई-रूप में अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है। इसने अपने संग्रह में विशिष्ट प्रकाशन, रिपोर्ट, डेटाबेस, ई-पत्रिकाएँ, मुद्रित पत्रिकाएँ, लेख आदि जोड़ने और नियमित रूप से स्वयं को अद्यतन करने का निरंतर प्रयास किया है। वर्तमान में, पुस्तकालय में 1,09,807 संसाधनों का एक प्रभावशाली संग्रह है, जिसमें 80,955 पुस्तक/सीडी-खंड, 19,032 जिल्दबंद पत्रिकाएँ और सांख्यिकीय सिद्धांत, बैंकिंग, उद्योग, प्रबंधन, विपणन, उपभोक्तावाद, भू-राजनीतिक आर्थिक प्रणालियाँ, सेवाएँ, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परिवहन और व्यावसायिक संचार आदि विषयों पर 363 पत्रिकाएँ शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, इसके संग्रह में शोध रिपोर्ट, कंपनी रिपोर्ट, सांख्यिकीय वार्षिक प्रकाशन, केस स्टडी सीडी-रोम और वीडियो कैसेट शामिल हैं। पुस्तकालय में अपने दिल्ली, कोलकाता और काकीनाडा परिसरों के लिए ई-संसाधनों का एक विशेष संग्रह है, और इसका एक विशिष्ट केंद्र, CRIT संसाधन केंद्र भी है, जो विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन और उससे जुड़े मुद्दों पर समृद्ध जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, ITC/UNCTAD/WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, भारत सरकार के मंत्रियों और विभागों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशनों से निरंतर समृद्ध होता रहता है।

सीआरआईटी संसाधन केंद्र सहित सभी आईआईएफटी परिसर पुस्तकालयों के लिए 2024-2025 के दौरान पुस्तकालय अधिग्रहण का अनुभाग-वार वितरण नीचे दिया गया है।

2024-2025 के दौरान पुस्तकालय अधिग्रहण की स्थिति

अनुभाग	2024-2025 में अधिग्रहण	कुल 31-3-2025 तक
पुस्तकें, रिपोर्ट, वीडियो कैसेट और सीडी-रोम	1239	80,955
दस्तावेज़	0	9,122
पत्रिकाओं के बाउंड संस्करण (प्राप्त निःशुल्क पत्रिकाओं सहित)	754	19,032
सदस्यता प्राप्त पत्रिकाएँ	130	363
डेटाबेस/ऑनलाइन साइटें/ई-पत्रिकाएँ	43	70
कुल	**2166**	**1,09,807**

ई-संसाधन

अपने केंद्रों, यानी दिल्ली, कोलकाता और काकीनाडा के पाठकों के लिए चौबीसों घंटे जानकारी की ऑनलाइन पहुंच की सुविधा के लिए पुस्तकालय ब्लूमबर्ग, सीएमआईई डेटाबेस (प्रोवेस, इंडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्री एनालिसिस सर्विस), कमोडिटी प्राइस बुलेटिन, डीजीसीआईएस स्टैटिस्टिक्स, एफार्मेल, आईएफएस, इंडिया स्टेट.कॉम, इनसाइड ट्रेड.कॉम, प्रोक्वेस्ट, सन्स मैगज़ीन, ट्रेड मैप, वर्ल्ड बैंक ऑनलाइन डेटाबेस, वर्ल्ड ट्रेड एटलस, डब्ल्यूआईटीएस जैसे 29 ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटाबेस और कई व्यक्तिगत पत्रिकाएँ जैसे ई-जर्नल पैकेज की सदस्यता, ईबीएससीओ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) ले रहा है। ये डेटाबेस देशों के अध्ययन पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं; कृषि, अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी, श्रम, मीडिया, शिक्षा बाजार पूर्वानुमान, बाजार रिपोर्ट, कंपनियों के शेयर बाजार टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के विवादों पर

वार्षिक डेटा विदेशी व्यापार, विभिन्न देशों के साथ भारत का क्षेत्रीय एकीकरण तथा विदेशी व्यापार से संबंधित कई अन्य क्षेत्र। CRIT संसाधन केंद्र WTO संसाधन केंद्र, जो पुस्तकालय में स्थापित है, एक प्रसिद्ध केंद्र है जो विशिष्ट WTO और संबंधित मुद्दों में विशेषज्ञता रखता है। केंद्र WTO से संबंधित मुद्दों और भारत पर इसके प्रभावों के बारे में शोध विद्वानों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों की जरूरतों को पूरा करता है। केंद्र में WTO और संबंधित मुद्दों पर पुस्तकों, रिपोर्टों, पत्रिकाओं, वीडियो कैसेट, सीडी-रोम और समाचार आइटम/लेखों का एक समृद्ध संग्रह है। आज तक, WTO के संग्रह में ई-संसाधनों के साथ लेख और पुस्तकें शामिल हैं। इसका संग्रह बड़ी संख्या में विषय क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिसमें कृषि कानून, एंटी-डंपिंग द्विपक्षीय व्यापार प्रतिपूरक शुल्क, देश जो प्रवेश चाहते हैं, सीमा शुल्क विवाद निपटान, आर्थिक बातचीत, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और WTO, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक मूल्य श्रृंखला वैश्वीकरण सरकारी खरीद क्षेत्रीय व्यापार व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार; व्यापार संबंधी निवेश उपाय; विश्व/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून; विश्व/अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र; सामान्यतः विश्व व्यापार संगठन और संजय बागची संग्रह आदि। इस संग्रह में लगभग 4900 पुस्तकें और पत्रिकाओं के जिल्दबंद खंड हैं। विभिन्न भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के शोध छात्र अपने डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरेट शोध कार्यों के लिए इस पुस्तकालय का उपयोग करते हैं।

पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और सेवाओं को यहां देखा जा सकता है: https://cc.iift.ac.in/library/index.asp

कंप्यूटर केंद्र और आईटी सहायता सेवाएँ

हाइपर कन्वर्ज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ संस्थान का अपना डेटा सेंटर स्थापित करके, कंप्यूटर सेंटर संस्थान की सभी महत्वपूर्ण आईटी सेवाओं, जैसे वेबसर्वर, ईमेल, डेटाबेस, वित्त और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा करता है। कंप्यूटर सेंटर ने निम्नलिखित कार्य भी किए हैं:

- कैंपस नेटवर्क, लैन पर अंतिम उपयोगकर्ताओं को 10 Gbps बैकबोन और 1 Gbps कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- दो अलग-अलग ISP से 1GBpS इंटरनेट कनेक्टिविटी।
- डेटा और फ़ाइल बैकअप सिस्टम।
- साइबर सुरक्षा के लिए हनीपोट, साइबर हमलावरों को लुभाने और सूचना प्रणालियों तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए हैकिंग के प्रयासों का पता लगाने, उन्हें रोकने और उनका अध्ययन करने के लिए।
- CERT-IN सूचीबद्ध सेवा प्रदाता के समन्वय में सुव्यवस्थित वेब सुरक्षा ऑडिटिंग प्रक्रिया।

(1) ऑनलाइन क्विज़ और परीक्षा का आयोजन: अपने आंतरिक रूप से विकसित कैम्पस प्रबंधन प्रणाली, कैम्पस360 के माध्यम से, संस्थान ने 348 ऑनलाइन क्विज़ और 29 ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की हैं।

(2) ऑन-प्राइमेजेस ई-ऑफिस: संस्थान ने ऑन-प्रिमाइसेस E-OFFICE (यानि अपने परिसरों में ई-ऑफिस सुविधा) लागू किया है और अब फ़ाइलों की आवाजाही पूरी तरह से स्वचालित है। 2024-25 के दौरान कुल 7000 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें बनाई गई हैं।

(3) एसएमएस गेटवे कार्यान्वयन: ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों और प्रवेश के लिए एक विशेष एसएमएस गेटवे पोर्टल कार्यान्वित किया गया।

(4) ऑनलाइन ग्रेडिंग प्रणाली: यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी संस्थान कार्यक्रमों में ऑनलाइन ग्रेडिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

(5) हनीपोट साइबर सुरक्षा का कार्यान्वयन: संस्थान की आईटी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए एनआईसी सर्ट-इन टीम के साथ समन्वय में हनीपोट साइबर सुरक्षा का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया।

(6) काकीनाडा में एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम (आईपीएम) के लिए प्रवेश पोर्टल: काकीनाडा परिसर में एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम (आईपीएम) के लिए प्रवेश पोर्टल को डिजाइन किया गया और उसे पूर्णत: तैयार किया गया ।

(7) ऑनलाइन वित्त प्रपत्र: वित्त अनुभाग के समन्वय से, विभिन्न प्रतिपूर्तियों के लिए सहज ज्ञान युक्त वेब प्रपत्रों को डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया।

(8) क्षेत्र-आधारित व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी): निर्यातकों और आयातकों के लिए सत्र आयोजित करने के लिए संस्थान के आंतरिक रूप से विकसित और होस्ट किए गए एमओओसी पोर्टल पर 2024-25 के दौरान 6,000 के करीब पंजीकरण की भारी संख्या देखी गई है।

(9) ग्रीन कैंपस पहल: जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे ग्रह के असुरक्षित स्तर तक गर्म होने का खतरा है, इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कैंपस360 (https://campus360.iift.ac.in) के माध्यम से ऑनलाइन क्विज़ और परीक्षाएँ आयोजित करके और 2024-25 के दौरान, संस्थान ने 22 पेड़ों के बराबर कागज़ बचाया है।

पत्रिका प्रभाग

प्रकाशन प्रभाग संस्थान की तीन प्रमुख पत्रिकाओं, अर्थात् फोकस डब्ल्यूटीओ (त्रैमासिक एवं आंतरिक पत्रिका), आईआईएफटी इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिव्यू (आईबीएमआर) (द्विवार्षिक पत्रिका और सेज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित), और फॉरेन ट्रेड रिव्यू (एफटीआर) (त्रैमासिक पत्रिका) पर काम करता है, साथ ही त्रैमासिक आईआईएफटी न्यूज़लेटर भी प्रकाशित करता है। ये तीनों पत्रिकाएँ शोधार्थियों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के पेशेवरों के लिए उभरते वैश्विक व्यापार मुद्दों से जुड़ने हेतु सूचना और सर्वोत्तम ज्ञान के महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती हैं। प्रकाशन प्रभाग आईआईएफटी वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी) का भी प्रबंधन करता है।

फॉरेन ट्रेड रिव्यू जर्नल: फॉरेन ट्रेड रिव्यू (FTR) एक समकक्ष-समीक्षित त्रैमासिक पत्रिका है जो अकादमिक शोध जगत में साढ़े चार दशकों से भी अधिक समय से मौजूद है। SAGE पब्लिकेशंस इंडिया इस पत्रिका का प्रकाशन करता है। यह पत्रिका निम्नलिखित सार और अनुक्रमण डेटाबेस में शामिल है: SCOPUS, चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ बिजनेस स्कूल्स (ABS), ABDC-B, और क्लेरिवेट एनालिटिक्स: इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स (ESCI)। यह पत्रिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय पर सैद्धांतिक और अनुभवजन्य शोध के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करने का इरादा रखती है। 2024-25 के दौरान, IIFT ने FTR के 4 अंक, खंड 59 संख्या 1, 2 और 3, और एक अंक खंड 60 संख्या 1 (मई, अगस्त, नवंबर 2024 और फरवरी 2025) प्रकाशित किया है।

नई पत्रिका 'आईआईएफटी इंटरनेशनल बिज़नेस एंड मैनेजमेंट रिव्यू जर्नल': आईआईएफटी ने SAGE के साथ मिलकर "इंटरनेशनल बिज़नेस एंड मैनेजमेंट रिव्यू (आईआईएफटी-आईबीएमआर) जर्नल" नामक एक द्विवार्षिक समकक्ष-समीक्षित जर्नल प्रकाशित किया है। इस जर्नल का उद्देश्य प्रबंधकीय मुद्दों, प्रथाओं और नवाचारों को एक साथ लाना है, जो दुनिया भर के विद्वानों, शिक्षकों, प्रबंधकों, उपभोक्ताओं, अन्य सामाजिक हितधारकों और नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी हों। इसका उद्देश्य प्रबंधन अनुशासन की विषयवस्तु और सीमाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, साथ ही व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय दायरे को कवर करना है, जिसमें एशिया (श्रीलंका, जापान और थाईलैंड), रूस, अमेरिका आदि में फैले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन के विविध क्षेत्रों के प्रख्यात प्रोफेसर शामिल हैं। प्रकाशन विभाग ने दिसंबर 2024 में आईआईएफटी आईबीएमआर खंड 2 अंक 1 विशेषांक प्रकाशित किया।

फोकस डब्ल्यूटीओ जर्नल: प्रकाशन विभाग फोकस डब्ल्यूटीओ (जर्नल ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड इंटरनेशनल बिजनेस) (प्रिंट और ऑनलाइन) प्रकाशित करता है, जो एक ब्लाइंड पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक जर्नल है। फोकस डब्ल्यूटीओ, आईआईएफटी का एक आंतरिक प्रकाशन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन अनुसंधान पर लेख, शोध पत्र, परिप्रेक्ष्य लेख, केस स्टडी, मोनोग्राफ और पुस्तक समीक्षाएँ प्रकाशित करता है। 2024-25 के दौरान, प्रकाशन विभाग फोकस डब्ल्यूटीओ खंड 26 के 3 अंक (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून और जुलाई-सितंबर 2024) प्रकाशित करेगा।

आईआईएफटी त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन: प्रकाशन विभाग आईआईएफटी त्रैमासिक न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है, जिसमें संस्थान के विभिन्न प्रभागों की गतिविधियाँ शामिल होती हैं। 2024-25 के दौरान, प्रकाशन विभाग ने आईआईएफटी न्यूज़लेटर के तीन अंक (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून और जुलाई-सितंबर 2024) प्रकाशित किए। 49 न्यूज़लेटर प्रकाशित हो चुके हैं और आईआईएफटी वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं।

कार्याधीन शोधपत्र: आईआईएफटी की वर्किंग पेपर श्रृंखला का उद्देश्य संकाय सदस्यों को प्रकाशन-पूर्व चरण में अपने शोध निष्कर्षों को पेशेवर सहयोगियों के साथ साझा करने में मदद करना है। ये पेपर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाते हैं और आईआईएफटी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। आईआईएफटी वेबसाइट पर कुल पचहत्तर वर्किंग पेपर अपलोड किए गए हैं।

आईआईएफटी संकाय द्वारा प्रकाशन

डॉ. राकेश मोहन जोशी, प्रोफेसर एवं कुलपति

- कपूर, एम. और जोशी, आर.एम. (2024), "ग्राहक जुड़ाव पर व्यापार आयोजनों संबंधित विपणन गतिविधियों का प्रभाव: एक बी2बी परिप्रेक्ष्य", इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग, खंड 54, अंक 8।
- खानम, एस. और जोशी, आर.एम. (2025), "उच्च शिक्षा में विपणन संचार के परिदृश्य का अवलोकन: एक व्यापक विषयगत समीक्षा और भविष्य के अनुसंधान निर्देश", जर्नल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस।

डॉ. सुगाता मार्जित, प्रतिष्ठित प्रोफेसर

- मार्जित, एस. और दास जी.जी. (2024), "संपर्क-तीव्रता, सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यवधान और वेतन असमानता: कोविड-19 संकट और उसके प्रभाव का एक मॉडल", सिंगापुर आर्थिक समीक्षा, खंड 69, अंक 5।
- मार्जित, एस., मंडल बी. और यांग एल. (2024), "नया व्यापार सिद्धांत पुराने व्यापार सिद्धांत में परिवर्तित होता है - एक प्रारंभिक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, खंड 20, अंक 4।
- बेलाडी, एच., मार्जित, एस., ओलाडी, आर. और रायई, एस. (2024), "वर्टिकल स्पेशलाइजेशन, सप्लाई चेन का वैश्विक विस्तार और कन्वर्जेंस", मैक्रोइकॉनॉमिक डायनेमिक्स, वॉल्यूम 29।
- मार्जित, एस., ओलादी, आर. और दास, जी.जी. (2024), "ग्रामीण रोजगार गारंटी और ग्रामीण न्यूनतम मजदूरी", अर्थशास्त्र में योगदान, खंड.भाग एफ3544।
- मार्जित, एस. (2024), "रॉबर्ट सोलो के लिए एक क्लासिकल रिक्विम", जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, खंड 22, अंक 2.
- मार्जित, एस. और मंडल, बी. (2024), "परिचय", अर्थशास्त्र में योगदान, खंड.भाग F3544.
- मार्जित, एस. और मंडल, बी. (2024), "प्रस्तावना", अर्थशास्त्र में योगदान, खंड.भाग F3544.
- रॉय, एस., मार्जीत, एस. और चौधरी, बी.आर. (2024), "एक खुली अर्थव्यवस्था के कृत्रिम बुद्धिमत्ता-प्रेरित गैर-व्यापारिक क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह के कारण एक क्षेत्रीय वेतन अंतर", अर्थशास्त्र में योगदान, वॉल्यूम.भाग एफ3544।
- मार्जित, एस., मुखर्जी, ए., जू, एक्स. और यांग, एल. (2024), "ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स में वित्त और मिलीभगत", नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, वॉल्यूम 76।
- मार्जित, एस., दास, जी.जी. और यांग, एल. (2025), "उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्त की भूमिका", नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, वॉल्यूम 75।
- बेलाडी, एच. और मार्जित, एस. (2025), "प्रोफेसर रोनाल्ड जोन्स के सम्मान में एफटीआर के विशेष अंक का परिचय", विदेश व्यापार समीक्षा, खंड 60, अंक 2।

डॉ. सुनीता राजू, प्रोफेसर

- राजू, एस. (2024), "चीन से आयात का भारतीय विनिर्माण प्रदर्शन पर प्रभाव: व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स। खंड 19, अंक 12।
- राजू, एस. और शर्मा, सी. (2024), "उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का प्राथमिकताओं का आकलन करते हुए कार्यान्वित करना", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक 34।
- राजू, एस. और सराधी, वी.आर. (2024), "भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग की समस्याएँ: एक आकलन", इंडियन इकोनॉमिक जर्नल।

डॉ. के. रंगराजन, प्रोफेसर

- त्रिपाठी, एस., तालुकदार, बी. और रंगराजन, के. (2024), "क्या आपूर्ति श्रृंखला का प्रदर्शन कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित करता है? भारतीय दवा उद्योग के संदर्भ में एक पूर्वानुमानात्मक दृष्टिकोण", आईआईएम कोझिकोड सोसाइटी एंड मैनेजमेंट रिव्यू, खंड 13, अंक 2।

डॉ. राधिका प्रोसाद दत्ता, प्रोफेसर

- दत्ता, आर.पी. (2024), "भारतीय विदेशी मुद्रा बाजारों का विश्लेषण: एक मल्टीफ्रैक्टल डिट्रेंडेड फ्लक्चुएशन एनालिसिस (एमएफडीएफए) दृष्टिकोण", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एम्पिरिकल इकोनॉमिक्स, खंड 3, अंक 3।
- मंडल, के. और दत्ता, आर.पी. (2024), "भारत में तेल मूल्य गतिशीलता और क्षेत्रीय सूचकांक - कोविड महामारी से पहले, बाद और उसके दौरान: वेवलेट-आधारित कारणता और एनएआरडीएल से तुलनात्मक साक्ष्य", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इश्यूज़, खंड 14, अंक 4।
- दत्ता, एस., दत्ता, आर.पी. और रेजेक, जे.एम. (2024), "स्पेस-टाइम फ्रैक्शनल श्रोडिंगर समीकरणों के लिए फेनमैन-कैक पथ इंटीग्रल सिमुलेशन की प्रयोज्यता पर", मोंटे कार्लो विधियाँ और अनुप्रयोग।

डॉ. बिस्वजीत नाग, प्रोफेसर

- तनेजा, एन., नाग, बी., जोशी, एस., रस्तोगी, आर. और दुआ, एस. (2024), "बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को होने वाले लाभों का आपूर्ति-श्रृंखला विश्लेषण", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक 46।

डॉ. संजय रस्तोगी, प्रोफेसर

- तनेजा, एन., नाग, बी., जोशी, एस., रस्तोगी, आर. और दुआ, एस. (2024), "बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को होने वाले लाभों का आपूर्ति-श्रृंखला विश्लेषण", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक 46।
- जैन, एम., तलवार, एस., रस्तोगी, आर., कौर, पी. और धीर, ए. (2024), "इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए नीति प्रोत्साहन: मुख्यधारा के मीडिया विमर्श का विश्लेषण", व्यावसायिक रणनीति और पर्यावरण", खंड 33, अंक 6।

डॉ. राम सिंह, प्रोफेसर

- चौधरी, ए. और सिंह, आर. (2024), "दाल व्यापार में खाद्य हानि की व्याख्या: भारतीय परिप्रेक्ष्य से स्थायी समाधान प्रस्तावित करना", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉजिस्टिक्स-रिसर्च एंड एप्लीकेशन्स। आईएसएसएन: 1367-5567।
- सिंह, एस. और सिंह, आर. (2024), "भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और डिजिटल-पुश के संदर्भ में स्मार्ट वेयरहाउस का विश्लेषण: एक आईएसएम-एमआईसीएमएसी तकनीक", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, खंड 74, अंक 2। आईएसएसएन: 1741-0401।

डॉ. प्रबीर कुमार दास, प्रोफेसर

- दास, पीयूष कुमार और दास, प्रबीर कुमार (2025)। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मुद्रास्फीति पूर्वानुमान: एक समकालीन परिप्रेक्ष्य। दक्षिण एशियाई समष्टि अर्थशास्त्र और लोक वित्त पत्रिका, 0(0)। https://doi.org/10.1177/22779787251318831।

- घोष, कौशिक और दास, प्रबीर कुमार (2024) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ - अनुसंधान प्रवृत्तियों की खोज में अनुसंधान विषयों पर एक ग्रंथसूची विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्रबंधन पत्रिका, उपलब्ध: https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2023-0252। अंक: मुद्रण से पहले। अंक: मुद्रण से पहले।
- दास, पीयूष कांति और दास, प्रबीर कुमार (2024) मुद्रास्फीति पूर्वानुमान में सुधार: मशीन लर्निंग मॉडल में मैक्रो डेटा के साथ टेक्स्ट माइनिंग को एकीकृत करना, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, खंड 16, संख्या 6, पृष्ठ 92-101, DOI:10.5539/ijef.v16n6p92।

- दास, पीयूष कांति और दास, प्रबीर कुमार (2024) मुद्रास्फीति दर के पूर्वानुमान और विश्लेषण: मशीन लर्निंग दृष्टिकोण का उपयोग, जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, 1-25, 10.1007/s40953-024-00384-z.https://link.springer.com/article/10.1007/s40953-024-00384-zI.

डॉ. सैकत बनर्जी, प्रोफेसर

- बनर्जी, एस. (2024), "राजनीतिक ब्रांड के आकर्षण और मतदान मंशाओं को प्रभावित करने वाले कारक", जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स, खंड 24, अंक 4.
- बनर्जी, एस. और चौधरी, बी.आर. (2024), "प्रौद्योगिकी-प्रधान भारतीय निर्यात: बाधाएँ और पहेलियाँ", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समकालीन मुद्दे: चुनौतियाँ और अवसर।

डॉ. वी. रवींद्र सारधी, प्रोफेसर
- बक्सी, ए. और सारधी, वी.आर. (2024), "संकटग्रस्त फर्मों में मानव पूंजी के विशिष्ट आयाम: फर्मों और अनुसंधान पर प्रभाव", विकल्प।
- राजू, एस. और सारधी, वी.आर. (2024), "भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग की समस्याएँ: एक आकलन", इंडियन इकोनॉमिक जर्नल।

डॉ. एम. वेंकटेशन, प्रोफेसर
- मोहन, एस., कुशवाहा, आर., वेंकटेशन, एम., सिंह, आर. और मिश्रा, एम. (2025), "मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों में रणनीतिक संरेखण पर सर्वेक्षण डेटा: इष्टतम प्रदर्शन के लिए एक संतुलित स्कोरकार्ड दृष्टिकोण का कार्यान्वयन", डेटा इन ब्रीफ, खंड 59।

डॉ. दीपांकर सिन्हा, प्रोफेसर
- बसु, एस., सिन्हा, डी. और शर्मा, एन. (2024), "अलग हुए कर्मचारियों, उत्तरजीवियों और संगठनों पर छंटनी के प्रभाव पर एक बहु-हितधारक अध्ययन: क्या किया जाना चाहिए?", प्रबंधन और श्रम अध्ययन, खंड 49, अंक 4।
- चक्रवर्ती, एस.एन. और सिन्हा, डी. (2024), "बंदरगाह प्रदर्शन का बहुआयामी मूल्यांकन: एक समग्र उपाय", जर्नल ऑफ मैरीटाइम रिसर्च, खंड 21, अंक 2।
- दुआ ए., सिन्हा डी., छाबड़ा आर. और शाह बी. (2024), "कंटेनरयुक्त बहुविध परिवहन द्वारा निर्यात में देरी के कारणों की खोज", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, खंड 15, अंक 4।

डॉ. पूजा लखनपाल, प्रोफ़ेसर
- सिन्हा, ए. और लखनपाल, पी. (2024), "क्या एआई प्रणालियाँ बुद्धिमान बन सकती हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक टिप्पणी", एआई और समाज, खंड 39, अंक 4।

डॉ. नीति नंदिनी चटनानी, प्रोफेसर
- रोशन और चटनानी, एन.एन. (2024), "कार्यशील पूंजी निवेश का फर्म मूल्य और दीर्घकालिक निवेश पर प्रभाव: भारतीय विनिर्माण क्षेत्र से साक्ष्य", साउथ एशियन जर्नल ऑफ बिजनेस स्टडीज, खंड 13, अंक 4, आईएसएसएन: 2398-628X।
- घई, आर., गोयल, पी., चटनानी, एन.एन. और मिश्रा, आर. (2025), "कोविड-19 महामारी के बाद एसएचजीएस उद्यमों की स्थिरता चुनौतियों की गुणात्मक जांच: भारत से साक्ष्य", जर्नल ऑफ एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज।
- माहेश्वरी, एस. और चटनानी, एन.एन. (2025), "ओएफएस में फ्लोर प्राइस का रिसाव और भारतीय पूंजी बाज़ारों के लिए प्रस्तावित निगरानी दृष्टिकोण", व्यवहार वित्त की समीक्षा, खंड 17, अंक 3।

डॉ. सास्वती त्रिपाठी, प्रोफेसर
- त्रिपाठी, एस. और रॉय, एस.एस. (2024), "आपूर्ति श्रृंखला प्रदर्शन को संगठनात्मक रणनीतिक प्रदर्शन से जोड़ना - एक समीक्षा और शोध एजेंडा", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, खंड 73, अंक 7.
- त्रिपाठी, एस., रॉय, एस.एस. और तालुकदार, बी. (2025), "निर्यात प्रदर्शन पर फर्म-विशिष्ट निर्धारकों का प्रभाव: आपूर्ति श्रृंखला प्रदर्शन की मध्यस्थ भूमिका", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, खंड 74, अंक 4.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर
- भट्टाचार्य एस., प्रसाद शर्मा आर. और गुप्ता ए. (2024), "ऑनलाइन रिटेलिंग की नैतिकता के बारे में उपभोक्ता धारणा: एक समीक्षा, संश्लेषण और भविष्य की शोध दिशाएँ", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग एंड रिटेलिंग, खंड 15, अंक 2।

डॉ. ओ.पी. वाली, प्रोफेसर
- गुप्ता, डी., कृष्णमूर्ति, बी. और वाली, ओ.पी. (2024), "भारत में डिजिटल परिवर्तन: कुछ खोजपूर्ण केस स्टडीज़", विकास के लिए लोकतंत्र, नवाचार और उद्यमिता में पैल्ग्रेव अध्ययन, खंड भाग F3719।

डॉ. आशीष पांडे, प्रोफेसर
- पांडे, ए. और उत्कर्ष (2024), "सकारात्मक वित्तीय व्यवहार के निर्धारक: एक समानांतर मध्यस्थता मॉडल", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, खंड 19, अंक 11.
- चंद्रा, एस., गुप्ता, ए., अग्रवाल, एस., खन्ना, के., पांडे, एस., नरवाल, एन. और सिंह, ए. (2024), "हरियाणा ब्यूटी सैलून: विस्तार के माध्यम से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना", प्रबंधन में समकालीन मामले: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य।

- सहगल, एस., पांडे, ए. और सेन, एस. (2024), "सापेक्ष, निरपेक्ष या संयुक्त शक्ति संवेग रणनीतियाँ: भारत के लिए क्या कारगर है?" उभरते बाज़ारों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।
- आनंद, वाई. और पांडे, ए. (2024), "चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का व्यवहार्यता अध्ययन: एक ग्रंथसूची और व्यवस्थित समीक्षा", ऊर्जा और पर्यावरण का अर्थशास्त्र और नीति, अंक 2।
- पांडे, एन., गुप्ता, एन., रस्तोगी, एस., सिंह, आर.आर. और मिश्रा, एम. (2024), "डिजिटल कूपन और जेन-ज़ी (Gen Z): एक मॉडरेटर के रूप में कूपन प्रवृत्ति के साथ प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल का एक अनुप्रयोग", इनोवेटिव मार्केटिंग, खंड 20, अंक 2।

डॉ. बिबेक राय चौधरी, प्रोफेसर

- सिंह, एस. और चौधरी, बी.आर. (2024), "भारत के उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहनों का आकलन: उद्देश्यों के पुनर्संरेखण का एक मामला", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक 49।
- भट्टाचार्य, एस., चौधरी, बी.आर., चटर्जी, एस. और चक्रवर्ती, डी. (2024), "भारत में फार्मास्युटिकल निर्यात और पेटेंट - एक प्रणालीगत दृष्टिकोण", इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिव्यू, खंड 17, अंक 3।
- रॉय, एस., मार्जीत, एस. और चौधरी, बी.आर. (2024), "एक खुली अर्थव्यवस्था के कृत्रिम बुद्धिमत्ता-प्रेरित गैर-व्यापारिक क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह के कारण एक क्षेत्रीय वेतन अंतर", अर्थशास्त्र में योगदान, खंड भाग F3544।

डॉ. देबाशीष चक्रवर्ती, प्रोफेसर

- चक्रवर्ती, डी. और डे, ओ. (2024), "व्यापार प्रवाह पर विश्व व्यापार संगठन और वैश्विक गतिशीलता का प्रभाव: एक मशीन-जनित साहित्य अवलोकन", स्प्रिंगर नेचर, आईएसबीएन: 978-981-99-7374-3।
- अहमद, ए., चक्रवर्ती, डी. और अग्रवाल, एस. (2024), "व्यापार उदारीकरण और श्रम बाज़ार गतिशीलता: भारत से साक्ष्य", जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, खंड 22, अंक 4।
- पंत, एस. और चक्रवर्ती, डी. (2024), "क्या सेवाकरण विनिर्माण निर्यात को लाभ पहुंचा सकता है? भारत के लिए अनुभवजन्य परिणाम", साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल, खंड 25, अंक 2.
- भट्टाचार्य, एस., चौधरी, बी.आर., चटर्जी, एस. और चक्रवर्ती, डी. (2024), "भारत में फार्मास्युटिकल निर्यात और पेटेंट - एक प्रणाली दृष्टिकोण", भारतीय विकास और विकास समीक्षा, खंड 17, अंक 3.
- अहमद, ए. और चक्रवर्ती, डी. (2024), "मेक इन इंडिया" के शुभारंभ के बाद एफडीआई सुधार और औद्योगिक वेतन: अनुभवजन्य साक्ष्य", ग्लोबल इकोनॉमी जर्नल, खंड 24, अंक 01n04।
- प्रधानी, एम.आर., चक्रवर्ती, डी. और घोष, टी.पी. (2024), "उत्पाद मानक चाय निर्यात को कैसे प्रभावित करते हैं? भारत से अनुभवजन्य साक्ष्य", एफआईआईबी बिजनेस रिव्यू।
- चक्रवर्ती, डी., (2025), "कोविड-19 महामारी और वैश्विक असमानता: श्रम बाजार, व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों में प्रभाव", फॉरेन ट्रेड रिव्यू, खंड 60, अंक 1, आईएसएसएन: 0015-7325

डॉ. आशिम राज सिंगला, प्रोफेसर

- गुप्ता, ए., गुप्ता, ए., अग्रवाल, एस., झाम्ब, डी.के., सिंगला, ए., कौर, एच. और सुमन, पी. (2024), "अमित बुक डिपो: अवसर का दोहन और गति बनाए रखना", प्रबंधन में समकालीन मामले: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य।
- राजू, एस. और सिंगला, ए. (2024), "क्या भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में उभर सकता है?", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक 12।
- सिंह, वी.जे. और सिंगला, ए.आर. (2024), "एमएसएमई द्वारा व्यावसायिक बुद्धिमत्ता को अपनाना: अनिश्चित समय में चुनौतियों पर काबू पाना", कार्यवाही - 2024 उन्नत कंप्यूटिंग और संचार प्रौद्योगिकियों पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आईसीएसीसीटेक 2024।
- मुंशी, ए. और सिंगला, ए.आर. (2025), "खाद्य विज्ञान में नवाचार के लिए सहयोगी अनुसंधान साझेदारी के निर्धारक", वैश्विक ज्ञान, स्मृति और संचार।

डॉ. जैकलीन सिम्स, एसोसिएट प्रोफेसर

- कुमार, एन. और सिम्स, जे. (2024), "यूक्रेन युद्ध के समय में कॉर्पोरेट नकदी धारण और फर्म का प्रदर्शन: एक साहित्य समीक्षा और आगे का रास्ता", जर्नल ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक एंड फॉरेन ट्रेड स्टडीज।
- नीतू और सिम्स जे. (2025), "क्या क्रिप्टोकरेंसी कॉर्पोरेट्स में वित्तीय बाधाओं की समस्या का समाधान कर सकती है? एक साहित्य समीक्षा और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य", क्वालिटेटिव रिसर्च इन फाइनेंशियल मार्केट्स, खंड 17, अंक 3।

डॉ. त्रिप्तेंदु प्रकाश घोष, एसोसिएट प्रोफेसर

- मुखर्जी, एस., एजाज, टी. और घोष, टी.पी. (2024), "भारतीय आईटी और आईटीईएस क्षेत्र का प्रदर्शन विश्लेषण: एडिटिव-डीईए और जी2एसएलएस का अनुप्रयोग", यूरेशियन जर्नल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, खंड 17, अंक 34।
- प्रधानी, एम.आर., चक्रवर्ती, डी. और घोष, टी.पी. (2024), "उत्पाद मानक चाय निर्यात को कैसे प्रभावित करते हैं? भारत से अनुभवजन्य साक्ष्य", एफआईआईबी बिजनेस रिव्यू।
- घोष, के. और दास, पी.के. (2024), "केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ - अनुसंधान प्रवृत्तियों की खोज में अनुसंधान विषयों पर एक ग्रंथसूची विश्लेषण", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट।

डॉ. अरीज़ आफ़ताब सिद्दीकी, सहायक प्राध्यापक

- अरोड़ा, के., और सिद्दीकी, ए.ए. (2024), "व्यापार और तकनीकी संबंधों की खोज: भारत की क्षेत्रीय जीवीसी भागीदारी से साक्ष्य", ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन रिव्यू, खंड 16, अंक 1.
- मलिक, एन., सिद्दीकी, ए.ए. और लाहमर, ए. (2025), "भागीदारों की समानता भारत के आर्थिक एकीकरण समझौतों और व्यापार मार्जिन को कैसे प्रभावित करती है? एक अनुभवजन्य विश्लेषण" जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।

डॉ. प्रीति टाक, सहायक प्रोफेसर

- विरमानी, के., और टाक, पी. (2024), "आगंतुकों की ब्रांड निष्ठा के पूर्ववर्ती: भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की एक जाँच", जर्नल ऑफ कन्वेंशन एंड इवेंट टूरिज्म, खंड 25, अंक 5।

डॉ. आशीष गुप्ता, सहायक प्रोफेसर

- अग्रवाल, एस., और गुप्ता, ए. (2024), "प्रबंधन में समकालीन मामले: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य", प्रबंधन में समकालीन मामले: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य।
- भट्टाचार्य, एस., शर्मा, आर.पी., और गुप्ता, ए. (2024), "मूल देश और ऑनलाइन खुदरा बिक्री नैतिकता: खरीद इरादे पर विश्वास और संतुष्टि की मध्यस्थ भूमिका", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, खंड 19, अंक 10।
- गोयल, ए., चंद्रा, एस., गुप्ता, ए., अग्रवाल, एस., राय, एस., गुप्ता, जी., भूरिया, एस. और जैन, सी. (2024), "नीरू मार्केटिंग कंपनी: खोई हुई ज़मीन कैसे वापस पाएं?" प्रबंधन में समकालीन मामले: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य।
- चंद्रा, एस., गुप्ता, ए., अग्रवाल, एस., खन्ना, के., पांडे, एस., नरवाल, एन. और सिंह, ए. (2024), "हरियाणा ब्यूटी सैलून: विस्तार के माध्यम से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना", प्रबंधन में समकालीन मामले: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य।
- कुमार, जे., दीक्षित, एस., गुप्ता, ए. और धारवाल, एम. (2024), "वर्जित उत्पाद की स्थिति: पीबडी", एफआईआईबी बिजनेस रिव्यू, खंड 13, अंक 5।
- बाथला, ए., अबरोल, एस., गुप्ता, ए., अग्रवाल, एस., बबुता, ए., दास, पी., कौर, ए. और सचान, ए. (2024), "हमहैं: व्यवसाय का विस्तार", प्रबंधन में समकालीन मामले: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य।
- येलमंचिली, आर.के., गुप्ता, ए., मीनू, एस., अग्रवाल, एस., बंसल, एस., मल्होत्रा, एस. और गिल, जे. (2024), "महत्वाकांक्षा कोचिंग क्लासेस: मार्केटिंग टर्नअराउंड रणनीति", प्रबंधन में समकालीन मामले: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य।
- कुमार, जे., गुप्ता, ए., धारवाल, एम., और गोविंदराजन, यू.एच. (2024), "सावंत इलेक्ट्रॉनिक्स स्थिरता या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व", कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पारिस्थितिकी तंत्र का प्रौद्योगिकी-संचालित विकास।
- गुप्ता, एस., गुप्ता, ए., और कुमार, जे. (2024), "संकट के दौरान वैश्विक व्यापार में लचीलापन बनाना: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य", संकट के दौरान वैश्विक व्यापार में लचीलापन बनाना: उभरते बाजारों के परिप्रेक्ष्य।
- भट्टाचार्य, एस., शर्मा, आर.पी. और गुप्ता, ए. (2024), "ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं की नैतिकता के बारे में उपभोक्ता धारणाओं के निर्धारक: पुष्टि कारक विश्लेषण का उपयोग करके एक जांच", विज़न, खंड 28, अंक 4।
- गुप्ता, ए.के., संगीता, एस. और कल्लुममल, एम. (2024), "फर्मों के निर्यात व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का प्रभाव: भारतीय समुद्री उद्योग का एक मामला", जर्नल ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी।
- बाथला, ए., चावला, जी., गुप्ता, ए., और होफैधलाउई, एम. (2025), "बोर्डरूम से परे: व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में मूल्य सृजन के लिए डिज़ाइन थिंकिंग और नेतृत्व", कॉजेंट बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, खंड 12, अंक 1।
- बाथला, ए., चावला, जी., और गुप्ता, ए. (2025), "शिक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में डिज़ाइन-थिंकिंग की बेंचमार्किंग: एक व्यवस्थित समीक्षा और भविष्य का अनुसंधान एजेंडा", बेंचमार्किंग, खंड 32, अंक 3।
- वर्मा, एस., काशिवे, एन., और गुप्ता, ए. (2025), "शैक्षणिक अनुसंधान में जनरेटिव-एआई स्वीकृति और उपयोग के पूर्वानुमानों की जांच: एक अनुक्रमिक मिश्रित-विधि दृष्टिकोण", बेंचमार्किंग।
- खन्ना, पी., सहगल, आर., गुप्ता, ए., दुबे, ए.एम., और श्रीवास्तव, आर. (2025), "ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म: एक समीक्षा, संश्लेषण और अनुसंधान निर्देश", मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड प्लानिंग, खंड 43, अंक 2।

डॉ. गिन्नी चावला, सहायक प्रोफेसर

- बाथला, ए., चावला, जी., गुप्ता, ए. और होफैदलाउई, एम. (2025), "बोर्डरूम से परे: व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में मूल्य सृजन के लिए डिज़ाइन थिंकिंग और नेतृत्व", कॉर्जेंट बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, खंड 12, अंक 1।
- बाथला, ए., चावला, जी. और गुप्ता, ए. (2025), "शिक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में डिज़ाइन-थिंकिंग की बेंचमार्किंग: एक व्यवस्थित समीक्षा और भविष्य का शोध एजेंडा", बेंचमार्किंग, खंड 32, अंक 3।

डॉ. दिव्या टुटेजा, सहायक प्राध्यापक

- भाटिया एस. और टुटेजा डी. (2025), "अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में संक्रमण और संबंध", इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, खंड 94।
- दुआ, पी. और टुटेजा, डी. (2024), "भारतीय वित्तीय बाजारों पर संकट का प्रभाव", मौद्रिक अर्थशास्त्र और बैंकिंग बुलेटिन, खंड 27, अंक 3।
- दुआ, पी. और टुटेजा, डी. (2025), "वित्तीय बाजारों में सहसंबंधों पर पारंपरिक और अपरंपरागत मौद्रिक नीति का प्रभाव: एक उभरती अर्थव्यवस्था से साक्ष्य", उभरते बाजार वित्त और व्यापार।

- **डॉ. अरुणिमा राणा**, सहायक प्रोफेसर
- राणा, ए., मुखर्जी, टी., और अदक, एस. (2025), "कोविड-19 से उबरने के दौरान गतिशीलता: सामाजिक प्रवर्धक के रूप में मीडिया और संस्कृति की भूमिका", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स, खंड 52, अंक 3।

डॉ. तुहीना मुखर्जी, सहायक प्राध्यापक

- सतीश, जी., मुखर्जी, टी., और साहनी, एस. (2024), "प्रवासी का परिवर्तनशील करियर अभिविन्यास और अंतर-सांस्कृतिक समायोजन: करियर अनुकूलनशीलता की मध्यस्थ भूमिका", जर्नल ऑफ ग्लोबल मोबिलिटी, खंड 12, अंक 4।

- मुखर्जी, टी., इलावरासन, पी.वी., और कर, ए.के. (2024), "डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण: भारत में कामकाजी उम्र की गरीब बेरोजगार महिलाओं का एक अनुभवजन्य अध्ययन", विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, खंड 30, अंक 3।
- राणा, ए. मुखर्जी, टी., और अदक, एस. (2025), "कोविड-19 रिकवरी के दौरान गतिशीलता: सामाजिक प्रवर्धक के रूप में मीडिया और संस्कृति की भूमिका", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स, खंड 52, अंक 3.
- मुखर्जी, टी., और सिंह, आर. (2025), "भारत की चिकित्सा उपकरण नीति: निर्यात उत्कृष्टता के लिए व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में निर्धारकों की खोज", जर्नल ऑफ हेल्थ ऑर्गनाइजेशन एंड मैनेजमेंट।

डॉ. ओइंद्रिला डे, सहायक प्रोफेसर

- चक्रवर्ती, डी. और डे, ओ. (2024), "व्यापार प्रवाह पर विश्व व्यापार संगठन और वैश्विक गतिशीलता का प्रभाव: एक मशीन-जनित साहित्य अवलोकन", व्यापार प्रवाह पर विश्व व्यापार संगठन और वैश्विक गतिशीलता का प्रभाव: एक मशीन-जनित साहित्य अवलोकन।
- डे, ओ. और चक्रवर्ती, डी. (2024), "क्या यात्री सार्वजनिक परिवहन के रूप में इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कारों का उपयोग करने का इरादा रखते हैं? शहरी भारत से साक्ष्य", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, खंड 19, अंक 10।
- कुमारी, जी. और डे, ओ. (2024), "क्या वैक्सीन का पुनर्वितरण वैश्विक कल्याण में सुधार कर सकता है? कोविड-19 से सबक", यूरोपियन जर्नल ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स, खंड 25, अंक 7.
- डे, ओ. और चक्रवर्ती, डी. (2024), "उद्योग या नागरिक समाज? कोविड-19 संकट प्रबंधन में संस्थानों की भूमिका", इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, खंड 71, अंक।
- चक्रवर्ती, एस. और डे, ओ. (2024), "नकारात्मक लाइसेंस शुल्क: एक अच्छा या बुरा सौदा? उत्तल लागत वाली मिश्रित तकनीक का मामला", अर्थशास्त्र में योगदान, खंड. भाग F3544.
- चक्रवर्ती, एस. और डे, ओ. (2025), "इंट्रा-ब्रांड लाइसेंसिंग को पुनर्परिभाषित करना: क्या वर्टिकल विभेदीकरण पेटेंट रणनीतियों को बदल सकता है?" जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स.
- चक्रवर्ती, एस. और डे, ओ. (2025), "ऋण तक पहुँच: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधा?" इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू.

डॉ. नमन शर्मा, सहायक प्रोफेसर

- बसु, एस., सिन्हा, डी. और शर्मा, एन. (2024), "छंटनी के अलग हुए कर्मचारियों, बचे लोगों और संगठनों पर प्रभाव पर एक बहु-हितधारक अध्ययन: क्या किया जाना चाहिए?" प्रबंधन और श्रम अध्ययन, खंड 49, अंक 4।

- शर्मा, एन., सिन्हा, ई., और शैलेंदर, के. (2024), "महिला उद्यमिता का समर्थित मॉडल: महिला उद्यमशीलता के इरादे के पूर्ववर्ती और उद्यमशीलता की आत्म-प्रभावकारिता की मध्यस्थ भूमिका", जर्नल ऑफ एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज, खंड 18, अंक 5.
- बनर्जी, पी., और शर्मा, एन. (2024), "उद्योग 4.0 में डिजिटल परिवर्तन और प्रतिभा प्रबंधन: एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा और भविष्य की दिशाएँ", लर्निंग ऑर्गनाइजेशन।
- गौतम, ओ., शर्मा, एन., और अग्रवाल, पी. (2024), "वैश्विक संकट: पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के लिए कोविड के बाद की स्थायी रणनीतियाँ", कोविड के बाद का पर्यटन और आतिथ्य गतिशीलता: पुनर्प्राप्ति, पुनरुद्धार और पुनः आरंभ।
- शर्मा, एम., सहाय, पी., सिंह, वी.के., और शर्मा, एन. (2025), "सोशल मीडिया प्रभावितों की विश्वसनीयता ब्रांड विश्वसनीयता, ई-वॉम और उपभोक्ता व्यवहार संबंधी इरादे से प्रभावित: खाद्य और फैशन ब्लॉगिंग का एक अध्ययन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन, खंड 40, अंक 1।
- शर्मा, एन. (2025), "बाधाओं को तोड़ना: ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को काम पर रखने के प्रति प्रबंधकीय हिचकिचाहट को संबोधित करना", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑर्गनाइजेशनल एनालिसिस, खंड 33, अंक 3।

डॉ. आंचल अरोड़ा, सहायक प्रोफेसर
- अरोड़ा, ए. और अग्रवाल, पी. (2024), "भारत में जैविक कृषि और खाद्य सुरक्षा: स्थिति, चुनौतियाँ और नीतिगत उपाय", विकासशील विश्व में खाद्य सुरक्षा: स्थिति, चुनौतियाँ और अवसर।

डॉ. पारुल सिंह, सहायक प्रोफेसर
- सिंह, पी., गहलोत, आर., यादव, एम.पी., और सिंह, आर. (2025), "क्या भारत में एफएमसीजी क्षेत्र में वित्तीय प्रदर्शन और फर्म की विशेषताओं से वित्तीय उत्तोलन प्रभावित होता है?" एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार।
- सिंह, पी., गहलोत, आर., यादव, एम.पी., और सिंह, आर. (2025), "क्या भारत में एफएमसीजी क्षेत्र में वित्तीय प्रदर्शन और फर्म की विशेषताओं से वित्तीय उत्तोलन प्रभावित होता है? (एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार, (2025), 10.1007/s10690-025-09516-8)" में सुधार, एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार।

डॉ. अंजू गोस्वामी, सहायक प्रोफेसर
- शर्मा, एस.के., माथुर, पी., शाहजहां, ए.ए., गंती, एल.एस. और गोस्वामी, ए. (2024), "विश्व व्यापार संगठन वार्ता और सतत भविष्य के लिए कृषि सब्सिडी का पुनर्प्रयोजन", अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते: राजनीति, कानून और अर्थशास्त्र, खंड 24।
- गोस्वामी, ए., और मलिक, पी. (2024), "कोविड-19 संकट के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय प्रदर्शन चालकों की पहचान", जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, खंड 22, अंक 3।
- गोस्वामी, ए. (2024), "ग्रीन बैंकिंग, सस्टेनेबिलिटी और कोविड-19: एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा", जर्नल ऑफ अकाउंटिंग लिटरेचर।
- गोस्वामी, ए., और मलिक, पी. (2025), "भारतीय बैंकों के जोखिम और वित्तीय प्रदर्शन: कोविड-19 अवधि पर एक सरसरी नज़र", बेंचमार्किंग, खंड 32, अंक 2।

डॉ. सुगंधा हुरिया, सहायक प्राध्यापक
- मंडल, एस., हुरिया, एस. और अज़हरुद्दीन, एस.एम. (2024), "क्या सेवा औद्योगिक उत्पादन के लिए उत्प्रेरक हो सकती है? भारतीय विनिर्माण उद्योगों से अंतर्दृष्टि", जर्नल ऑफ़ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स।
- पंत, एम. और हुरिया, एस. (2024), "श्रम, व्यापार और मजदूरी असमानता: कुछ नए परिणाम", अर्थशास्त्र में योगदान। खंड F3544।

डॉ. तौफीक एजाज, सहायक प्रोफेसर
- मुखर्जी, एस., एजाज, टी. और घोष, टी.पी. (2024), "भारतीय आईटी और आईटीईएस क्षेत्र का प्रदर्शन विश्लेषण: एडिटिव-डीईए और जी2एसएलएस का अनुप्रयोग", यूरेशियन जर्नल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, खंड 17, अंक 34।

डॉ. कनुप्रिया, सहायक प्राध्यापक
- कनुप्रिया, (2024), "कोविड-19 के संदर्भ में प्रतिमान परिवर्तन सिद्धांत और संकट नेतृत्व मॉडल का अध्ययन", कोविड-19 महामारी के बाद नेतृत्व के नए दृष्टिकोण।
- कनुप्रिया, (2024), "व्यापार, लिंग और पर्यावरण के बीच संबंध: भारत के वस्त्र क्षेत्र के संदर्भ में एक समीक्षा", डिसीजन, खंड 51, अंक 3।
- कनुप्रिया, (2025), "भारत के व्यापार समझौतों पर फिर से बातचीत: जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों के संदर्भ में एक अध्ययन", इंडियन इकोनॉमिक जर्नल।

- कनुप्रिया, (2025), "सुधारों के बाद की अवधि में भारत के रोजगार और उत्पादकता पैटर्न: केएलईएमएस डेटा का उपयोग करके विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के संबंध में एक संक्षिप्त विश्लेषण", इंडियन इकोनॉमिक जर्नल।

डॉ. ओली मिश्रा, सहायक प्रोफेसर
- मिश्रा, ओ. (2024), "ट्विर्ल स्टोर: लूप को बंद करके सतत वस्त्र प्रथाओं में अग्रणी", एमराल्ड इमर्जिंग मार्केट्स केस स्टडीज़, खंड 14, अंक 4।
- मिश्रा, ओ., गिरिजा, एस. और मल्लेला, जे. (2024), "कोविड-19 कॉलर ट्यून की भूमिका और टीकाकरण कराने का इरादा: स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का एक अनुप्रयोग", जर्नल ऑफ क्रिएटिव कम्युनिकेशंस।
- मिश्रा, ओ. और धर्मावरम, वी.जी. (2025), "एक बुद्धिमान साइबर सुरक्षा प्रणाली की ओर: मशीन लर्निंग की भूमिका", उद्योग 5.0 में साइबर अपराधों की तकनीकी-कानूनी गतिशीलता।
- मिश्रा, ओ. (2025), "बाधाओं से मैट्रिक्स तक: सामाजिक और वाणिज्यिक कपड़ा उद्यमों में परिपत्र अर्थव्यवस्था को लागू करना", सतत स्टार्टअप विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी को नेविगेट करना।

डॉ. रघुवीर नेगी, सहायक प्रोफेसर
- नोमानी, ए., रिथी, एस.आर., और नेगी, आर. (2025), "उभरती अर्थव्यवस्थाओं से विकसित देशों की ओर विदेशी निवेश (ओएफडीआई) का मानचित्रण: निवेश बहिर्वाह और ओएलआई प्रतिमान का एक परिणामी अभिसरण", थंडरबर्ड इंटरनेशनल बिजनेस रिव्यू।

डॉ. सिद्धार्थ शंकर राय, सहायक प्राध्यापक
- राज, वी.ए., जसरोटिया, एस.एस., और राय, एस.एस. (2024), "व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता के अनुसंधान परिदृश्य का मानचित्रण: अंतर्दृष्टि और भविष्य की दिशाएँ", उच्च शिक्षा, कौशल और कार्य-आधारित शिक्षा, खंड 14, अंक 5।
- जसरोटिया, एस.एस., राय, एस.एस., राय, एस., और गिरी, एस. (2024), "चरणबद्ध हरित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और पर्यावरण प्रदर्शन: ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रभाव", अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रबंधन डेटा अंतर्दृष्टि जर्नल, खंड 4, अंक 2।
- राज, वी.ए., जसरोटिया, एस.एस. और राय, एस.एस. (2024), "अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल) सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं के व्यवहारिक इरादे पर कथित जोखिमों और कथित लाभों की भूमिका", जर्नल ऑफ फैसिलिटीज मैनेजमेंट। खंड 23, अंक 2।

डॉ. रश्मि रस्तोगी, सहायक प्राध्यापक
- तनेजा, एन., नाग, बी., जोशी, एस., रस्तोगी, आर. और दुआ, एस. (2024), "बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता: भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को होने वाले लाभों का आपूर्ति-श्रृंखला विश्लेषण", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59, अंक 46।
- जैन, एम., तलवार, एस., रस्तोगी, आर., कौर, पी., और धीर, ए. (2024), "इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए नीति प्रोत्साहन: मुख्यधारा के मीडिया विमर्श का विश्लेषण", बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड द एनवायरनमेंट, खंड 33, अंक 6।

डॉ. कविता वाधवा, सहायक प्रोफेसर
- वाधवा, के., और गुडेल, जे.डब्ल्यू. (2024), "राजनीतिक अनिश्चितता और स्टॉक मूल्य दुर्घटना जोखिम: उभरते बाजार में राज्य-चुनावों से अंतर्दृष्टि", वित्तीय विश्लेषण की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, खंड 95।

डॉ. मिकलेश प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक
- आबेदीन, एम.जेड., गोल्डस्टीन, एम.ए., मल्होत्रा, एन., और यादव एम.पी. (2024), "मध्य पूर्व संघर्ष और ऊर्जा कंपनियाँ: वैश्विक ऊर्जा शेयरों पर हवाई और ड्रोन हमलों का प्रभाव", वित्त अनुसंधान पत्र, खंड 69।
- तबस्सुम, एस., ढिल्लों, एल.के., यादव, एम.पी., खान, के., सैफी, एम.ए., और जुल्फिकार जेड. (2024), "ईएसजी अनुपालक, फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयरों के बीच समय-भिन्न संबंधों का रहस्य उजागर करना", जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑर्गनाइजेशनल चेंज।
- लोहाना, एस., यादव, एम.पी., और रेखा ए.जी. (2024), "कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चीनी शेयर बाजार से जी20 शेयर बाजारों में अस्थिरता का प्रभाव", प्रशांत बेसिन वित्तीय बाजारों और नीतियों की समीक्षा, खंड 27, अंक 2.
- गुप्ता, एन., सहाय, एन., और यादव, एम.पी. (2024), "ब्रिक्स शेयर बाजारों पर तेल मूल्य परिवर्तनों के भिन्न प्रभावों का विश्लेषण", एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार।
- शर्मा, एस., यादव, एम.पी., भारद्वाज, आई., और रीपू (2024), "चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में - क्या प्रौद्योगिकी-आधारित संपत्तियां और ग्रीन इक्विटी सूचकांक विकसित और उभरते बाजार सूचकांक के साथ सुरक्षित निवेश हैं?" एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार।

- यादव, एम.पी., विग कुशवाह, एस.वी., तगीज़ादेह-हेसरी, एफ., और मिश्रा, एन. (2025), "प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रकोपों के बीच ऊर्जा, विदेशी मुद्रा और वित्तीय बाजारों के बीच गतिशील संबंधों का अनावरण", लेखांकन और वित्त की समीक्षा, खंड 24, अंक 1।
- यादव, एम.पी., पुरी, एन., भाटिया, पी., और शोर, ए.पी. (2025), "क्राड वित्तीय बाजारों पर कच्चे तेल की अस्थिरता के पर्यावरणीय और प्रबंधकीय प्रभावों की खोज: गतिशील जुड़ाव में अंतर्दृष्टि", जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट, खंड 373।
- रब्बानी, एम.आर., तबस्सुम, एस., यादव, एम.पी., और कयानी, यू.एन. (2025), "इस्लामिक वित्तीय बाजारों में सममित अस्थिरता स्पिलओवर की जांच: इस्लामिक इक्विटी, क्रिप्टोकरेंसी, सुकुक और हलाल-एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से साक्ष्य", जर्नल ऑफ इस्लामिक मार्केटिंग।
- चिंकी राणा, एस., यादव, एम.पी., और सिन्हा, एन. (2025), "उपभोक्ताओं को प्रभावित करने के लिए कथाएँ गढ़ना: कहानी कहने वाले विपणन की एक व्यवस्थित समीक्षा", एशिया-प्रशांत जर्नल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
- सिंह, पी., गहलोत, आर., यादव, एम.पी., और सिंह, आर. (2025), "क्या भारत में एफएमसीजी क्षेत्र में वित्तीय उत्तोलन वित्तीय प्रदर्शन और फर्म विशेषताओं से प्रभावित होता है?" एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार।
- राघवेंद्र, सी., यादव, एम.पी., शरीफ, टी., और अबेदिन, एम.जेड. (2025), "क्या मानव पलायन और ब्रेन ड्रेन सीमा पार अधिग्रहण को प्रभावित करते हैं? टोबिट और द्विपद प्रतिगमन मॉडल में अंतर्दृष्टि", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में अनुसंधान, खंड 75।
- अल-कुदाह, ए.ए., अल-ओकैली, एम., और यादव, एम.पी. (2025), "विकासशील देशों में फिनटेक और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का विकास: यूएई के साक्ष्य", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, खंड 33, अंक 2।
- पंवार, के., यादव, एम.पी., और पुरी, एन. (2025), "धातु और बुलियन बाजार के साथ ग्रीन बॉन्ड का स्पिलओवर प्रभाव", एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार, खंड 32, अंक 1।
- सिंह, पी., गहलोत, आर., यादव, एम.पी., और सिंह, आर. (2025), "सुधार: क्या वित्तीय उत्तोलन भारत में एफएमसीजी क्षेत्र में वित्तीय प्रदर्शन और फर्म विशेषताओं से प्रभावित होता है? (एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार, (2025), 10.1007/s10690-025-09516-8)", एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार।
- श्रॉफ, एस., अग्रवाल, एन., पालीवाल, यू.एल., और यादव, एम.पी. (2025), "चयनित परिसंपत्ति वर्ग अचानक झटकों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? घटना अध्ययन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इज़राइल-हमास संघर्ष से साक्ष्य", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में अनुसंधान, खंड 75।

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र द्वारा प्रकाशन

डॉ. प्रीतम बनर्जी, प्रोफेसर

- बनर्जी, पी., और शर्मा, एन. (2024), "उद्योग 4.0 में डिजिटल परिवर्तन और प्रतिभा प्रबंधन: एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा और भविष्य की दिशाएँ", लर्निंग ऑर्गनाइज़ेशन।

डॉ. मुरली कल्लुममल, प्राध्यापक

- कल्लुममल, एम., गुरुंग, एच.एम., और खोसला, एस. (2024), "विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित अनुरूपता मूल्यांकन आवेदनों का वैश्विक अवलोकन", गुणवत्ता प्रणाली, मान्यता और अनुरूपता मूल्यांकन पुस्तिका।
- गुप्ता, ए.के., संगीता, एस., और कल्लुममल, एम. (2024), "फर्मों के निर्यात व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का प्रभाव: भारतीय समुद्री उद्योग का एक मामला", जर्नल ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी।

डॉ. सचिन कुमार शर्मा, प्रोफेसर

- शर्मा, एस.के., माथुर, पी., शाहजहां, ए.ए., गंती, एल.एस., और गोस्वामी, ए. (2024), "डब्ल्यूटीओ वार्ता और सतत भविष्य के लिए कृषि सब्सिडी का पुनर्प्रयोजन", अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते: राजनीति, कानून और अर्थशास्त्र, खंड 24, आईएसएसएन: 1567-9764।
- शर्मा, एस.के., और शाहजहां, ए.ए. (2024), "डब्ल्यूटीओ और खाद्य सुरक्षा के लिए एक स्थायी समाधान: भूख-मुक्त विश्व के लिए प्रयास", खाद्य सुरक्षा, खंड 16, अंक 2।
- शर्मा, एस.के., दास, ए., माथुर, पी., लाहिड़ी, टी., और नियोगी, एस. (2024), "डब्ल्यूटीओ में कृषि घरेलू समर्थन सुधार: आनुपातिक कमी दृष्टिकोण का आकलन", अंतर्राष्ट्रीय वार्ता, खंड 29, अंक 2।
- शर्मा, एस.के., माथुर, पी., शाहजहां, ए.ए., गंती, एल.एस. और गोस्वामी, ए (2024), "डब्ल्यूटीओ वार्ता और एक सतत भविष्य के लिए कृषि सब्सिडी का पुन: उपयोग", अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते-राजनीति कानून और अर्थशास्त्र, खंड 24, अंक 23.

डॉ. प्रलोक गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर

- शर्मा, एस., अरोड़ा, आर., और गुप्ता, पी. (2024), "डीप सर्विस प्रोविजन्स के माध्यम से जीवीसी का सर्विसिफिकेशन: स्ट्रक्चरल ग्रेविटी और मशीन लर्निंग से नई अंतर्दृष्टि का खुलासा", वर्ल्ड इकोनॉमी, खंड 47, अंक 10।

व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र (CTIL) द्वारा प्रकाशित

डॉ. जेम्स नेदुम्पारा, प्राध्यापक

- नेदुम्परा, जे.जे., लड्ढा, ए., और जनार्दन, एस. (2024), "निवेश संधियाँ और न्यायपालिका की भूमिका: 2015 मॉडल बीआईटी के बाद भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण का मानचित्रण", भारत की द्विपक्षीय निवेश संधियाँ 2.0: धारणाएँ, उभरते रुझान और संभावित संरचना।
- नेदुम्परा, जे.जे. और शर्मा, ए. (2024), "तुर्की: दवा उत्पादों के उत्पादन, आयात और विपणन से संबंधित कुछ उपाय: प्रथम डब्ल्यूटीओ अनुच्छेद 25 अपील मध्यस्थता पुरस्कार का आलोचनात्मक मूल्यांकन", जर्नल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, खंड 58 अंक 6।

सुश्री शाइनी प्रदीप, सहायक प्रोफेसर

- प्रदीप, एस. (2024), "निवेश संधियों में स्थिरता: भविष्य में क्या होगा?" भारत की द्विपक्षीय निवेश संधियाँ 2.0: धारणाएँ, उभरते रुझान और संभावित संरचना.

राजभाषा हिंदी की गतिविधियां

संस्थान संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से जागरूक व वचनबद्ध है। संस्थान में राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार दिन-प्रतिदिन उन्नयन की ओर अग्रसर है। राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए संस्थान को समय-समय पर माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार तथा वाणिज्य मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा शील्ड ट्रॉफी प्रदान की गई है, जो इसकी प्रमाणिकता को दर्शाता है। संस्थान में कार्यालयीन कामकाज के साथ-साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण में भी हिंदी की उपयोगिता को बढ़ावा दिया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित किए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:

धारा 3(3) का अनुपालन - संस्थान में सभी कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचनाएं, संविदाएं, करार, निविदाओं के फार्म और नोटिस, नियम-पुस्तिका, इत्यादि सभी द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 का अनुपालन - संस्थान के कोड, भर्ती नियम, संविधान, पुस्तकालय नियम व विनियम, अंशदायी भविष्य निधि नियम, सेवाओं की पुस्तिका, नागरिक प्राधिकार, परामर्श नियम, आदि को द्विभाषी रूप में अद्यतन किया गया है।

(क) सभी साइनेज, रबड की मोहरें, नामपट्ट, लोगो, सीलें, पत्र शीर्ष, विजिटिंग कार्ड आदि द्विभाषी रूप में उपयोग किए गए।

(ख) संस्थान में कर्मचारियों द्वारा सभी प्रपत्र, जैसे अवकाश आवेदन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल, यात्रा रियायत बिल, वाहन व्यय, ट्यूशन फीस इत्यादि पूरी तरह द्विभाषी रूप से उपयोग में लाए गए।

(ग) संस्थान में आयोजित होने वाले सभी शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रवेश - पत्र, बैनर आदि को द्विभाषी रूप में तैयार किया गया।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन - संस्थान के सभी अनुभागों / विभागों में प्राप्त हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया गया।

पत्राचार की स्थिति - संस्थान 'क' क्षेत्र में स्थित है, इस प्रकार 'क' और 'ख' क्षेत्रों में अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी/द्विभाषी रूप में किया गया, जो वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित हिंदी पत्राचार के लक्ष्य के लगभग अनुरूप है। इस प्रकार संस्थान के हिंदी पत्राचार की स्थिति संतोषजक है।

संस्थान की द्विभाषी वेबसाइट - संस्थान की वेबसाइट हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है तथा वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया गया।

नराकास की बैठक - संस्थान 'क' क्षेत्रा में स्थित होने के कारण, माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(नराकास दक्षिण दिल्ली-3) का सदस्य कार्यालय है। संस्थान ने वर्ष के दौरान नराकास द्वारा समय-समय पर आयोजित सभी बैठकों में अपनी सहभागिता दर्ज की है।

तिमाही बैठक -2024-25 के दौरान राजभाषा नियमों के अनुपालनार्थ प्रत्येक तिमाही में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों/कार्यों का संक्षिप्त विवरण:-

(1) यज्ञ अंक: 15, का विमोचन व वितरण दिनांक 2 मई, 2024 को संस्थान के स्थापना दिवस पर किया गया।

(2) हिंदी पुस्तक: कार्यालय पद्धति ई - नियम पुस्तिका का वितरण कुल 94 संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 18.11.2024 किया गया।

(3) संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण: दिनांक 21.11.2024 को ओबेराय होटल में किया गया था, उपरोक्त निरीक्षण के दौरान हिंदी अनुभाग के द्वारा राजभाषा प्रदर्शिनी भी लगाई गई।

(क) हिंदी पखवाड़ा: राजभाषा नीति के अनुपालन में संस्थान में हिंदी पखवाड़ा दिनांक 16-30 सितंबर, 2024 को आयोजित किया गया था। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनका विवरण क्रमश: (1) कथा कहानी अपनी जुबानी प्रतियोगिता (मौखिक) (2) हिंदी टंकण प्रतियोगिता (3) हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (लिखित) (4) हिंदी निबंध प्रतियोगिता (लिखित)। हिंदी पखवाड़ा -2024 में कुल 143 कर्मचारियों के द्वारा सहभागिता प्रदान की गई। हिंदी पखवाड़ा - 2024, हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची निम्न लिखित है:-

कथा कहानी अपनी जुबानी प्रतियोगिता: -

क्र. सं.	प्रतिभागी का नाम	स्थान प्राप्त किया	पुरस्कार राशि (रु)
1.	सुश्री शालू वशिष्ठ	प्रथम	2000.00
2.	श्री एस. बाला जी (अहिंदी भाषी)	प्रथम	2000.00
3.	श्री राजपाल	द्वितीय	1500.00
4.	श्री मनीष शर्मा	तृतीय	1000.00
5.	श्री दीपांशु सक्सेना	प्रोत्साहन	500.00
6.	श्री रंजन कुमार	प्रोत्साहन	500.00
7.	सुश्री सविता अरोड़ा बेदी	प्रोत्साहन	500.00
8.	सुश्री अनीता महतो	प्रोत्साहन	500.00

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता: -

क्र. सं.	प्रतिभागी का नाम	स्थान प्राप्त किया	पुरस्कार राशि (रु)
1.	श्री करण चोपड़ा	प्रथम	2000.00
2.	श्री जी. मुनिविनय (अहिंदी भाषी)	प्रथम	2000.00
3.	श्री संजीव कुमार	द्वितीय	1500.00
4.	श्री राकेश कुमार ओझा	तृतीय	1000.00
5.	श्री संजय वर्मा	प्रोत्साहन	500.00
6.	सुश्री नीलम दहिया	प्रोत्साहन	500.00
7.	श्री राजन	प्रोत्साहन	500.00
8.	सुश्री सुशील रानी	प्रोत्साहन	500.00
9.	श्री आशीष कुमार	प्रोत्साहन	500.00

हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता: -

क्र. सं.	प्रतिभागी का नाम	स्थान प्राप्त किया	पुरस्कार राशि (रु)
1	श्री प्रवीण कुमार यादव	प्रथम	2000.00
2	श्री प्रणित लांडगे (अहिंदी भाषी)	प्रथम	2000.00
3	श्री सोजल गुप्ता	द्वितीय	1500.00
4	श्री ईशव	द्वितीय	1500.00
5	श्री वैभव यादव	तृतीय	1000.00
6	श्री अनिल कुमार	प्रोत्साहन	500.00
7	श्री लक्ष्मीकांत नागर	प्रोत्साहन	500.00
8	श्री सुनील कुमार	प्रोत्साहन	500.00
9	सुश्री सुरभि वत्स	प्रोत्साहन	500.00
10	श्री उत्सव कुशवाहा	प्रोत्साहन	500.00

निबंध प्रतियोगिता :-

क्र. सं.	प्रतिभागी का नाम	स्थान प्राप्त किया	पुरस्कार राशि (रु)
1	सुश्री नीरू वर्मा	प्रथम	2000.00
2	श्री नीरज कुमार	प्रथम	2000.00
3	सुश्री पी जी दीपा (अहिंदी भाषी)	प्रथम	2000.00
4	श्री राकेश कुमार यादव	द्वितीय	1500.00
5	सुश्री मीन मरोठिया	तृतीय	1000.00
6	श्री गिरीश कुमार	प्रोत्साहन	500.00
7	सुश्री करिश्मा खान	प्रोत्साहन	500.00
8	श्री नवीन	प्रोत्साहन	500.00
9	श्री यतिन कुमार	प्रोत्साहन	500.00
10	सुश्री गुरदीप कौर	प्रोत्साहन	500.00

(2) हिंदी कार्यशाला एव संगोष्ठी:

(क) कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी एवम् वाक्य सांच्य विषय पर कर्यशाला: दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को संस्थान के कर्मचारियों के लिए कार्यशाला में प्रयोग की जाने वाली हिंदी एवम् वाक्य सांच्य विषय पर कार्याशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में डॉ. एस. एस. कुथुरिया (संयुक्त निदेशक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को आमंत्रित किया गया था।

(ख) कार्यालय में हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग विषय पर कार्यशाला: दिनांक 19 मार्च, 2025 को संस्थान के कर्मचारियों के लिए कार्यालय में हिन्दी का व्यावहारिक प्रयोग के विषय पर कार्याशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में डॉ. रेखा चंदोला, राजभाषा अधिकारी, हुडको, को आमंत्रित किया गया था।

(3) दीक्षांत समारोह में द्विभाषी डिग्रीः

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का 57वां दीक्षांत समारोह, दिनांक 11 नवम्बर, 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें श्री जयेन मेहता, (गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड- अमूल) के प्रबंध निदेशक मुख्य अतिथि रहे। दीक्षांत समारोह के दिन स्नातकोतर की शिक्षा पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को कुल 529 द्विभाषी डिग्री प्रदान की गई।

शिक्षण /प्रशिक्षण

(1) निर्यात बंधु योजनाः भारत सरकार के निर्यात बंधु योजना के अंर्तगत आई.आई.एफ.टी द्वारा चलाए जा रहे मैसिव-ओपन-आनलाइन कोर्स(एमओओसी-मूक) कार्यक्रम को वर्ष 2024-25 के दौरान जारी रखा गया तथा इसके अंतर्गत लगभग 134 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इन सभी आनलाइन निर्यात- आयात व्यापार में प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों में अंग्रेजी- हिंदी की मिली-जुली भाषा का उपयोग किया गया।

(2) एमडीपी प्रभाग ने विभिन्न स्तरों के प्रबंधकों और अधिकारियों के लिए कुल 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। (आईटीएस परिवीक्षार्थियों और सशस्त्रा बलों के अधिकारियों और पीएसयू के अधिकारियों के लिए)। इसके अलावा 3 कार्यक्रम 6 माह एवम् 1 कार्यक्रम 11 माह की अवधि के प्रमाणपत्र कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इन कार्यक्रमों से कुल 397 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। इन सभी कार्यक्रमों में अंग्रेजी- हिंदी की मिली-जुली भाषा का उपयोग किया गया।

संस्थान में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यथासंभव प्रयास किए गए।

वार्षिक लेखा
2024-25

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रबंधन बोर्ड के सदस्य
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
(सोसायटी पंजीकरण अधिनियम**, 1860** के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था**)**
(मानित विश्वविद्यालय**)**
बी-**21,** कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट
राय
हमने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च 2025 तक का बैलेंस शीट, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय विवरण और प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण, तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, शामिल हैं।
हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
(क) बैलेंस शीट के मामले में, 31 मार्च, 2025 तक सोसायटी की कार्य स्थिति।
(ख) आय-व्यय विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सोसायटी की आय-व्यय।
(ग) प्राप्तियों और भुगतानों के विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का।

राय का आधार
हमने लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुसार संस्थान (आईआईएफटी) से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

Emphasis of Matter मामले पर ज़ोर

1) हम वित्तीय विवरण की अनुसूची 17 के नोट संख्या 10 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्य मानदंडों के लिए ₹1.5 करोड़ का प्रावधान दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष के अंत में ₹3 करोड़ का संचित शेष रहा। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई और प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्निहित देयता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

2) हम वित्तीय विवरण की अनुसूची 17 के नोट संख्या 11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि इकाई अनुसूची 3 - चालू देयताओं के अंतर्गत ₹77,69,937 की राशि को आगे ले जाना जारी रखे हुए है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले से बकाया है। इस राशि के संबंध में कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है या नहीं, यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य या मूल्यांकन उपलब्ध नहीं कराया गया। हमारे विचार से, इसके परिणामस्वरूप देनदारियों को संभवतः अधिक दर्शाया गया है और आय*शुद्ध* परिसंपत्तियों को समान राशि से कम दर्शाया गया है।

3) हम वित्तीय विवरण की अनुसूची 17 के नोट संख्या 3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए संस्था के वित्तीय विवरण। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य (WDV) पद्धति पर लगाया गया है। हालाँकि, प्रबंधन बोर्ड ने वर्ष 2017-18 में एक अचल संपत्ति नीति को मंजूरी दी थी, जिसमें अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने के लिए सीधी रेखा पद्धति (SLM) निर्धारित की गई थी।

4) हम वित्तीय विवरण की अनुसूची 17 के नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि संगठन के पास चेक के रूप में अनसुलझे देय राशियाँ हैं, जो कुल मिलाकर 19,94,574/- रुपये के अनसुलझे लिखत/अनिर्णित चेक हैं (2022-23 के लिए 2,88,410 रुपये, 2023-24 के लिए 3,08,320 रुपये और 2024-25 के लिए 13,97,844/- रुपये)। यह देखा गया कि इन अनसुलझे लिखतों की संचयी राशि को संबंधित विक्रेता बहीखातों के माध्यम से उचित रूप से रूट करने के बजाय, व्यय को कम करके समायोजित किया गया है। इसके अलावा, इस लेखांकन उपचार का समर्थन करने वाले ठोस लेखापरीक्षा साक्ष्य, जिसमें आंतरिक अनुमोदन या दस्तावेजी औचित्य शामिल हैं, हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए।

5) हम वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट संख्या 21 और नीचे सूचीबद्ध विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो महत्वपूर्ण समायोजनों के प्रभावों का वर्णन करते हैं। इन विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है। सीपीएफ खाते और संबंधित आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों का वित्तीय विवरण, जो सोसायटी के भीतर बनाए रखा जाता है, संलग्न वित्तीय विवरण का हिस्सा नहीं बनाया गया था।

उपरोक्त विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के प्रबंधन और संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की ज़िम्मेदारियाँ

सोसायटी का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सोसायटी की स्थिति, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस ज़िम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो एक सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतफ़हमी से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन, सोसाइटी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन सोसाइटी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।
प्रशासन के प्रभारी, सोसाइटी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा-परीक्षण हमेशा किसी महत्वपूर्ण ग़लतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। ग़लतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।
एसएएस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन सोसायटी के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सोसाइटी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण सोसाइटी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

. • प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतबयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना उत्पन्न करती है कि वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलतबयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी जाँच से पता चलता है, सोसायटी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बही रखी गई है।

ग) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय-व्यय विवरण और प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण लेखा-बही के अनुरूप हैं।

केजीआरएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 310014 ई

एस देब बर्मन
भागीदार
सदस्यता संख्या 301207
यूडीआईएन: 25301207BMLWXT3291

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 अक्तूबर 2025

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट

राशि (रु.)

विवरण	अनुसूची	31-03-2025	31-03-2024
कॉर्पस / पूंजी निधि और देयताएं			
कॉर्पस, पूंजी और अन्य निधियाँ	1	9,064,819,158	7,889,842,116
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	2	140,797,357	139,952,154
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	3	586,160,934	677,088,126
कुल		**9,791,777,448**	**870,68,82,395**
संपत्तियाँ			
स्थायी संपत्तियाँ	4	2,744,843,534	1,937,059,820
निर्धारित निधियों में निवेश	5	140,797,357	139,952,154
अन्य में निवेश	6	5,228,934,988	4,493,942,246
निवेशों पर अर्जित ब्याज	7A	557,392,836	534,298,104
चालू संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	7	1,119,808,735	1,601,630,071
कुल		**9,791,777,448**	**870,68,82,395**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	16		
आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ	17		

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
केजीआरएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 310014 ई

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के लिए

सीए एस देब बर्मन
भागीदार
सदस्यता संख्या 301207
यूडीआईएन: 25301207BMLWXT3291
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 अक्तूबर 2025

श्री पीताम्बर बेहरा
उप. वित्त अधिकारी

श्री गौरव गुलाटी
रजिस्ट्रार
(अतिरिक्त प्रभार)

प्रो. आर.एम. जोशी
कुलपति
(अतिरिक्त प्रभार)

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

विवरण		अनुसूची	31-03-2025	31-03-2024
क आय				
सेवाओं से आय		8	1,294,420,485	121,36,49,909
आईआईएफटी के लिए प्राप्त अनुदान		9	100,000,000	-
सीआरआईटी के लिए प्राप्त अनुदान		9A	450,000,000	30,75,00,000
सीआरआईटी की आय		9B	4,356,091	1,63,01,293
शुल्क/सदस्यताएँ		10	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		11	30,813	10,213
अर्जित ब्याज		12	385,222,770	405,681,001
निवेश पर अर्जित ब्याज		12A	-	-
अन्य आय		13	39,472,465	59,897,266
पूर्व अवधि की आय		13A	-	-
	कुल (ए)		**2,273,502,624**	**2,003,039,681**
ख. व्यय				
sस्थापना व्यय		14	479,240,898	44,26,58,489
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		15	562,050,817	47,45,74,544
मूल्यह्रास - (अनुसूची 4 के अनुरूप)		4	44,086,266	4,50,84,700
पूर्व-अवधि मदें (शुद्ध)		15A	-	-
CRIT के लिए व्यय		15B	440,514,721	34,88,41,990
कुल (B)	कुल (बी))		**152,58,92,701**	**131,11,59,723**
शेष राशि व्यय पर आय की अधिकता है (ए - बी)			**74,76,09,923**	**69,18,79,958**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
केजीआरएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 310014 ई

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के लिए

सीए एस देब बर्मन
भागीदार
सदस्यता संख्या 301207
यूडीआईएन:25301207BMLWXT3291
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 अक्तूबर 2025

श्री पीताम्बर बेहरा
उप. वित्त अधिकारी

श्री गौरव गुलाटी
रजिस्ट्रार
(अतिरिक्त प्रभार)

प्रो. आर.एम. जोशी
कुलपति
(अतिरिक्त प्रभार)

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	31-03-2025	31-03-2024	भुगतान	31-03-2025	31-03-2024
I. I. प्रारंभिक शेष			**I. खर्च**		
((क) नकद एवं स्टाम्प हाथ में	7,263	47,961	(क) स्थापना व्यय	626,882,847	547,416,825
(ख) बैंक जमा			(ख) प्रशासनिक व्यय	527,079,461	363,318,567
(i) चालू खाते	530,435,656	383,577,595			
(ii) जमा खाता (एसटीडी)	339,010,984	318,872,643	**किए गए निवेश और जमा राशि**		
(iii) बचत बैंक	41,651,155	13,509,609			
			स्वयं के धन से (निवेश-अन्य)	3,048,383,000	1,964,783,500
II. अनुदान प्राप्त हुआ					
(क) आईआईएफटी	-	4,732,301	**II अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्यों पर व्यय प्रगति पर है**		
(ख) भारत सरकार (सीआरआईटी) से	450,000,000	307,500,000			
(ग) एमओसी (कैपेक्स) से - काकीनाडा	250,000,000	249,900,000			
(घ) एपी (कैपेक्स) से - काकीनाडा	204,000,000				
(ई) एमओसी (ऑपेक्स) से	-	100,000,000			
III. निवेश पर आय					
			अचल संपत्तियों की खरीद	13,452,746	19,972,667
(क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	-	-			
			IV. अन्य भुगतान	954,527,199	784,549,155
IV. प्राप्त ब्याज					
			V. समापन शेष		
(क) बैंक जमा पर	302,088,669	275,416,523			
(ख) ऋण, अग्रिम आदि।			(क) नकद एवं स्टाम्प हाथ में	35,374	7,263
			(ख) बैंक बैलेंस		
V. अन्य आय			(i) चालू खाते	274081298.2	530,435,656

			(ii) जमा खाते (एसटीडी)	119,509,943	339,010,984
(क) बाजार सर्वेक्षण / सेमिनार शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क/संपत्ति आय	1,414,421,332	1,179,007,183	(iii) बचत बैंक	194,396,277	41,651,155
VI. अन्य प्राप्तियां					
(क) एफडी की परिपक्वता	1,867,305,607	1,563,330,149			
(क) विविध अचल संपत्तियों की बिक्री	359,427,479	195,251,807			
कुल	5,758,348,145	4,591,145,771	**कुल**	5,758,348,145	4,591,145,771

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
केजीआरएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 310014 ई

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के लिए

सीए एस देब बर्मन
भागीदार
सदस्यता संख्या 301207
यूडीआईएन:
25301207BMLWXT3291
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अक्तूबर 2025

श्री पीताम्बर बेहरा
उप. वित्त अधिकारी

श्री गौरव गुलाटी
रजिस्ट्रार
(अतिरिक्त प्रभार)

प्रो. आर.एम. जोशी
कुलपति
(अतिरिक्त प्रभार)

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: -1 पूंजी, कॉर्पस फंड और अन्य फंड राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025		31-03-2024	
A. पूंजी निधि				
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि				
भूमि और भवन के लिए पूंजी अनुदान		127,818,479		12,78,18,479
नए भवन के लिए पूंजी अनुदान		107,289,068		10,72,89,068
छात्रावास सी-9 के निर्माण के लिए पूंजी अनुदान		28,600,000		2,86,00,000
iमैदान गढ़ी में भूमि के लिए पूंजीगत अनुदान		406,370,863		40,63,70,863
मैदान गढ़ी भवन के निर्माण के लिए अनुदान	-		30,00,00,000	
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	300,000,000	-	30,00,00,000
कोलकाता में लीज़होल्ड भूमि		1		1
कोलकाता परिसर के निर्माण के लिए पूंजी अनुदान	1,215,918,678		124,32,60,058	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि			-	
जोड़ें: समायोजन	- 26,009,523	1,189,909,155	(27,341,380)	121,59,18,678
शिमला में एमएसएमई की स्थापना के लिए पूंजी अनुदान			1,88,00,000	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएँ: शिमला परियोजना में किया गया व्यय	-	-	1,88,00,000	
काकीनाडा परिसर के निर्माण के लिए पूंजी अनुदान				-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि - एपी 20.40 करोड़ रुपये + डीओसी 25 करोड़ रुपये)	364,800,000		11,49,00,000	
	454,000,000		24,99,00,000	

	जोड़ें: समायोजन	-	818,800,000	-	36,48,00,000
	वर्ष की शुरुआत में अन्य अनुदानों का शेष	153,402,257		15,34,02,257	
	घटाएँ: ग्रेच्युटी रिज़र्व फंड/अवकाश नकदीकरण रिज़र्व फंड में स्थानांतरित/	-		-	
	वर्ष के अंत में अन्य अनुदानों का शेष	-	153,402,257	-	15,34,02,257
	दान की गई संपत्ति निधि				
	दान की गई संपत्ति का आरंभिक शेष	10,998		10,998	
	जोड़ें: दान की गई संपत्ति निधि में स्थानांतरित	-		-	
	घटाएँ: मूल्यह्रास	-	10,998	-	10,998
	स्थायी सदस्यता				
	स्थायी सदस्यता का आरंभिक शेष	12,270,394		1,22,70,394	
	जोड़ें: ब्याज (समायोजन घटाकर)	-	12,270,394	-	1,22,70,394
B.	**सामान्य निधि**				
	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	5,173,361,377		442,43,65,917	
	जोड़ें: पिछले वर्ष का अप्रयुक्त प्रावधान, कोष में वापस जोड़ा गया	- 623,357		5,71,15,502	
	जोड़ें: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय का शेष	747,609,923		69,18,79,958	
	जोड़ें: सहायता अनुदान (सीटीएफएल आय) से हस्तांतरण			-	
	घटाएँ: छात्र कल्याण (एचसीआईएम) में हस्तांतरण			0	

	जोड़ें: कोलकाता भवन का समायोजन			-	
	घटाएँ/जोड़ें: पेंशन कोष में हस्तांतरित		5,920,347,943		517,33,61,377
C	पिछली अवधि के लिए समायोजन				
	कुल		**9,064,819,158**		**7,889,842,116**

अनुसूची: -1ए इंटरयूनिट बैलेंस

	विवरण	**31-03-2025**		**31-03-2024**	
	अंतर-इकाई देय		2267256206		4,024,015,979
	अंतर-इकाई प्राप्य		-2267256206		- 4,024,015,979
	कुल		-		-

** दिल्ली से काकीनाडा और दिल्ली से कोलकाता के बीच अंतर-इकाई संतुलन और इसके विपरीत*

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: -2 निर्धारित / बंदोबस्ती निधि

राशि (रु.)

फंड	(क) निधियों का आरंभिक शेष (01.04.2024 तक)	(ख) 2024-25 के दौरान निधियों में वृद्धि		कुल (a+b)	(ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय	TOTAL (c)	वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (a+b-c) 31.03.2025 तक	पिछले वर्ष [31.03.2024 तक]
		(i) निधियों के कारण किए गए निवेश से आय	(ii) अन्य परिवर्धन		(i) राजस्व व्यय / हस्तांतरण			
पुरस्कारों के लिए बंदोबस्ती								
एके सेनगुप्ता पुरस्कार	13,795	828	-	14,623	-	-	14,623	13,795
बीएम घई पुरस्कार	49,454	2,967	-	52,421	-	-	52,421	49,454
डन एंड ब्रैड स्ट्रीट अवार्ड	4,565	274	-	4,839	-	-	4,839	4,565
रंगास्वामी पुरस्कार	16,345	981	-	17,326	-	-	17,326	16,346
श्रीनिवास अयंगर पुरस्कार	21,069	1,264	-	22,333	-	-	22,333	21,070
डॉ. बसंत के साहू, (स्वर्ण पदक)	500,000	30000	-	530,000		-	530,000	500,000
डॉ. वी. के. पांडे (स्वर्ण पदक)	1,000,000	59999	-	1,059,999	60,500	60,500	999,499	1,000,000
अध्यक्षों के लिए बंदोबस्ती								
एपीडा अध्यक्ष	7,703,801	462,228	-	8,166,029	-	-	8,166,029	7,703,801
ईडीआई अध्यक्ष वीएसएनएल	13,071,239	784,274	-	13,855,513	-	-	13,855,513	13,071,238
ईडीआई अध्यक्ष बामर-लॉरी	2,889,680	173,381	-	3,063,061	-	-	3,063,061	2,889,680

एसटीसी अध्यक्ष	8,722,174	523,330	-	9,245,504	-	-	9,245,504	8,722,173
छात्रवृत्ति निधि								
छात्रवृत्ति रसीद खाता	161,187	9,671	-	170,858	-	-	170,858	161,187
सुमित्रा चिश्ती पुरस्कार	77,417	4,645	-	82,062	-	-	82,062	77,417
ऑरनेट सोलर	671,460	40,288	-	711,748	20,000	20,000	691,748	671,460
अन्य निधियाँ								
एमएमटीसी कोष	6,592,565	395,554	-	6,988,119	-	-	6,988,119	6,592,565
पीईसी कोष	1,264,844	75,891	-	1,340,735	-	-	1,340,735	1,264,842
छात्र कल्याण कोष (एचसीआईएम)	97,192,560		-	97,192,560	1,639,874	1,639,874	95,552,686	97,192,560
				-				
वित्तीय वर्ष का कुल 2024-25	**139,952,156**	**2,565,575**	**-**	**142,517,731**	**1,720,374**	**1,720,374**	**140,797,357**	**139,952,154**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: -3 वर्तमान देयताएं और प्रावधान राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025		31-03-2024	
A. वर्तमान देनदारियां				
1. विविध लेनदार		2,873,780		697,479
2. कर्मचारियों को देय		38,403,842		34,761,480
3. प्राप्त अग्रिम राशि		-		-
3A. छात्रों से प्राप्त अग्रिम राशि		-		-
4. सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि		14,634,429		15,271,929
5. पुराने चेक				
क) 12 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया	-		288,410	
ख) 12 महीने से कम अवधि के लिए बकाया	-	-	144,475	432,885
6. निधियाँ				
क) आईआईएफटी पूर्व छात्र निधि	20,525,971		11,883,734	
ख) आईएमएफ निधि (प्राप्ति योग्य)	-3,912,089	16,613,881	- 6,952,997	4,930,737
7. अन्य चालू देयताएँ				
क) अन्य चालू देयताएँ	91,369,741		90,602,243	
ख) अग्रिम अनुदान	4,492,435		-	
ग) छात्रवृत्तियाँ	498,453		-	
घ) ईसीजीसी	1,766,577		375,000	
ङ) वैधानिक देय	15,606,127	113,733,332	13,712,186	104,689,428
कुल (क)		**186,259,265**		**160,783,938**
B. प्रावधान				
1. ग्रेच्युटी		172,354,125		176,732,858
2. संचित अवकाश नकदीकरण		155,504,203		159,909,783
3. बोनस		-		481,257
4. अन्य प्रावधान		72,043,341		79,180,290
कुल (ख)		**399,901,669**		**416,304,188**
C. अगले वर्ष के लिए हस्तांतरित जीआईए का शेष		**-**		**100,000,000**
कुल (क +ख)		**586,160,934**		**677,088,126**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4: अचल संपत्तियां

विवरण		प्रतिपूर्ति की दर.	सकल ब्लॉक			
			01.04.2024 पर	परिवर्धन	समायोजन	31.03.2025 पर
1	**भूमि**					
	(क) लीज़होल्ड - दिल्ली परिसर		27,738,561			27,738,561
	(ख) लीज़होल्ड - मैदानगढ़ी, दिल्ली		416,404,588	-	-	416,404,588
	(ग) लीज़होल्ड - कोलकाता परिसर		1			1
2	**भवन**		-			-
	(क) सीडब्ल्यूपी-एनबीसीसी लिमिटेड (मैदानगढ़ी)		27,938,486	-	-	27,938,486
	(क) लीज़होल्ड	**1.58%**	154,940,714	-		154,940,714
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर [सी9]		-			-
	(ग) लीज़होल्ड (नेफेड)		-	-	-	-
	(घ) भवन		40,058,778	-	-	40,058,778
	(ङ) कोलकाता भवन		1,215,006,089	-		1,215,006,089
	(च) निदेशक निवास		5,231,158	-		5,231,158
	(छ) कोलकाता सीडब्ल्यूआईपी		-	15,404,317	-	15,404,317
	(छ) काकीनाडा सीडब्ल्यूआईपी			814,492,150		814,492,150
3	**फर्नीचर और फिक्स्चर, विद्युत उपकरण, टेप रिकॉर्डर और सहायक उपकरण, ऑडियो विजुअल उपकरण**	**9.50%**	198,278,861	9,359,852	50,519	207,588,194
4	**वाहन**	**9.50%**	2,959,169	-	-	2,959,169
5	**कार्यालय उपकरण, टाइपराइटर, डुप्लीकेटर, एयर कंडीशनर, ट्रांसफार्मर और वाटर कूलर**	**9.50%**	46,357,446	4,171,661	286,466	50,242,641
6	**कंप्यूटर हार्डवेयर**	**25%**	187,249,405	6,098,667	-	193,348,072
7	**पुस्तकें**	**33.33%**	43,071,920	2,680,322	-	45,752,242
8	**सौर पैनल**	**1.58%**	19,945,072			19,945,072
9	**रसोई उपकरण (कोलकाता)**		-			-
10	**जिम उपकरण**	**9.50%**	1,129,318	-	-	1,129,318
11	**संयंत्र और मशीनरी**	**6.33%**	92,213,810	-	-	92,213,810
12	**ज्ञान के पंख**		1,499,850			1,499,850
कुल (ए)			**2,480,023,226**	**852,206,969**	**336,985**	**3,331,893,210**

अन्य अचल संपत्तियाँ			-			-
(a) संपत्ति SIDA						
(i)	फोटो कापियर , पुस्तकें/व्यापार निर्देशिका, प्रिंटिंग मशीन/लेटरिंग मशीन और टाइपराइटर	**9.50%**	568,982	-	-	68,982
(ii)	ऑडियो-विजुअल उपकरण और माइक्रो फिश रीडर	**9.50%**	897,520	-	-	897,520
(ख) दान की गई संपत्ति निधि			-			-
(i)	कंप्यूटर	**25%**	2,136,528	-	-	2,136,528
(ii)	फव्वारा और सरस्वती मूर्ति	**9.50%**	77,000	-	-	77,000
कुल (बी)			**3,680,030**	**-**	**-**	**3,680,030**
कुल योग (ए+बी)			**2,483,703,256**	**852,206,969**	**336,985**	**3,335,573,240**
पिछले वर्ष			**2,426,318,969**	**67,896,602**	**10,512,315**	**2,483,703,256**

मूल्यह्रास					नेट ब्लॉक	
31.03.2024 तक	कटौती	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2025 तक	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
-				-	27,738,561	27,738,561
-				-	416,404,588	416,404,588
-				-	1	1
-				-	-	-
-	-	-	-	-	27,938,486	27,938,486
95,249,962		943,114		96,193,076	58,747,638	59,690,752
-				-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6,862,213		524,506		7,386,719	32,672,059	33,196,565
74,208,263		18,024,607		92,232,870	1,122,773,219	1,140,797,826
408,038		76,203		484,241	4,746,917	4,823,120
-	-	-	-	-	15,404,317	-
				-	814,492,150	
113,413,344		8,558,583	-	121,971,930	85,616,264	84,865,517
1,579,301		131,086		1,710,387	1,248,782	1,379,868
29,377,253		960,443	-	30,337,696	19,904,945	16,980,193
159,213,860		7,933,157		167,147,017	26,201,055	28,035,545
38,169,280		2,074,988		40,244,269	5,507,973	4,902,640
1,765,462		287,238		2,052,700	17,892,372	18,179,610
-				-	-	-
387,041		70,516		457,557	671,761	742,277
21,183,212		4,496,237		25,679,449	66,534,361	71,030,598
1,146,178		5,588		1,151,766	348,084	353,672
542,963,407	**-**	**44,086,266**	**-**	**587,049,676**	**2,744,843,534**	**1,937,059,819**
-					-	-
-				-	-	-
568,982		-		568,982	-	-
897,520		-		97,520	-	-
-				-	-	-
2,136,528		-		2,136,528	-	-
77,000		-		77,000	-	-
3,680,030	**-**	**-**	**-**	**3,680,030**	**-**	**-**
546,643,437	**-**	**44,086,266**	**-**	**590,729,706**	**2,744,843,534**	**1,937,059,820**
501,558,736	**-**	**45,084,701**	**-**	**546,643,437**	**1,937,059,819**	**1,924,760,233**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: -5 निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों में निवेश राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
A निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	140,797,357	13,99,52,154
कुल	**14,07,97,357**	**13,99,52,154**

अनुसूची: -6 निवेश-अन्य राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
A कॉर्पस		
क) सावधि जमा में - कॉर्पस	4,683,076,750	401,23,49,170
B ग्रेच्युटी रिज़र्व फंड	172,354,125	8,62,74,899
C अवकाश नकदीकरण रिज़र्व फंड	155,504,203	53,725,051
D पेंशन/बोनस कॉर्पस	38,000,000	4,45,93,226
E आयकर प्रयोजनों के लिए	179,999,910	29,69,99,900
कुल	**522,89,34,988**	**449,39,42,246**

अनुसूची: -7 निवेश पर अर्जित ब्याज (लेकिन देय नहीं) राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
1 सावधि जमा पर	540,948,274	52,80,47,688
2 स्वीप खाते पर	16,430,239	6,236,093
3 बचत बैंक खाते पर	14,323	14,323
कुल	**55,73,92,836**	**53,42,98,104**

नोट: उपार्जित परंतु देय नहीं ब्याज, अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज को दर्शाता है। संबंधित प्रभाव को कॉर्पस/आय खाते में दर्ज किया गया है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: -7ए चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि। राशि (रु.))

विवरण	31-03-2025		31-03-2024	
A. चालू संपत्तियाँ:				
1 इन्वेंट्री:				
(क) स्टेशनरी/कंप्यूटर उपभोग्य सामग्रियों आदि का स्टॉक (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लागत पर)		-		-
2 विविध देनदार:				
(क) 6 महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण	31,703,129		3,00,25,445	
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-		0	
	31,703,129		3,00,25,445	
(ख) 6 महीने से कम अवधि के बकाया ऋण	19,516,998		1,02,87,541	
(ग) छात्रों से प्राप्तियां	313,500	5,15,33,627	3,03,999	4,06,16,985
3 नकद और स्टाम्प (नकद अग्रदाय सहित)		60,374		7,362
4 बैंक शेष:				
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ:				
चालू खाता (इंडियन बैंक)				
अल्पकालिक जमा (स्वीप खाता)	274,081,298		20,01,28,184	
अन्य बैंक खाते	119,509,858		33,90,10,984	
	194,396,363	58,79,87,518	37,19,58,623	91,10,97,791
5 छठे वेतन आयोग का बकाया		-	-	-
कुल (ए)		**63,95,81,520**		**95,17,22,138**
B. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ:				
1 ऋण:				
(क) कर्मचारी (कर्मचारी अग्रिम सहित)		8,519,249		44,15,442
2 नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:				
(क) पूर्व भुगतान	19,527,620		1,03,13,706	
(ख) अन्य (बयाना राशि/सुरक्षा जमा सहित)	341,643,871		52,09,97,925	
(ग) एनबीसीसी काकीनाडा/सीडब्ल्यूआईपी				
(घ) पुराने चेक	-	36,11,71,491	0	53,13,11,631
3 स्रोत पर कर कटौती		110,536,475		11,41,80,861
कुल (बी)		**48,02,27,215**		**64,99,07,933**
कुल (ए+बी)		**111,98,08,735**		**160,16,30,071**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: - 8 सेवाओं से आय राशि (रु.)

विवरण		31-03-2025	31-03-2024
1	सेवाओं से आय		
	(क) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	455,673	5,49,828
	(ख) प्रशिक्षण/अनुसंधान कार्यक्रम	1,293,043,612	121,31,00,081
	(ग) गिफ्ट सिटी आय	921200	
कुल		**129,44,20,485**	**121,36,49,909**

अनुसूची: - 9 अनुदान राशि (रु.)

विवरण		31-03-2025	31-03-2024
1	अफ्रीकी नागरिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (बी/एफ)		-
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		-
	घटाएँ: कार्यक्रमों पर व्यय (बी)		
	अगले वर्ष के लिए आगे ले जाएँ (सी)		
3	एमएसएमई शिमला परिसर की स्थापना		-
	पिछले वर्ष के लिए आगे ले जाएँ		-
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		-
	घटाएँ: समायोजन		-
	घटाएँ: कार्यक्रमों पर व्यय (डी)		-
	अगले वर्ष के लिए आगे ले जाएँ (ई)		-
	अनुदान से आय - काकीनाडा	100,000,000	-
कुल		**100,000,000**	**-**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: -9ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र के लिए अनुदान

राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
1 केंद्र की गतिविधियों के लिए प्राप्त अनुदान	450,000,000	30,75,00,000
कुल	**45,00,00,000**	**30,75,00,000**

अनुसूची: -9बी क्रिट आय

राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
1 वर्ष के दौरान प्राप्त आय	4,356,091	16,301,293
2 विश्व व्यापार संगठन जनशक्ति सेवाएँ		-
कुल	**4,356,091**	**16,301,293**

अनुसूची: -10 सदस्यताएँ

राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
1 वार्षिक सदस्यताएँ	-	-
कुल	**-**	**-**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: -11 प्रकाशनों से आय राशि (रु.))

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
1 प्रकाशनों से आय	30,813	10,213
कुल	**30,813**	**10,213**

अनुसूची: -12 अर्जित ब्याज राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
1 :सावधि जमा पर:		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	338,233,854	37,96,73,160
2 बचत बैंक खाते पर	46,657,243	2,24,53,443
3 ऋण पर:		
(क) कर्मचारी / स्टाफ	331,673	2,56,334
4 इनकम टैक्स रिफंड पर	-	32,98,064
कुल	**38,52,22,770**	**40,56,81,001**

अनुसूची: -13 अन्य आय राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
1 विविध आय	11,603,196	32,555,886
2 प्रायोजन	1,859,746	
3 आस्थगित अनुदान आय	26,009,523	27,341,380
कुल	**39,472,465**	**59,897,266**

अनुसूची: -13A पूर्व अवधि की मदें राशि (रु.)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
1 कार्यक्रम शुल्क	-	-
2 प्रकाशन आय	-	-
3 आरआईपी पर ब्याज	-	-
4 विविध आय डब्ल्यूटीओ	-	-
5 विविध पूर्व अवधि डेबिट	-	-
कुल	**0.00**	**0.00**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: -14 स्थापना व्यय राशि (रु.)

विवरण		**31-03-2025**	**31-03-2024**
1	वेतन, भत्ते और मजदूरी	378,884,654	33,70,80,852
2	भविष्य निधि में योगदान	12,649,069	1,28,20,217
3	एनपीएस में योगदान	19,619,268	1,90,82,763
4	कर्मचारी कल्याण व्यय	12,118,970	77,31,863
5	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभों पर व्यय	8,008,740	1,99,63,287
6	अन्य (संविदा कर्मचारियों और अन्य को वेतन)	42,098,407	3,92,64,783
7	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	5,861,790	67,14,724
कुल		**479,240,898**	**44,26,58,489**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची:-15 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि। राशि (रु.)

विवरण		31-03-2025	31-03-2024
1	विज्ञापन एवं प्रचार	1,143,388	18,17,087
2	लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	903,284	3,41,864
3	बैंक और बीमा शुल्क	223,407	18,18,087
4	कंप्यूटर और नेटवर्किंग अनुभव.	18,521,481	1,59,36,881
5	बिजली और पानी के शुल्क व्यय	39,110,268	3,63,73,080
6	सुरक्षा और हाउसकीपिंग पर खर्च	40,164,345	3,37,37,470
7	शैक्षणिक और प्लेसमेंट व्यय	176,196,632	12,80,58,920
8	जीएसटी / टीडीएस व्यय	55,251	5,444
9	विदेशी मुद्रा के लिए हानि/(लाभ)	276,587	537,421
10	गेस्ट हाउस सामान्य एवं रखरखाव व्यय	33,150,817	22,15,138
11	कानूनी / परामर्श शुल्क	3,785,613	29,96,826
12	पुस्तकालय व्यय	35,737,018	5,06,11,074
13	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	5227874.37	39,04,595
14	मरम्मत एवं रखरखाव	38,583,448	6,21,31,751
15	सदस्यता व्यय (प्रकाशन व्यय)	9079	13,245
16	वाहन संचालन एवं रखरखाव	371,353	3,78,470
17	विविध व्यय/शुल्क	5,787,441	57,88,498
18	भूमि किराया और संपत्ति कर	37,192,411	2,73,43,916
19	प्रशासन सामान्य व्यय	15,059,388	1,38,01,388
20	राजभाषा (हिंदी) का विकास	848,114	2,30,536
21	कार्य मानदंड	-	1,50,00,000
22	छात्रावास आवास और मेस शुल्क	26,078,703	3,73,58,600
23	गुजरात में आईआईएफटी परिसर की स्थापना	81,960,077	34,174,253
24	दुबई में आईआईएफटी परिसर की स्थापना	1,664,839	-
कुल		**562,050,817**	**474,574,544**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची- :15A पूर्व अवधि की मदें (शुद्ध) राशि (.रु)

विवरण		**31-03-2025**	**31-03-2024**
1	वेतन और कर्मचारी कल्याण व्यय		
2	कार्यक्रम व्यय		
3	मरम्मत एवं रखरखाव		
4	किराया दरें और कर		
5	मुद्रण और स्टेशनरी व्यय		
6	डाक और तार व्यय		
7	कानूनी और परामर्श शुल्क		
8	विविध पूर्व अवधि डेबिट		
9	विविध पूर्व अवधि क्रेडिट		
10	प्रकाशनसदस्यता/		
11	उपार्जित ब्याज		
12	विविध व्यय		-
कुल		**-**	**-**

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-:15बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र के लिए व्यय (सीआरआईटी)

राशि ((.रु)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
1 वेतन, भत्ते	192,437,088	167,372,428
2 चिकित्सा के खर्चे	497,381	606,126
3 पट्टा किराया (नेफेड)	53,533,212	51,886,161
4 sअध्ययन, सेमिनार और कार्यक्रम व्यय	158,112,235	102,671,659
5 आईआईएफटी को देय किराया और जनशक्ति लागत	1,200,000	1,200,000
6 अनुसंधान परियोजना	4,298,417	1,058,747
7 आउटरीच कार्यक्रम	395,533	214,872
8 पुस्तकालय की पुस्तकें, पत्रिकाएँ और समाचार पत्र	3,112,120	3,404,478
9 प्रकाशनों	-	100,300
10डेटाबेस	13,749,047	12,070,967
11विविध कार्यालय व्यय	5,153,769	4,036,485
12आईटी सुविधाएं	3,974,167	2,464,506
13अन्य बैठकों के लिए संकाय की यात्रा	2,217,578	1,660,151
14संकाय और कर्मचारी विकास कार्यक्रम	1,765,461	95,110
15वेबसाइट विकास एवं रखरखाव	68,713	-
16NAFED भवन निर्माण व्यय NAFED	-	-
कुल	**440,514,721**	**34,88,41,990**

आईआईएफटी संकाय
(प्रकाशन तिथि के अनुसार)

नाम	योग्यता	विशेषज्ञता
कुलपति		
डॉ. राकेश मोहन जोशी	पीएच.डी., एम.बी.ए., ई.एम.आई.टी. (स्वर्ण पदक विजेता) आईआईएफटी	अंतर्राष्ट्रीय विपणन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता।
प्रभागों/केंद्रों के प्रमुख		
डॉ. के. रंगराजन	पीएच.डी., एम.कॉम., ए.एम.टी. ए.ए.एम.ए. (ऑस्ट्रेलिया)	रणनीतिक प्रबंधन और व्यवसाय योजना, संगठनात्मक पुनर्गठन, क्लस्टर विकास और रणनीतियाँ, टीपीओ और राज्य उद्यमों का प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्र।
डॉ. रवीन्द्र सारधी वडलामुडी	पीएच.डी. (आईआईएम - अहमदाबाद) - एम.कॉम.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, वित्तीय प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन, प्रबंधन लेखांकन, स्प्रेडशीट मॉडलिंग, सुरक्षा विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन
डॉ. सैकत बनर्जी	पीएच.डी., "ग्लोबल बिज़नेस मैनेजमेंट प्रोग्राम" (थंडरबर्ड स्कूल ऑफ़ ग्लोबल मैनेजमेंट एरिज़ोना, अमेरिका), एम.बी.ए. (स्वर्ण पदक विजेता), पी.जी.डी.पी.आर., पी.जी.डी.एम. और एस.एम.	ब्रांड प्रबंधन, उपभोक्ता व्यवहार और विपणन संचार।
डॉ. रणजॉय भट्टाचार्य	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र), एम.फिल. (अर्थशास्त्र), एम.एससी. (अर्थशास्त्र)	अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और पर्यावरण अर्थशास्त्र।
डॉ. नीति नंदिनी चटनानी	Ph.D., M.B.A., B.Sc. पीएच.डी., एम.बी.ए., बी.एससी.	वित्त: वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षा विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन, कमोडिटी ट्रेडिंग और मूल्य जोखिम प्रबंधन, और आपूर्ति श्रृंखला वित्त।
डॉ. प्रबीर कुमार दास,	पीएच.डी., एमएससी (कृषि सांख्यिकी)	व्यवसाय सांख्यिकी, व्यवसाय अनुसंधान विधियां, उन्नत अनुसंधान विधियां एवं परियोजनाएं, विपणन अनुसंधान, परिचालन अनुसंधान, उन्नत विश्लेषण, वित्तीय जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन एवं रणनीति पर उन्नत पाठ्यक्रम, अनुप्रयुक्त विपणन अनुसंधान, व्यवसाय अनुप्रयोगों के लिए उन्नत पूर्वानुमान तकनीकें, बहुभिन्नरूपी डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान तकनीकें, सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धति, तथा बिग डेटा विश्लेषण।
डॉ. विश्वजीत नाग,	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र), एम.ए. (अर्थशास्त्र), वित्तीय प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा	औद्योगिक अर्थशास्त्र, अनुप्रयुक्त अर्थमिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त।
डॉ. शीबा कपिल	पीएच.डी., एम.बी.ए. (वित्त),	वित्तीय प्रबंधन, विलय और अधिग्रहण, व्यवसाय मूल्यांकन, निवेश विश्लेषण और

	यूजीसी-नेट, हार्वर्ड लॉ स्कूल से अंतर्राष्ट्रीय वित्त	मूल्यांकन।
डॉ. राम सिंह,	पीएच.डी., एम.बी.ए. यूजीसी-नेट एमजीजी (जर्मनी) एससीएम और लॉजिस्टिक्स में मास्टर सर्टिफिकेट (एमएसयू-यूएसए)	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन और रसद।
डॉ. पूजा लखनपाल	पीएच.डी. (संगठन व्यवहार) (आईआईटी, मुंबई), पोस्ट-डॉक्टरल (जर्मनी), एम.ए. (मनोविज्ञान)	प्रबंधकों के लिए मनोविज्ञान, संगठनात्मक व्यवहार, मानव संसाधन प्रबंधन, क्रॉस-सांस्कृतिक प्रबंधन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व।
डॉ. रोहित मेहतानी	पीएच.डी. अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन / अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति (एटीडब्ल्यूएस/एआईएस/जेएमआई), वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में स्नातकोत्तर (हल, इंग्लैंड/ब्रिटिश शेवनिंग स्कॉलर), एमबीए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कानूनी अध्ययन (डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया), एमएस. प्रबंधन परामर्श (बिट्स पिलानी), एमबीए औद्योगिक प्रबंधन (एनपीसी), एमपीए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन (पीयू), पीजीपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईआईएफटी दिल्ली) पीजीपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईआईएम कलकत्ता) बी.एस. (हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रणनीति, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यावसायिक वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताएँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन
डॉ. आशीष पांडे	पीएच.डी. (वित्त) पी.जी. प्रबंधन डिप्लोमा एम.कॉम., बी.कॉम.	सुरक्षा विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन, और निगम वित्तीय मूल्यांकन।
डॉ. संजय रस्तोगी,	पीएच.डी. पोस्ट-डॉक्टरल (जर्मनी), एम.एससी. (सांख्यिकी)	व्यवसाय सांख्यिकी, मात्रात्मक तकनीक, व्यवसाय अनुसंधान, विपणन अनुसंधान, अर्थमितीय मॉडलिंग और पूर्वानुमान।
डॉ. बसंत के. साहू,	पीएच.डी., अर्थशास्त्र, एम.फिल., अर्थशास्त्र, एम.ए., अर्थशास्त्र, बी.ए. (ऑनर्स), अर्थशास्त्र	विकास अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक नीति, समष्टि अर्थशास्त्र, कृषि और घरेलू अर्थशास्त्र, सूक्ष्म वित्त।
डॉ. जयंत कुमार सील,	पीएच.डी., सीएमए, एम.फिल.	कॉर्पोरेट वित्त, डेरिवेटिव और जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, सुरक्षा विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन, वित्तीय और प्रबंधन लेखांकन।
डॉ. आर.पी. शर्मा,	पीएच.डी., एम.बी.ए., एम.ए. (भूगोल)	विपणन प्रबंधन, सेवाओं का विपणन और बिक्री प्रबंधन।
डॉ. अशीम राज सिंगला,	एम.सी.ए.,	सूचना प्रणाली, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली,

	पीएच.डी.	ई-कॉमर्स, ईआरपी सिस्टम, सिस्टम विश्लेषण और डिज़ाइन, एमएस एक्सेल का उपयोग करके डेटा मॉडलिंग, और बिजनेस इंटेलिजेंस।
डॉ. दीपंकर सिन्हा,	पीएचडी (औद्योगिक एवं सिस्टम इंजीनियरिंग) आईआईटी, खड़गपुर एमबीए (वित्त), इग्नू एमएससी (भौतिकी-इलेक्ट्रॉनिक्स), एनआईटी, राउरकेला कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, एसीएल संचालन अनुसंधान में डिप्लोमा (ओआरएसआई)	अंतर्राष्ट्रीय रसद और संचालन प्रबंधन, बंदरगाहों और शिपिंग में एमआईएस, बीपीआर और लीन कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध प्रबंधन, सड़क रसद नियामक मामले और रेलवे रसद।

प्रोफेसर		
डॉ. देबाशीष चक्रवर्ती,	पीएच.डी., एम.फिल. (अर्थशास्त्र), एम.ए. (अर्थशास्त्र)	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि, पर्यावरणीय स्थिरता।
डॉ बिबेक रे चौधरी,	NET-JRF पीएच.डी. (अर्थशास्त्र), एम.फिल. (अर्थशास्त्र), एम.ए. (अर्थशास्त्र), नेट-जेआरएफ	समष्टि अर्थशास्त्र, उत्पादकता विश्लेषण, अनुप्रयुक्त अर्थमिति, सर्वेक्षण (निर्यात क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता, आदि), सेवा व्यापार, सूक्ष्म वित्त।
डॉ. ओ.पी. वली,	पीएच.डी. (जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय), ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर (आईआरएमए), प्रमाणित सॉफ्टवेयर गुणवत्ता पेशेवर चीनी भाषा में प्रमाणपत्र कार्यक्रम, सीएसईबी (यूके) से आईटीआईएल फाउंडेशन में प्रमाणित, एमजीजी (जर्मनी)	विपणन, सूचना प्रणाली और परियोजना प्रबंधन, अनुसंधान विधियां, और निर्णय मॉडलिंग।
डॉ.राधिका प्रसाद दत्ता,	पीएच.डी. (अर्लिंग्टन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय), एम.एस. (कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी), एम.एससी. (आईआईटी), बी.स्टेट. (आईएसआई)	प्रबंधन सूचना प्रणाली, डेटा माइनिंग (गोपनीयता-संरक्षण डेटा माइनिंग सहित), फ्रैक्टल्स और जटिल प्रणालियों में स्केलिंग।
डॉ. (श्रीमती) विजया कट्टी, (पुनः नियोजित)	पीएच.डी., एम.ए. (अर्थशास्त्र), पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च	सार्क के साथ भारत का व्यापार, भारत-नेपाल आर्थिक संबंध, विश्व व्यापार संगठन, आरटीए और संबंधित मुद्दे, वैश्विक व्यापार वातावरण, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत और व्यापार नीति से संबंधित मुद्दे।
डॉ. श्वेता श्रीवास्तव मल्ला,	पीएच.डी., एम.ए.	संगठनात्मक व्यवहार, व्यवहार विज्ञान, व्यावसायिक नैतिकता, संगठनात्मक न्याय, सकारात्मक मनोविज्ञान, सीएसआर, कॉर्पोरेट प्रशासन, सतत व्यवसाय।
डॉ. (श्रीमती) डी. सुनीता राजू,	पीएच.डी., एम.ए.	कृषि व्यापार मुद्दे, आर्थिक वातावरण और नीति, उद्योग क्षेत्र विश्लेषण, क्षेत्रीय व्यापार समझौते।
डॉ. नितिन सेठ, (प्रतिनियुक्ति पर)	पीएच.डी. (आईआईटी दिल्ली), पोस्ट-डॉक्टरल (जर्मनी), एम.टेक. (प्रोडक्शन आईआईटी दिल्ली), एम.ई. (औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन),	परिचालन प्रबंधन, सेवा परिचालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कुल गुणवत्ता प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन।

	बी.ई. (मैकेनिकल)	
डॉ. शाश्वती त्रिपाठी,	पीएच.डी. (गणित), नेट योग्यता प्राप्त सीएसआईआर फेलो प्रमाणित एससीओआर-पी प्रोफेशनल, एपीआईसीएस, यूएसए द्वारा प्रदत्त (आपूर्ति श्रृंखला पेशेवरों के लिए एपीआईसीएस से अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन) एम.फिल. (अनुप्रयोग गणित) एम.एससी. (अनुप्रयोग गणित)	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, संचालन प्रबंधन, संचालन अनुसंधान, व्यवसाय सांख्यिकी, व्यवसाय अनुसंधान विधियां (बीआरएम), ग्राफ सिद्धांत, संख्यात्मक विधियां, रैखिक और गैर-रैखिक अंतर समीकरण।
डॉ. एम. वेंकटेशन,	पीएच.डी. (सामाजिक मनोविज्ञान), एम.फिल. (सामाजिक मनोविज्ञान), एम.ए. (मनोविज्ञान)	संगठनात्मक व्यवहार, व्यवहार विज्ञान, मनोमितीय परीक्षण, मानव संसाधन प्रबंधन, योग्यता मानचित्रण, मात्रात्मक अनुसंधान विधियां, परिवर्तन प्रबंधन, वैश्विक नेतृत्व, उद्यमिता, कर्मचारी परामर्श, कर्मचारी सहभागिता।

सह आचार्य		
डॉ. त्रिप्तेंदु प्रकाश घोष,	पीएच.डी., एम.फिल., एम.ए. (अर्थशास्त्र)	वित्तीय प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, वित्त में एक्सेल स्प्रेडशीट मॉडलिंग, पारिवारिक फर्मों का प्रदर्शन और कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्तीय बाजार और संस्थान, निश्चित आय प्रतिभूतियां, सुरक्षा विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन।
डॉ. हिमानी गुप्ता,	पीएच.डी. (आईआईटी रुड़की), एम.फिल. (सांख्यिकी), एम.एससी. (सांख्यिकी), एफडीपी (आईआईएम-ए)	सांख्यिकी, अनुमान सिद्धांत, परिचालन अनुसंधान, व्यवसाय अनुसंधान विधियां, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण स्थिरता मुद्दे।
डॉ. जैकलीन सिम्स,	पीएच.डी., एम.कॉम., यूजीसी-जेआरएफ	वित्तीय और प्रबंधकीय लेखांकन, निवेश बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं का प्रबंधन।
डॉ. कौशिक भट्टाचार्जी,	बी.एससी, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पीएच.डी.	वित्तीय मॉडलिंग-वित्तीय विश्लेषण
सहायक प्रोफेसर		
डॉ. आंचल अरोड़ा,	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र) नेट (यूजीसी), एम.फिल. (अर्थशास्त्र) एम.ए. (अर्थशास्त्र) बी.ए. (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र
डॉ. तौफीक अजाज़,	पीएच.डी. नेट (यूजीसी), एम.फिल. (अर्थशास्त्र) एम.ए. (अर्थशास्त्र) बी.ए. (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र
डॉ. अनिर्बान विश्वास,	पीएच.डी. नेट (यूजीसी), एम.फिल. (अर्थशास्त्र) एम.ए. (अर्थशास्त्र) बी.ए. (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र
डॉ. आर्य के. सृष्टिधर चंद,	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र), एम.ए. (अर्थशास्त्र), बी.एससी. (भौतिकी)	आर्थिक सिद्धांत, वित्तीय अर्थशास्त्र औद्योगिक संगठन, अर्थमिति और समष्टि अर्थशास्त्र।
डॉ. गिन्नी चावला,	पीएच.डी., एम.बी.ए. (मानव संसाधन प्रबंधन),	मानव संसाधन प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन

	यूजीसी-नेट और जेआरएफ	
डॉ. सौरव दास,	पीएच.डी., एम.टेक, एमसीए, सांख्यिकी में बी.एससी. (ऑनर्स), यूजीसी नेट-प्रबंधन	प्रबंधकों के लिए डेटा विश्लेषण, अनुप्रयुक्त परिचालन अनुसंधान, व्यावसायिक विश्लेषण और बुद्धिमत्ता, सांख्यिकीय अनुप्रयोग, और परिचालन विश्लेषण, प्रबंधकों के लिए बुनियादी अर्थमितीय सांख्यिकी, व्यावसायिक विश्लेषण और परिचालन अनुसंधान।
डॉ. ओइंद्रिला डे	पीएच.डी., एम.ए. (अर्थशास्त्र), बी.एससी. (अर्थशास्त्र), नेट (यूजीसी)	अनुप्रयुक्त सूक्ष्मअर्थशास्त्र सिद्धांत, खेल सिद्धांत, औद्योगिक संगठन, श्रम अर्थशास्त्र, प्रायोगिक अर्थशास्त्र, परिवहन अर्थशास्त्र।
डॉ. पापिया घोष,	पीएच.डी., नेट एम.ए. (अर्थशास्त्र)	नेटवर्क का अर्थशास्त्र, कानून और अर्थशास्त्र, सामाजिक विकल्प सिद्धांत, अनुप्रयुक्त सूक्ष्मअर्थशास्त्र।
डॉ अंजू गोस्वामी,	पीएच.डी. (वित्त अर्थशास्त्र), यूजीसी नेट (प्रबंधन) एमबीए (वित्त) बीबीए	बुनियादी और उन्नत अर्थमिति, अनुसंधान पद्धति, दक्षता उत्पादकता विश्लेषण।
डॉ. चारु ग्रोवर,	पीएच.डी., नेट (यूजीसी), एम.फिल. (अर्थशास्त्र), एम.ए. (अर्थशास्त्र), बी.ए. (अर्थशास्त्र)	पर्यावरण अर्थशास्त्र, व्यापार, अर्थमिति, सूक्ष्म अर्थशास्त्र।
डॉ. आशीष गुप्ता,	पीएच.डी., एम.बी.ए. (मार्केटिंग), यूजीसी-नेट	विपणन प्रबंधन, उपभोक्ता व्यवहार, विज्ञापन और ब्रांड प्रबंधन, डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग।
सुश्री नेहा जैन, (अनुबंध पर)	पीएच.डी. एम.फिल. (अर्थशास्त्र) एम.ए. (अर्थशास्त्र)	अर्थमिति, विकास अध्ययन।
डॉ. प्रियंका जयसवाल,	पीएच.डी., एमबीए (मानव संसाधन प्रबंधन एवं संगठनात्मक व्यवहार), बी.एससी.	मानव संसाधन प्रबंधन एवं संगठनात्मक व्यवहार।
डॉ. कनुप्रिया, (अनुबंध पर)	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र), एम.ए. (अर्थशास्त्र), बी.ए. (ऑनर्स) (अर्थशास्त्र)	(अर्थशास्त्र)
डॉ तनवीर अहमद,	पीएच.डी., बी.ई., एम.टेक.,	संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन; मात्रात्मक तकनीक
डॉ. प्रतीक माहेश्वरी,	पीएच.डी., एम.बी.ए. (मार्केटिंग) यूजीसी-नेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक संकाय विकास में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीएफडी), एस्टन विश्वविद्यालय, बर्मिंघम, यूके	अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रबंधन, विज्ञापन और प्रचार प्रबंधन, ग्रामीण विपणन, प्रबंधन के मूल सिद्धांत।
डॉ. ओली मिश्रा,	पीएच.डी., यूजीसी नेट (प्रबंधन), एम.बी.ए. (आईबी), बीबीए	वपणन प्रबंधन के क्षेत्र में शोधकर्ता और शक्षा वद। शोध के क्षेत्र हैं:- डजिटल मार्केटिंग, सामाजिक उद्य मता, मतव्ययी नवाचार, उपभोक्ता व्यवहार शक्षण रु च के क्षेत्र:

		उपभोक्ता व्यवहार, वपणन प्रबंधन, उद्य मता
डॉ. तुहीना मुखर्जी,	पीएच.डी., नेट (यूजीसी), मनोविज्ञान, एम.ए. (मनोविज्ञान)	संगठनात्मक व्यवहार/मानव संसाधन प्रबंधन।
डॉ. रघुवीर नेगी, (अनुबंध पर)	पीएच.डी. (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार), एम.कॉम. (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार), बीबीए (प्रबंधन), निर्यात प्रबंधन में डिप्लोमा	व्यापार और रसद
डॉ. मुहम्मद रफ़ी ओपीसी,	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र), एम.फिल. (अर्थशास्त्र), एम.ए. अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, बी.ए. (अर्थशास्त्र)	अर्थशास्त्र
डॉ. सिद्धार्थ शंकर राय,	बीबीए, एमबीए, पीएचडी.	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, रसद और वितरण प्रबंधन, संचालन प्रबंधन, स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला जवाबदेही, मानवीय रसद
डॉ अरुणिमा राणा,	पीएच.डी. (बिट्स पिलानी), एम.बी.ए. (मार्केटिंग), यूजीसी-नेट	विपणन प्रबंधन, ब्रांड प्रबंधन, उपभोक्ता व्यवहार मॉडलिंग, डिजिटल मार्केटिंग।
डॉ. नमन शर्मा,	पीएच.डी. (प्रबंधन), एम.बी.ए., यूजीसी-नेट	सामान्य प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार मानव संसाधन प्रबंधन।
डॉ. पारुल सिंह	पीएच.डी., एम.बी.ए. (मानव संसाधन, विपणन), नेट और जेआरएफ (यूजीसी), बी.टेक. (कंप्यूटर साइंस)	सूचना प्रौद्योगिकी और विपणन
डॉ. प्रीति टाक,	पीएच.डी., एम.बी.ए. (मार्केटिंग) यूजीसी-नेट	विपणन प्रबंधन, सेवाओं का विपणन, उपभोक्ता व्यवहार, बिक्री और वितरण प्रबंधन।
डॉ. दिव्या टुटेजा,	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र), यूजीसी नेट, एम.ए. (अर्थशास्त्र), बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	समष्टि अर्थशास्त्र, वित्तीय बाजार, मौद्रिक सिद्धांत, अर्थमिति और पूर्वानुमान, विकास अर्थशास्त्र।
डॉ. जे.के. वर्मा,	पीएच.डी., एम.टेक., बी.टेक.	शोध क्षेत्र: क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल: हाडोप, आर, पायथन, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, ईआरपी सिस्टम
डॉ. सोनू वर्मा,	पीएच.डी., एम.बी.ए. (मार्केटिंग, स्वर्ण पदक विजेता), प्रबंधन में नेट (यूजीसी), बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स)	व्यवसाय सांख्यिकी, व्यवसाय अनुसंधान विधियां, विपणन अनुसंधान, संचालन प्रबंधन, अनुसंधान पद्धति, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
डॉ. कविता वाधवा,	पीएच.डी. (वित्त), पी.एच.डी. (लेखा), विजिटिंग स्कॉलर प्रोग्राम (वीएसपी), व्हिटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क एम.फिल. (वित्त एवं लेखा), एम.कॉम. (वित्त एवं लेखा)	वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन, वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधन और म्यूचुअल फंड, एमएस-एक्सेल का उपयोग करके वित्तीय मॉडलिंग।
डॉ. रश्मि रस्तोगी	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र), बिजनेस इकोनॉमिक्स में एम.फिल., बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, बी.कॉम. (ऑनर्स)	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पर्यावरण, सार्वजनिक वित्त।

डॉ. मिकलेश प्रसाद यादव	पीएच.डी. (वित्त), यूजीसीनेट (प्रबंधन), एम.बी.ए. (वित्त)	शोध रुचि: अस्थिरता पूर्वानुमान, स्पिलओवर अस्थिरता, कॉर्पोरेट वित्त, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शिक्षण रुचि: कॉर्पोरेट वित्त, सुरक्षा विश्लेषण और मूल्यांकन, पोर्टफोलियो प्रबंधन, वित्तीय व्युत्पन्न, वित्तीय अर्थमिति

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र		
प्रोफ़ेसर एवं प्रमुख		
डॉ. प्रीतम बनर्जी,	पीएचडी (लोक नीति) एम.ए. (अर्थशास्त्र)	विश्व अर्थव्यवस्था, रसद क्षेत्र।
प्रोफेसर		
डॉ. मुरली कल्लुममल,	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र) एम.ए. (औद्योगिक अर्थशास्त्र), एम.फिल. (औद्योगिक अर्थशास्त्र),	व्यापार और पर्यावरण, निवेश और व्यापार, गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए) मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ वार्ता, एसपीएस और टीबीटी उपाय (गैर-टैरिफ उपाय), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मानकों की भूमिका, एसपीएस और टीबीटी पर वेब पोर्टल, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)।
डॉ. सचिन कुमार शर्मा,	पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)	व्यापार और विकास, कृषि और विश्व व्यापार संगठन।
एसोसिएट प्रोफेसर		
डॉ. प्रलोक गुप्ता	पीएच.डी., एम.बी.ई., यूजीसी - नेट	सेवा व्यापार का अर्थशास्त्र, विश्व व्यापार संगठन और संबंधित मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, व्यापार और निवेश संबंध, ई-कॉमर्स।
सहायक प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर स्तर के सलाहकार		
डॉ. अनिमेष कुमार,	पीएच.डी., एम.एससी.	अर्थशास्त्र।
व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र		
प्रोफ़ेसर एवं प्रमुख		
डॉ. जेम्स जे. नेदुम्पारा,	पीएच.डी. (एनएलएस, बी'लोर), एलएलएम (कैम्ब्रिज), एलएलएम (एनवाईयू), एलएलएम (एनयूएस), एलएलबी (एमजीयू)	सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, निवेश कानून, व्यापार उपचार, एसपीएस/टीबीटी, डब्ल्यूटीओ विवाद।
एसोसिएट प्रोफेसर		
सुश्री शैलजा सिंह,	एलएलएम, एलएलबी (ऑनर्स), बीए,	विश्व व्यापार संगठन विवाद, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित अन्य कानूनी पहलू, निवेश और ई-कॉमर्स
सहायक प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर स्तर के सलाहकार		
सुश्री शाइनी प्रदीप	एलएलएम, बीएएलएलबी (ऑनर्स)	अंतर्राष्ट्रीय कानून और पर्यावरण कानून और व्यापार का इंटरफेस।
श्री सात्विक शेखर,	एलएलएम, एलएलबी	डब्ल्यूटीओ कानून, व्यापार विनियमन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून।
सुश्री अपर्णा भट्टाचार्य,	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून।

	से बी.ए. एलएलबी (ऑनर्स), ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून में एल.एल.एम.	
सुश्री सुनंदा तिवारी,	ए मटी वश्व वद्यालय, उत्तर प्रदेश से बी.ए. एलएलबी (ऑनर्स)। एलएलएम - ए डनबर्ग वश्व वद्यालय, यूनाइटेड कंगडम	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून
सुश्री रोंजिनी रे,	बीबीएएलएल.बी. - सम्बायो सस लॉ स्कूल, पुणे, एलएलएम - अंतर्राष्ट्रीय कानून में ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज (आईएचईआईडी), जिनेवा	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून

आईआईएफटी प्रशासन
(प्रकाशन तिथि के अनुसार)

पदनाम	गैर-शिक्षण कर्मचारियों का नाम	फोन नंबर
कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)	श्री. गौरव गुलाटी	011-39147210 011-39147211
उप कुलसचिव (परियोजना, शैक्षणिक, पुस्तकालय, हिंदी)	श्री. गौरव गुलाटी	011-39147306
उप वित्त अधिकारी	श्री पीतांबर बेहरा	011-39147317
उप कुलसचिव संपदा एवं रखरखाव, मानव संसाधन, सामान्य प्रशासन, आरटीआई और व ध वभाग	श्री. अमित कुमार चनपुरिया	011-39147200 (एक्स 508)
सहायक कुलसचिव	श्री भुवन चंद्र	011-39147200 (एक्स 615)
	श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना	011-39147200 (एक्स 505)
	श्रीमती नलिनी मेश्राम	011-39147249 (एक्स 506)
	श्री विनय गोयल	
	श्री पार्थ शाह	
सहायक वित्त अधिकारी	श्रीमती दीपा पी जी	011-39147247
अनुभाग अधिकारी	श्री अनिल कुमार मीणा	011-39147226
	श्री द्वैपायन ऐश	033-24195700
	श्री गौरव गुप्ता (प्रतिनियुक्ति पर)	
	श्रीमती होइजाहत बाइट	011-39147322
	सुश्री जया फुलवानी	
	श्री जितेंद्र सक्सेना	011-39144221
	श्री करुण दुग्गल	011-39147319
	श्रीमती कविता शर्मा	011-39147213
	श्रीमती ललिता गुप्ता	011-39147200
	श्रीमती मोहिनी मदान	011-39147323
	श्री राहुल कपूर	011-39147315
	श्री राकेश कुमार ओझा	011-39147321
	श्रीमती सुमिता मरवाहा	011-39147223
लेखा अधिकारी	श्री एम. वादी वेलु	033-24195700
हिंदी अधिकारी	श्रीमती कविता शर्मा (अतिरिक्त प्रभार)	011-39147321

आईआईएफटी सहायता सेवाएँ

गैर-शिक्षण कर्मचारियों का नाम	पदनाम	फोन नंबर
प्रमुख, सीआर सी ए डी	सैकेत बनेर्जी	
सिस्टम प्रबंधक	श्री बिमल कुमार पांडा	011-39147222
सहायक सिस्टम प्रबंधक	श्री एस बालासुब्रमण्यम	011-39147200 (एक्स 102)
कंप्यूटर प्रोग्रामर	श्री सनी कुमार	011-39147200 (एक्स 103)
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	श्री प्रणित लांडगे	011-39147383
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	सुश्री वैदेगी धमोदरन	

अतिथि संकाय

नाम	पदनाम	संगठन
प्रोफेसर चन्द्रशेखर भुवनगिरी	प्रोफेसर	डीकिन विश्वविद्यालय, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर (गुजरात) में विजिटिंग फैकल्टी
प्रोफेसर हर्ष वर्धन	प्रोफेसर	विभिन्न प्रसिद्ध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर
प्रो बिप्लब भट्टाचार्य	सह - प्राध्यापक	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो अरुण पांडे	प्रोफेसर	संस्थापक एवं प्रबंध निदेशकSANPRI कंसल्टेंसी, ह्यूस्टन, टेक्सास (अमेरिका)
प्रो.संजीव शंकर दुबे	प्रोफेसर	भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रसिद्ध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर
प्रो नीता त्रिपाठी	व्यावसायिक विशेषज्ञता	अतिथि समन्वयक
प्रो शिखर रंजन	निदेशक	एशियाई अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन दिल्ली
प्रोफेसर राकेश सेठ	संस्थापक निदेशक	नेतृत्व के विषय में प्रो. सेठ का कथन
प्रोफेसर सुनीता डेनियल	सह - प्राध्यापक	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
डॉ गौरव कुमार	सहायक प्रोफेसर	एनआईटी जालंधर
डॉ.नलिन जैन	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
डॉ.सतीश दुबे		
डॉ शिलादित्य दासगुप्ता	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
डॉ.अरुण के.पांडेय	संस्थापक और प्रबंध निदेशक	संप्री कंसल्टेंसी
डॉ.राहुल मिश्रा	प्रोफेसर	आईआईएलएम, नई दिल्ली
डॉ.एम.पी.सिंह	निदेशक,	एसएमआई, दुबई
डॉ. प्रवेश अघी	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
डॉ अर्घो बंद्योपाध्याय	लेक्चरर	आरएमआईटी मेलबोर्न
डॉ अनिता सिंह	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक	एमडीआई, गुड़गांव
डॉ.हर्षवर्धन	प्रोफेसर	ओ.पी.जिंदल विश्वविद्यालय
डॉ.जीता सरकार	सहायक प्रोफेसर	जयपुरिया प्रबंधन संस्थान
डॉ. साहिल गुप्ता	सह - प्राध्यापक	जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस
प्रो.अंकिता नागपाल	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी

प्रो. नितिन सेठ	निदेशक	उन्नत अनुसंधान संवर्धन हेतु भारत-फ्रांसीसी केंद्र
प्रोफेसर अनिरुद्ध घोष	फैकल्टी	आईसीएफएआई बिजनेस स्कूल, गुरुग्राम
प्रोफेसर आशीष द्विवेदी	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो विपुलेश शरददेव	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो.नीरज गेहानी	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो कुमार गौरव	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रोफेसर सुनीता डेनियल	सह - प्राध्यापक	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
प्रो बिप्लब भट्टाचार्य	सह - प्राध्यापक	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो. शशांक शेखर शर्मा	सीईओ और संस्थापक	ब्रेनपैन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
प्रो अभिषेक मित्तल	निदेशक एम एंड ए	मेर्सक सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
प्रो राहुल प्रताप सिंह कौरव	फैकल्टी	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
प्रो. रिक पॉल	फैकल्टी	बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय
प्रोफेसर हर्ष वर्धन	प्रोफेसर	विभिन्न प्रसिद्ध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर
प्रोफेसर चन्द्रशेखर भुवनगिरी	प्रोफेसर	डीकिन विश्वविद्यालय, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर (गुजरात) में विजिटिंग फैकल्टी
प्रोफेसर सरबजीत बुटालिया	प्रशिक्षण सलाहकार	वीशिप्स (यूके)
प्रो. तरूण केहैर	सीए	सीए तरुण केहैर एंड कंपनी
प्रो. मनप्रीत कौर	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रोफेसर दिशांत पोपली	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी
प्रो.योगेश कुमार वर्मा	सीईओ	प्रबंधन परफेक्ट स्क्वायर
प्रो. शशांक शेखर शर्मा	सीईओ और संस्थापक	ब्रेनपैन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
प्रो अभिषेक मित्तल	निदेशक एम एंड ए	मेर्सक सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
प्रोफेसर नवीन कुमार	फैकल्टी	संस्थापक और प्रबंध साझेदार, नवीन एंड नवीन
प्रोफेसर रमेश बहल	प्रोफेसर एवं निदेशक	आईएमआई, नई दिल्ली
प्रो.संजीव नंदवानी	महासचिव	व्यावसायिक विशेषज्ञता अतिथि समन्वयक
प्रो. तमन्ना चतुर्वेदी	विजिटिंग फैकल्टी	विजिटिंग फैकल्टी

स्थायी सदस्यों की सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	ए सरकार एंड कंपनी (ज्वैलर्स) प्रा. लिमिटेड कोलकाता
2.	कृषि. एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नई दिल्ली
3.	अल्लाना कोल्ड स्टोरेज प्रा. लिमिटेड मुंबई
4.	अमरावती टेक्सटाइल्स करूर
5.	अमृतांजन लिमिटेड चेन्नई
6.	एंग्लो फ्रेंच ड्रग कंपनी (ईस्टर्न) लिमिटेड बेंगलुरु
7.	एआईएमआईएल लिमिटेड नई दिल्ली
8.	एलेप्पी कंपनी लिमिटेड एलेप्पी
9.	प्रबंधन अध्ययन अकादमी देहरादून
10.	अलंकार ग्लोबल प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली
11	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली
12.	अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड अहमदाबाद
13.	बी.टी.एक्स. केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड मुंबई
14.	बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड चेन्नई
15.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु
16.	भारत मोटर्स चेन्नई
17.	बर्ड एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड कोलकाता
18.	बैंक ऑफ बड़ौदा नई दिल्ली
19.	बॉम्बे डाइंग एंड एमएफजी. कंपनी लिमिटेड मुंबई
20.	भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली
21.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद मुंबई
22.	भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद कोचीन
23.	सिएट टायर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई
24.	चेज़ ब्राइट स्टील कंपनी लिमिटेड, मुंबई
25.	चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट, भारत नई दिल्ली

26.	चिलीज़ एक्सपोर्ट हाउस लिमिटेड विरुधुनगर
27.	सिम्को इंटरनेशनल नई दिल्ली
28.	कैपेक्सिल(CAPEXIL) कोलकाता
29.	कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु
30.	कॉयर बोर्ड कोच्चि
31.	वाणिज्य एवं निर्यात संवर्धन विंग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
32.	चमड़ा निर्यात परिषद चेन्नई
33.	कालीन निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली
34.	क्रिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई
35.	उद्योग निदेशालय हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
36.	उद्योग निदेशालय मध्य प्रदेश सरकार भोपाल
37.	उद्योग निदेशालय महाराष्ट्र सरकार मुंबई
38.	डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, हैदराबाद
39.	निर्यात संवर्धन एवं विपणन निदेशालय उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर

40.	उद्योग और वाणिज्य निदेशालय कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु
41.	धनलक्ष्मी वीविंग वर्क्स, कन्नानोर (केरल)
42.	डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड मुंबई
43.	ईसीजीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई
44.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली
45.	एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई
46.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक नई दिल्ली
47.	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
48.	एस्कॉर्ट्स लिमिटेड फ़रीदाबाद
49.	फ़ेडरल बैंक लिमिटेड अलवे
50.	फर्न्स एक्सपोर्ट्स मुंबई
51.	खाद्य निगम भारत, नई दिल्ली
52.	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
53.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड, कोचीन

54.	फिकॉम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मुंबई
55.	फोम मैटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड एलेप्पी
56.	जीएसटी निगम नई दिल्ली
57.	जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड नई दिल्ली
58.	ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड मुंबई
59.	ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड मुंबई
60.	मूंगफली एक्सट्रेक्शन्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन मुंबई
61.	गुजरात अल्कलीज़ एंड केमिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा
62.	गुरु नानक मर्केंटाइल कंपनी जालंधर
63.	गुजरात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद गांधी नगर
64.	गीके एक्ज़िम (आई) लिमिटेड मुंबई
65.	गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम) विशाखापत्तनम
66.	जी प्रेमजी लिमिटेड बैंकॉक
67.	गीतांजलि एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई
68.	जेम एंड ज्वैलरी ईपीसी मुंबई
69.	गीतांजलि जेम्स लिमिटेड मुंबई
70.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटेड चंडीगढ़
71.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड बैंगलोर
72.	हीरो साइकिल प्रा. लिमिटेड लुधियाना
73.	प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटेड शिमला
74.	हिल टिलर एंड कंपनी बेंगलुरु
75.	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रांची
76.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई
77.	हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड मुंबई
78.	हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर
79.	हैदराबाद लैम्प्स लिमिटेड सिकंदराबाद
80.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड नई दिल्ली
81.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली

82.	आईटीसी लिमिटेड कोलकाता
83.	भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली
84.	भारत-सीआईएस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली
85.	भारतीय निर्यात एवं आयात प्रबंधन संस्थान मुंबई
86.	इंडियन बैंक चेन्नई
87.	इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन, नई दिल्ली
88.	इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई
89.	इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली
90.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई
91.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मुंबई
92.	इंडिया शुगर एंड जनरल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
93.	भारतीय निर्यात प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु
94.	इम्केमेक्स इंडिया लिमिटेड मुंबई
95.	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड नई दिल्ली

96.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड, श्रीनगर
97.	भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कोलकाता
98.	किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड पुणे
99.	केरल राज्य निर्यात व्यापार विकास परिषद त्रिवेन्द्रम
100.	किसान उत्पाद लिमिटेड बेंगलुरु
101.	किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड पुणे
102.	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम तिरुवनंतपुरम
103.	केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, कोच्चि
104.	कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम लिमिटेड बेंगलुरु
105.	खुशीराम बिहारी लाल लिमिटेड दिल्ली
106.	कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड बेंगलुरु
107.	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड कोयंबटूर
108.	लोटस इंटरनेशनल मुंबई
109.	एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड, कोयंबटूर

110.	लिबर्टी फुटवियर कंपनी करनाल
111.	मारुति उद्योग लिमिटेड नई दिल्ली
112.	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई
113.	मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई
114.	मैग्नम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली
115.	मैसूर कॉफ़ी क्योरिंग वर्क्स लिमिटेड, चिकमंगलूर
116.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि
117.	एमएसटीसी लिमिटेड कोलकाता
118.	मेटल बॉक्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड चेन्नई
119.	महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम लिमिटेड मुंबई
120.	मेकॉन लिमिटेड नई दिल्ली
121.	मीका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड कोलकाता
122.	एमएमटीसी लिमिटेड नई दिल्ली
123.	एमएसएसआईडीसी लिमिटेड मुंबई

124.	मोहन एक्सपोर्ट्स (इंडिया) लिमिटेड नई दिल्ली
125.	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड पुणे
126.	मैक्सवेल एक्ज़िम लिमिटेड पांडिचेरी
127.	एमवीआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पांडिचेरी
128.	मेट्रोकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड अहमदाबाद
129.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली
130.	नागार्जुन साइनॉड्स लिमिटेड हैदराबाद
131.	नरूला उद्योग (आई) प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली
132.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद
133.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद
134.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली
135.	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई
136.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड नई दिल्ली
137.	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नई दिल्ली

138.	न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता
139.	नव भारत कॉर्पोरेशन मुंबई
140.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुंबई
141.	आयुध फैक्टरी बोर्ड कोलकाता
142.	ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली
143.	पैन फूड्स लिमिटेड पानीपत
144.	पावरलूम विकास एवं ईपीसी मुंबई
145.	पैम फार्मास्यूटिकल्स (दिल्ली) लिमिटेड दिल्ली
146.	पीएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोयंबटूर
147.	पीसीआई लिमिटेड नई दिल्ली
148.	पॉलीओलेफिन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई
149.	पारेख ब्रदर्स मुंबई
150.	पंजाब एंड सिंध बैंक नई दिल्ली
151.	प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली

152.	पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली
153.	रानी एजेंसी सेलम
154.	रबर बोर्ड कोट्टायम
155.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम
156.	रेकिट एंड कोलमैन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता
157.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर
158.	सु-राज डायमंड्स (आई) लिमिटेड मुंबई
159.	सतनाम ओवरसीज लिमिटेड नई दिल्ली
160.	शाह न्यूमेटिक्स मुंबई
161.	सांगली बैंक लिमिटेड सांगली
162.	श्रीजी केमिकल्स अहमदाबाद
163.	शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड मुंबई
164.	एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली
165.	श्रीराम जूट मिल्स लिमिटेड, कोलकाता

166.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता
167.	सेल इंटरनेशनल लिमिटेड नई दिल्ली
168.	सांघवी एक्सपोर्ट्स मुंबई
169.	सिंथेटिक एवं रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मुंबई
170.	मसाला बोर्ड कोचीन
171.	स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नई दिल्ली
172.	सेठ घासीराम गोपीकिशन बद्रुका एजुकेशनल सोसायटी (पंजीकृत) हैदराबाद
173.	टी. अब्दुल वाहिद एंड कंपनी चेन्नई
174.	टाटा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मुंबई
175.	टाटा इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड मुंबई
176.	टेक्नोफैब इंजी. लिमिटेड नई दिल्ली
177.	टेक्समैको लिमिटेड कोलकाता
78.	चाय बोर्ड कोलकाता
179.	थर्मैक्स लिमिटेड पुणे
180.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद
181.	टीएनटी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली
182.	यूबी एक्सपोर्ट्स बेंगलुरु
183.	यूपी कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ
184.	यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली
185.	उषा इंटरकांटिनेंटल (भारत) नई दिल्ली
186.	वीडी स्वामी एंड कंपनी लिमिटेड चेन्नई
187.	वीएस डेम्पो एंड कंपनी लिमिटेड पणजी
188.	वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स लिमिटेड लुधियाना
189.	वासु अगरबत्तीज़ मैसूर
190.	विक्टर टूल्स प्रा. लिमिटेड जालंधर
191.	वीबीसी एजुकेशनल सोसायटी विशाखापत्तनम
192.	वोल्टास लिमिटेड हैदराबाद यूनिट हैदराबाद

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित)

दिल्ली कैम्पस
आईआईएफटी भवन, बी–21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016
फोनः 011–39147200 – 205 (पीबीएक्स)

कोलकाता कैम्पस
1583, मदुरदाहा, चौबाघा रोड, वार्ड नंबर 108, बोरो XII,
कोलकाता–700107
फोनः 033–35014500, 35014600 (पीबीएक्स)

काकीनाड़ा कैम्पस
आईआईएफटी बिल्डिंग, जेएनटीयूके कैंपस
काकीनाड़ा–533003
फोनः 0884–2944655, 2944955

गिफ्ट सिटी कैम्पस
गिफ्ट टावर 2, 16वां एवं 17वां तल,
रोड 5सी, जोन, गिफ्ट सिटी,
गांधीनगर–382050
फोनः 9875171119

www.iift.ac.in